राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] चौदहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या: 10

गुरुवार,
09 मार्च 2017

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री शंकरसिंह।

प्रदेश में रोडवेज को घाटे से उबारने की योजना

190. श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में लोक परिवहन सेवा किस उद्देश्य से चालू की गयी है एवं इसके तहत संचालकों को किन शर्तों एवं नियमों के तहत स्वीकृति दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 को लोक परिवहन बस संचालकों द्वारा ब्यावर डिपो के अंदर घुसकर रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट की गयी थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त डिपो में लोक परिवहन संचालकों की मिलीभगत से पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया? यदि हां, तो कब व लोक परिवहन संचालकों एवं रोडवेज कर्मचारियों द्वारा दर्ज शिकायतों पर संबंधित पुलिस थाने द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राजस्थान रोडवेज को उबारने के लिए लोक परिवहन सेवा को बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री युनुस खान): (1) प्रदेश में लोक परिवहन सेवा राज्य के नागरिकों को सड़क परिवहन की सुलभ, सुरक्षित एवं सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चालू की गयी है। इन बसों के संचालन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार के प्रस्ताव संख्या एस.टी.ए.-03/2015 दिनांक 02.09.2015, प्रस्ताव संख्या-01/2016/615 दिनांक 13.01.2016 एवं क्रमांक एफ.9 (253) परि/आरटीए/एसटीए/98-99 /पार्ट-3179 दिनांक 18.02.2016 के द्वारा लोक परिवहन सेवा हेतु मॉडल कंडीशन एवं अन्य शर्तों का निर्धारण किया गया है। प्रस्तावों की छाया प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। दिनांक 15.12.16 को ब्यावर डिपो के अन्दर मारपीट की घटना न होकर डिपो के बाहर सड़क पर मारपीट हुई है। इस संबंध में लोक परिवहन बस संचालकों तथा रोडवेज कर्मचारियों ने मारपीट इत्यादि के संबंध में एक दूसरे के विरुद्ध पुलिस थाना ब्यावर सिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट (मुकदमा संख्या-860 व 861 दिनांक 15.12.16) दर्ज करवायी है जिसमें तफ्तीश जारी है जिसकी प्रफोर्मा अनुसार सूचना मय प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है। उपरोक्तानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान जारी है। उक्त प्रकरण में दिनांक 15.12.2016 को ही श्री भगवाना राम पुत्र श्री भागीरथ राम निवासी रासीसर, बीकानेर को जाप्ता फौजदारी की धारा 151 में गिरफ्तार किया गया। वर्तमान में उक्त दोनो प्रकरणों (एफ.आई.आर.) में तफ्तीश जारी है।

(4) जी नहीं। रोडवेज को उबारने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई अन्य तरह की वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायताएं दी जा रही हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, नम्बर एक।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम, लोक परिवहन सेवा के संचालकों द्वारा रोडवेज कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ में मारपीट हुई। झगड़ा रोडवेज परिसर के अदंर हुआ था। पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। लोक परिवहन की बसों को,

(श्री शंकर सिंह)

रोडवेज डिपो के बिलकुल सामने लाकर खड़ी करके, उनको भरने का काम, इजाजत पुलिस के द्वारा दी गयी थी। उसके ऊपर रोक लगाई जाए। अगर रोडवेज को हम उबारने का काम कर रहे हैं तो, घाटे से उबारने का काम करें। रोडवेज के सामने लोक परिवहन सेवा की गाड़ियां नहीं रुकें, इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, आपके पास यह गलत रिपोर्ट पेश की गई है। यह झगड़ा हुआ उस दिन मैं ब्यावर ही था। यह रोडवेज परिसर के अंदर हुआ इसलिए उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। आपकी तरफ से इसके ऊपर यह बात आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को जो अभी एफआईआर मिली है। चाहे 860 नम्बर का मुकदमा है या 861 का है, दोनों में ही घटना स्थल बाहर दिखाया गया है। दोनों ही प्रकरण दर्ज हुए हैं। उसी के आधार पर मैंने सदन में जवाब दिया है। चूंकि अभी तफ्तीश जारी है। इसका अनुसंधान होने के बाद ही, जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और पूछना चाहूंगा, क्या यह लोक परिवहन सेवा की गाड़ियां, डिपो के अंदर ही खड़ी रहेंगी?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चूंकि दोनों केस पुलिस ने दर्ज किए हैं इसलिए अब तक जो कुछ भी प्रोग्रेस है वह भी मैं आपके सामने रख देता हूं। 15.12.16 की घटना थी। यह सही है कि पुलिस दोनों ही केस में, घटना बाहर की बता रहे हैं। आपका कहना है कि घटना अंदर की है। मैं इसको दुबारा किसी वरिष्ठ अधिकारी से एक बार और दिखवा लूंगा।

दूसरा यह है कि 480 है इसमें जो 7 मुल्जिम हैं उनको गिरफ्तार भी किया और उनका 6.3 को हमने कोर्ट में चालान कर दिया, आदेश 82/17 के तहत चालान पेश कर दिया। जो 861 है उसमें अभी इन्वेस्टीगेशन चल रहा है

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

क्योंकि उन्होंने उसमें 379 उनके ऊपर लगाई है। वास्तव में कोई चीज चोरी या नहीं चोरी हुई है। रोड़वेज कर्मचारियों पर लगाई है उसका इन्वेस्टीगेशन अभी बाकी है। बाकी जो लोक परिवहन है उनके लोगों को हमने गिरफ्तार करके कोर्ट में चालान पेश कर दिया।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय गृहमंत्री के द्वारा बिलकुल सत्य बात कही जाती है। पीड़ित के प्रति आप हमेशा अच्छा सोच रखकर, अच्छा न्याय करने की कोशिश करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि पुलिस के द्वारा मुकदमे दर्ज किए थे, उसमें रोडवेज कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई और लोक परिवहन कर्मचारियों द्वारा संयुक्त गिरोह बनाकर, उन अधिकारियों को भी मारा, अभी उस का यहां से ट्रान्सफर भी कर दिया। खैर, कोई बात नहीं ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है लेकिन मारपीट उन्हीं के साथ हुई। जिस कंडक्टर के साथ बुरी तरह से मारपीट हुई, मैं सारे प्रूफ लेकर आया हूं, आप जिस दिन कहोंगे मैं बता दूंगा समय देकर। उनको न्याय मिलना चाहिए। उन्हीं को मुलजिम बनाया और उन्हीं के द्वारा वह पिट रहा है। कंडक्टर के पास पैसे होंगे, कंडक्टर ने सामने वाले, लोक परिवहन वाले के पैसे निकाल दिए, यह समझ से परे की बात है। उलटे मुक़दमे दर्ज किए गए हैं। उसमें पुलिस की बहुत ज्यादा लापरवाही रही है। मेरा आपसे आग्रह है कि थोड़ा सीरियसली लेकर आप उसमें सुधार करवाएं, न्याय दिलाए जाने की कृपा करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो मुकदमा 860 है, नम्बर 17, वह रोड़वेज कर्मचारियों के द्वारा दर्ज किया हुआ लोक परिवहन पर है। उसका हमने इन्वेस्टीगेशन करके उन सात लोगों को मुलजिम मानते हुए उनका कोर्ट में चालान पेश कर दिया। लोक परिवहन के लोगों ने रोडवेज़ के कर्मचारियों पर जो 861 लगाया है उसमें उन्होंने एक धारा 379 लगाई है। इसके कारण से उसका इन्वेस्टीगेशन अभी पूरा नहीं हुआ है। कोई पैसा चोरी, या निकाला, यह अभी तक प्रमाणित नहीं हो रहा है। इसके कारण से रोडवेज के लोगों के खिलाफ केस हैं उसमें अभी चालान

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं किया गया है, अभी वह इन्वेस्टीगेशन में चल रहा है। आपका यह कहना कि बाहर हुआ या अंदर हुआ, इसमें मैं एडिशनल एस.पी. को जांच हेतु भेजता हूं। वस्तुस्थिति, अगर अंदर हुआ तो धाराएं भी बदलेंगी, केस भी बदलेगा, अगर बाहर हुआ है तो जैसा केस दर्ज हुआ उसके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा निवेदन यह है कि पैसे की जो बात आती है, मैं नहीं मानता हूं कि झगड़े के अंदर, झगड़ा करेगा आपस में, उसको मारपीट करेगा या पैसा निकालने के लिए जेब में हाथ डालेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज): यहां इन्वेस्टीगेशन थोड़े हो रहा है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इस प्रकार की बात नहीं है। उसको न्याय दिलाएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, आ गया जवाब। पूरक प्रश्न श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा इतना ही निवेदन है कि लोक परिवहन सेवा और रोडवेज़ जनोपयोगी सरकार के द्वारा एक निगम है। इसका संरक्षण सरकार को करना चाहिए। कहीं ऐसी प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से माफिया डवलप नहीं हो जाए, इस बात का विचार हमें करना चाहिए। दूसरा, गृह मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके लिए भी मेरा निवेदन है कि .....

श्री अध्यक्ष: जब मंत्री इन्वाल्व हो गये, आप किस मंत्री से जवाब चाहेंगे?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सदन में माननीय सदस्य ने कहा है, इसलिए इनसे भी जानकारी लेकर इसकी तटस्थता से पूरी खोजबीन होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): अगर लोक परिवहन वालों ने गड़बड़ की है तो उनको पूरी सज़ा मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। कौन देगा जवाब? आ गया, जवाब पहले ही आ गया।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं ही दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप दे दीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है कि माफिया नहीं पनपना चाहिए। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रदेश है और हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें नई सड़कों का निर्माण भी हुआ है, जनसंख्या भी बढ़ी है। जहां तक रोडवेज का सवाल है, यह बात सही है कि वह ऑटोनोमस बॉडी है, उसका काम है जनता को सेवाएं देना।

अगर हम पिछले 30 साले की हिस्ट्री देखें, सरकार किसी की भी रही हो, उस 20 साल में रोडवेज का जो फ्लीट है उसका औसत लगभग 4591 बसों का रहा है। 4591 बसें टोटल फ्लीट में रही हैं चाहे कांग्रेस के दो रिज्यूम देख लो और यह दूसरा रिज्यूम हमारा चल रहा है। इनमें औसत जो बसों की सेवाएं हैं वो तो 4591 हैं और जो हमारे रूट्स या परमिट हैं वो लगभग 6000 रोडवेज के पास रहते हैं जबकि राजस्थान में आज की तारीख में लगभग 44 हजार प्राइवेट सैक्टर के लोग स्टेट कैरिज के माध्यम से सेवाएं देते हैं। राज्य सरकार का हमेशा यह ध्येय रहता है कि हम जनता को सेवाएं कैसे दें। उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी बसें चलानी होती हैं, नेशनल हाइवेज पर भी चलानी होती हैं तो उसमें समय-समय पर अलग-अलग स्कीम हम इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कभी सब-अरबन के लिए, कभी अरबन के लिए, कभी स्टेट कैरिज में सुविधाएं देते हैं। उसी की कड़ी में ये जो हमारे नेशनलाइज्ड रूट्स थे उन पर हमने लोक परिवहन सेवा की शुरूआत की और अब मैं इतना हाउस को और माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि दोनों का अनुसंधान एडिशनल एस.पी. के स्तर पर हो जाएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।

लेकिन मैं इतना कहूंगा कि चाहे लोक परिवहन सेवाएं हों, चाहे रोडवेज की बसें हों, चाहे प्राइवेट सैक्टर का व्यक्ति हो, कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। रोडवेज के लोगों की जिम्मेदारी है कि जो उनको परमिट दिया

(श्री युनुस खान)

गया है उस पर चलें, लोक परिवहन सेवा वालों की जिम्मेदारी है कि उनका परमिट दिया उस पर चलें और प्राइवेट लोगों की जिम्मेदारी है कि जो उनको परिमिट दिये हैं उन पर चलें। लेकिन समय-समय पर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं वो नहीं हों उसके लिए हम प्रयास करें, बैठकर भी समझाइश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वस्त कर सकता हूं कि अनुसंधान बिल्कुल निष्पक्ष होगा और माननीय गृह मंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर इस बात का जवाब दे दिया तो निश्चित रूप से एडिशनल एस.पी. स्तर के अधिकारी से ये जांच करा ही रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक परिवहन सेवा का सरकार के द्वारा परमिट दिया गया है। झगड़े की जो मूल जड़ है वह सरकार ही है माननीय अध्यक्ष महोदय। इन्होंने लोक परिवहन सेवा को परमिट दे दिए। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि लोक परिवहन सेवा की बसें आपके रोडवेज बस स्टैण्ड से चलेंगी या कहीं बाहर से उनकी अलग से आपने कोई व्यवस्था की है? उसमें जो मूल है, लोक परिवहन सेवा के जो नियम, कानून, कायदे आपने बनाये हैं उन नियम, कानून, कायदों को सरकार फोलो नहीं कर रही है। अब आपने उनको लिखकर दे दिया लोक परिवहन को कि रोडवेज बस स्टैण्ड के अन्दर आपको एक डैस्क दी जाएगी, आप वहां अपनी बुकिंग कर सकते हो, वहां से सवारियां उठा सकते हो। रोडवेज बस और उनके आपस में झगड़ा इसी बात का है। लोक परिवहन सेवा को आपने परमिट दे दिया, पैसे आपने ले लिए, एक-एक बस से आप 50-50 हजार रुपये महीने के टैक्स ले रहे हो। उनमें ऐसे-ऐसे ओनर बैठे हैं, आपने पहले तो उसमें यह कर दिया कि लोक परिवहन सेवा की वो कम्पलीट बसें बनाकर फिर एप्लाई करेगा और आज वो बसें बनी हुई पड़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज एक बस 40 लाख रुपये में बनती है 3X2 की। 40 लाख रुपये की बसें आज सड़क पर खड़ी हैं और आप उनको परमिट नहीं दे रहे हैं। जिसको आपने परमिट दिया है वो भी रो रहा है और जिसको परमिट नहीं दिया वो भी रो रहा है। ऐसे हालात आपने पूरे प्रदेश के अन्दर

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

कर दिए हैं। रोडवेज को हम यह कह रहे हैं, हम सबका दायित्व है रोडवेज को बचाना, उसका संरक्षण करना, वो किस तरीके से फायदे में चले, लेकिन आपने रोडवेज का बिलकुल भट्टे बिठा दिया, आपने उसके बराबर लोक परिवहन सेवा चालू कर दी। आपने लोक परिवहन सेवा वालों को और मार दिया कि जिस तरीके से नियम, कानून बनाये थे उन नियम, कानून के आधार पर उनको आप चलने ही नहीं देते तो, झगड़े तो होंगे ही होंगे। आज जो यह कह रहे हैं कि कहीं तो बाहर हो गया, कहीं अन्दर हो गया। ये झगड़े हमेशा होते हैं और थाने में तो कम पहुंचते हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इस तरीके के हालात हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं आपने सत्यानाश कर दिया रोडवेज का, रोडवेज का सत्यानाश कर दिया आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें, प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो अनुबंधित बसे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा .... (व्यवधान) एक मिनट आप सुन लो, सुनने में कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत है सुनने में? (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): क्वेश्चन के बीच में भाषण कहां से आ गया माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान) भाषण के लिए अलग से टाइम लो..... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह हम सबका दायित्व है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): प्रश्नकाल में आप प्रश्न करें, भाषण तो बाद में दे देना। मेरा कहना है नेता जी, आप प्रश्न करो, प्रश्नकाल है। भाषण देने का समय आए तब भाषण दे देना। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप क्वेश्चन के बीच में भाषण देने लग गये। आप कम से कम संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखो। यह क्या बात हुई?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या हो रहा है? मैं मेरी बात रख रहा हूं और आपकी परमिशन लेकर मैं खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अभी डिमाण्ड्स चालू होंगी तो भाषण देना आप और उसमें तैयार करो जोरदार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं जवाब दिलाता हूं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं प्रश्न पर आ रहा हूं तो आपको कहां इतनी दिक्कत हो रही है। हम सब का दायित्व नहीं है कि रोडवेज सुचारू व्यवस्था से चले, रोडवेज पूरी सेवाएं दें, रोडवेज सशक्त और मजबूत हों? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी आपको जवाब दिलाता हूं। इसमें विवाद की आवश्यकता नहीं है, प्रतिपक्ष के नेता, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): यह हाउस नहीं चाहता? हम सब नहीं चाहते?

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह क्वेश्चन के बीच में बोलने का विषय ही नहीं है। (व्यवधान) डिमाण्ड पर बोलो ऐसे विषयों को। आप क्यों क्वेश्चन ऑवर को खा रहे हो? जिन लोगों के क्वेश्चन हैं वो इंतजार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन आपने लोक परिवहन सेवा के मालिकों को मारकर रख दिया, झगड़े तो होंगे ही होंगे। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप बैठो, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बिठाने वाले नहीं हो। आप बिठाने वाले नहीं हो। यह फालतू की बातें नहीं चलेंगी। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आप क्वेश्चन के बीच में इंट्रप्शन करके क्या चाहे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं....

श्री अध्यक्ष: जवाब दिलवाता हूं मैं मंत्री जी।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जान-बूझकर क्वेश्चन आवर को खराब करना चाह रहा है विपक्ष। डिमांड पर बोलो न, कौन मना कर रहा है आपको? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, मैं जवाब दिलवाता हूं। यह क्वेश्चन आपका बहुत लम्बा हो गया है। कोई पाइंटेड सवाल पूछ लीजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा हूं कि लोक परिवहन सेवा की बसें रोडवेज डिपो के अन्दर से चलेंगी या बाहर से चलेंगी?

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं इनको तो कृपया आप बोलने दो। मैं अलाऊ कर रहा हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): फिर आपने सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उसमें किया कि लोक परिवहन सेवा की बसें पंजाब से लाकर लगा दीं। पंजाब से लाकर लगा दीं। (व्यवधान) फिर आप हल्ला कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह क्या तमाशा हो रहा है, ये किस विषय पर बोल रहे हैं? यह विषय ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): नेता प्रतिपक्ष, केवल सवाल करें। प्रश्नकाल को बिगाड़ें नहीं। (व्यवधान) प्रश्नकाल का उपयोग हो जाएगा। आप प्रश्न करो, गुरुदेव।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप बैठो तो सही। किसके बारे में पूछ रहा हूं?

श्री मदन राठौड़ (उप मुख्य सचेतक): आप भाषण मत दो, प्रश्न करो। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके कहां दिक्कत हो रही है? प्रदेश का जो मुद्दा है उसको आप सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता, स्थान ग्रहण कीजिये। प्रतिपक्ष के नेता, मेरा निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण कीजिये। अब जवाब आ रहा है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि लोक परिवहन, और जो रोडवेज की अनुबंधित बसे हैं उनमें रेट समान है या अलग-अलग रेट है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): पंजाब वालों की रेट वो ही है और राजस्थान की भी वो ही है? मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान और पंजाब के अन्दर फर्क है क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब दिलाता हूं सवाल का। आपके सवाल का जवाब आ रहा है। (व्यवधान) नहीं, बिलकुल नहीं। नहीं, फिर मैं इनका जवाब नहीं दिलवाऊंगा। मिस्टर डोटासरा का एक शब्द अंकित मत करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपके प्रश्न का जवाब दिलवा रहा हूं उसमें आपका ही व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है और इनका एक शब्द नहीं आएगा। डोटासरा का नहीं लिया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: डोटासरा का एक शब्द नोट नहीं होगा। प्रतिपक्ष के नेता, आप बिठा सकते हैं या नहीं? प्रतिपक्ष के नेता, मुझे अफसोस है, आपके सवाल का जवाब आ रहा है और आपके ही पक्ष के लोग जिस तरह आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं यह देखकर मुझे शर्म आती है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने तीन मुद्दे उठाये हैं। मैं इनके भाषण पर नहीं जाना चाहता। इन्होंने कहा कि रोडवेज का सत्यानाश कर दिया। (व्यवधान) आप सुन लें, साहब। एक मिनट रुक जाओ, मुझे बोलना आता है। किसने सत्यानाश किया, अगर आप कहें तो मैं 1998 से 1993, सारे आंकड़े पेश कर देता हूं कि इस रोडवेज का सत्यानाश किसने किया। मैं आंकड़े पेश कर देता हूं। आप बैठ जाओ न, साहब, बैठ जाओ। (व्यवधान) रोडवेज का भट्टा किसने बिठाया, वो आपको पता है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आपने बिठाया है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप सुन लो न, वो भी सुन लो कि किसने बिठाया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सत्यानाश करने का कम्पीटिशन है क्या साहब?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रोडवेज को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए और जो सरकार के द्वारा वित्तीय एड हम देते हैं उसके आंकड़े भी मेरे हाथ में हैं। 2009-10 से लेकर 2013-14, 5 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, उसमें इन्होंने 930.32 करोड़ रुपये किसी न किसी हैड में रोडवेज को अनुदान दिया हो, वित्तीय मदद की हो या कोई पुनर्भरण किया हो और इन सब एड में 930 करोड़ रुपये दिये हैं 5 साल में। माननीय नेता प्रतिपक्ष जो सत्यानाश की बात कर रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि हमने मात्र इन 3 साल में 1110 करोड़ 73 लाख रुपये रोडवेज को उठाने के लिए दिये हैं।

दूसरा, यह बात सही है, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से सहमत हूं कि जब लोक परिवहन सेवा का विज्ञापन दिया था उस समय हमने यह कहा था कि हम रोडवेज बस टर्मिनल से इन लोक परिवहन बसों का संचालन करेंगे। यह बात इनकी सही है। उस आधार पर बहुत सारे लोगों ने परमिट भी लिए लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आज हाउस में आया है, यह तो ब्यावर का एक प्रकरण है, इस तरीके के प्रकरण पूरे राजस्थान में चाहे वो हनुमानगढ़ है, चाहे बीकानेर है, चाहे नागौर, चाहे सीकर है, हर जगह दोनों में आपस में झगड़े होने शुरू हुए तो सरकार ने अपना पहला सर्कुलर निकाला था, आदेश संख्या 37/2015, 24.11.2015 को, उसमें हमने यह शर्तें रखी थीं। उसको हमने 23..11.2016 को विदड्रा कर लिया। अब हमने सारे जिला कलेक्टर्स को भी कहा है, प्लस हमारा प्रयास भी है, और जयपुर में हमने एक स्टेशन भी तय कर दिया कि जो लोक परिवहन सेवा की बसें हैं, वे चलेंगी मैट्रो के यहां से। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह एक नई स्कीम इण्ट्रोड्यूस करवाई है राजस्थान की जनता को सेवा देने के लिये, इसलिये अलग से उनके बस स्टेण्ड्स की व्यवस्था करने का सरकार प्रयास कर रही है। मैं हाउस को आश्वस्त करता हूं कि अगले तीन महीने में यह सारी व्यवस्थाएं करके इन दोनों के आपस में झगड़े नहीं हों, इस तरीके का हम काम करेंगे।

तीसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पंजाब की बसों का और इनका

(श्री युनुस खान)

दे दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में कागज हैं। लोक परिवहन सेवा में, पहले चरण में हमारे पास 218 आवेदन आये, जिनमें से हमने 77 लोगों को पहले चरण में लोक परिवहन सेवा के परमिट दिये। दूसरे में हमारे पास 5502 आवेदन आये, उनमें से 921 लोगों को दिये। तीसरे में कुल मिला करके 3176 आये, 565 लोगों को परमिट दिये। कुल मिला करके 1563 परमिट स्वीकृत किये। उसमें मात्र 04 परमिट ऐसे हैं, जिनका गाड़ी नम्बर पंजाब का हैं, तो 04 गाड़ियां स्थानीय लोग भी, मतलब चूरू, जो बार्डर एरिया के, हनुमानगढ़, गंगानगर के लोग ले लेते हैं। जिन रूट्स पर हमने एप्लीकेशंस दीं, उनमें उन्होंने ही की, तो कानूनन कहीं नहीं है कि देश के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को हम परमिट लेने से रोक सकते हैं। क्योंकि यह जो मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 है, वह सैण्ट्रल एक्ट है, कोई स्टेट का एक्ट नहीं है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। जब कोई भी आरोप लगाएं तो अख़बार पढ़ कर नहीं लगाएं। उनके तथ्यों को जानें और उसके बाद में कोई आरोप लगाएं। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि चार बसों को हमने परमिट दिये। उसके अलावा हमने किसी को परमिट नहीं दिया।

मैं आज आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो बसें रह गयीं, उसके लिये हमने रोडवेज में 500 नई बसें खरीदने की कोशिश की है, तो 31 मार्च तक हम ले लेंगे, 705 बसें ऐसी हैं जिनको हम अनुबंध पर ले रहे हैं। रोडवेज ने अंदरूनी रूप से यह फैसला किया था कि इन लोगों को एडजस्ट करने के लिये, जो माननीय नेता, प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये लोग घूम रहे हैं, वास्तव में सही बात है कि जिन्होंने परमिट लेने के लिये बस खरीद ली उसका पैसा लग गया। उसकी चिंता हमारे को है, हमने पहले चरण में उनको एडजस्ट करने की कोशिश की है तो यह 700 परमिट देंगे। उसमें कुछ लोग एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद भी यदि, अध्यक्ष महोदय, कोई रह जाएंगे तो उनके लिये हम अलग से योजना ला करके जिन लोगों ने अब तक बसें बना ली हैं उनको नुकसान नहीं हो, उसकी चिंता सरकार को है, उनको एडजस्ट करेंगे। यह मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री रामलाल।

(श्री अध्यक्ष)

...(व्यवधान)... देखिये, प्रतिपक्ष के नेता, नियम आप जानते हैं, नहीं। मैंने आपको ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरा जवाब नहीं आया ना, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नियम आप जानते हैं। ...(व्यवधान)... आ गया, जो जितना आया, सरकार उतना ही देगी। जवाब देने की जरुरत नहीं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपकी जो 1500 बसें हैं, 1500 बसों के अन्दर जो अनुबंधित की हुई हैं उनकी रेट्स क्या-क्या हैं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं। ...(व्यवधान)... जो प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, जवाब देने की जरूरत नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): चार रुपये, साढ़े चार रुपये में कितनी बसें हैं, सात रुपये के अन्दर कितनी बसें हैं, पर-किलोमीटर वही बस है, थ्री-बाय-टू की बस है।

श्री अध्यक्ष: जवाब देंगे क्या आप?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने दो चीजें मिक्स कर दी हैं। लोक परिवहन सेवा का जिस दिन नोटिफिकेशन किया था, उस दिन हमने उनका टैक्स भी निर्धारित कर दिया था, पर-किलोमीटर। अब जितना वह व्यक्ति चलायेगा, उसी के अकोर्डिंग हम उनसे टैक्स लेंगे। एक लम्पसम टैक्स भी हमने लिया है। अब रही बात रोडवेज की बसें जो कम्पीटीशन में जाती हैं, टैण्डर लगता है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अनुबंधित बसों की रेट्स क्या हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं आ रहा हूं, माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मैं उसी पर आ रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सौ बसें ले रहे हैं। रोडवेज सौ बसें ले रही है, उसमें टैण्डर निकाला। कभी 07 रुपये 62 पैसे प्रति किलोमीटर आ जाता है। दुबारा टैण्डर निकालते हैं, वह 05 रुपये 60

(श्री युनुस खान)

पैसे आ जाता है। तीसरी बार टेण्डर, तो अलग-अलग चरणबद्ध तरीके से मतलब जो एल-1 होगा, लोएस्ट होगा, उसी को देंगे। अब उसमें लोएस्ट, एल-1 जो भी आयेगा उसको देना, कानूनन हम बाध्य हैं। इसलिये कोई पार्शिएलटी इस तरीके से नहीं होती है। ...(व्यवधान)... आपको अगर कोई भी आंकड़े चाहिए तो रोडवेज के आंकड़े भी हम सदन की मेज पर रख देंगे, लोक परिवहन सेवा के भी रख देंगे, अन्य आंकड़े भी रख देंगे। इसमें हमारी पूरी पारदर्शिता है और रहेगी, यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री राम लाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे-वैसे आपको परिवहन सेवाओं के अन्दर वृद्धि करनी पड़ेगी। लेकिन अभी लोक परिवहन सेवाओं के जो परमिट आपने दिये हैं वे नेशनल और स्टेट रट्स के ऊपर दिये हैं या ग्रामीण क्षेत्र में भी दिये हैं, और इन सेवाओं से कितनी पापुलेशन को लाभ मिला। तीसरा, इनकी जो रेट है वह राजस्थान रोडवेज और लोक सेवा परिवहन की रेट एक है या अलग-अलग है?

श्री अध्यक्ष: बस, बैठिये। मंत्री महोदय।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जो लोक परिवहन सेवाएं हैं, लोक परिवहन सेवाओं को, सिर्फ हमारा नेशनलाइज्ड रूट्स हैं, 16338 किलोमीटर के, उन्हीं को डिमोडिफाई किया है। उन्हीं पर 476 जो रूट्स थे, उन पर जो जगह खाली थी, वहीं इण्ट्रोड्यूस किया है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, बस हो गया ना।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, एक दूसरा और पूछा है। जहां तक ग्रामीण सेवाओं की बात है, समानान्तर रूप से हमारी अलग-अलग योजनाएं चलती हैं, तो ग्रामीण परमिट्स में भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस वर्ष 1023, जो हमारे 12 आर.टी.ओ. आफिस हैं, उनके अनुसार मेरे पास आंकड़े हैं, 1023 नये रूट्स हमने खोले हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सारे माननीय जन प्रतिनिधि यहां विराज रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर नया

(श्री युनुस खान)

रुट खुलवाना चाहेगा तो पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 1500 नये रूट्स खोलने की बात कही थी, उनमें से 1023 तो खोल दिये और कर देंगे। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। अब आप विराजिये। हो गया। ...(व्यवधान)... अगला सवाल श्री कल्याण सिंह।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लास्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट चाहिए, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आ गया, अब इनका जवाब आने दीजिये। श्री कल्याण सिंह।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नेता, प्रतिपक्ष ने बात उठाई। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिये, मैं कह रहा हूं, आप विराजिये।

नाथद्वारा में बजरी खनन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

191. श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में बजरी खनन के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को कब-कब, किस-किससे व क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्राप्त शिकायतों पर कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी? गत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों व उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खान (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में बजरी खनन के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को गत तीन वर्षों में सुगम/राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर 20 शिकायतें, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर है, जिला कलेक्टर, राजसमन्द को सीधे 23 शिकायतें, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर है, उप खण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को 12 शिकायतें, जिनकी सूची, परिशिष्ट-3

(राज्य मंत्री, खान)

पर हैं, तहसीलदार नाथद्वारा को 6, जिनकी सूची परिशिष्ट-4 पर हैं, यानी 61 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों पर की गयी कार्यवाही का विवरण कार्यालयवार/परिशिष्टवार संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: कल्याण सिंह चौहान, पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं कि जो बजरी की लीज दी गयी है, जिस लीज धारक ने नियम विरुद्ध अवैध खनन किया है, उसके खिलाफ विभाग ने राज्य सरकार को अवैध खनन की कार्यवाही भेजी है, उस पर राज्य सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है, माननीय मंत्री महोदय बताएं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख हमारा बजरी का स्रोत बनास नदी है, यह राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली से निकलती है जिसके अन्दर हमारे विधायकजी का नाथद्वारा भी आता है। नाथद्वारा के अन्दर बनास और खारी नदी, इसमें एक एल.ओ.आई. हुई है, हिम्मतसिंह के नाम से है। इसके सम्बन्ध में, जैसे मैंने बताया, 61 शिकायतें आज तक प्राप्त हुई हैं। उन सबकी हमने जांच करवाई है और उन सब पर हमने कार्यवाही की है, जिसमें 51 प्रकरण अवैध खनन के पाये गये हैं, चार एफ.आई.आर. हुई हैं और 37.55 लाख जुर्माना हुआ है।

जो आप कह रहे हैं, यह शिकायत इनके क्षेत्र नमाना में आई थी कि चारागाह, वृक्षारोपण, श्मशान, इसके आस-पास जो एल.ओ.आई. धारक है, वह अवैध खनन कर रहा है। हालांकि यह चारागाह का एरिया है, यह पंचायत के अन्तर्गत आता है। लेकिन हमारे अधिकारियों की टीम वहां गयी। वहां अवैध खनन पाने पर जो एल.ओ.आई. धारक था, 23.01.2017 को 2,31,800/- रुपये का जुर्माना उस पर किया गया। वहां पर जो श्मशान का पिलर था, उसका मेजरमेंट करके पिलर भी लगा दिया, जो उन्होंने शिकायत की थी कि इसको लेवल कर दो, लेवल भी करा दिया, जो गड्ढ़े थे, वे भरा दिये।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आज तक हमें शिकायतें मिली हैं, उन सब पर हमने कार्यवाही की है। जैसा कि मैंने बताया 51 प्रकरण केवल आपके क्षेत्र में पकड़े हैं, उसके अंदर हमने 37.65 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और चार एफ.आई.आर. भी हमने दर्ज करवा दी हैं। क्योंकि यह चारागाह है, यह जिला कलक्टर या रेवेन्यू का मामला है लेकिन पैनल्टी लगाने के बाद हमने कलक्टर को भी लिखा है कि क्योंकि यह खनन का जो क्षेत्र है, यह चार जगह बंटा हुआ है। खनन विभाग का कुछ क्षेत्र है, कुछ वन विभाग में भी खनन होता है, कुछ यू.आई.टी. का जो एरिया है तो उसमें यू.आई.टी. कार्यवाही करती है और जो चारागाह है, उसमें पंचायत करती है। क्योंकि, यह नदी से चिपका हुआ चारागाह था, लेकिन हमने फिर भी कार्यवाही की है, पैनल्टी भी लगायी है और उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कलक्टर से परीक्षण करके तुरंत रिपोर्ट भी मांगी है।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम इसमें जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी, जो भी इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, वह करेंगे और वहां पर अवैध खनन नहीं हो, इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट, तथ्य आपके सामने पेश किये हैं विभाग ने, यह बिलकुल ही गलत है। आप एक कमेटी गठित करें और उस कमेटी को मेरे साथ भेजें। पूरी बनास नदी की जो हालत, जो दयनीय स्थिति कर रखी है, आप स्वयं अगर देखें तो कोई खड्डा भरा हुआ नहीं है, कोई समतलीकरण किया हुआ नहीं है और कोई वृक्षारोपण करा हुआ नहीं है। ईवन चरनोद भूमि पर जो पंचायत द्वारा, किसी भामाशाह द्वारा हमने वृक्षारोपण करवाया, उस पर भी अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन के लिए हमने जिला कलक्टर को भी निवेदन किया, जिला कलक्टर ने एक कमेटी बनाई। कमेटी वहां पर गयी है और अवैध खनन करते हुए ठेकेदार, लीजधारक को पकड़ा है और पकड़ने के बाद पुलिस, रेवेन्यू और माइनिंग विभाग ने सामूहिक कार्यवाही की है। इतना खौफ है उस बजरी

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

खनन अवैध ठेकेदार का कि उनसे साधन छुड़वा कर ले गये और अभी तक उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर मैं माननीय मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक कमेटी गठित करें। बनास नदी, जो एक रीढ़ की हड्डी है, जिस पर जयपुर-बीसलपुर बांध बना हुआ है, इतने खड्ड़े कर दिये, 20-20 फीट, 25-25 फीट, 30-30 फीट और खोदने के लिए मशीनें वहां पर चल रही हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। माइनिंग वालों को कहते हैं तो यह हमारा काम नहीं है। उनको कहते हैं तो यह हमारा काम नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध दोहन, ठीक है आपकी नदी पेटा है, बनास पेटा है, उस पर लीज दे रखी है, आप करें। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): लेकिन चरनोट भूमि पर आपको कोई अधिकार नहीं है अवैध खनन करने का, इसको रोकने का पूरा प्रयास करें और कमेटी गठित करके हमारे साथ आप भेजें तो आपको पता पड़ेगा कि विभाग की मिलीभगत से यह सब अवैध खनन हो रहा है, मैं आपको सदन में यह अवगत करवाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी इसी जनवरी में हमने शिकायत पर वहां हमारी टीम भेज कर उसके अंदर कार्यवाही करते हुए उस पर पैनल्टी भी लगायी, पिलर भी लगवाये। फिर भी अगर माननीय सदस्य को यह शिकायत है कि अभी भी वहां ऐसा कोई गलत काम है, क्योंकि यह चारागाह का एरिया है, हमारी संयुक्त टीम बनाकर, जिला कलक्टर, खनन विभाग और पुलिस, तीनों से हम इसकी जांच करवा लेंगे और अगर एल.ओ.आई. धारक की कोई भी कमी पायी गयी तो हम उसके खिलाफ ठोस कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा, पूरक प्रश्न। यह देखिए कि नाथद्वारा की बजरी खनन से संबंधित प्रश्न है।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा ही हमारे उदयपुर को रेती सप्लाई कर रहा है। सर, नाथद्वारा की ही बात कर रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: हां।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि ठेका जिसको दिया है, उसका कोई एरिया फिक्स है? जैसा हमारे सदस्य महोदय ने कहा कि बीस-बीस फीट खड्डे हो गये हैं। रेती का ठेकादार, मनमर्जी, अपने हिसाब से ही चला रहा है और हमारे उदयपुर का दुर्भाग्य है कि पास में खरका नदी है, वहां से रेती नहीं आती है। वहां अब दे ही नहीं रखा खनन के लिए, भीलवाड़ा और नाथद्वारा से जो रेती जा रही है ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, आप अपना सवाल कीजिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): वही मैं पूछ रहा हूं, सर, क्या उसका एरिया फिक्स है, कितनी गहराई तक यह खोद सकता है? उसका कोई फिक्स है तो, मंत्री महोदय स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद में जैसा मैंने पहले बताया कि 2 एल.ओ.आई. है और उनका एरिया फिक्स है। राजसमंद में हमने अवैध बजरी खनन के आज तक 119 प्रकरण पकड़े हैं, उसके अंदर 49.65 लाख का हमने जुर्माना लगाया है, 15 एफ.आई.आर. की है और 160 वाहन हमने जब्त किये हैं। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो अवैध बजरी खनन में 3209 प्रकरण हमने पकड़े हैं, 258 एफ.आई.आर. करवायी है और 11.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

जहां भी हमें शिकायत मिलती है हम जाते हैं। जहां भी अवैध खनन पाया जाता है तो एफ.आई.आर. करवाते हैं, वाहन भी जब्त करते हैं और सख्त कार्यवाही करते हैं। लीज के बारे में आपने पूछा, यह 773 हैक्टेयर की राजसमंद में लीज है। इसके अंदर जो एल.ओ.आई. हुई है, वह तीन मीटर तक गहराई में खोद सकता है। नदी की चौड़ाई जितनी होती है, उसका 3/4

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

पोर्शन में वह खनन कर सकता है और जितनी चौड़ाई है उसका 1/8 हिस्सा, 1/4 बच गया दोनों साइडों में, वह किनारों के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। नदी के किनारे जो वनस्पति है उसको वह डिस्टर्ब नहीं कर सकता और एक किलोमीटर खनन के बाद उसको 50 मीटर का गैप छोड़ना पड़ेगा। बजरी खनन करने के बाद उसको वह लेवलिंग भी भराव की जगह करके देगा और बजरी के स्टॉक का वह भंडारण नहीं करेगा। यह एल.ओ.आई. की शर्तें हैं, अगर कोई भी शर्तों का पालन नहीं करता तो विभाग उसमें कड़ी कार्यवाही करता है। जो कार्यवाही मैंने की है, वह आपको प्रदेश की बता दी। राजसमंद में भी 119 और प्रदेश में 3209 प्रकरण पकड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'। नाथद्वारा का है यह।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से जो बनास नदी निकल रही है, उसके अलावा आउट आफ डिस्ट्रिक्ट में, आउट आफ जिले में जहां लीज अभी आपने चालू भी नहीं करी है, वहां भी अवैध नाके लगा रखे हैं, वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी दे रखी है और जो लूट-खसोट हो रही है, आप देख लो कि उनकी एक-एक गाड़ी के कम से कम 20-20, 25-25, 30-30 हजार की, 40 हजार की, 2 लाख 60 हजार की पैनल्टी फाड़ रहे हैं। तो जो नाके आपने बनास नदी में जहां पर लीज दे रखी है, वहीं नाके लगा रखे हैं या दूसरे जिलों में भी आपने सब जगह नाके लगा रखे हैं, माननीय मंत्री महोदय, यह बताएं। अंधाधुंध उनसे पैसे ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। आपका इसके बाद।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजसमंद के अंदर 50 वर्षों से खनन हो रहा थी, कोई एल.ओ.आई. नहीं थी इसीलिए वहां पर फ्री-स्टाइल काम चल रहा था। अब पहली बार हमने, एल.ओ.आई. हुई है, नाके लगाये हैं तो जो अवैध खनन वाले हैं, उनको तकलीफ हो रही है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जब हम पकड़ते हैं तो उनको वह जो पुराना काम चल रहा है, वह बंद होता है। कई दफा वह हमारे, जो अधिकारी हैं उनके ऊपर हमला भी कर देते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

नाजायज नाका कोई नहीं होगा और जो भी रिकवरी है, वह तो सरकार करेगी। जिसने टैंडर लिया है, वह वसूली तो करेगा। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है आपका।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): जो भी कोई एल.ओ.आई. धारक होता है, वह जहां से चोर रास्ते होते हैं तो लोग उधर से, उसके एरिये में से, उसको पैसा देना है, रॉयल्टी देनी है, डैड रेंट देना है तो वह अपने नाके लगाता है ताकि इधर से निकलेगा, अगर वह नाके नहीं लगाये तो लोग इधर-उधर से सारा ही खनन कर लेंगे। सरकार को रॉयल्टी का नुकसान हो जाएगा और एल.ओ.आई. धारक है, उसको भी पैसा वसूल नहीं होगा इसलिए कोई भी नाजायज नाका नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। 'आक्या' साहब, हो गया। अलग से आप बता दो। हो गया। श्री मानिक चन्द सुराना, तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने कहा कि यह चारागाह है, यह यू.आई.टी. का एरिया है, यह खेती का एरिया है, माइनिंग जहां भी होती है, वह चाहे खेती हो, चाहे चारागाह हो, चाहे यू.आई.टी. का एरिया हो, पंचायत का एरिया हो, सारा माइनिंग एक्ट के परव्यू में आता है इसलिए यह जो खांचे इन्होंने चार बना लिये हैं अपने मन से कि साहब, यह तो चारागाह है। चारागाह है तो अवैध खनन को रोकना आपका काम है। आप इसमें यह बहानेबाजी नहीं ले सकते। ....(व्यवधान).... बैठें, आप बैठें।

श्री अध्यक्ष: मानिकजी, सवाल कीजिए। सवाल कीजिए आप। हां, सवाल कीजिए आप।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): यानी, पहली बात मैं यह पूछना चाहता हूं जो अवैध खनन हुआ, आपने कहा न कि यह 35 लाख की पेनल्टी लगायी। यह पैनल्टी क्या दस गुना, जो अवैध खनन हुआ उसकी कीमत का दस गुना है? आप तो यह बताएं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूं और मेरे तो यह

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

राजनीति के मार्गदर्शक भी हैं। विभाग के अंदर यह स्पष्ट लैटर आया है कि जो वन विभाग का एरिया होगा, उसमें खनन विभाग हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम संयुक्त ड्राइव चलाते हैं और आठ ड्राइव चलाये हैं, जिसके अंदर पुलिस भी, खनन विभाग भी और प्रशासन का तहसीलदार भी, सब रहते हैं, तब हम संयुक्त कार्यवाही करते हैं और मैं पत्र की कॉपी आपको दे दूंगा, आज ही दे दूंगा। आप सुन तो लो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अगला सवाल श्री कैलाश चौधरी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: नो-नो, श्री कैलाश चौधरी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बनास नदी मेरे इलाके में बहती है।..(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, विराजिये आप। आप विराजिये। मैं अलाउ नहीं करूंगा। तीन सवाल हो गये। बैठिये आप। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बैठिये व्यवस्था के हिसाब से। ...(व्यवधान)... अर्जुनजी, आपसे निवेदन कर रहा हूं बैठिये आप।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 20-25 वर्षों से यह पता नहीं है कि वह तीन मीटर खुदी या दस मीटर खुद गयी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप बैठिये। अगला प्रश्न।

कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण

192. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किसान को अपनी उपज को बेचने पर फसल की समुचित लागत भी प्राप्त नहीं होती है?

(2) क्या सरकार किसानों के हित को देखते हुए किसानों की फसल का समुचित मूल्य दिलाने का विचार रखती है?

(श्री कैलाश चौधरी)

(3) क्या सरकार प्रदेश में समस्त प्रकार के कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी नहीं।

(2) जी हां। सरकार का यही प्रयास रहता है कि किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्राप्त हो।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

वर्तमान में खरीफ फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंग, उडद, कपास, तिल, अरहर, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, नाइजर बीज तथा रबी फसलों के लिए गेहूं, जौं, चना, सरसों, मसूर, कुसुम और वाणिज्यिक फसलों में जूट, गन्ना, नारियल आदि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को कि जो कल बजट आया उसमें किसानों के हित के बहुत कुछ लाभ देने का काम किया। अभी पिछले दिनों में जिस तरह से चने के ऊपर समर्थन मूल्य के अंदर जहां 3500 रुपये पहले थे, उसकी जगह 4 हजार किये और सरसों में भी 3350 की जगह 3700 रुपये किये। गेहूं के अंदर भी 1500 से बढ़ाकर 1525 फिर उसको 1625 किये। जौ के अंदर भी 1225 से बढ़ाकर 1325 किये, निश्चित रूप से मैं राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को इसमें धन्यवाद प्रेषित करूंगा। अन्य भी कई फसलों के अंदर इस तरह से समर्थन मूल्य को बढ़ाया है, लेकिन किसान के साथ में हमेशा यह होता रहा है कि किसान जब फसल बोता है, उस समय उस फसल की रेट अलग होती है। जैसाकि अभी गेहूं की बात करें तो गेहूं के अंदर वर्तमान में 1700 से 1900 के बीच में मिल रहा है लेकिन उसका जो समर्थन मूल्य है, वह 1625 रुपये है। इसी तरह अगर अपन

(श्री कैलाश चौधरी)

सरसों की बात करें तो आज उसका समर्थन मूल्य 3700 है और उसका जो मार्केट में रेट है, वह 3200 और 3400 के बीच में मिल रही है तो इस तरह से किसान के लिये हमेशा दुविधा खड़ी रहती है। जो सक्षम काश्तकार है, वह तो गेहूं या अन्य फसल को रोककर रखता है।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): लेकिन जो सक्षम नहीं है, वह उस फसल को रोककर नहीं रख सकता। मंत्री महोदयजी से निवेदन करूंगा कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि सरकार हमेशा किसान हितैषी रही है, तो ऐसे अधिकारी जो फसल का समर्थन मूल्य जिस समय किसान बेचना चाहता है, उस समय न देकर कुछ समय बाद जब वह फसल बेच देता है, उसके बाद में समर्थन मूल्य पर कांटे लगाते हैं और वह खरीदते हैं। इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या आप कार्यवाही करेंगे जो वास्तव में लेट करते हैं।

दूसरा, मेरा प्रश्न जिस तरह से बोनस के रूप में किसान की आमदनी अपन डबल करना चाह रहे हैं, तो बोनस के रूप में क्या किसान को, जिस तरह से पहले गेहूं के ऊपर 150 रुपये देते थे, क्या इसको वापस बढ़ाने का विचार रखते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय, विराजिये, इसका जवाब आने दीजिये। मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समर्थन मूल्य के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न इंगित किया है, मेरा निवेदन है कि समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा सभी राज्यों से प्रस्ताव मंगवाकर उनका कोस्ट ऑफ कल्टीवेशन, थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग सारे विषयों को जोड़कर किया जाता है। इसलिये स्टेट लेवल पर समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाकर भारत सरकार के लेवल पर होता है और जहां तक आपने यह प्रश्न किया है कि क्या बोनस के बारे में सरकार गेहूं देने का विचार रखती है, तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भारत सरकार के

(श्री प्रभू लाल सैनी)

द्वारा एक आदेश जारी किया कि पूरे देश में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चावल पर और गेहूं पर 2014 के बाद में बोनस नहीं देने की बात कही गयी है और उन्होंने यह कहा कि यदि गेहूं और चावल कोई भी सरकार यदि अबॉव देती है या बिलो देती है तो एफ.सी.आई. पार्टिसिपेट पर्चेज में नहीं करेगी। इसलिये ऐसी स्थिति में दलहन को छोड़कर गेहूं के बारे में समर्थन मूल्य के प्रावधान अभी 2014 के बाद से नहीं है।

इसके अलावा जहां तक मस्टर्ड के बारे में आपने कहा, उसमें बोनस का प्रावधान किया हुआ है और अभी वर्तमान में यदि हम यह देखें तो मंडियों की जो व्यवस्था हम लोगों ने देखी है, जो भाव मंगवाये थे, वह सरसों में जनवरी में 3713 रुपये और अभी 3500-3600 रुपये मंडियों में भाव चल रहा है। फेयर एवरेज क्वालिटी जहां थोड़ी कम है, उसमें निश्चित रूप से भाव 3400 तक भी आये हैं। लेकिन एवरेज यदि हम बात करें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 3713 रुपये अभी जनवरी और फरवरी का जो अंतिम आया, उसमें 3400 से 3500-3600 रुपये लगभग-लगभग एवरेज राजस्थान में आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदयजी, निश्चित रूप से मंत्री महोदय जी ने जो जवाब दिया है, वह ठीक है। इसमें मेरा एक निवेदन मंत्री महोदय जी से यह रहेगा कि किसान फसल काटता है, काटने के बाद में जब खेत में फसल रहती है, कई बार बरसात हो जाती है, बरसात की वजह से जो गेहूं या धान होता है उसके मिट्टी चिपक जाती है और वह जब मंडी के अंदर बेचने के लिये जाते हैं या जहां पर तुलवाते हैं वहां पर उसको अलग कर देते हैं कि आपकी फसल को हम नहीं लेंगे। उस किसान के लिये वह फसल तो बहुत कीमती है, तो मेरा आने वाले समय के अंदर आप मिट्टी को काटकर जो भी गेहूं या धान है, उसको लेने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारिश से खराब होने वाली फसल के बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि उसके भाव में कमी होती है तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना अभी आयी

(श्री प्रभू लाल सैनी)

है। इस फसल बीमा योजना के अन्तर्गत यदि आपकी कटी हुई फसल 14 दिन तक आपके खेत में बारिश के कारण से खराब हो जाती है तो उसका मुआवजा देने के प्रावधान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में रखे गये हैं। जहां तक मंडी में क्वालिटी की बात करें तो किसी भी माल का खरीदना, नहीं खरीदना, यह उस ट्रेडर पर, उस लाइसेंसी पर डिपेंड करता है। वह क्वालिटी के आधार पर खरीदकर उसको बेचता है। इसलिये इसमें किसी को पाबन्द किया जाना विधिसम्मत नहीं है। फिर भी हम लोग यह कोशिश करते हैं कि फेयर एवरेज क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए समर्थन मूल्य पर जब क्रय का काम शुरू होता है, जैसाकि भारत सरकार द्वारा एक अप्रैल से पूरे देश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद करने की घोषणा की गयी है। मैं समझता हूं कि जहां क्वालिटी का सवाल है, उसके आधार पर उसका नुकसान यदि फसल बीमा में कवर होगा तो उसमें हम उनकी राशि का पुनर्भरण कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला पूरक प्रश्न श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग मेरे प्रश्नों के जवाब तो आ गये, परन्तु जो सरसों का समर्थन मूल्य है, उसमें एक तो राज्य सरकार की तरफ से बोनस कितना दिया जा रहा है?

नम्बर दो अभी जो आपके खरीद हो रही है, वह बाजार के अंदर 3300 से 3400 आज भी किसान 300 से 400 रुपये नुकसान उठा रहा है और अभी तक अगेती फसल कुछ आई है, कोई ज्यादा फसल नहीं आई है। सरसों की बम्पर फसल हुई है और जब वह पूरी बाजार के अंदर आएगी, मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि 2800 से 3 हजार तक इसका भाव रहने वाला है। इसकी खरीद के लिये आप क्या आदेश करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पिछले 10 वर्षों में यह जो रबी 2016-17 चल रहा है, 27 से 30 लाख हैक्टेयर में पूरे राजस्थान में सरसों की बम्पर बुआई की गयी है। और जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोडेक्टिविटी भी 20 क्विंटल पर हैक्टेयर के लगभग इस साल रहने वाली है जो 13-14 क्विंटल

(श्री प्रभू लाल सैनी)

से ज्यादा कभी नहीं रही। यानी राजस्थान में लगभग 40 लाख मैट्रिक टन सरसों का उत्पादन होगा।

जहां तक मस्टर्ड के बोनस का सवाल है, भारत सरकार के द्वारा सरसों पर 3600 रुपये प्लस 100 रुपये का बोनस देने की घोषणा की गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की ओर से अभी पिछले दिनों ही भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी से और सहकारिता मंत्री जी से हम लोगों ने बात भी की है कि समर्थन मूल्य पर सरसों के केन्द्र शीघ्र खोल जाएं। साथ ही हम लोगों ने यह भी निवेदन किया है कि हमें जो बोनस की अनुमति आपने दी है, शीघ्र अनुमति मिलने के बाद प्रिक्योरमेंट किया जायेगा लेकिन फिलहाल अभी बहुत अच्छी फेयर एवरेज क्वालिटी की मस्टर्ड मंडियों में आ रही है, अभी रेट 3500, 3600, 3700 एवरेज के लगभग चल रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे, जितने भी भाव गिरेंगे तो उसके आधार पर जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया को भारत सरकार की अनुमति के पश्चात शुरू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि रबी और खरीफ पर बात हो गयी, जो किसान सब्जी पैदा करता है और मेहनत से सब्जी पैदा कर के जब उसको बाजार में बेचने के लिए जाता है, सब्जी वाला किसान नहीं है क्या, वो भी किसान है। अध्यक्ष महोदय, बेचने के लिए जाता है तो उसको सस्ते भाव में लिया जाता है, दो से तीन रुपये किलो, चार रुपये किलो, पांच रुपये किलो और बाजार में उसी सब्जी का भाव पचास से साठ रुपये किलो होता है। मजबूरन, उसका खर्चा नहीं निकल पाता है तो उसको सड़कों पर सब्जी फैंकने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो कर्जे के नीचे डूबता हुआ जाता है।

मंत्री महोदय, जो आप अनेक तरह की फसल बीमा योजना चला रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री योजना हो चाहे मुख्यमंत्री योजना हो, लेकिन वो किसान तक पहुंचे। आप सरकार की तरफ से फ्री में किसान का बीमा करने का प्रावधान रखेंगे या नहीं रखेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): और अब चने आने वाले हैं तो क्या उसका भी मूल्य निर्धारित करेंगे या नहीं करेंगे? वो भी महंगे भाव में लेकर के बीज बोया है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, अभी जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहूंगा। आपने तीन सवाल किये हैं, पहला सवाल आपने किया है कि सब्जियों के भाव फ्लैक्चुऐट रहते हैं, कभी एक रुपये, कभी दस रुपये, कभी सौ रुपये और व्यापारी उसको अधिक भाव में बेचता है। निश्चित रूप से, मैं इसको स्वीकार करता हूं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने काफी प्रयास किये हैं और हम कर रहे हैं। हम लोग कांट्रेक्ट फार्मिंग, अब सब्जी उत्पादन करने वाले फार्मर्स के साथ में कांट्रेक्ट फार्मिंग सीधे कर के उसकी रेट का निर्धारण संविदाकर्ता के और किसान के बीच में हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल एग्रीटेक मीट में कई ऐसे प्रपोजल्स हम लोगों ने उनसे प्राप्त भी किये हैं। यदि टमाटर बहुत अधिक तादाद में पैदा होता है तो टमाटर के जो मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेसर्स हैं उनके साथ टाइअप कर के इस प्रक्रिया को, यानी सभी क्रॉप्स में, जो पैरेलल क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं।

इसके अलावा डाइरेक्ट मार्केटिंग की भी एक अनुमति दी है। यदि काई भी वेजिटेबल, फ्रूट्स में या पल्सेज और ग्रेन्स में एक्सपोर्ट करने के लिए डाइरेक्ट मार्केटिंग करना चाहेगा मंडी के बाहर जाकर भी तो भी उसको अनुमति देने के मंडी समिति में हमने प्रावधान किये हैं। साथ में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान प्रसंस्करण एवं कृषि विपणन प्रोत्साहन नीति लागू की है ताकि किसान की फसल को कोई भी उपभोक्ता के अलावा प्रोसेसर उसको खरीदेगा तो निश्चित रूप से भाव का

(श्री प्रभू लाल सैनी)

निर्धारण सही हो सकेगा। देश के प्रधानमंत्री जी का जो विजन ई-मार्केट है वो ई-मार्केट का कॉसेप्ट पूरे देश को एक बाजार के रूप में विकसित कर के, कहीं से भी कोई व्यापारी जो रजिस्टर्ड है वो उसमें ऑक्शन लगा कर, क्योंकि जहां प्रोडेक्शन बहुत अधिक होता है उस समय भाव बहुत ज्यादा गिरते हैं, इसलिए पूरे देश में एक समान नीति लागू हो जाए।

साथ में आपने चने के बारे में प्रश्न किया, क्या चने पर भी समर्थन मूल्य की घोषणा की गयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्य को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि 3800 रुपये चने की कीमत का और 200 रुपये उस पर बोनस का, यानी 4000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से एम.एस.पी. यदि शुरू होता है तो इस रेट पर उसको खरीदा जाएगा। लेकिन एम.एस.पी. से ज्यादा आज भी उसके मंडियों में भाव अधिक होने से एम.एस.पी. अभी शुरूआत नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री नारायण सिंह देवल।

श्री रामचन्द्र (डग): अध्यक्ष महोदय, पीछे के माइक बंद हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माइक बंद हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: नारायण सिंह जी देवल का प्रश्न लिया है मैंने।

श्री रामचन्द्र (डग): सर, यहां पर माइक बंद हैं। ...(व्यवधान)...

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वर्तमान में राजस्थान में किन-किन जिलों में समर्थन मूल्य पर खरीद हो रही है? और जो खरीद हो रही है उसमें किसानों को समय पर पैसा भी नहीं मिल पाता है, तो इसके बारे में मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में कहीं भी समर्थन मूल्य पर कोई भी प्रिक्योरमेंट को-आपरेटिव विभाग के द्वारा और किसी विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है।

जहां तक समर्थन मूल्य पर खरीदने वाले के पैसे का भुगतान है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सही कह रहे हैं कि पिछले दिनों एम.एस.पी.

(श्री प्रभू लाल सैनी)

पर खरीद में मूंग की फसल का प्रिक्योरमेंट किया था, 67 सेण्टर बनाये थे और 16 लाख 41 हजार 712 क्विंटल मूंग का प्रिक्योरमेंट हुआ था। उसका जो अमाउंट था वो 866.71 करोड़ का था, उसमें से अभी तक 698.34 करोड़ का भुगतान हो चुका है और 168.37 करोड़ का जो एफ.सी.आई. का इनका भुगतान बाकी है, वो भारत सरकार से शीघ्र भुगतान करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शुभकरण चौधरी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): प्रश्न संख्या 193.

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी बटन दबाया था।

श्री अध्यक्ष: आपका नम्बर है इसमें?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरी सुनो आप।

यह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है ...(व्यवधान)... मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लियर हो गयी, 100 रुपये बोनस के दे दिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने अगला प्रश्न पुकार लिया, पुराने प्रश्न पर सवाल खड़ा कर रहे हैं यह। अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्नकर्ता को पुकार लिया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इसके बावजूद भी औने पौने भाव में किसान अपनी सरसों बेचने को मजबूर है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह सरकार खरीद केन्द्र नहीं खोल रही माननीय मंत्री जी...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। मंत्री जी, आपको भी जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: कोई वक्तव्य दोनों में किसी का अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: दस-दस बटन दबते हैं उसमें से तीन को दे सकता हूं मैं, सबको नहीं दे सकता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं दे सकता, दबाया होगा। सबके साथ न्याय करना है मुझे। कोई आपकी ठेकेदारी नहीं है कि आपका लेऊं ही लेऊं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं। आप देखिये, प्रतिपक्ष के नेता, बैठाइये। यह व्यवस्था का प्रश्न है। किरोड़ी लाल जी को भी मैंने अलाउ नहीं किया, बोलना चालू कर रहे हैं, नहीं। नहीं, बिलकुल नहीं, किसी का अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री अध्यक्ष: यह बटन वाली व्यवस्था मेरी सुविधा के लिए है। यहां जो नाम आ जाते हैं उनमें से मैं पिकअप करता हूं और तीन पूरक प्रश्न पिकअप करता हूं। बटन दबाने की गारंटी नहीं है कि मैं उसको लूंगा ही। अभी 15 बटन दबे हुए हैं, 15 में से 15 ही ले लूं? सिर्फ तीन लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित करने की जरूरत नहीं। अगला सवाल, श्री शुभकरण चौधरी। कोई अंकित नहीं हो। कोई अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: चिल्लाने से विधान सभा प्रभावित नहीं होती है ...(व्यवधान)... मैं भी प्रभावित नहीं होता हूं। मैं भी चिल्लाने से प्रभावित नहीं होता हूं। जो चिल्लाएं उनको चिल्लाने दो, नोट करने की जरूरत नहीं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: चिल्लाना अंकित नहीं हो। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... यह स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे सदन चलाना है, यहां से मैं जो परमिशन दूंगा वो ही अंकित होगा और वो ही आएगा। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

उदयपुरवाटी में इनडोर/आउटडोर स्टेडियम की स्थापना

193. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में कोई इनडोर व आउटडोर स्टेडियम नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए उक्त विधान सभा क्षेत्र में इनडोर व आउटडोर स्टेडियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

युवा मामले एवं खेल मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): जी हां। समन्वित स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यक्रम 2015 के तहत उपखण्ड स्तर पर 8.00 हैक्टेयर भूमि की उपलब्धता होने पर निम्नांकित खेल मैदान बनाये जाने का प्रावधान है:-

1. 200 मीटर एथलेटिक ट्रैक

2. बास्केटबाल

3. वॉलीबाल

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

4. खो-खो/कबड्डी मैदान

5. कार्यालय भवन

6. दर्शक दीर्घा

7. जिम्नेजियम

उक्त नियत प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए खेल सुविधाओं के निर्माण हेतु विचार किया जाएगा।

समन्वित स्टेडियम (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अंतर्गत संभाग/जिला/उपखण्ड/तहसील/ पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं हेतु मापदंड नियत किये गये हैं।

उक्त संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। ...(व्यवधान)...

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जोधपुर जिले के बजरी ट्रक चालकों से बजरी पर रायल्टी राशि के अतिरिक्त अवैध वसूली किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से जिला पाली में दिनांक 09 फरवरी, 2017 को एक युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के उपरांत उसकी हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री सुखराम विश्नोई एवं श्री पूरणमल सैनी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने का समय दिया जाएगा।

आपका पूरक प्रश्न है लेकिन वह उसमे आ गया पर्ची में। मेवाराम जी जैन, आपका पर्ची में नाम आ गया। जिस विषय पर आपने दिया है, उस पर पर्ची में नाम आया है, विस्तार से आप बोल सकेंगे।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि पहुंचाने के संबंध में।
2. श्री जगदीश नारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में भवन विहीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में भवन बनाए जाने के संबंध में।
3. श्री दलीचंद डांगी, सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय मावली में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में।
4. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सरकारी महाविद्यालय खोलने के संबंध में।
5. श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलने के संबंध में।
6. श्री भजनलाल जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा वैर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में।
7. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत में रबी की फसल के खराबे का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में।
8. श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से जिला सिरोही में

(श्री अध्यक्ष)

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, आबू रोड द्वितीय को आबू रोड से पिंडवाड़ा स्थानांतरित करने के संबंध में।

9. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत सहायिका, आशा सहयोगिनियों व साथिनों का मानदेय बढ़ाने व इनको स्थाई किए जाने के संबंध में।

10. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में राजकीय महाविद्यालय खोलने के संबंध में।

11. श्री शुभकरण चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में मंदिर माफी की कृषि भूमि पर काबिज काश्तकारों को बिजली कनेक्शन देने के संबंध में।

12. श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से कोटा व बारां जिले की सांगोद, कनवास, दीगोद, अंता एवं मांगरोल तहसील में जारी बजरी खनन पट्टों को निरस्त कर 5-5 हैक्टेयर के बजरी खनन पट्टे जारी करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 9 मार्च, 2017 को शून्यकाल में बोलने हेतु 49 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयी, जो निम्नांकित हैं:-

क्र. सं.	नाम माननीय विधायक	विषय
1.	श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा	नागौर शहर में कथित रूप से गत 3 माह से अनेक युवतियों के लापता होने तथा बढ़ती हुई चोरियों की वारदातों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2.	श्री मेवाराम जैन	बाड़मेर शहर के ठोस कचरा संग्रहण केन्द्र के बंद पड़े कार्य को पुन: प्रारंभ किए जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

3.	श्री कैलाश चौधरी	बायतू विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय गिड़ा पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए जाने के संबंध में।
4.	श्री शंकर सिंह राजपुरोहित	जवाई बांध पुनर्भरण एवं सेई बांध से जवाई बांध में आने वाली पानी की टनल की चौड़ाई बढ़ाये जाने के संबंध में।

श्री सुखराम विश्नोई।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जोधपुर जिले के बजरी ट्रक चालकों से अवैध वसूली

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले को बजरी सप्लाई करने के लिए पहले लूणी में टैंडर हुआ। वह टैंडर 2012 में बंद कर दिया। उसके बाद बजरी की सप्लाई पाली जिले से रोड के द्वारा की जा रही है। 2013 से लेकर के पिछले 3, साढ़े 3 साल से ट्रकों के द्वारा बजरी सप्लाई हो रही है। लेकिन पिछली 5 तारीख को उन्होंने अचानक रेट बढ़ा दी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि जो सूर्या एसोसिएट, सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, तहसील जोधपुर की है, वह एक तो रसीद देती है खान एवं भूविज्ञान विभाग की 347 रुपये की, यह आप देखिए रसीद। उसके बाद में वह रॉयल्टी के साथ में अपनी खुद की कंपनी सूर्या एसोसिएट की तरफ से 1800 रुपये की, 2200 रुपए की, प्रत्येक ट्रक से 2 से ढाई हजार से रॉयल्टी के अलावा अलग से अवैध रूप से वसूले जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत खान मंत्री जी से चाहूंगा कि जोधपुर जिले के सारे ट्रक पिछली 5 तारीख से रोहट में, जहां से बजरी निकलती है, वहां हड़ताल करके बैठे हैं। आज कई दिन हो गये हैं। आप यह दूसरी रसीद सूर्या एसोसिएट की देखिए, यह पक्की रसीद है। उस पर साइन हैं। दो रसीद हैं। एक तो रॉयल्टी की रसीद है और दूसरी इसकी रसीद है। इस बात को

(श्री सुखराम विश्नोई)

लेकर के जोधपुर जिले के सारे ट्रक जो कि बजरी का परिवहन करते हैं, उस खान पर हड़ताल करके बैठे हैं। अध्यक्ष जी, यह क्या समझ रखा है।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। हां, माननीय विश्नोई जी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो लोग हड़ताल करके बैठे हैं, ट्रक लेकर के बैठे हैं, उनको न्याय दिलाया जाए। जो सूर्या एसोसिएट 2200-2300 की एक्सट्रा रसीद काट रही है, उस पर रोक लगाई जाए। उनसे पैसे वसूल किए जाएं और आज ही पुन: खान को चालू किया जाए। जवाब चाहते हैं मंत्री जी से।

श्री अध्यक्ष: रेसपोंड करना चाहेंगे?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अध्यक्ष महोदय, लूणी नदी का बहाव क्षेत्र जोधपुर में से होकर के निकलता है। इसके चार एलओआई हैं। एक तो सूर्या एसोसिएट, एक ओसियां में हिम्मत कल्याण 668 में, कुबेर 2130 सैक्टर में और बिलाड़ा में हिम्मत।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो 2 पर्चियों का मामला उठाया है, यह दोनों पर्चियां मेरे पास भी हैं। एक पर्ची तो खनन विभाग की है जो कि रॉयल्टी के पैसे के लिए काटी जाती है। दूसरी पर्ची इसलिए है कि जब रेट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गये, बीच में खनन बंद हो गया था, तो सरकार ने कोशिश की कि असेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर जिला कलक्टर रेट तय करें। लेकिन यह एलओआई धारक कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने कह दिया कि रेटों का निर्धारण सरकार नहीं कर सकती। उन्हें हमें रॉयल्टी देनी है तो वह खुद रेट तय करेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह कोई जवाब है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं कह रहा हूं ना। सुन लो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह जवाब है मंत्री जी का?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं जवाब दे रहा हूं ना।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह कोई जवाब है आपका?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं दे रहा हूं ना जवाब। सुन तो लो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इसका मतलब मनमर्जी की फीस तय कर दी आपने। माननीय मंत्री जी, एक रसीद 1800 की है, एक 2200 की है और एक 2500 की है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मेरी बात सुन लो आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह क्या बात हुई। आपने तो छूट दे रखी है ठेकेदार को। आपका कोई कमीशन साथ में है क्या? अध्यक्ष जी, यह कोई जवाब है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आप सुनते क्यों नहीं हो?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): रॉयल्टी दे दी। ठेका किस बात का है? आप तय करो रेट।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): जो उन्होंने माल बेचा है, उसकी कीमत है। जो आदमी एलओआई से अपने साधनों के अलावा, अपना कोई माल ले जाता है, उसको काटकर देते हैं कि मैंने इतने क्विंटल इतने रुपयों में बेची और उसकी कीमत इतनी है। यह बिल है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, वही ट्रक है, 6 टायरों का ट्रक है, एक से तो 2200 ले रहा है, एक से 1800 रुपए ले रहा है। यह किस चीज की रेट तय कर रखी है? यह रेट कौन तय करता है? माननीय मंत्री जी, रेट कौन तय करता है? आप तय करते हो या कलक्टर तय करता है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आप सुनिए। आप सुन क्यों नहीं रहे? सुन तो लो, एक मिनट बैठ जाइए आप। देखिए, रेट तय करने के लिए जिला कलेक्टर को राज्य सरकार ने अधिकृत कर दिया था और जो बजरी धारक थे, वह कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने यह कहा कि सरकार रेट तय नहीं करेगी। जिन्होंने ठेका लिया है, वह अपना बेचेंगे।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह क्या जवाब है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): यह कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने कह दिया कि अब सरकार नहीं, कलेक्टर नहीं कर सकता।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह जवाब है? कोर्ट ने कहां कहा है बता दो? मंत्रीजी बता दें कि कहां है कोर्ट का जवाब? कहां है ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं आपको कह रहा हूं कि राजस्थान ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनके बाद आप बोलिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि हमारे से त्रुटि हो गयी है। प्रश्नकाल के बाद में जब भी सूची में शोकाभिव्यक्ति होती है,

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति को मैं इसके बाद लेने वाला था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसके पहले होती है।

श्री अध्यक्ष: हो गई, चूक हो गयी। हो क्या गया? ऊपर नीचे हो गया। ...(व्यवधान)... माननीय घनश्यामजी, आपने पाइंट आउट किया है, आपका आभार। आप विराजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऊपर-नीचे मत हुआ करें आप। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजिए। ...(व्यवधान)... प्रतिपक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं? ...(व्यवधान)... इनके बाद बोलिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 टन के ट्रक और ट्रोला में 16 टन के लिए 2500 रुपये में 270 रुपये तो रॉयल्टी होती है, 50 रुपये परमिट फीस होती है, 27 रुपये डीएमएफ की होती है और 360 रुपए भराई होती है और 1893 रुपये बजरी की कीमत की पर्ची होती है कि 1893 रुपये की बजरी है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): टोटल कितने हुए?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): टोटल पच्चीस सौ।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह मेरे पास पड़ी है 1800 की और 2200 की, वही ट्रक है, वही ट्रक नम्बर है, दो रसीदें पड़ी हुई है मेरे पास।

(श्री सुखराम विश्नोई)

एक में 2200 और एक में 1800, मनमर्जी का रेट है, मनमर्जी का, माननीय मंत्रीजी, यह क्या तरीका हुआ, बजरी के ठेकेदार लूट रहे हैं। आप उनकी पैरोकारी कर रहे हो बिलकुल ही। ...(व्यवधान)... यह दो रसीदें अलग-अलग पड़ी हुई हैं मेरे पास, वही ट्रक है वही।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): यह तो उसकी कीमत की और यह सरकार की रॉयल्टी की है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब है इनका?

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ...(व्यवधान)... वही ट्रक है एक की 1800 रुपये, आप जोड़ो, ...(व्यवधान)...।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): यह उसकी रॉयल्टी की है और यह उसकी बजरी की कीमत की है। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 2500 कैसे हुए बताओ आप? ...(व्यवधान)... जोड़ो। कैसे होते हैं बताओ? ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, 18.05.2015 को सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया है कि राज्य सरकार रेट निर्धारित नहीं कर सकती। ...(व्यवधान)... आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूं न। ...(व्यवधान)... सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप चाहे जो जवाब नहीं दिया जा सकता। ...(व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इसके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाते?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): हमारे पास तो नहीं है ...(व्यवधान)... आप पैरोकारी कर रहे हैं, कोर्ट का फैसला कहां है? माननीय मंत्रीजी, कौनसी तारीख का फैसला है?

श्री अध्यक्ष: जवाब दे दिया, आप विराजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): दिनांक 18.05.2015 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कौनसी तारीख है फैसले की, मनमर्जी फैसला बता रहे हो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 18.05.2015 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ...(व्यवधान)... सरकार रेट तय नहीं कर सकती। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। ...(व्यवधान)... अब और जवाब की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य, श्री पूरणमल सैनी। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की स्थिति बनी हुई है। एक जोधपुर की नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठेकेदार ही मनमानी से तय करेगा? सरकार नहीं तय करेगी? ...(व्यवधान)... एक ही ठेकेदार जिसकी मोनोपोली है वही बजरी की रेट ऊटपटांग तय करके राजस्थान की जनता को लूटता रहेगा और बजरी के भाव आसमान छूते रहेंगे, इस पर सरकार कोई नियंत्रण की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट जाने का विचार रखती है या नहीं रखती?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। ...(व्यवधान)... श्री पूरणमल सैनी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बोलिए, मनमानी कर रहा है ठेकेदार। ...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): सुखरामजी, आप विराजो। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, बजरी की चर्चा कई दफा चली है और यह पूरे प्रदेश का गंभीर मामला है। ...(व्यवधान)... मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बैठकर ऐसा कोई समाधान निकालें कि आम आदमी को उसका फायदा मिले। इसको गम्भीरता से आप लें, क्योंकि बजरी वाली इतनी लूट प्रदेश में मची हुई है। खाली एक जोधपुर का मामला नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश का मामला है इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि बजरी वाले मामले में सरकार चिंतन और मंथन करे और ऐसा कोई समाधान निकाले जिससे आम आदमी को फायदा हो सके।

श्री अध्यक्ष: विराजो। ...(व्यवधान)... अब मैं इजाजत नहीं दूंगा, बहुत हो

(श्री अध्यक्ष)

गया। ...(व्यवधान)... माननीय पूरणमलजी। ...(व्यवधान)... विराजिए आप। पूरणमल सैनी। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, पूरणमल सैनी के अलावा कोई वक्तव्य रेकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। ...(व्यवधान)... मैंने पूरणमलजी को पुकारा है, आप विराजिए। ...(व्यवधान)...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं आएगा। ...(व्यवधान)... मंत्रीजी, जवाब नहीं देना है। ...(व्यवधान)...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री अध्यक्ष: आपका वक्तव्य खतम हो चुका है। ...(व्यवधान)... पूरणमलजी सैनी के अलावा और किसी का रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: यह रिकार्ड पर नहीं आएगा यह जो बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: आप वहां बैठिए, नो, नो, इस तरह से नहीं हो सकता। ...(व्यवधान)... इस तरह नहीं हो सकता, आप अपनी सीट पर जाइए। बार-बार उठक-बैठक करते हैं। माननीय सदस्य, किरोड़ीजी, आप बैठिए, मैं आपसे कह रहा हूं। मैं बिना परमीशन के नहीं बोलने दूंगा। चाहे आप कितने ही वरिष्ठ हों। ...(व्यवधान)... आप बोल चुके। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, इनकी पैरवी करने की आपको जरूरत नहीं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 000

श्री अध्यक्ष: आपको पैरवी करने की जरूरत नहीं है। ...(व्यवधान)... श्री पूरणमल सैनी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी के अलावा और किसी का रिकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)... यह रिकार्ड नहीं होगा। ...(व्यवधान)... आप बैठिए, बार-बार उछल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: रेकार्ड पर नहीं लिया, ...(व्यवधान)... रेकार्ड पर नहीं लिया। ...(व्यवधान)... बिलकुल नहीं। ...(व्यवधान)... इनका रेकार्ड पर नहीं जाएगा। ...(व्यवधान)... पूरणमल सैनी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड पर नहीं जा रहा है कुछ भी। ...(व्यवधान)...

पाली जिले में युवती का अपहरण एवं दुष्कर्म उपरांत हत्या

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विधान सभा की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर और मेरी बात को सुनने के लिए समय दिया समय दिया उसके लिए आपका आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय का ध्यान पाली जिले के बाली विधान सभा क्षेत्र के सेवाड़ी गांव की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसमें एक महीने पहले 9 फरवरी को भारती नाम की लड़की जिसके पिता का नाम साकलचंद था उनको माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी लंबे समय से फोन पर धमकियां भी देता रहा। उसके बाद एक दिन उनकी बड़ी बहन को धमकी दी, अंत में उस धमकी को कार्य रूप में परिणित करते हुए उस भारती नाम की लड़की को उठा कर ले गये और उस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ। उसके बाद उस भारती नाम की लड़की को जवाई बांध में डाल दिया।

(12.17 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसका जवाई बांध में डाल देने के बाद भी और मर्डर किया गया, जो भी थोड़े बहुत दिखाई देने वाले सबूत थे उन सबूतों को भी उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री पूरणमल सैनी)

उसके बाद पाली जिले के लोग और बाली के लोग एसपी, पाली से जाकर मिले लेकिन आज दिनांक तक उस पीड़ित परिवार को जिनकी बेटी का गैंग रेप ही नहीं हुआ उसका मर्डर तक कर दिया न्याय नहीं मिला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल यही बात नहीं है, पिछले दिनों मैं कह रहा था चिट्ठी के माध्यम से और झुन्झुनूं जिले में 27 तारीख को हमने धरना देकर बताया कि झुंझुनूं जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में, झुन्झुनूं थाने में 22 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ 17 में, मलसीसर में 101 नम्बर का मुकदमा, पिलानी में 385, झुंझुनूं में 172, थाना गुढ़ा में 376, मलसीसर में मुकदमा संख्या 7, ऐसे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाह रहा हूं कि मलसीसर में 101 मुकदमे पर अगर कार्यवाही कर ली जाती तो अगले महीने में क्या दूसरा मुकदमा दर्ज होता? 7 दिन बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं हैं। मैं मांग करना चाहूंगा कि आए दिन दलित समाज की शोषित समाज की महिलाओं और बच्चियों के साथ इस तरीके से रेप किया जाएगा और सरकार, सरकारी अधिकारियों पर कोई जूं तक नहीं रेंगेगी। झुंझुनूं जिले में भी जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय के सामने 27.01 को प्रदर्शन किया गया।

पाली जिले के लोग भी एसपी साहब से जाकर इस तरह से मिले लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें लग रहा है कि निश्चित रूप से इन बदमाशों को किसी न किसी दृष्टि से राजनीतिक संरक्षण है इसलिए उनको पकड़ा और जेल में नहीं डाला जा रहा है। पीड़ितों और दलितों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से कि दोनों जिलों के ये जो विभिन्न मुकदमें मैंने बताएं हैं, इन पर कार्यवाही फर्माते हुए पाली जिले की भारती नाम की लड़की के साथ जो जुर्म किया गया उन जुर्म करने वालों के खिलाफ कब तक कार्यवाही करवा देंगे? माननीय गृह मंत्रीजी जवाब दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में माननीय सदस्य ने जो घटना उठायी है वह गंभीर किस्म की है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। घटना 3 तारीख की है। यह एक मेडिकल स्टोर पर काम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करने वाले बालक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जवाई गयी थी। जवाई जाकर, इसका किसी और व्यक्ति से भी पुराना कोई संबंध था, उसने टेलीफोन पर बात की, उसके बाद उसने उसके साथ अपनी सहमति नहीं जतायी तो वह कूद गई। यहां जो गलती है उस मेघवाल बालक की, वह वहां से इस भय से कि वह कूद गई और डूब गई, वह भाग गया। दो दिन बाद वह लौटकर आया। 4 तारीख को उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज करायी वह गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करायी। 9 तारीख को जवाई से यह लाश बरामद हुई। पोस्टमार्टम में डूबने से हुआ, यह मेडिकल रिपोर्ट कहती है। किसी प्रकार का रेप नहीं हुआ, यह भी मेडिकल रिपोर्ट कह रही है। लेकिन यह तो सही है कि जिसके साथ गयी उसके खिलाफ जिस प्रकार का मुकदमा बनकर जिस ढंग से जांच होनी चाहिए ताकि इसके आगे की अगर कोई लाइन होगी तो मिलेगी।

पुलिस इन्वेस्टीगेशन तो कर रही है, उस लड़की की जितनी भी मोबाइल पर कॉल डिटेल है, उसकी बहन के साथ बात हुई, उसको भी इकट्ठा किया है। किन-किन लोगों के साथ फेसबुक पर बातचीत हुई है वह भी सारी रिकॉर्ड की है, लेकिन अभी टू दी पाइंट पर नहीं पहुंच पाये कि इसमें घटनाक्रम कहां से चला और 302 का मुलजिम अगर कोई है, 302 का मुलजिम तो इसलिए नहीं हो सकता सामान्यत: देखने से, क्योंकि किसी ने उसको मारा नहीं है, वह स्वयं कूदी है। फिर भी जिसके साथ गयी और जो यह कह रहा है कि वह कूदकर डूब गयी। मैं आपको विश्वास दिलाऊं हमारे राजस्थान में पालीग्राफिक टैस्ट हमने शुरू कर दिया है। यह पहला व्यक्ति जिसके साथ उसने मोटरसाइकिल पर जाना बताया है उसका पालीग्राफिक टैस्ट कराऊंगा, एडिशनल एसपी को इसकी जॉच दूंगा। अगर इसमें और भी कोई लाइन मिलेगी तो निश्चित रूप से दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करूंगा और इसको स्वीकार करता हूं, एक महीना घटना होने के बाद जो कार्यवाही तुरंत हो जानी चाहिए उसमें डिले हुआ है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): बात यह नहीं है। आपके पास जो सूचना है वह वास्तव में गलत है। आपकी सूचना में यह बताया गया है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा परिवार आया और

(श्री पूरणमल सैनी)

यह बात आपकी भी सही है कि वह किसी दूसरे के साथ नहीं थी। वे दोनों नामजद लोग हैं, जिनका मुकदमा दर्ज है। उन दोनों में इस बात का कंपीटिशन हुआ और दूसरे लोगों को बुलाया गया, गैंगरेप हुआ, उसके बाद यह कूदी नहीं। इसको मजबूर किया गया, इसको ब्लैकमेल किया गया। उसको धक्का देकर उसमें डाला गया। यही नहीं, धक्का नहीं, मरी लाश को जवाई बांध में डाला गया है। जो बदमाश लोग हैं, वे मजबूत किस्म के लोग हैं, कहीं न कहीं डाइरेक्ट, इनडाइरेक्ट वे राजनीति में अपना प्रभाव रखते हैं तथा अधिकारियों के साथ उनकी कहीं न कहीं मिलीभगत है। ऐसी परिस्थिति में माननीय गृह मंत्री के पास रिपोर्ट सही नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप इसकी एसओजी से जांच करवाएं। वास्तव में यह मर्डर है, गैंगरेप है। इसकी बड़ी बहन को भी अब धमकी आ रही है और वह परिवार आज भी सहमा हुआ बैठा है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं जो शंकाएं आपको हैं उन शंकाओं को भी ध्यान रखते हुए पालीग्राफिक टैस्ट में जिस मेघवाल बालक के साथ गयी है और डिप्रेशन के कारण वह 30 तारीख से मेडिकल स्टोर से ट्राइका की दवाई ले रही थी। उस दिन भी वह ट्राइका की दवाई लेने के लिए गयी थी। वहां पर उसने कहा कि मुझे घुमा लाओ और वह उसे ले गया, जैसा वह कह रहा है। गैंगरेप नहीं हुआ, इसका तो मेरे पास और कोई एविडेंस नहीं मेडिकल के अलावा। जो मेडिकल उसका हुआ है उसमें गैंगरेप नहीं आया है। फिर भी आपके इस संदेह को पालीग्राफिक टैस्ट के अंदर जो क्वश्चनेयर बनेगा उसमें डालकर निश्चित रूप से (व्यवधान) मृत्यु पूर्व डूबना तो इसलिए है कि मेडिकल रिपोर्ट में पानी में डूबने के कारण जो पेट में पानी मिलता है उससे तय होता है। मेडिकल रिपोर्ट तो दोनों यह बता रही हैं कि वह पानी में डूबकर मरी है। गैंगरेप उसके साथ नहीं हुआ है। जाना तय है, जाने वाले व्यक्ति का नाम तय है, जिसके साथ उसका संबंध था उसका नाम तय है। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि राजस्थान में हमने पालीग्राफिक टैस्ट शुरू कर दिया है। इस केस में इसका उपयोग करूंगा और आप जिस अधिकारी से भी चाहो, बड़े से बड़े अधिकारी को भेजकर, इसमें

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कोई भी दोषी होगा और मेरी पुलिस के लेवल पर भी कहीं अगर ढिलाई रही है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही करूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सैकिण्ड उपाध्यक्ष महोदय। मैं गृहमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि पालीग्राफिक टैस्ट का आश्वासन आपके अधिकारी भी कई जगह हमें आंदोलनों के अंदर देते हैं। फिर कोर्ट के अंदर उस बात को नकार देता है कि नहीं करा सकते पालीग्राफी टैस्ट। उसके बाद क्या करेंगे ? आगे कोई अपील करते हो क्या इसकी ? इसका बताओ आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): देखो, कोर्ट से ऊपर तो मैं भी नहीं हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अगले कोर्ट में अपील हो जाए। वह वहीं उसको कह दे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने कहा, मेरी भावना के अनुसार मैं चलूंगा। अगर कोई की दखलंदाजी आ जाती है तो मेरी मजबूरी होगी। लेकिन इस केस में जो भी मेरे पास अच्छे से अच्छे अधिकारी उपलब्ध हैं, उनको भेजकर उसकी पूरी जांच कराकर कोई भी दोषी हो, एक्स, वाई, जैड, उसके खिलाफ कार्यवाही करने का मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पॉलीग्राफी टैस्ट के लिए क्या न्यायालय में अभियुक्त की हां आवश्यक है? यदि अभियुक्त हां नहीं करेगा तो पालीग्राफी टैस्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है नार्को टैस्ट के बारे में तो कोर्ट की राय का असर रहता है। पॉलीग्राफी टैस्ट के बारे में सामान्यत: ऐसी कोई दखलंदाजी नहीं है। कोई आएगी तो फिर उसके हिसाब से देखेंगे। (व्यवधान) नार्को में है।

श्री उपाध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

रवि राय, श्री, पूर्व लोक सभा अध्यक्ष

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं पूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री रवि राय के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व लोक सभा अध्यक्ष श्री रवि राय का जन्म 26 नवम्बर, 1926 को उड़ीसा के पुरी जिले के भौरागढ़ में हुआ। आपने बी.ए. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त की।

श्री रवि राय चौथी, नौवीं तथा दसवीं लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1979 से 1980 तक केन्द्रीय सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे। श्री राय नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति तथा लोकपाल विधेयक सम्बन्धी संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य तथा कार्य मंत्रणा समिति के सभापति भी रहे। श्री राय दिसम्बर, 1989 से जुलाई, 1991 तक नौवीं लोक सभा के अध्यक्ष रहे। आपने पद की गरिमा के अनुरूप कार्य करते हुए संसद के कार्यकरण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रक्रियागत नवाचारों की शुरुआत की। श्री राय वर्ष 1974 से 1980 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

सामाजिक क्रियाकलापों में रुचि रखने वाले श्री राय हिन्दी पाक्षिक "चौखम्बा" तथा उड़िया मासिक "समता" के सम्पादक रहे। आपने अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया। आप समाजवादी दल और जनता दल के महामंत्री तथा प्रेस परिषद् के अध्यक्ष भी रहे। विभिन्न सामाजिक आन्दोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री राय ने जेल यात्रा भी की।

श्री रवि राय का दिनांक 6 मार्च, 2017 को निधन हो गया।

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री रवि राय को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके

(श्री उपाध्यक्ष)
शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री उपाध्यक्ष: विराजें। अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

अनुपस्थिति अनुमति

चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती, सदस्य को दिनांक 27.02.17 से सत्रांत तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 27 फरवरी, 2017 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

दिनांक 09 मार्च, 2017 को अनुमति प्रदान की गयी

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत। श्री शंकर सिंह रावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

ब्यावर के जिला परिवहन अधिकारी द्वारा की जा रही राजस्व हानि

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख - ब्यावर जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि के संबंध में।

(श्री शंकर सिंह)

ब्यावर जिला परिवहन कार्यालय में कार्यरत जिला परिवहन अधिकारी श्री तिलोकचन्द मीणा द्वारा राज्य सरकार को करोड़ों रुपये की राजस्व हानि पहुंचाई जा रही है। जब से श्री मीणा ब्यावर जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित हुए हैं, तब से ही इस कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसकी लोगों द्वारा बार-बार शिकायत आने पर दिनांक 07.12.2015 को मैंने लिखित में शिकायत की थी। जिसकी जांच करने में विभाग को करीब आठ माह लग गये और अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) डा. मनीषा अरोड़ा के पत्र क्रमांक प.3(1)(98)परि/शिकायत/16/14801 जयपुर दिनांक 29.7.2016 द्वारा जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर के विरुद्ध अनियमितता के संबंध में मुझे अवगत कराया गया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर द्वारा की गयी जांच में दोषी पाये जाने पर भी मात्र कारण बताओ नोटिस देकर इतिश्री कर ली गयी है और आज दिनांक तक इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गयी है। यह एक जांच का विषय है। 000

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो आपने लिखकर दिया है, कृपा करके वही पढ़ें। मैं अनेक बार आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): जी साहब। (व्यवधान) जिला बन जाएगा भाई, तसल्ली रखो। नहीं नहीं, जिला बन जाएगा। 000

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय, यह आपने कहां लिखा है ?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सर, इसमें लिखा हुआ है। देखो आप। करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है। 000

श्री उपाध्यक्ष: "साथ ही निवेदन है कि श्री सीमेंट, अंधेरी देवरी से रोजाना करीब 500 ट्रेलर तथा राजसमंद से करीब 500 ट्रेलर ओवरलोड होकर रोजाना ब्यावर से गुजरते हैं।" अब इसके आगे आप पढ़ना चालू करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): लेकिन किसी भी ट्रेलर का चालान नहीं कर अवैध वसूली कर छोड़ दिया जा रहा है... पढ़िये साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आगे चलिये। यह ऐसे ही पढ़िये, जैसा लिखा हुआ है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ...जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों की राजस्व हानि हो रही है। अत: माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से

(श्री शंकर सिंह)

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर जिला परिवहन अधिकारी श्री तिलोक चन्द मीणा राज्य सरकार को प्रतिमाह राजस्व की वसूली पहुंचाकर प्रति ट्रेलर अवैध वसूली के करोड़ों रुपये डकार गया है। क्या उससे वापस वसूल कर इनके खिलाफ कठोर जांच कराने का विचार रखते हैं? यह मेरा निवेदन है। माननीय मंत्री महोदय से थोड़ा जवाब दिलवाने की कृपा करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

जमवारामगढ़ के भवन रहित रा.प्रा.विद्यालयों में भवन निर्माण

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में भवन विहीन राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन बनाये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में निम्नलिखित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन रहित संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को पढ़ाई करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं शिक्षा मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में भवन रहित निम्नांकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवन शीघ्र बनाये जाने की कृपा करें:-

(1) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बावरियों की ढाणी, नांगल तुलसीदास।

(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बलाइयों की ढाणी रामजीपुरा, डांगरवाड़ा।

(3) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, रामगढ़ बांध, सामरेड कलां।

(4) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मेवालों की ढाणी लांगड़ियावास।

(5) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, क्यार की ढाणी, लांगड़ियावास।

(6) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पाट्या की ढाणी, राहौरी।

(श्री जगदीश नायायण)

(7) राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गोकल्यावास। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दलीचन्द डांगी।

मावली उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की मावली तहसील काफी बड़ा क्षेत्र है। मावली तहसील में कुल 49 ग्राम पंचायतों के 181 ग्रामों में लगभग तीन लाख की जनसंख्या निवास करती हैं। उपखण्ड क्षेत्र में 52 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 11 राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। मावली से 45 किलोमीटर तक के दायरे में कोई राजकीय महाविद्यालय नहीं है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी कालेज जाने से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं होने से उच्च शिक्षा की पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। उक्त क्षेत्र शिक्षा में काफी पिछड़ा हुआ है तथा सभी कृषि पर निर्भर हैं। यहां से 12वीं पास करने के बाद बालक/बालिकाएं उच्च अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाने से पढ़ाई छोड़ देते हैं।

मैं माननीया मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उपखण्ड मुख्यालय मावली में नया राजकीय महाविद्यालय खोलने का आदेश प्रदान कराएं जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में आसानी हो सके। महाविद्यालय के लिए नगरपालिका, फतहनगर, सनवाड़ और ग्राम पंचायत मावली के बीच पर्याप्त जमीन भी है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम जी।

मारवाड़ जंक्शन में सरकारी महाविद्यालय की स्थापना

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र

(श्री केसाराम चौधरी)

मारवाड़ जंक्शन बहुत ही बड़ा विधान सभा क्षेत्र है जो पूर्णतया ग्रामीण एवं अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। तीन पंचायत समितियों में कुल 75 ग्राम पंचायतें हैं एवं 125 किलोमीटर लम्बाई में फैला हुआ है।

इस विधान सभा क्षेत्र में इस वर्ष सीनियर सैकण्डरी की 2,272 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 1,225 लड़के एवं 1,047 लड़कियां अपने भविष्य का फैसला कर रही हैं, किन्तु सीनियर उत्तीर्ण करने के बाद इस क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय नहीं होने से विद्यार्थियों को करीब 50 से 75 किलोमीटर दूर अन्यत्र महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है, जो उनके लिए लम्बी दूरी पड़ती है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को प्राइवेट महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर गरीब तबके के माता-पिता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। अत्यधिक दूरी के कारण 12वीं के पश्चात् अभिभावक अपनी बालिकाओं को घर से दूर महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा के लिए भेजना उचित नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप बालिका शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है एवं कई छात्राएं जोकि उच्च शिक्षा के प्रति रूझान रखती हैं, वे चाहते हुए भी अपनी शिक्षा निरन्तर जारी नहीं रख पा रही हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़कर घर पर ही बैठना पड़ रहा है। सरकारी महाविद्यालय नहीं होने से कई लड़के एवं लड़कियां गरीबी के कारण अपना अध्यापन आगे प्राइवेट कालेजों की फीस ज्यादा होने की वजह से उच्च शिक्षा लेने से वंचित रह जाते हैं। अत: मेरा आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध है कि वे मारवाड़ जंक्शन में एक सरकारी महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान कर मुझे अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री जी कुछ कहना चाह रही हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जी।

श्री उपाध्यक्ष: ये वैसे आपका 295 है जिसका लिखित में जवाब आएगा। अगर नहीं आये तो आप आसन को अवगत कराना। श्रीमती शकुंतला रावत।

बानसूर में सरकारी महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि बानसूर विधान सभा क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत विस्तृत क्षेत्र है एवं यहां पर अधिकतर क्षेत्रवासियों का मुख्य धन्धा कृषि एवं पशुपालन है।

अत: अधिकतर युवाओं को सीनियर सैकण्डरी पास करके घर बैठना पड़ता है, जिससे अधिकतर लड़कियों को 12वीं पास करके घर बैठना पड़ता है क्योंकि बानसूर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय नहीं होने के कारण यहां की युवा पीढ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है।

मैंने पिछले 3 वर्षों में विधान सभा सदन के अन्दर कई बार नियमों के तहत सरकारी महाविद्यालय की मांग की है, परन्तु सदन में बार-बार यह कह दिया जाता है कि वहां पर प्राइवेट महाविद्यालय है व बजट नहीं होने की बात जवाब में दे देते हैं। प्राइवेट महाविद्यालय तो अधिकतर सभी विधान सभा क्षेत्रों में खुले हुए हैं। ऐसा कोई विधान सभा क्षेत्र नहीं होगा, जहां पर प्राइवेट कालेज नहीं हो।

अत: माननीय मुख्यमंत्री महोदया से निवेदन है कि देवनारायण योजना से बजट लेकर सरकारी कालेज एवं नारायणपुर में कन्या महाविद्यालय खुलवाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भजन लाल जाटव।

वैर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री भजन लाल (वैर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में दो उपखंड हैं वैर व भुसावर, जहां पर युवा विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत अधिक है जिन्हें अपने अध्ययन हेतु महाविद्यालय भरतपुर अथवा जयपुर जाना पड़ता है जिससे क्षेत्र के गरीब तबके के बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित हो जाते हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब बच्चे तो धन के अभाव में अपनी शिक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विधान सभा क्षेत्र वैर का आबादी क्षेत्र भी काफी विस्तृत एरिये में फैला हुआ है।

अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा

(श्री भजन लाल)

कि आज मेरे विधान सभा क्षेत्र वैर में नवीन महाविद्यालय खोलने की कृपा करें, ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गरीब विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भंवर सिंह।

कोलायत में रबी की फसल के खराबे का मुआवजा

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से फसल रबी सम्वत् 2072 में बीकानेर जिले में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के संबंध में निवेदन है कि सम्पूर्ण बीकानेर जिला द्विफसलीय क्षेत्र है, जहां खरीब और रबी दोनों फसलें पकती हैं। सम्वत् 2072 की रबी फसल में भी लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र में फसल रबी का बीजान किया गया था। मार्च, 2016 में प्राकृतिक आपदा (अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भयंकर तूफान) से बीकानेर जिले के काफी क्षेत्र की फसलें खराब हुईं। विशेषकर कोलायत तहसील के बज्जू उप तहसील क्षेत्र के 40 से अधिक गांवों के किसानों की फसल रबी के दौरान बोई गयी फसल, पशु-पक्षी, मवेशी जानवर एवं कच्चे मकानों को भारी नुकसान हुआ।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार लघु, सीमान्त व अन्य कृषकों को श्रेणीवार 33 प्रतिशत से अधिक तक का नुकसान मानते हुए नुकसान का आकलन किया गया एवं उक्त आकलन जिला कलेक्टरों के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किए गये थे, परन्तु राज्य सरकार/आपदा एवं राहत विभाग के निर्देशानुसार 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान वाले कृषकों को ही नुकसान का मुआवजा दिया गया, जबकि केन्द्र सरकार के द्वारा 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान का मुआवजा देने की घोषणा की गयी थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जिससे 33 से 50 प्रतिशत हुए नुकसान वाले किसान आज तक मुआवजे से वंचित हैं।

अत: मेरा सदन के माध्यम से आपदा राहत मंत्रीजी से निवेदन है कि बीकानेर जिले व कोलायत तहसील क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में फसल रबी सम्वत्

(श्री भंवर सिंह)

2072 के 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक फसल खराबे का मुआवजा अतिशीघ्र दिलवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय आबूरोड़ द्‌वितीय का आबूरोड़ से पिण्डवाड़ा से स्थानान्तरण

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू सिरोही जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र से अत्यधिक संख्या में दीवानी एवं फौजदारी के मुकदमे होने से आमजन एवं बार के द्‌वारा पिण्डवाड़ा मुख्यालय पर एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की मांग की जा रही थी। जिसे स्वीकार कर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय आबूरोड़ द्‌वितीय के नाम से स्थापित कर उसका मुख्यालय आबूरोड़ रखा गया है, जो कि उचित नहीं है क्योंकि आबूरोड़ में पहले से ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित था।

आबूरोड़ में स्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्‌वितीय में अधिकतम प्रकरण पिण्डवाड़ा क्षेत्र के हैं। पिण्डवाड़ा से आबूरोड़ की दूरी 50 से 55 किलोमीटर है। पिण्डवाड़ा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है न्यायालय हेतु पर्याप्त भूमि व भवन उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में आमजन एवं जनप्रतिनिधियों व बार के माननीय सदस्यों की मांग के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय आबूरोड़ द्‌वितीय को पिण्डवाड़ा मुख्यालय पर स्थानान्तरित किया जाए।

अत: आम जनता के हितार्थ उक्त विषय के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत है। सधन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया।

प्रदेश में आंगनबाडी केन्द्रों पर कार्यरत सहायिका, आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्‌धि व स्थायीकरण

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरा निवेदन है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी व साथिनें लंबे समय से अपनी कुछ मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 0-6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं जिनकी सार-संभाल, पोषाहार, टीकाकरण इत्यादि इनके द्वारा किया जाता है। परंतु इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियों को ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन किसी भी प्रकार की राज्य सरकार द्वारा छुट्टी नहीं मिल रही है। सरकार स्कूलों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भी अवकाश प्रदान करे। इसी प्रकार हमारे पड़ौसी राज्यों में कार्यकर्ता, सहायिका व साथिनों का मानदेय हमारे राज्य राजस्थान से ज्यादा है। राजस्थान में मानदेय कार्यकर्ता का 4,462 रुपये, सहायिका का 2,600 रुपये, साथिन का 2,800 रुपये व सहयोगिनी का मात्र 1,800 रुपये है। आंगनबाड़ी केन्द्रों का टाइम...।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, जो हमको भेजा है आदरणीय, वो ही पढ़ें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ये ही है, सर।

श्री उपाध्यक्ष: ये नहीं है। हम बताएं ?

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): कोई एक-दो लाइन कट पेस्ट हो गयी होगी साहब, कंप्यूटर में।

श्री उपाध्यक्ष: अगर आपके पास में वो नहीं है तो आप यहां से ले, हम दे देते हैं।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ठीक है। दुबारा पढ़ूं या वहीं से पढ़ूं ?

श्री उपाध्यक्ष: आप ...1800 रुपये है से चालू कर लें। 1800 तक तो आप ठीक थे।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ... अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए तथा इनको स्थाई भी किया जाए। ये सभी कार्यकर्ता सर्दियों में 10.00 बजे से 2.00 बजे तक तथा गर्मियों में 8.00 से 12.00 बजे तक कार्य करती है। इन 4 घंटों में गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं व किशोरी बालिकाएं और बच्चों की निगरानी का कार्य भी कर रहे हैं।

(श्री अभिषेक मटोरिया)

अत: मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इनका समाधान किया जाए।

सधन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंहजी।

किशनगढ़बास में राजकीय महाविद्यालय

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास के उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़बास में राजकीय महाविद्यालय खोलना अति आवश्यक है। उक्त उपखण्ड मुख्यालय पर खैरथल व किशनगढ़बास दो बड़े कस्बे एवं लगभग 150 गांव हैं जिनमें हजारों छात्र छात्राएं कालेज स्तर के हैं। उपखण्ड क्षेत्र किशनगढ़बास में लगभग 3 लाख की जनसंख्या है। जो लगभग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़बास में राजकीय महाविद्यालय नहीं होने से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। विशेषकर छात्राओं को ग्रामीण क्षेत्र में आवागमन के पर्याप्त साधन नहीं होने से उच्च शिक्षा की पढ़ाई से वंचित होना पड़ता है। उक्त क्षेत्र में बहुत बड़ा मेवात क्षेत्र भी आता है। उपखण्ड क्षेत्र किशनगढ़बास में 25 ग्राम पंचायत व दो नगरपालिका है तथा 35 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 21 निजी उच्च माध्यमिक विद्यालय है। जिनमें लगभग 10,000 से भी अधिक छात्र एवं छात्राएं अध्ययनरत हैं। उक्त क्षेत्र से कोटकासिम, तिजारा, मुण्डावर, उमरैण एवं रामगढ़ आदि पंचायत समितियों की भी सीमा लगती हुई है। उक्त क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने हेतु जनप्रतिनिधियों, बद्धिजीवियों, वकीलों एवं आमजन द्वारा स्थानीय स्तर पर अनेकों बार राजकीय महाविद्यालय खुलवाने की मांग रखी जाती रही है।

अत: मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़बास में अतिशीघ्र राजकीय महाविद्यालय खोला जाना चाहिये जिससे

(श्री रामहेत सिंह यादव)

कि ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर मेवात के छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढाई करने में आसानी हो सके, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

प्रदेश में मंदिर माफी की कृषि भूमि पर काबिज काश्तकारों को बिजली कनेक्शन

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मंदिर माफी की कृषि भूमि पर काबिज काश्तकारों को बिजली कनेक्शन देने के संबंध में निवेदन है कि प्रदेश में अधिकांश काश्तकार मंदिर माफी की भूमि पर काबिज हैं। मंदिर माफी भूमि पर ये काश्तकार कई वर्षों से रह रहे हैं तथा ये सम्पत्ति उनके पास सुरक्षित है। प्रदेश की कुल कृषि भूमि में से काफी हद तक कृषि भूमि मंदिर माफी की है। उक्त कृषि भूमि पर काश्तकार खेती नहीं कर सकते क्योंकि खेती करने के लिये बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है, पूर्व में एक उपखण्ड स्तरीय कमेटी थी जो इस प्रकार की भूमि पर कृषि कनेक्शन हेतु एनओसी जारी करती थी किंतु सरकार ने वो प्रावधान भी बंद कर दिया। अत: काश्तकार अपनी मंदिर माफी की भूमि को कृषि के लिये उपयोग नहीं कर सकता जबकि वर्षों से उस पर काबिज है। कृषि रोजगार का साधन उपलब्ध होने के बावजूद भी अधिकांश काश्तकार बेरोजगार है। बड़ा दुर्भाग्य है कि काश्तकारों के पास कृषि हेतु भूमि उपलब्ध होने के बावजूद भी वो अपनी मंदिर माफी की भूमि पर खेती नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि सरकार द्वारा उक्त मंदिर माफी की भूमि पर बिजली कनेक्शन दिया जाता है तो फसल की पैदावार बढ़ेगी और निरन्तर बढ़ रही महंगाई में भी कमी आएगी तथा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। अत: सरकार द्वारा मंदिर माफी की कृषि भूमि पर बिजली कनेक्शन दिया जाए व पुराने एनओसी दिये जाने वाली कमेटी का पुन: गठन हो जिससे प्रदेश के काश्तकारों को जीवन यापन के साधन के साथ-साथ निरन्तर बढ रही महंगाई से राहत मिल सके, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर (अनुपस्थित), मुख्य सचेतक महोदय, अगर सदस्य आज पधारे हैं और यहां 295 के समय मौजूद नहीं है तो मैंने पहले भी निवेदन किया है, पाबंद करें, सुनिश्चित करें। श्री हबीबुर्ररहमान।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

नागौर में युवतियों की गुमशुदगी तथा चोरी की वारदातें

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, नागौर विधान सभा क्षेत्र में हो रही वारदातों के लिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर में पुलिस के भरोसे कोई सुरक्षित नहीं है। दिन में बदमाश घरों में घुस कर वारदात कर जाते हैं। पुलिस मौक़े पर पहुंचने में देरी करती है तो लोग खुद बदमाशों को पकड़ कर पुलिस को सौंपते हैं फिर भी उन पर कोई कार्यवाही करने के बजाय पुलिस उनको बचाने के रास्ते ढूंढती है।

यही नहीं कोई महिला या युवती लापता हो जाए, पुलिस उन्हें ढूंढने के लिये परिजनों से गाडी मंगाकर गश्त का इंतजार करती है। यह छवि है नागौर पुलिस की। गश्त में 60 प्रतिशत तक नफरी घटा दी गयी। एक साल पहले शहर में सीआरपीएफ के स्पेशल जवान AK-47 लेकर गश्त करते थे, अब वह भी नजर नहीं आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो क्राइम की रिपोर्ट आई है उसमें सदर थाने को नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरों ने पिछले साल रिपोर्ट में सबसे बेकार थाना बताया था। उसके बाद इसी थाने क्षेत्र में बासनी गांव में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई। मुख्य आरोपी को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है जबकि तीन-तीन डिप्टी एसपी ने इसकी जांच की, लेकिन मुलजिमों को अभी भी पकड़ नहीं पाई है। गत दो माह में पांच महिलाओं का अपहरण हो गया, जिसमें तीन शादीशुदा व दो महिला कुंवारी हैं। महिला थाने में दर्ज मुकदमा नंबर 2016 है, मालगांव की लड़की का मामला, कुम्हारों की लड़की का मामला 11/2017, सढाऊ की नाबालिग लड़की रतनबेन स्कूल से गायब हो गई, मुकदमा नंबर 15/2017 है। जाजोलाई की विवाहिता महिला, मुकदमा नंबर 18/2016, दिल्ली दरवाजे से लड़की गायब, मुकदमा नंबर 19/2017, बच्चाखाड़ा क्षेत्र की विवाहिता लापता हुई। रिपोर्ट कराने पुलिस थाने पहुंचे लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बजाय पीड़ित परिवार को इधर उधर

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

टरकाते रहे। 28 फरवरी को बासनी गांव की एक विवाहिता शादी करने के लिये अपने पीहर आई थी और वह नागौर 28 फरवरी को पहुंची और एक घंटे बाद मालूम पड़ा कि विवाहिता घर नहीं पहुंची है फिर भी घर वाले सदर थाना गये, कोतवाली गये और महिला थाने में गये लेकिन किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तीन दिन बाद मेरे कहने पर उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। अभी तक उस महिला का कोई भी समाचार नहीं है।

दिनांक 17 फरवरी को डेर रोड से शिक्षक की पत्नी तुलसा देवी के घर में घुस कर सुबह साढ़े दस बजे गहने लूटे गये। लोगों ने बदमाश को पकड़ा भी लेकिन कोतवाली ने पूछताछ की खानापूर्ति की और उसको छोड दिया गया। संदिग्ध की तलाश नहीं की गयी। 15 जनवरी, 2017 को बदमाशों ने दिन दहाड़े राठौडी कुआं क्षेत्र में एक कार के शीशे फोड़ दिये और 15 हजार रुपये चुरा ले गये। जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 21 फरवरी, 2017 को लवारपुरा की महिला को इलाज के लिये अस्पताल ले गये थे, मकान सूना था, चोर दिन में घर में घुस कर दो लाख रुपये नकदी और जेवर चुरा कर ले गये। वारदात के 10 दिन तक पुलिस ने मौका देखकर वापस फाइल की तरफ देखा ही नहीं। 15 दिसम्बर को एचडीएफसी बैंक के काउंटर से 9 लाख रुपये गायब हो गये। सीसी टीवी कैमरे में बदमाशों की तस्वीर कैद हुई लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी को नहीं पकड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, नागौर शहर की यातायात व्यवस्था बहुत चरमरा गयी है। नागौर शहर का मुख्य बाजार गांधी चौक, तहसील चौक, बी रोड, ए रोड पर यातायात का भारी दबाव रहता है परंतु वहां पर यातायात की कोई भी माकूल व्यवस्था नहीं है। मात्र कलेक्ट्री चौराहा, बासनी पुलिया और मानाचर रोड पर ही ट्रैफिक वाले खड़े रहते हैं। मेरा मंत्री महोदय से यही कहना है कि जब सदर थाना कोतवाली की इतनी रिपोर्ट आई है तो इस कोतवाली थाने को पूरा ही चेंज किया जाए। मैंने मंत्री महोदय से पहले भी कहा था कि मेरे तीन तीन थाने हैं, तीन-तीन सीआई हैं, एक महिला थाना सीआई है, कोतवाली सीआई है, सदर का सीआई है। तीनों एक किलोमीटर की रेंज में है फिर भी इतने अपराध बढ़ रहे हैं, चोरियां हो रही है, महिलाएं गायब हो रही हैं। मैं आपसे यह मांग करुंगा कि जो आप अटैच लगाते हो वह मेरे इन

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

तीनों थानों में नहीं लगाये। अटैच कांस्टेबल लगा देते हो जो कि पूरा थाना वही चलाते हैं, सीआई को तो वह पूछते भी नहीं। रिपोर्ट दर्ज करानी है तो उनसे पूछो, हकीकत है, जो सीआई आता है वह अटैच, तीनों सीआई को मालूम ही नहीं है कि कोतवाली में, सदर में, महिला थाने में क्या होता है।

दूसरी बात जो पांच-पांच साल से चाहे एसएचओ हो, चाहे एएसआई हो, पांच-पांच साल से, तीन-तीन साल से बैठे हैं उनको तुरंत हटाओ। जो पुराने कांस्टेबल बैठे हैं उनको भी हटाओ। जयपुर से भी मैंने तबादले कराये, एसपी साहब ने भी अभी तबादले किये लेकिन उनको कोई रिलीव ही नहीं करता है, क्या मालूम क्यों नहीं करता है। हमारे नागौर का यह हाल है। गांवों में भी चोरियां हो रही हैं, लेकिन इसकी कोई रोकथाम है ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि..।

(13.00 बजे)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपकी सरकार में चलती नहीं है। इसलिए नहीं हो रहा, और क्या ?

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): चलती नहीं है, वह बात नहीं है। लेकिन इन तीनों सी.आई. को चेंज करें, क्योंकि महिला थाने में तो कभी सी.आई. बैठता ही नहीं है, अटैच लगा हुआ है। वहां एक एस.आई. संभालता है। तहसील चौक में भी एक एस.एच.ओ. को बैठा रखी है, जो बिलकुल ही नाकाम है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसका जवाब दें और तीनों थानों में ऐसे आदमी लगाएं, जिससे नागौर शहर में लोग सुरक्षित रह सकें। आज पूरे नागौर शहर की जनता भयभीत है कि कब, कौन चोर आएगा, हमें लूटकर ले जाएगा? यही मुझे कहना है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टाइम दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो सूचना मांगी थी, वहां तक तो मंगाकर मैं जवाब देने की स्थिति में हूं। आपने कई चीजें इसमें नई जोड़ दी हैं। आपके द्वारा जो भी जोड़ा गया है, यहां से लेकर प्रत्येक का जवाब दो दिन में आपके पास भेजूंगा कि वस्तुस्थिति क्या है। लेकिन जो आपने पूछा, उतना तो मेरे पास है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आपका यह कहना है कि इन तीन महीनों में तीन युवतियां गयी थीं। इन तीन युवतियों के बारे में, पहली है साजुबानो, पुत्री श्री जाखिम मुसलमान। इसकी रिपोर्ट 2/17 दर्ज हुई थी और रिपोर्ट गुमशुदा की हुई। उन्होंने इसकी जांच की। 28.02.17 को वापस साजुबानो मिल गयी। इससे पुलिस ने रिकार्ड पर पूछताछ की, उसने कहा कि मैं, मेरी इच्छा से अपने रिश्तेदार के यहां गयी, जो मेरा रिकार्ड कह रहा है।

दूसरा, सुश्री आरती, पुत्री श्री इन्द्रचंद, निवासी - डी कालोनी, नागौर, लापता हो गयी। इस पर गुमशुदा की रिपोर्ट 04/17 दर्ज की गयी। उन्होंने जांच दिनांक 16.2.17 लड़की को बरामद कर लिया और उसने अपने रिकार्ड में बताया कि मैंने शादी कर ली। क्योंकि वह बालिग है। हम उसके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकते, पर लेकर आये और लेकर आने के बाद, उसके बयान रिकार्ड करने के बाद उसने शादी करना कबूल किया है।

तीसरा मुकदमा, सुश्री मुमताज, पुत्री श्री अल्लाह बख्श। इसकी भी गुमशुदा रिपोर्ट 06/17, 27.02.17 को दर्ज हुई थी। 27 को रिपोर्ट दर्ज हुई, 28 को उसको बरामद कर लिया गया और उसने भी अपनी इच्छा से शादी करना जाहिर किया।

तो तीन ये गुमशुदा लड़कियों के जाने की बात है, वह बात ठीक है। आपकी इस बात में थोड़ा-सा मुझे भी लगता है कि वास्तव में, चोरी और नकबजनी के बारे में पिछले साल में कुछ कमजोर स्थिति रही, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं। क्योंकि 2014 में शहरी क्षेत्र में 55 चोरियां हुईं, उसमें से 14 में चालान कर दिया और ग्रामीण क्षेत्र में 29 चोरियां हुईं, उसमें से 13 में चालान हुआ। हमारा रिकवरी परसेंटेज 2014 का 70 प्रतिशत था। 2015 में शहरी क्षेत्र में 84 वारदातें हुईं, 12 में ही चालान कर पाये, 72 में एफ.आर. लगी। निश्चित रूप से यह एक गंभीर विषय ध्यान में है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में 21 मामले दर्ज हुए, चालान 2 हुए। चालानी परसेंटेज, बरामदगी परसेंटेज इनका 39 रहा। जो कि लगभग स्टेट के एवरेज के आसपास है। 2016 में 111 मुक़दमे शहरी क्षेत्र में दर्ज हुए, चालान 21 के हुए और रिकवरी पर्सेटेज भी कम रहा। इसको मैं स्वीकार करता हूं। निश्चित रूप से चोरी और नकबजनी की वारदातें

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

पिछले कुछ समय में पुराने वर्षों की तुलना में बढ़ी है, आपके नागौर शहरी क्षेत्र में, आपके विधान सभा क्षेत्र में।

हमारा कहना है कि निश्चित रूप से आपने जो सुझाव दिए हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं जो कुछ भी मेरे पास...आपने कहा कि पांच साल से अधिक, मैंने आपके कहने के पहले ही पूरे राजस्थान में एस.पी. से इस बात का सर्टिफिकेट लिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में टुकड़े-टुकड़े में भी अगर कभी रहा हो और उसकी जोड़ पांच साल हो जाती है तो वह उस थाने में नहीं रहेगा। इस आदेश की पालना के लिए मैंने सभी से सर्टिफ़िकेट लिया है, अगर आपको किसी थाने में ऐसा व्यक्ति लगता है कि जो इस नियम के विरुद्ध आज की तारीख में है तो आप मुझे नाम लिखकर दो। मैं निश्चित रूप से, जिस एस.पी. ने मुझे सर्टिफ़िकेट दिया है कि 'मेरे जिले में कोई भी व्यक्ति पांच साल से अधिक एक स्थान पर नहीं है', अगर अवहेलना हुई तो निश्चित रूप से कार्यवाई करूंगा और इसमें सुधार के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अगर इसमें कुछ बदलाव करना पड़ा, कुछ लोगों को बदलना पड़ा तो वो भी बदलूंगा। निश्चित रूप से जनता जिस बात की मुझसे उम्मीद करती है, मैं उस पर प्रयत्न करके खरा उतरने का प्रयास करूंगा।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मंत्री महोदय, जो आप कह रहे हो, यह कानून हमारे नागौर में लागू हुआ ही नहीं। कोतवाली से सदर में भेज देते हैं, सदर से महिला थाने में भेज देते हैं। यह हमारे यहां लागू नहीं हुआ। आप रिकार्ड मंगा लें सभी का।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): शहरी क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में ही कानून नहीं है। नागौर में राजस्थान का अलग कानून चलता है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपको कह रहा हूं कि आप दो-चार नाम लिखकर मुझे दें। उसी थाने में, वह व्यक्ति उस जिले में तो है अभी, रह सकता है। एक ही जगह, एक ही थाने पर अगर वह पहले दो साल कांस्टेबल वहां रहा, फिर हैड-कांस्टेबल रह गया, फिर ए.एस.आई. हो गया और उसका सारा पीरियड जोड़कर पांच साल हो गया तो इसका मतलब

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

है कि उसको उस थाने में कभी भी नहीं आना है। यह मैंने नीतिगत निर्णय किया है और उसकी पालना के लिए मैंने हर एस.पी. से सर्टिफिकेट लिया है कि 'मेरे जिले में इस प्रकार से कोई पांच साल से अधिक एक स्थान पर नहीं है'। अगर उसमें कहीं चूक रह गयी है तो नाम लिखकर दें। मैं उसको दिखवाकर उनके खिलाफ कार्यवाई करूंगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। गृह मंत्री महोदय, आपके वृत क्षेत्र में कानून व्यवस्था के नाम से हर थाने में उस क्षेत्र के लोग लगे हुए हैं। आप इसकी जांच करा लें। आपका सर्कुलर है, आपका आदेश है, उसके बाद खूब थानों में लगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर के ठोस कचरा प्रबन्धन के कार्य

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपने पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय प्रधानमंत्रीजी और हमारी मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि स्वच्छ भारत कैसे हो? कैसे हमारा भारत स्वच्छ हो? राजस्थान स्वच्छ हो? कैसे शहर और गांव स्वच्छ हो? उसी के तहत मैं कहना चाहूंगा कि बाड़मेर शहर में ठोस कचरा संग्रहण.. बाड़मेर शहर के कचरे के लिए बाहर एक गेहूं गांव है, वहां पर उसके लिए जमीन अलॉटमेंट हुई। दिल्ली की एक फर्म, मैसर्स हाइड्रो टैक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को 11.10.2010 को कार्य आदेश दिया। नगर परिषद ने उस क्षेत्र में जो अलॉट हुआ उसके अंदर चारदीवारी बना दी और एक नाला भी बना दिया। बाड़मेर शहर का पूरा कचरा, मृत पशु, जितनी गन्दगी है, वह सारी सात साल से वहां डाल रहे थे। अभी एक-डेढ़ साल से वह जगह भर चुकी है। ठेकेदार ने काम नहीं किया, बंद करके भाग कर चला गया। सारा कचरा उसके अंदर सड़ रहा है। इतनी बदबू और गंदगी है कि आस-पास में जितनी आबादी रह रही है, उनका जीना मुश्किल हो गया। हर एक-दो महीने में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग उस गंदगी में रहे कैसे?

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री मेवाराम जैन)

यह ठोस कचरा है, इसको किसी तरह से, चाहे वहां दूसरी कम्पनी से काम कराएं उसका निस्तारण हो। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा इतनी समस्या है कि शहर का यह कचरा बाहर नहीं जाएगा, उसको कहीं डालने नहीं देंगे और उसका निस्तारण नहीं होगा, बीमारियां फैलेंगी। शहर के अंदर रहेगा। आज स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। स्वच्छ शहर की बात कर रहे हैं। अब कचरे को या तो इस माध्यम से बाहर ले जा रहे हैं।

दूसरा, शहर के अंदर जो गंदगी है उसे सीवरेज के माध्यम से बाहर कैसे भेजें ? बाड़मेर शहर में सीवरेज को चार भागों में बांटा। तीन के टैण्डर हो गये हैं। एक जो मेन बीच शहर में है, उसको बिलकुल छोड़ ही दिया। करोड़ों रुपये खर्च हो गये। पैसे भी बेकार गये, न कोई शहर साफ हो पायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से चाहूंगा कि ठोस कचरा संग्रहण की तत्काल व्यवस्था की जाए और शहर के अंदर गंदगी भर पड़ी हुई है, उसके लिए सीवरेज सिस्टम को पूरा कर, चालू करायें। ताकि करोड़ों रुपये जो सरकार के इस पर लगे हैं, उसका लाभ आम जनता को मिल सके। धन्यवाद। मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बाड़मेर शहर के ठोस कचरा संग्रहण केन्द्र के बंद पड़े कार्य को प्रारम्भ करने के बारे में समस्या बताई है। यह बात सही है कि बाड़मेर शहर में दिनांक 22.10.2007 को ठोस कचरा संग्रहण केन्द्र पर कम्पोस्ट प्लांट लगाने हेतु बीओटी आधारित ऑफर आमंत्रित किए गये थे। हाईड्रो टैक्निकल लिमिटेड़ को कार्यादेश दिया गया जिसमें धर्मकांटा, शेड, कमरों का निर्माण कार्य, पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट का कार्य तथा सालिड वेस्ट को रीसाइकिल करके कचरे को व्यवस्थित करवाना था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी को ठेका हुआ था उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया। लेकिन माननीय सदस्य आपको जानकारी होगी कि उसके बाद नगर परिषद ने अपने स्तर पर डामरीकरण का कार्य किया, चारदीवारी का कार्य करवाया तथा वर्तमान में भी नगर परिषद चारदीवारी का निर्माण कार्य अपने स्तर पर वहां पर करवा रही है, मेरी जानकारी में। इसके साथ ही मौके पर जिस कचरे की आप बात कर हैं उस कचरे का भी लेवलीकरण करके, इकट्ठा करके,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

उसका कार्य भी अभी चल रहा है, वहां पर नगर परिषद है वह कर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि वर्तमान में डीएलबी स्तर पर सालिड वेस्ट के सांइटिफिक डिस्पोजल हेतु तीन बार हमने टैंडर आमंत्रित किए, लेकिन अभी तक कोई भी टैंडर नहीं आया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इसका शीघ्र एक बार फिर हम टैंडर आमंत्रित करेंगे और निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप कह रहे हैं नगर परिषद द्वारा चारदीवारी का कार्य कराया जा रहा है। जो अलाटमेंट जमीन है वह सारी भर गयी है इन 8-9 साल से। वहां अब कचरा डालने की जगह नहीं है। कचरा बाहर फैल रहा है। बाहर फैलने से गंदगी फैल रही है और उससे बीमारियां फैल रही हैं। पास में जितनी ढाणियां और गांव है वह वहां पर रह नहीं पा रहे हैं। इतनी बदबू हैं। मृत पशु वहां पर डाल रहे हैं। पूरे शहर की गंदगी वहां डाल रहे हैं। इसलिए आप इसको तुरंत, जल्दी कराएं ताकि उनको राहत मिल सके।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज ही इस बात की जानकारी ले लूंगा। आप कह रहे हैं कि वहां कचरा फैल रहा है, लोग हड्डियां डाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आने वाले महीने में सफाई कराकर कम्पलीट करा दूंगा उसको। ...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सीवरेज....

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): इसकी भी मैं जानकारी ले रहा हूं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): करोड़ों रूपये खर्च हो रहे हैं। एक हिस्सा बीच वाला छोड़ दिया।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सीवरेज की जो योजना बनती है वह पूरी प्लानिंग से बनती है उसके बावजूद भी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

अगर कोई हिस्सा छोड़ दिया है, मैं उसकी जानकारी ले लूंगा। उसकी भी निश्चित रूप से नियमानुसार कार्यवाही कर देंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मेन शहर का हिस्सा छोड़ दिया, वह नहीं जुड़ेगा तो आपका पूरा सिस्टम ही फेल है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं आज ही उसकी जानकारी लेकर कार्यवाही करा दूंगा ।...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

गिड़ा तहसील मुख्यालय (बायतू) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बायतू विधान सभा क्षेत्र पूरा रेगिस्तान के अंदर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। उस रेगिस्तान के अंदर एक पीएचसी गिड़ा है। वहां का आउटडोर देखें तो आउटडोर की दृष्टि से राजस्थान के अंदर जोधपुर संभाग में सबसे ज्यादा 34200 उसका आउटडोर है। पिछले एक वर्ष में 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर तक आउटडोर 34200 है तथा संभाग में भी यह प्रथम स्थान पर है। स्वच्छता के अंदर भी पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर उसको सम्मानित किया गया। गिडा, के लोगों को इलाज कराने के लिए बहुत दूरी तक जाना पड़ता है। वहां के लोगों को बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के जो मापदण्ड़ है उन मापदण्डो को भी वह निश्चित रूप से पूरा कर रहा है। सीएचसी के मापदण्ड है उसके अनुसार एक लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार गिडा पंचायत समिति की 1 लाख 18 हजार 920 जनसंख्या भी है। इस हिसाब से देखें तो जो नोर्म्स है उसको पूरा करते हैं। वहां पर आउटडोर है उसके साथ इनडोर की संख्या भी एक हजार से ऊपर हर वर्ष रहती है। रेगिस्तान का क्षेत्र है उसके अंदर सर्पदंश के भी कई ऐसे केस आते हैं जिसके अंदर कई व्यक्तियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इस वर्ष 50 से ऊपर ऐसे केस आए, लोगों को वहां पर समस्या का सामना करना पड़ा। मैं यह कह सकता हूं कि यहां पर जो लोग है उनको अपना इलाज करवाने के लिए बालोतरा या जौधपुर जाना

(श्री कैलाश चौधरी)

पड़ता है। वहां से 50 किलोमीटर दूर बालोतरा है और कुछ लोगों को 80 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे मरीज होते हैं जिनका पूर्ण रूप से गिडा के अंदर इलाज नहीं होता, जोधपुर जाते हैं, बीच रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। इंटीरियर है, रेगिस्तान के अंदर, जो नोर्म्स को पूरा करते हैं, ऐसा पीएचसी गिडा है उसकी अगर सीएचसी में क्रमोन्नत करते हैं तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी।

मंत्री महोदयजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वह सरल हृदय के हैं। उन्होंने पहले भी, जो कहा, पूरा किया है। स्वच्छता के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर उस हास्पिटल को सम्मानित किया गया है, उसके साथ ही आउटडोर भी पर्याप्त मात्रा में है। मैं मंत्री महोदयजी से आश्वासन चाहूंगा कि गिडा में आप इसी सत्र के अंदर घोषणा कर दें तो गिडा क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ऐसी मैं मंत्री महोदयजी से आशा करूंगा । धन्यवाद।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह बिलकुल सही है। सीएचसी में क्रमोन्नत होने के लिए मापदण्ड भी यह पीएचसी पूरा करती है। इसका गुण दोष के आधार पर परीक्षण करवाकर उचित निर्णय लेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह राजपुरोहित।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): गुण-दोष पूरे करते हैं भाई साहब, गुण अवगुण पूरे हैं। मंत्री महोदयजी, गुण अवगुण पूरे हैं, इसी सत्र में इसकी स्वीकृति कराएं, यह आपसे विशेष निवेदन है।

जवाई बांध का पुनर्भरण व सेई बांध टनल का चौड़ाईकरण

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है। जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई नदी लगभग 300 किलोमीटर जालौर जिले में छूती हुई आगे जाती है। जवाई बांध बनने से पहले या बनने तक, जवाई नदी के किनारे लगभग 270 गांव है, जिनके सारे कुएं सूख गये। नदी डार्क जोन में आ गयी। जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है उससे पाली और जालौर में सिंचाई होती है। पाली जिले के 600

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

गांवों को पेयजल उपलब्ध होता है। मानसून पर आधारित जवाई बांध है। मानसून अगर अच्छा होता है तो जवाई बांध भरता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है कि जवाई बांध का पुनर्भरण, नदियों से नदियां जोड़ने वाली हमारी जो स्कीम है और हमारे मुख्य मंत्रीजी की एक सोच है, तो पाली,जालौर, बाड़मेर, सिरोही यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा डैम है। इस बांध के पुनर्भरण के लिए, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने इसके पुनर्भरण की डीपीआर बनाने की घोषणा की है, इसमें सीडब्ल्यूसी को भेजा है और वहां से इसकी परमीशन, लगभग साढ़े बारह करोड़ रुपये सरकार ने स्वीकृत कराए इस डीपीआर के लिए, मंत्री महोदय आपका और मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन यह है कि इसको थोड़ी गति देना आवश्यक है। पुनर्भरण होगा तभी लगभग 300-400 गांव जीवित रहेंगे। ढाई हजार करोड़ से ऊपर की योजना है, हमारे पश्चिमी राजस्थान का एक जीवंत बांध है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मंत्री महोदय, डीपीआर और यह सारा विषय, आपकी घोषणा हुई है। तो मैं आपके माध्यम से सदन को, सदन के माध्यम से जनता भी जानना चाहेगी।

इसके साथ-साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जवाई बांध में एक सेई बांध का पानी आता है। वह टनल जब बनी थी, तब बनी थी। उसके बाद आज दिन तक उस टनल की सफाई नहीं हुई। टनल, सेई बांध से ओवर-फ्लो होकर पानी गुजरात में वेस्ट जाता है। आज प्रति दिन लगभग 34 एम.सी.एफटी. पानी जवाई बांध में आता है। इसको डबल कर दिया जाए, बहुत छोटा सा खर्चा है। सरकार की मंशा भी है, आगे अधिकारियों ने रिपोर्ट भी दी है, 34 एम.सी.एफटी. की जगह 70 एम.सी.एफटी. कर दिया जाए तो जो गुजरात में लगभग साढे तीन हजार एम.सी.एफटी. पानी वेस्ट जाता है, इसका अगर आज की तारीख में 800 से 1000 एम.सी.एफटी. पानी आता है, उसकी जगह 2000 एम.सी.एफटी. पानी आएगा तो कम से कम यह पानी, जब जवाई बांध भरता है, तब सिंचाई और पेयजल के अधिकारियों में खींचातानी चलती है, यह बंद हो जाए। किसानों को भी बराबर अपने हक का पानी मिले। दूसरा, इस टनल को चौड़ा कराने वाली डी.पी.आर. के लिये आप

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

फर्माएं। तब तक इस टनल के सफाई की कोई न कोई व्यवस्था करें, जिससे कम से कम थोड़ा-बहुत पानी जवाई डैम में आए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जवाई डैम में लगभग 7000 एम.सी.एफटी. पानी की कैपेसिटी है। 62 फीट तक यह भरता है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि इसमें लास्ट में कोई 500-700 एम.सी.एफटी. की खींचातानी पेयजल और सिंचाई वालों में चलती है। अब इस चौड़ा करने के बाद अगर यह 1500 एम.सी.एफटी. पानी बढ़ता है तो हमेशा-हमेशा के लिये तकलीफ से पार हो जाते हैं और पाली, जालौर दोनों जिलों को पूरी मदद मिलेगी।

दूसरा, मेरा एक निवेदन है कि जवाई बांध के अन्दर राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा बीच-बीच में कुछ ऐसे एनीकट बने हुए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है। न तो पास में कोई कुएं हैं, जो रिचार्ज होते हों, तो मेरा एक निवेदन है कि जो नाकारा एनीकट हैं उनको या तो तोड़ दिया जाये, जिससे जवाई डैम में पूरा पानी मिल सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस मामले में बहुत ही संवेदनशील हैं, खाली निवेदन आपके माध्यम से इतना ही रहेगा कि यह जवाई बांध, पुनर्भरण यह मेरे जालौर की तो बिलकुल सांस है। अगर जवाई बांध भरता है और जवाई नदी में थोड़ा-बहुत पानी रिचार्ज होकर जाता है, मेरे आहौर के इलाके के लिये एक समय कहा गया था कि बेदाना अनार, जिसमें दाना नहीं होता था, इतने अनार के बगीचे थे, आज सूख गया है पूरा। लगभग 190 ऐसे ट्यूबवैल बने हुए हैं, हमारे पी.एच.ई.डी. के, वह भी काफी तकलीफवश, इस बार जो पानी हमारा चला है, और मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार जैसे जवाई डैम लगभग 55 फीट से ऊपर आते ही, आपने नदी में थोड़ा-थोड़ा पानी छोड़ना चालू करवाया तो मैं जालौर की जनता की ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अब यह भाव हमारा, कम से कम 52 से 55 फीट के ऊपर नदी में पानी छोड़ने का भी, जिससे नदी रिचार्ज हो जाए और जवाई बांध का पुनर्भरण, यह हमारे जालौर जिले के लिये जीवन है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है कि इन बातों को, डी.पी.आर. बन गयी, आदेश फर्मा दें इस काम को, अगर वास्तव में हो गयी है तो आप फर्माएं और गति देवें। सेई की जो टनल है, उसको सफाई करना और टनल को चौड़ी करने की अपन मंशा रखें तो पानी डबल आ जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाई पुनर्भरण की योजना है यह हमारे पाली और जालौर के लिये जीवन का आधार है। पीने के पानी के लिये जो जवाई से परियोजनाएं बनी हैं, उनके लिये जवाई में पर्याप्त मात्रा में पानी हो, और डी.पी.आर. के लिये आपने जो व्यवस्था की है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस डी.पी.आर. को तुरन्त प्रभाव से लागू करने के लिये, आपने 12 करोड़ रुपये डी.पी.आर. के लिये दिये हैं तो अधिकारी को लगा करके वह डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्दी तैयार करके उसके पुनर्भरण की व्यवस्था करें, पाली और जालौर जिले आपका आभार व्यक्त करेंगे। आपने डी.पी.आर. के लिये स्वीकृति जारी की है, उसके लिये भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं, राजस्थान सरकार का और मंत्री महोदय, आपका।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माही का भी साथ में कह दीजियेगा।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सर्वोच्च सदन को चलाने के लिये प्रक्रिया और नियमों के बारे में जितने आप स्ट्रिक्ट हैं, और कोई नहीं हो सकता। आपकी छवि इस किस्म की है। पर्ची के माध्यम से एक माननीय सदस्य उठाते हैं, दूसरे एक और खड़े हो जाते हैं। फिर रेस्पांड करने के बाद में सप्लीमेंट्रीज करते हैं। तो थोड़ा-सा इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। ...(व्यवधान)...

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): तीसरा खड़ा नहीं हुआ, अच्छा हुआ।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): यही तो मैं कह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, जालौर और यह पार्ट हमारा बहुत ही डेफिसिट है। चाहे पेयजल की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, इसके पुनर्भरण की घोषणा ही नहीं की है मुख्य

(डा. रामप्रताप)

मंत्रीजी ने, इसके डी.पी.आर. का काम हमने वापकोस लिमिटेड को दे दिया है। दिसम्बर, 2017 तक का उसका टाइम लिमिट है। उसके आने के बाद में इसको टैक्निकली और बी.सी. रेशो वगैरह देख करके अगर फिजीबल होगा तो संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेई से जो पानी जवाई बांध को जाता है उसकी टनल को बड़ा करने के लिये इन्होंने बताया। इसको दिखवा करके अगर यह फिजीबल होगा तो इसका कार्य हम करवा देंगे।

यह दो मुख्य बातें थीं। तीसरी आपने एनीकट्स की बात कही है। मेरे ख्याल से ऐसी बात पहली दफा आई है कि उनकी उपादेयता नहीं है। उसको भी दिखवा लेंगे। अगर कोई ऐसा एनीकट जिसका कोई यूज नहीं हो रहा है और कोई आब्स्टेकल खड़ा करता है तो उसको हटवा देंगे।

व्यवस्था

पर्ची पर पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं दी जाएगी

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सदन को यह सूचित करना है कि सम्माननीय मंत्री महोदय द्वारा आपत्ति जताई गई है। अगर सदन की अनुमति हो तो पर्ची के भी नियम बना दें। पर्ची के कोई नियम नहीं हैं। एक परम्परा है कि पर्चियां चार व्यक्तियों की खुलती हैं और उसके आधार पर, परम्परा के आधार पर हम वक्तव्य देते हैं। कई बार बहुत से सम्माननीय सदस्यों को निवेदन करते हैं कि पर्ची के माध्यम से आप अपना वक्तव्य सीमित रखें और जो जानकारी आपको चाहिये, वह जानकारी आप प्राप्त कर लें। उसके उपरान्त भी एक के बाद एक पर्ची पर बोलते हैं। आसन कई बार मानवता के नाते शिथिलता प्रदान करने के लिये बाध्य भी हो जाता है। इसलिये अनुशासन की आपसे आस करते हैं। अगर आप चाहें तो फिर कॉपी-बुक फैशन में आसन भी उतना ही सख्त हो जाएगा।

इसलिये आप सबसे यह निवेदन है कि समय का भी और विषय का भी, और जैसा कि मंत्री महोदय ने ठीक फर्माया, जो विषय प्रथम सम्माननीय सदस्य ने पर्ची से उठाया था, तकरीबन वह सारा विषय उसमें

कवर हो गया था। इसलिये अब पर्ची पर न तो कोई सप्लीमेंट्री और न ही किसी और को बोलने की इजाजत दी जाएगी।

पर्ची का यह प्रथम नियम आज आसन बनाता है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि ये पर्चियां चार की जगह दस कर दी जाएं ताकि हमें बोलने का मौका मिले।

श्री उपाध्यक्ष: अगर पर्चियों पर इसी प्रकार के वक्तव्य आते रहे तो शायद हो सकता है, चार से दो भी कर दी जाए।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री राजपालसिंहजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

आउटपुट बजट (वर्ष 2015-16) व आउटकम बजट (वर्ष 2016-17)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट बजट वर्ष 2015-16 एवं आउटकम बजट वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र.सं. 30)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार,

(श्री कालू लाल गुर्जर)

दिनांक 08 मार्च, 2017 को मध्याह्न पश्चात् 2.45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 09 मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

गुरुवार, दिनांक 09 मार्च, 2017 शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च, 2017	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 पर सामान्य वाद-विवाद
शनिवार, दिनांक 11 मार्च, 2017 रविवार, दिनांक 12 मार्च, 2017 सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2017 मंगलवार, दिनांक 14 मार्च, 2017 बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2017	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2017	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद
शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च, 2017	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-18 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की और से उत्तर।
शनिवार, दिनांक 18 मार्च, 2017 रविवार, दिनांक 19 मार्च, 2017	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2017	1- अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2016-17 (द्वितीय संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2017 का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 2- अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(श्री कालू लाल गुर्जर)

मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017 बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2017 गुरुवार, दिनांक 23 मार्च, 2017 शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 2017 शनिवार, दिनांक 25 मार्च, 2017	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
रविवार, दिनांक 26 मार्च, 2017	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 27 मार्च, 2017 मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2017	अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
(आय-व्ययक अनुदान वर्ष 2017-18 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर दिनाकं 28 मार्च, 2017 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी)	
बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 2017	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 30 मार्च, 2017	1- राजस्थान वित्त विधेयक, 2017; एवं 2- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017-पर विचार एवं पारण।
शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 2017	1- राजस्थान नगरपालिका (द्वितीय संसोधन) विधेयक, 2017; एवं 2- राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संसोधन) विधेयक, 2017-पर विचार एवं पारण।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री बाबूसिंहजी।

याचिका

शेरगढ़ में सड़कों का नवीनीकरण

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सड़कों के नवीनीकरण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

किशनगढ़ उपखंड मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) उपखंड मुख्यालय पर बजट वर्ष 2017-2018 में विधि महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति जारी करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी।

रायसिंहनगर में बालिका महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर (जिला श्रीगंगानगर) में बालिका महाविद्यालय खोले जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर। (अनुपस्थित)

श्री केसाराम चौधरी।

मारवाड़ जंक्शन में आई.टी.आई. की स्थापना

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में आई.टी.आई. खोले जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि आबंटन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

घोषणा

आय-व्ययक वर्ष 2017-2018 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का आवंटन

श्री उपाध्यक्ष: आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का आवंटन।

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2017-2018 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिया जाना का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

भारतीय जनता पार्टी	-	12 घंटे 48 मिनट
इण्डियन नेशनल कांग्रेस	-	01 घंटे 57 मिनट
नेशनल पीपुल्स पार्टी	-	20 मिनट
बहुजन समाज पार्टी	-	10 मिनट

(श्री उपाध्यक्ष)

नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	-	10 मिनट
निर्दलीय	-	35 मिनट
		कुल-16 घंटे

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। ....(व्यवधान)....

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शुरूआत तो इधर से होनी चाहिए, ऐसा नियम है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह नियम है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण पर वाद-विवाद तो पहले सत्ता पक्ष शुरू करता है और बजट पर वाद-विवाद पहले प्रतिपक्ष शुरू करता है। नियम तो यही है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी अगर इजाजत हो तो इधर से चालू करा दें?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपने पुकारा, मेरे बाद आप बोल देना।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं। Let us follow it. श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर सामान्य वाद-विवाद के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने कल जो बजट प्रस्तुत किया, लोगों को आशा थी, लोगों को अपेक्षा थी, हमारे विधायक साथी जो सामने बैठे हैं, इनको भी बहुत आशाएं थीं, कुछ लोगों ने सोच रखा था कि, हमारी जिला बनाने की मांग बहुत दिनों से चल रही है, जिले की घोषणा होगी। कुछ लोगों ने सी.एच.सी, पी.एच.सी., सड़क, किसी ने बांध की और प्रदेश की जनता ने सोचा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी परियोजना मिलेगी, बड़ा काम होगा, इस प्रदेश में निवेश आएगा, लेकिन कल जो बजट प्रस्तुत किया

(श्री रमेश)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ऐसा लगा कि पिछली बार भी इन्होंने बजट में घोषणाएं कीं, वह घोषणाएं धरातल पर नहीं आ पाई हैं और घोषणाएं थोथी साबित हो रही हैं। तो अब जनता भी जान चुकी है इस राजस्थान की, भारतीय जनता पार्टी को राज्य में आए हुए सवा तीन साल से अधिक हो गया और इनको भी यह महसूस हो गया है कि अब हम दुबारा आने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह सरकार जनाधार खो चुकी है। लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और इसका उदाहरण अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने तीन साल का समारोह मनाया था, जश्न मनाया था, यह सालाना मनाते हैं, तो इन्होंने अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए लोगों को बुलाया। कुर्सियां खाली पड़ी रहीं क्योंकि लोग जान चुके। यह बुला रहे थे कि उपलब्धियां सुनो, लोगों ने कहा कि उपलब्धियां नहीं सुना रहे हैं, यह थोथी घोषणाएं सुना रहे हैं तो सुनने से कोई फायदा नहीं है और आम आदमी जान चुका है कि इस सरकार ने हमें ठगा है।

जिस प्रकार इन्होंने बजट में घोषणा की है, किसी को थोड़ी रेवड़ी बांट दी, किसी को हैंडपम्प दे दिया, किसी को छोटी-मोटी सड़क दे दी, किसी के कोई सब्जैक्ट आर्ट का खोल दिया, कहीं साइंस का खोल दिया, कहीं कॉमर्स का खोल दिया, छोटे-मोटे काम कर दिये। इस प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप होना था, जो कर्ज बढ़ रहा है, उस कर्ज को कैसे रोकना था, इस प्रदेश में कैसे खुशहाली आएगी, इस प्रदेश का समग्र विकास कैसे होगा, इस बारे में सरकार ने नहीं सोचा। सरकार एक बात सोचती है कि इस राजस्थान की सम्पत्ति को कैसे बेचा जाए? जो सम्पत्ति है हमारी राजस्थान की, इनका पी.पी.पी. मॉडल पर या निजीकरण कैसे किया जाए? तो मैं कह सकता हूं कि यह सरकार नहीं है। जिस प्रकार इस भारत देश में ईस्ट इंडिया कम्पनी आयी थी, उसी प्रकार यह सरकार काम कर रही है।

राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कर्ज को बढ़ाया है, उसके बारे में मैं पीछे से चलकर आगे बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार कहती है जो भी काम किया है, अच्छा काम किया है, उसके बारे में गिनती नहीं होती कांग्रेस पार्टी की। बात आती है कि कांग्रेस ने करप्शन किया, कांग्रेस ने कर्ज को बढ़ाया, तो 1990 तक राज्य पर कर्ज केवल 6127

(श्री रमेश)

करोड़ रुपये था और ब्याज के रूप में 437 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा था लेकिन आपकी भाजपा सरकार आने के बाद 1990 से 1998 के आठ सालों में यह कर्ज 23532 करोड़ 96 लाख रुपये हो गया। जिसके ब्याज के पेटे, 1999 में हमारी सरकार के समय 2243 करोड़ 43 लाख रुपये का भार आ गया था। 8 सालों में आपने कर्ज को चार गुना बढ़ा दिया।

हमारी पार्टी के 1998 से 2003 के कार्यकाल में 2003 तक कर्ज 53300 करोड़ रुपये होने के कई कारण हैं। लेकिन वह वित्तीय कुप्रबन्धन नहीं कह सकते बल्कि विकास और कुशल प्रबन्धन के गवाह रहे। उस समय राज्य में सबसे भयानक अकाल पड़ा, जिसका हमारी सरकार ने सफल प्रबन्धन किया। हमने बिजली का उत्पादन राज्य में दुगना करके दिखाया। हमने किसानों को बिजली छह से आठ घंटे दी। इसके बाद 2003 में जब आप सत्ता में आये तब तक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज केन्द्र सरकार की अपेक्षा आधा था। 1998 से 2003 के दौरान देश के सभी राज्यों का ऋण भार दो से तीन गुना हो गया था। ऐसी स्थिति में हमने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य के वित्तीय प्रबन्धन को संभालकर रखा और विकास भी किया।

2003 में आपके सत्ता में आने के बाद पांच सालों में कर्ज 82 हजार 858 करोड़ रुपये हो गया। आपके समय में न तो अकाल की समस्या थी, न कमजोर आर्थिक स्थिति थी, न बिजली की समस्या थी। इसके बाद भी वित्तीय प्रबन्धन के नाम पर राज्य की भूमि को आपने बेचा। आपने सम्पत्ति बेचकर वित्तीय प्रबन्धन किया। इतना सब करने के बाद भी राज्य पर कर्जा बढ़ा।

हमने 2009 से 2013 के बीच में कर्जा लिया, लेकिन राज्य का इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारा। देश का सबसे बड़ा 700 के.वी. के जी.एस.एस. स्थापित किये, सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया। नि:शुल्क दवा, नि:शुल्क जांच, सामाजिक पेंशन, अन्य जन कल्याण के सबसे अधिक लाभ देने वाली योजनाएं चलायीं। हमने कर्ज लेकर कोई फिजूलखर्च नहीं किया।

2014 में जब आप पुन: सत्ता में आए तो कर्ज एक लाख करोड़ से अधिक हो गया। हमने कर्ज लेकर राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया। सड़कों का जाल और किसानों के हित में बिजली, ऊर्जा के परम्परागत स्रोत

(श्री रमेश)

और कर्मचारी कल्याण के लिये कार्य किया। हमने कर्मचारियों को पदोन्नति के भरपूर अवसर दिये। लेकिन आपने आते ही वह सब छीन लिये। आपने 2014 में सत्ता में आने के बाद पहले कर्ज लेने को गलत बताया। लेकिन आपने सत्ता में आते ही एक साल बाद ही जनवरी, 2015 में आपने 19 हजार 393 करोड़ रुपये 98 लाख का कर्जा ले लिया।

देश के सभी राज्य कर्जा लेते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको उत्पादक कार्यों पर लगाना चाहिये। आज हमारे देश में महाराष्ट्र जैसा प्रदेश है, उस पर सबसे ज्यादा कर्ज है, लेकिन उसकी जी.एस.डी.पी. 20 से 22 प्रतिशत है। इसी तरह तमिलनाडु प्रदेश है, वहां 2010 से 2015 तक कुल कर्ज के बराबर उन्होंने कर्जा लिया है लेकिन वह इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्लान में खर्च कर रहे हैं। हमें जी.डी.पी. और ऋण के अनुपात का ध्यान रखना चाहिये, लेकिन यह निरन्तर तेजी से बढ़ रहा है। कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आपने उदय योजना के नाम पर बिना जनमत जाने 62 हजार करोड़ का बिजली कम्पनियों पर जो बोझ डाला, वह आम जनता पर बोझ है। तो इस प्रकार के आपने कदम उठाये।

राज्य की अर्थव्यवस्था की आपने कमर तोड़ दी। आज राज्य की आर्थिक स्थिति कर्ज और उसके बाद इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने की क्षमता को आंकने के बाद निवेशक राज्य में निवेश से भी बच रहे हैं। पहले केवल बिजली कम्पनियों का दिवाला हो रहा था, आज पूरा राज्य दिवालियापन के कगार पर आ गया है। क्योंकि सरकार प्लान एक्सपेंडिचर पर ज्यादा खर्च करे, मितव्ययता बरते, मंत्री-अधिकारियों को बार-बार लवाजमा लेकर विदेश यात्राएं करना, हवाई यात्राएं करना, राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह बिलकुल उचित नहीं है और अभी तक इनके कोई परिणाम नहीं आये हैं। केवल हमारे अधिकारी और मंत्री विदेशों में घूमकर आ गये हैं।

राज्य की जी.एस.डी.पी. में आपकी सरकार आने के बाद निरन्तर गिरावट आयी है। 2012-13 में 13.50 प्रतिशत थी, 2013-14 में 11.23 प्रतिशत रह गयी, 2014-15 में 10.59 प्रतिशत रह गयी, 2015-16 में 10.12 प्रतिशत रह गयी। अब 2016-17 में आप अनुमानित बढ़ोतरी 11.44 प्रतिशत बता रहे हो, लेकिन यह भी वास्तविक है कि 10 प्रतिशत से नीचे रहेगी।

(श्री रमेश)

जब आपका बजट ही पूरा खर्च नहीं कर पा रहे हो, तो जी.एस.डी.पी. कैसे बढ़ेगी।

राज्य के प्रति व्यक्ति की आय 2012-13 में 11.12 प्रतिशत बढ़ी, जबकि आपकी सरकार आने के बाद 2014-15 से 2016-17 तक इसमें लगभग 9 प्रतिशत औसत बढ़ोतरी हुई और वह भी थोक मूल्य सूचकांक एवं प्राथमिक वस्तु समूहों में बढ़ोतरी के कारण नगण्य साबित रही।

आप वित्तीय प्रबन्धन की बात करते हैं, लेकिन आप आंकड़ा देखें तो जो राजकोषीय घाटा है 2011-12 में, 3,626 करोड़ था, 2012-13 में 8,538 करोड़ रहा। आपकी सरकार आने के बाद 2014-15 में यह आंकड़ा 19 हजार करोड़ पर पहुंच गया। 2015-16 में 2,320 करोड़ रहा, जोकि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.42 प्रतिशत रहा। राजकोषीय घाटा उदय योजना सहित बात कर रहे हैं, तो 63,070 करोड़ रहा, जोकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 9.38 प्रतिशत रहा। हमारे कार्यकाल में जो कर्जा था, वित्तीय घाटा था, वह 10 हजार से कम था। जब आपके शासन में आने के बाद प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार कर्जा बढ़ रहा है।

अगर हम प्रदेश में कर और राजस्व की बात करें तो विगत छह वर्षों के दौरान लगातार 13.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जब आपको कर और राजस्व भरपूर बढ़कर मिल रहा है, उसके बाद भी आपका घाटा बढ़ रहा है तो इससे आपका अकुशल वित्तीय प्रबन्धन का एक उदारहण है।

आपने राज्य की जनता से सुराज संकल्प यात्रा के दौरान बहुत सारे वायदे किये थे। बजट भाषण है, आपकी जनसभाएं हैं और जनहित के कार्यों के लिये बहुत सारी घोषणाएं कीं, लेकिन जिस प्रकार आपने बजट का आकार बड़ा होता है, पैसा कम खर्च किया जाता है, उस पैसे को बचाकर नैक्स्ट बजट में एडजस्ट करना और उसको आप लाभ में दिखाते हो। दिसम्बर, 2016 तक आपके काफी सारे ऐसे विभाग हैं, मनमानी बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं, उसमें आप 50 प्रतिशत तक भी खर्च नहीं कर पाये हैं और तीसरी तिमाही की समाप्ति तक विभागों को अपना औसत 75 प्रतिशत तक पैसा व्यय करना चाहिये था, लेकिन वह नहीं कर पाये।

(श्री रमेश)

कृषि में, आपके सत्ता में आने के बाद राज्य की जी.डी.पी. कृषि का योगदान आपके आने के बाद निरन्तर घटा है। राज्य में कृषि को आबंटित बजट भी हर वर्ष घटा है। इसमें बुरी स्थिति यह रही कि कम आबंटित बजट भी पूरा खर्च नहीं हुआ। 2015-16 में आपने कुल बजट का 5.57 प्रतिशत यानी 3,975.84 करोड़ कृषि को आबंटित हुआ था, जिसमें से केवल 3,271.82 करोड़ ही खर्च किया। 2016-17 में कुल बजट का 5.62 प्रतिशत बजट आबंटित किया, जो 5,606.74 करोड़ था, लेकिन दिसम्बर, 2016 तक आप केवल 1756.51 करोड़ ही खर्च कर पाये, यानी केवल 31.32 प्रतिशत हुआ। अब बाकी पैसा आप तीन माह में कैसे खर्च करेंगे ? इससे तो ऐसा होगा कि भ्रष्टाचार होगा या पैसे को इधर-उधर खुर्द-बुर्द किया जाएगा। आपने 2017-18 के बजट आबंटन में फिर 0.05 प्रतिशत घटा दिया, जबकि आप एग्रीटेक आयोजित करने जा रहे हैं, किसानों के विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी किसान का बजट नहीं बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आपकी 2017-18 की घोषणा हर संभाग में एग्रीटेक मीट आयोजित करेंगे, उससे किसान को क्या लाभ मिलेगा ?

हम ग्रामीण विकास की बात करें, माननीय राठौड़ साहब, आप सुन लें, आपके विभाग की बात हो रही है। 2016-17 में आबंटित बजट 12292.44 करोड़ में से दिसम्बर, 2016 तक केवल 6586.15 करोड़ यानी 53.58 परसेंट ही आप व्यय कर पाये हैं। इसके बाद आपने अगले बजट के लिए आबंटित राशि घटा कर 10872.60 करोड़ कर दी, यानी 11.56 प्रतिशत की कमी हो गयी, एक तरह से 12 परसेंट की बजट में कमी। इतना बड़ा ग्रामीण विकास, पहले आपने 2015-16 में ग्रामीण विकास को 15.48 परसेंट बजट आबंटित किया था, उसके बाद 2016-17 में 12.33 प्रतिशत, यानी 3.15 प्रतिशत की कमी और अब उसमें भी 11.56 प्रतिशत कम राशि आबंटित कर के आप इस विभाग को, इसकी योजनाओं को समाप्त करना चाहते हैं। या ऐसा लग रहा है कि राजेन्द्र राठौड़ साहब हैं, जो बढ़ना चाह रहे थे, आपके पावर को कम किया जा रहा है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है, राज में कहीं न कहीं कुछ लीक हुआ है।

तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, इसी प्रकार खनिज और उद्योग

(श्री रमेश)

में आपने 2016-17 में 530.45 करोड़ का आबंटन किया लेकिन आप दिसम्बर, 2016 तक केवल 32.28 प्रतिशत यानी 171.13 करोड़ रुपये खर्च कर पाये यह आपके नाकारापन को घोषित करता है कि आप काम करना नहीं चाहते। आपको राजस्व मिलता, खनिज और उद्योग, लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है।

आपके सत्ता में आने के बाद हमारे द्वारा जनवरी, 2015 में खनिज घोटाले की बात उठायी गयी, आपने नहीं मानी और इस प्रदेश को करीब 40 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। अभी भी मैंने विधान सभा में जो क्वेश्चन लगाया था कि आपकी सरकार केन्द्र में बैठी है उसके बाद आपके तर्क को नहीं मान खान बहाली के आदेश आपको दे रही है, आपका विधिक परीक्षण बाद में हो रहा है। तो यह सब चीजें आपकी लापरवाही, अवेयरनैस का एक नमूना है।

इसी तरह आप 2016-17 में बजट का एक-तिहाई खर्च कर पाये, तो आपने बजट को ही घटा दिया। 2017-18 में उद्योग, खनिज के लिए केवल 319.84 करोड़ दिया। बाकी का 1120.40 आपने रिफाइनरी के लिए लिया है, जिसके लिए आपने पहले केवल 80 करोड़ का प्रावधान किया, तो आखिर शायद जनता की आवाज आप तक पहुंच गयी है कि हम ज्यादा नहीं दबा सकेंगे रिफाइनरी की बात को। अच्छी बात है अगर मुख्यमंत्री और सरकार ने सोचा है कि रिफाइनरी लगेगी। उसके लिए आपने 1120.40 करोड़ का प्रावधान किया है, आपको ध्यान आया है तो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा लेकिन आपने तीन साल तक इसको क्यों लटकाये रखा ? क्योंकि अब जो भी लागत आयेगी उसके अतिरिक्त दस से बारह हजार करोड़ का अतिरिक्त खर्चा आयेगा। पर फिर भी आप रिफाइनरी लगाते हैं, हमारे राज्य का प्रतिशत कितना रहता है, कितने करोड़ खर्च होगा, कम लागत में लगेगी, कितने दिनों में बन कर तैयार होगी जिससे हमारे प्रदेश को जो बीस हजार करोड़ के करीब राजस्व मिलना चाहिए, क्रूड ऑयल बाहर जा रहा है, यदि रिफाइनरी लगती है तो अच्छी बात है। इसकी थोथी घोषणा नहीं होनी चाहिए, यह हमारा आपसे निवेदन है।

इसी तरह आपने गलत नीतियों के कारण रिसर्जेण्ट राजस्थान मनाया।

(श्री रमेश)

उसमें 3.21 लाख करोड़ के 295 एम.ओ.यू. किये। धरातल पर मात्र 2016-17 दिसम्बर तक राज्य में केवल 1189.79 करोड़ का निवेश हुआ और केवल 25465 रोजगार उपलब्ध करवाये। यह आपके डाटा दे रखे हैं। 2016-17 दिसम्बर तक 5678.40 एकड़ भूमि रीको द्वारा अवाप्त की गयी जिसमें केवल 554.94 एकड़ भूमि ही विकसित की गयी जबकि आपने 2016-17 के बजट में 10 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनाने की बात कही। तो आखिर इतनी भूमि का उपयोग क्या होगा जबकि निवेश तो आ ही नहीं रहा? यहां तक कि आपने रिसर्जेण्ट राजस्थान का पुन: आयोजन तक निरस्त कर दिया है।

हम परिवहन विभाग की बात करें तो उसमें कुल आबंटित बजट 6327.14 करोड़ का केवल 28.14 प्रतिशत, यानी केवल 1780.44 करोड़ ही दिसम्बर, 2016 तक खर्च कर पाये। ऐसे में राज्य की परिवहन व्यवस्था कैसे सुधरेगी? फिर बात होती है, हमारे मंत्रीजी हैं, यूनुस खान नहीं हैं, नम्बर दो की बात हो रही है, रोजाना प्रदेश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी किसी दिन 17 एक स्पॉट पर मर जाते हैं, कहीं रोजाना सैकड़ों लोग मर रहे हैं। जितने लोग बीमारी से नहीं मर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं लेकिन इस सरकार के मंत्री और सरकार बिलकुल मौज में सो रही है, इसको कोई लेना-देना नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि परिवहन विभाग में केवल 28.14 प्रतिशत खर्च कर पाये और फिर दोबारा उतना ही पैसा आबंटित कर दिया, इन तीन महीनों में कैसे खपाया होगा? तो इस पैसे को आप बचा रहे हो या भ्रष्टाचार में लगा रहे हो? इसकी भी जांच होनी चाहिए।

वैज्ञानिक सेवाओं पर, राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण की बात करती है और राज्य को स्वच्छ राजस्थान बनाने का वादा करती है लेकिन आवश्यक वैज्ञानिक सेवाओं के लिए पिछले तीन सालों में राशि हर साल घटायी जा रही है। 2015-16 में 123.23 यानी प्वाइंट 17 प्रतिशत, 2016-17 में 113.78 यानी प्वाइंट 11 प्रतिशत, जिससे केवल 18.81 करोड़ यानी केवल 16.90 प्रतिशत राशि व्यय हुई। अब 2017-18 के बजट घटा कर 63.82 करोड़ कर दिया है यानी 44 प्रतिशत की भारी कमी।

(श्री रमेश)

इसके बाद राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, जिसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, जलदाय विभाग है, नगरीय विकास है, श्रम कल्याण है, समाज कल्याण है, पिछड़ी जाति कल्याण है, जनजाति कल्याण है, विशेष योग्यजन कल्याण है, अल्पसंख्यक विकास, देवस्थान जैसे महत्वपूर्ण विभाग आते हैं, उसका बजट भी दिसम्बर, 2016 तक 54.54 प्रतिशत व्यय हो पाया है। राज्य सरकार ने जनता से सीधे जुड़े हुए इन महत्वपूर्ण विभागों का बजट निश्चित समयावधि अनुसार व्यय करने के स्थान पर अगले बजट में इस मद में आबंटित राशि घटा दी, जो कि हर साल इस मद में बढ़ती थी, यानी 8 प्रतिशत घटा दिया गया और 2017-18 में केवल 35357.60 करोड़ राशि ही आबंटित की।

इसी प्रकार मिड डे मील की बात करें, जितनी राशि आबंटित की थी क्या उससे नामांकन बढ़ेगा? आपने उच्च शिक्षा, साक्षरता एवं सतत शिक्षा का बजट घटा दिया। खेल युवा कल्याण की राशि घटा दी। ऐसे में आप किस प्रकार विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करोगे? आपने चिकित्सा विभाग का बजट घटा दिया जबकि बढ़ती आबादी, नित नई महामारियों के कारण इसको बढ़ाना आवश्यक था। एन.आर.एच.एम. का बजट घटा दिया। आवास एवं नगरीय विकास का बजट आधा कर दिया। कुपोषण दूर करने का दावा करने वाली सरकार ने पोषाहार के बजट को भी घटा दिया। अगला निशाना जिसकी आप बात करते हैं, अल्पसंख्यक, आपने अल्पसंख्यक कल्याण का बजट ही आधा कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जो सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के बजट में इतनी भारी कटौती करती है तो, एक तरह से यह भावना ठीक नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सरकार बड़े बहुमत के साथ आयी और आम लोगों के साथ चौथे बजट की जो घोषणा है, इससे पहले के बजट की घोषणा है, घोषणाएं थोथी निकल रही हैं।

(14.00 बजे)

आम आदमी के साथ दगा हो रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा बिजली के बारे में बताना चाहूंगा। उदय योजना के माध्यम से, राज्य सरकार, भारत सरकार और डिस्कॉमों के बीच में एक त्रिपक्षीय एमओयू किया गया था।

(श्री रमेश)

उसमें 80,900 करोड़ का लोन लिया गया। उसमें कंडीशन, टर्म ऐसी थी कि राज्य सरकार 75 परसेंट टेकओवर करेगी। उसके बाद हमारी सरकार ने इन 2 सालों में 64,421.96 करोड़ का ऋण भार अपने ऊपर ले लिया है। इसमें मई, 2015 में 2,700 करोड़ रुपये एवं 2015-16 में 37,349.77 करोड़ रुपये का टेक ओवर किया। 2016-17 में 20,400 करोड़ का ऋण टेकओवर किया। जो 64 हजार करोड़ का आपने लोन लिया है, बांड जारी किए हैं, इन पर ब्याज 9.70 परसेंट, 9.80 परसेंट के बांड जारी किए गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक तरफ कर्जा अपने सर पर ले लिया। उसके बावजूद भी कंपनियां कर्ज बढ़ा रही हैं। आरईसी और पीएफसी को पिछले साल की रेवेन्यू के 25 प्रतिशत के पेटे वर्किंग कैपिटल लोन के लिए राशि 5,808 करोड़ की रिकवेस्ट भेजी है। जिसके बदले में पीएफसी ने 2,904 करोड़ तो सैंक्शन कर दिए हैं। इसी तरह से आरईसी का इंतजार है कि वह भी सैंक्शन करेगी। इसके अलावा डिस्कॉम ने 4 हजार करोड़ के वर्किंग कैपिटल लोन के लिए अन्य 4 बैंको से 1-1 हजार के, 4 हजार करोड़ के आउटस्टैंडिंग पावर परचेज की लाइबिलिटी पे करने के लिए रिकवेस्ट की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पीएफसी, आरईसी से पावर परचेज लाइबिलिटी कम करने के लिए रेगुलेरिटी असिस्ट के आधार पर आरईसी और पीएफसी से 8,144 करोड़ के ऋण की रिकवेस्ट की है।

इस प्रकार राज्य सरकार ने उदय योजना के माध्यम से कर्ज अपने ऊपर लिया। उसके बावजूद भी जो कंपनियां हैं, वह लोन ले रही हैं। उससे फिर कर्ज बढ़ेगा। उससे बिजली बोर्ड तो दिवालियापन पर जाएगा। लेकिन राज्य सरकार समय पर नहीं चेती, इनकी सही मानिटरिंग नहीं हुई, क्योंकि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको नहीं रोका गया, लापरवाही को नहीं रोका गया तो जो 64 हजार करोड़ का कर्ज राजस्थान सरकार ने टेकओवर किया है, इसका भी ब्याज हमें 9.70 और 9.80 प्रतिशत के हिसाब से देना है। लगभग यह मान लो कि प्रदेश की जनता पर सालाना 5 हजार करोड़ कर्ज के ब्याज का भार आएगा। मूल रकम तो है जो है। इस प्रकार से प्रदेश का जो कर्जा है, यह कह रहे हैं कि हमने कर्ज को कम कर दिया, हमने छीजत को कम कर दिया, वह बढ़ेगा।

(श्री रमेश)

दूसरी तरफ हमारी जो बिजली कंपनियां हैं, वह सस्ती बिजली की आड़ में, सरकारी पावर हाउस बंद, प्राइवेट कंपनियों से महंगी बिजली खरीदी जा रही है। 31 मार्च, 2016 तक 59,395 मिलियन यूनिट बिजली खरीदी गयी। 2015-16 में 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदी। सबसे महंगी बिजली आज तक खरीदी, 28,558 करोड़ की। हमें अभी जो बिजली पड़ रही है 2014-15 में वह 8 रुपये 83 पैसे प्रति यूनिट कंज़्यूमर तक पहुंचने तक। 2015-16 में 9 रुपये 20 पैसे पर यूनिट पड़ रही है कंज़्यूमर तक पहुंचने के लिए। आप कह रहे हो कि हमने बिजली के कर्ज में कमी की है। बिजली हम कम रेटों पर खरीद रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, घाटे का जो वास्तविक कारण है, पावर ट्रेडिंग के जरिये पिछले 5 साल में महंगी रेट पर बिजली खरीदना, ट्रांसफार्मर, मीटर, केबल व अन्य मैटेरियल खरीद, टैंडरों में गड़बड़ी, स्क्रेप की नीलामी में घपला। सिस्टम के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च, फिर भी बिजली छीजत में कमी नहीं आई। सरकार द्वारा उन परियोजनाओं पर निवेश किया जा रहा है, जिनमें वाणिज्य उत्पादन अभी प्रारंभ हुए 2 से 3 साल हुए हैं।

हम बात करें, छबड़ा का एनटीपीसी को दे दिया। काली सिंध के लिए निविदा निकाल दी। हमारी बात थी कि समय पर कामर्शियल उत्पादन नहीं हो पाया, उसमें कुछ ज्यादा पैसा लग गया। आपके 2008-09 के समय में काली सिंध नदी के जो टैंडर हुए थे, बीजीआर कंपनी थी, वह बाहर की कंपनी थी। उसने टैंडर में एक शर्त रख दी कि मैं जो पैसे लूंगी वह डालर के रूप में लूंगी। उस समय काम करते-करते डालर की कीमत ज्यादा बढ़ गयी और उत्पादन निगम को उसके पेटे 1400 करोड़ का अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी क्रीम बिजली कंपनियां हैं, छबड़ा है, काली सिंध है, वह अब प्रोफिट में हैं। उसके बाद भी आप उनको बेचना चाहते हो। एक तरफ आप सूरतगढ़ में परियोजनाओं को बंद कर देते हो, दूसरी परियोजनाएं बंद की कि घाटे का सौदा है। आपका लोड फैक्टर कम है। आपकी हीटिंग रेट ज्यादा है, इसलिए बिजली की कीमत ज्यादा आ रही है। दूसरी तरफ आप 1320 की एक यूनिट भी बना रहे हो

(श्री रमेश)

और पुरानी हजार वाली को बंद कर रहे हो। पूरे प्रदेश में 7 थर्मल इकाइयों को बार-बार बंद करना और फिर चालू करना, इससे आपको पता है कि घाटा तो बढ़ेगा ही। जब हम पुन: किसी यूनिट को चालू करेंगे तो कोयले की भी खपत ज्यादा होगी। ऑयल भी ज्यादा आएगा। बड़ी इकाइयां हैं, हजार मेगावाट की है या 1320 मेगावाट की है, उसमें 30 से 40 लाख रुपये का पुन: चालू करने में खर्चा आता है। सरकार द्वारा अपने सरकारी पावर हाउस को बंद करके, प्राइवेट से महंगी बिजली खरीदना, इस तंत्र को डुबोना ही है।

इस विद्युत तंत्र में जो बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने ऊर्जा विकास निगम बना लिया। वित्त निगम बना लिया। यहां से विधेयक भी पास करा लिया। लेकिन अभी वह एक्ट लागू नहीं हुआ है। यह लोग, सफेद हाथी यहां बैठे हैं। इनको यहां से कंट्रोल करो। बिजली बोर्ड में जो छीजत है, उसको आप कम करो तो इससे बिजली का घाटा कम होगा। वर्ना तो आप इस तरह से टेकओवर करते रहेंगे और प्रदेश की जनता पर भार डालते रहेंगे। प्रदेश की जनता आपको टैक्स के रूप में पैसे देती रहेगी। लेकिन अब जनता जान चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप सबको पता है कि कोटा थर्मल में आंदोलन हो रहा है। बीकानेर में निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। अजमेर में आंदोलन हो रहा है। जगह-जगह हो रहा है। आपके चाहे सूरतगढ़ के कर्मचारी हैं, चाहे छबड़ा के कर्मचारी हैं, चाहे काली सिंध के कर्मचारी हों, सभी आंदोलनरत हैं। लेकिन सरकार मदमस्त है। सरकार को कोई चिंता नहीं है। इनको तो इस प्रदेश की सारी संपत्ति बेचनी है। लेकिन इसको बेचकर के यह मंत्री लोग कहां जाएंगे? क्या यह भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, जो साथ ही चले जाएंगे? मेरा सरकार से निवेदन है कि यह जो बिजली का तंत्र है इसको खुर्द-बुर्द नहीं किया जाए और बिजली में जो अनियमितताएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोका जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हो गया, मसाला खतम हो गया।

श्री रमेश (सपोटरा): अभी रुक जाओ, राजेन्द्रजी। आपकी बात नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप ज्यादा कहोगे तो आपकी भी बात कर लेंगे।

(श्री रमेश)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जिस प्रकार पंजाब में, अन्य स्टेटों में किसानों को फ्री बिजली दी जाती है। लेकिन वहां छीजत बहुत कम है, रिकवरी अधिक है। यहां तो जो हमारे सरकारी विभाग हैं, वही पैसा नहीं दे रहे हैं। पीएचईडी पर करोड़ों रुपया बकाया है। नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, उन पर करोड़ों रुपया है। लेकिन वहां पर 80 परसेंट रिकवरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि किसानों को मुफ्त में बिजली दो, आपके पास अभी मौका है। नहीं तो, हमारी सरकार आएगी, हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हम किसानों को फ्री बिजली दें। यह हम आपसे सदन में कह रहे हैं। हम फ्री बिजली देंगे। हां, फ्री देंगे बिजली। यह हम आपको बताने जा रहे हैं। कह रहे हैं आपको, मौका है दे दो। दूसरे स्टेट भी दे रहे हैं, छीजत को कम कर दो, छीजत को कंट्रोल कर दो। ...(व्यवधान)... हम आपको बताने जा रहे हैं, यह हम आपको मौका दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं ये।

श्री रमेश (सपोटरा): हसीन सपने तो आप देखना अभी डेढ़ साल बाद। इस सदन की सीढ़ियां चढ़ने में बड़ा जोर आएगा, कुछ लोग बैठे हैं, ईमानदार लोग हैं दो-चार, ये ही चढ़ पाएंगे, बाकी तो रह जाएंगे पीछे ही।

आपकी स्थिति, हमारे पूर्व एनर्जी मिनिस्टर बैठे हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच साल में आपने क्या किया? आपने तो देश को डुबो दिया।

श्री रमेश (सपोटरा): वह तो सब जनता जान गयी है। ...(व्यवधान)... आपके खुद के काम नहीं हो रहे हैं, आप बैठ जाओ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2014 में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का बताउंगा आपको कि 2014-15 में विंड एनर्जी 3941.46 मिलियन यूनिट और सोलर एनर्जी 392.80 मिलियन यूनिट, 2015-16 में आपके पास बिजली विंड एनर्जी से मिली है 4485.57 मिलियन यूनिट और सोलर एनर्जी 118.90

(श्री रमेश)
मिलियन यूनिट, 2016-17 जनवरी तक 4045.30 मिलियिन यूनिट और आपके सोलर एनर्जी है 557, तो आपने जिस प्रकार रिसर्जेंट राजस्थान में बड़े-बड़े एमओयू किए सोलर एनर्जी के लिए, विंड एनर्जी के लिए और सोलर और विंड एनर्जी के लिए आपने लाखों बीघा जमीन अलोट कर दी लेकिन आपका रिजल्ट यह देख लो आपकी स्थिति क्या है। क्योंकि आपके छीजत जो हो रही है डिस्काम्स में 24 परसेंट, 27 परसेंट, 14 से 16 के बीच में है। बिजली खरीद की रेट 3.74 जो अपना सरकारी निगम है, उनसे तो खरीद रहे हैं 4 रुपये 70 पैसे में और बाहर से आप बिजली खरीद रहे हैं 6 रुपये में। आपका टैरिफ है। भारत सरकार, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच में भी तय हुआ है कि आप प्रति वर्ष टैरिफ बढ़ाएंगे, राज्य सरकार को पाबंद किया है कि इतने प्रतिशत छीजत लाएंगे, यह करेंगे, यह तय है। तो जो उसमें एग्रीमेंट हो गया वह तय है, लेकिन 2012 से 18.58 परसेंट, 2013 में 160 परसेंट, 2014 में 17.25 परसेंट, 2015 में 17 परसेंट, 2016 में 11.50 परसेंट टैरिफ बढ़ाया गया है। कोई पहली बार नहीं बढ़ाया है। आपने एक तरफ तो लोन टेक ओवर किया, पूरी जनता पर डाल दिया दूसरी तरफ आपने महंगी बिजली कर दी। कहा कि किसानों ने आंदोलन किया तो 25 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई उसको वापस ले लिया। दूसरी तरफ किसानों की जो महंगी भूमि आपने अवाप्त की पावर प्लांट्स के लिए कौड़ियों में औने-पौने दामों में, अब सैकड़ों करोड़ों रुपये के लाभ के लिए आप उनको बेच रहे हैं। जबकि आपको काम यह करना था कि उनके सामाजिक सेवाएं जो सीएसआर का पैसा है उनके विकास के काम आए लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी उस पैसे को सीएसआर के पैसे को जो दो परसेंट पैसा मिलता है उसको आप जल स्वावलम्बन योजना में खर्च कर रहे हो, वह भी दूसरी जगह। पैसा तो वहीं खर्च होना चाहिए लेकिन अब सरकार की मर्जी है। कुछ लोग इस विभाग में कंसलटेंसी के नाम पर करोड़ों रुपये उठा रहे हैं। वैसे तो कंसल्टेंसी हर विभाग में चाहे हैल्थ हो, कृषि हो, सभी विभागों में, जैसे कुकुरमुत्ते का रोग होता है उस तरह पूरे राजस्थान में सभी विभागों में फैल गया है कि कोई भी डीपीआर बनवानी है, कोई भी काम करना है, कोई भी सर्वे करना है, कोई भी किसी भी प्रकार की इन्क्वायरी करनी है तो कंसल्टेंसी से बात करो।

(श्री रमेश)

कंसल्टेंसी में ऐसे-ऐसे लोगों को नियुक्त कर रखा है जो एज पर नोर्म्स नहीं हैं, 65 साल से ऊपर की आयु के हो चुके हैं डिस्कॉम में लेकिन उनकी तनख्वाहें 40 हजार से लेकर 70 हजार तक है जो प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों का चूना लगा रहे हैं तो वह कर्ज तो बढ़ेगा ही।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको दो मिनट, इनको याद दिला दूं, शायद याद आ जाए सरकार को, पिछले तीन साल में आपने जो बजट घोषणाएं की, कुछ पर तो मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल चुका हूं, उनको शायद यह कर दें। इन्होंने बोला है, बजट में, मेनीफेस्टो में इन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 10 परसेंट के अनुसार बढ़ाएंगे, 1 हजार किलोमीटर का ईस्ट-वैस्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा, राज्य में कुल 70 हजार करोड़ का विनिवेश करेंगे जिसमें राज्य सरकार 20 हजार करोड़ का विनिवेश करेगी, प्रति दिन 15 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेंगे, आपने इसके लिए राजस्थान हाई वे अथोरिटी बनाई, इसके बाद क्या प्रगति हुई, सब जानते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद भी आप केन्द्र सरकार से 4 से अधिक हाई वे नहीं ला पाए। आपने राजस्थान स्टेट बस पोर्ट अथोरिटी का गठन किया। उस रोडवेज की स्थिति क्या है और कितना सुधार हुआ, आप इसकी जानकारी सदन को दें। आप पिछले तीन साल में फिक्स राशि रोडवेज को दे रहे हैं, न तो घटा रहे हैं, न बढ़ा रहे हैं और आपके उठाए हुए कदमों से रोडवेज की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में बताएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने दूरदराज के गांवों में जहां कम जनसंख्या है वहां विद्युत ग्रिड के स्थान पर लोकल सोलर ग्रिड एवं स्टेंड अलोन सोलर सिस्टम से 5 साल में 10 हजार गांव और ढाणियों में बिजली सुविधा देने का वादा किया था उसमें कितनी क्रियान्विति हुई? नए ऊर्जा स्रोतों के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बनाएंगे वह कहां है ? 23956 गुणवत्ता प्रभावित ग्राम और ढाणियों में एक हजार आर ओ, लगाएंगे, बताइए अभी 3 साल में कितने आर ओ लगाए, कितने चालू हैं?

(श्री रमेश)

दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कारिडोर का विकास करेंगे और 2 नए शहरों का निर्माण करेंगे। तीन साल में आपने क्या किया, उन दो शहरों का नाम तो बता दें। राजस्थान ड्रिंकिंग पावर ग्रिड की घोषणा हुई, वह कहां है? 2014 में पीपीपी मॉडल पर स्किल university की घोषणा की वह 3 साल में अभी बिल लेकर आएं हैं। आपने 2014 के बजट में औद्योगिक क्षेत्र में स्किल डवलपमेंट पर हब स्थापित करने की घोषणा की थी, कितने हब स्थापित हुए? आपने पशुओं के लिए 2 हजार इंटीग्रेटेड लाइवस्टोक डवलपमेंट सेंटर खोलने की बात की थी लेकिन उसके स्थान पर आप बीमा योजना लेकर लाए। लाइवस्टोक डवलपमेंट और बीमा योजना, यह अलग-अलग सब्जैक्ट हैं। 2014 के बजट में आपने कहा था सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में 15 लाख रोजगार देंगे, बाद में आप कहते हैं कि ऐसा करना संभव नहीं, इसका क्या मतलब है? आपने राज्य की जनता के साथ धोखा किया है, असत्य वायदे किए हैं और आप सत्ता में आ गये। आपने 2014 में कहा था कि 2019 तक 40 लाख बेरोजगार होंगे लेकिन आपने रोजगार के बारे में कोई प्रयास नहीं किए। 5 साल में 13 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे। जबकि आप यूनिवर्सिटी ही सवा तीन साल बाद लाए हैं, कब स्थापित होगी, कब एडमिशन होंगे, कैसे आप पौने दो साल में 13 लाख को प्रशिक्षण देंगे? राज्य के सैकेंडरी, हायर सैकेंडरी की औसत ट्रांजक्शन रेट देश की औसत रेट से से 10 प्रतिशत कम है। कक्षा एक से आठ तक बच्चों का सभी विषयों का स्तर जानने के लिए ऑनलाइन सुपरविजन किया जाएगा। राज्य में पीपीपी मोड पर आर्चरीज शूटिंग रेंज, नाइट शूटिंग रेंज का क्या हुआ 3 साल में कहीं नहीं दिख रही? राज्य में 18 गोल्फ कोर्स बनाने की घोषणा की, बाद में संख्या घटा दी, अब गोल्फ कोर्स का सपना ही है। राज्य सरकार के अधिकारी हैं, बात मान ही नहीं रहे हैं।

फोर वाटर कंसेप्ट की परियोजना जनवरी, 2015 तक पूरी होनी थी, उसकी क्या स्थिति है? आपने गुड गवर्नेस का बहुत हल्ला मचाया बजट भाषण में, बिल लाने की बात कही लेकिन 3 साल में आप नहीं लाए और नहीं लाएंगे क्योंकि सब जानते हैं कि गुड गवर्नेस क्या होती है? 2015-16 के बजट में प्रत्येक संभाग में एमबीए कालेज खोलेंगे, थ्री डी प्रिंटिंग, राज्य में

(श्री रमेश)

हॉकी, बॉस्केटबाल अकादमियों की स्थापना का क्या हुआ? राज्य में उच्च शिक्षायुक्त साइंस एंड ह्यूमेनिटीज फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। आपने 2016-17 में खाद्य का भंडारण घटा दिया, 2014, 2015, 2016, 2017 का आपने किसानों के कृषि कनेक्शन की, कृषि नीति की बात हुई थी, इसकी घोषणा की और अभी आपने घोषणा की है कि दो साल में एक लाख नए कनेक्शन देंगे। अभी तो आपने अक्टूबर, 2009 व दिसम्बर, 2010 फरवरी तक चालू किए हैं जिसमें 40-42 हजार आएंगे, पुराने अभी जो पैंडिंग चल रहे हैं कृषि कनेक्शन उन्हीं को आप नहीं दे पाए तो थोथी घोषणाएं क्यों कर रहे हो? किसानों के प्रति इस तरह की असत्य बात क्यों कह रहे हो? आपका दूसरा उदयपुर संभाग में घोषित ट्राइबल टूरिज्म सर्किट कहां है? आपने 770 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास रूम बनाने की घोषणा की थी उनमें से कितने बने? ग्रामीण क्षेत्रों में ई-हैल्थ कार्ड की व्यवस्था करने वाले थे उसका क्या हुआ? 354 करोड़ की लाइवलीहुड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट योजना का क्या हुआ?

जिसमें 100 कार्य दिवस पूरे करने वाले 86 हजार परिवारों को कौशल प्रशिक्षण देना था, उनको कौनसा कौशल प्रशिक्षण दिया गया। 2016-17 में 2 हजार खेल मैदान विकसित करने वाले थे, कितने किये ? साइबर क्राइम हेतु पुलिस स्टेशनों को सशक्त करने की बात थी, आज वहां थानेदार भी नहीं लगा हुआ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार कारिडोर की बात, रिंग रोड की बात, रिफाइनरी की बात, रिसर्जेंट राजस्थान के माध्यम से निवेश लाने की बात, कृषि में एग्रीटेक मीट के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने की बात, लेकिन इन्होंने बजट में जो घोषणा की, लोगों को सपने दिखाये, उनमें सभी स्तर पर सरकार विफल रही। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने भारतीय संविधान में जो बाध्यकारी प्रावधान बनाये गये हैं, हमारे विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन के जो नियम बनाये हैं, उनके तहत यानी

(श्री जोगाराम पटेल)

आर्टिकल 202 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोविजन बनाये गये हैं और नियम 138, 139 और 141 में इस बजट के संबंध में जो प्रावधान हैं। आपने नियम 141 के तहत मुझे अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका, राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्रीजी, मौजूदा इस बजट पर वाद-विवाद हो रहा है, एक ऐतिहासिक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ-सबका विकास के रूप में एक विजन डाकूमेंट के रूप में जो बजट पेश किया है और मुझे उस पर अवसर दिया है, मैं आदरणीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, सचेतक तथा उप सचेतक महोदय का भी आभारी हूं कि मुझे सत्ता पक्ष की ओर से अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट कोई एक या दो गलती निकालने का नहीं है, यह बजट कोई आलोचना करने का विषय नहीं है। यह बजट वह बजट है जो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। यह वह बजट है जो आने वाले एक वर्ष के उपरान्त ही, जो इसमें विजन दिया गया है वह राजस्थान का सर्वांगीण विकास करेगा।

इस बजट पर मानकर चलते हैं कि हमारे प्रतिपक्ष के साथी आरोप लगाएंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि हम एक जगह पर कहीं न कहीं इतने साल के बाद एक स्टेट पर जहां पर केवल आरोप और प्रत्यारोप न लगाएं, राजस्थान की जनता के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए और हिन्दुस्तान में जो हमारी भागीदारी है, उसके विकास के लिए हम कहीं ठोस परिणाम के साथ पहुंचें। हम तर्क और वितर्क अवश्य करें, लेकिन जैसा सपोटरा से आने वाले मेरे साथी ने अभी कहा, कहीं के आंकड़े इकट्ठे करके और कोशिश की कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलती निकाल प्रयास नहीं करूं, यह बजट का मामला नहीं है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कितना फण्ड हमारा था, हम किस स्टेज पर जा रहे हैं, राजस्थान का जो बजट पेश होता है, आज तक जो भी सरकारें आयी उन्होंने पेश किया है। समाचार-पत्रों में इसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं, अर्थशास्त्री इसकी प्रतिक्रियाएं करते हैं, विपक्ष के साथी इसकी प्रतिक्रियाएं करते हैं, लेकिन कल से सारे समाचार-पत्र, टीवी चैनल, अर्थशास्त्री और हमारे प्रतिपक्ष के जो वरिष्ठ साथी हैं उन्होंने एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बताया जिसके आधार पर वास्तव में कह सकें कि इस बजट

(श्री जोगाराम पटेल)

पर कोई क्रिटिसिज्म हुआ है। हां, यह उनका धर्म था। ये कहते कि निराशाकारी बजट है, लेकिन तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ, विजन के साथ एक भी ऐसा तथ्य नहीं बताया जिससे इस बजट के बारे में कुछ कहा जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट आधारभूत संरचना और और सामाजिक निवेश को समर्पित बजट है। इस बजट में सामाजिक संरचना, निवेश और आधारभूत संरचना निवेश को इस तरह से एक-दूसरे के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया है कि उसमें पूरकता और सहसंबंध दोनों के संबंध ही मजबूत हो रहे हैं। यह सराहनीय प्रयास है। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के रोडमैप की रूपरेखा बजट के माध्यम से तय की गयी है, उसी रोडमैप के आधार पर राजस्थान के विकास की नीति का एक पैराडाइज यह बजट है। आज इस बजट के माध्यम से उन्होंने एक ओर जहां कंसोलिडेट किया है वहीं दूसरी ओर जनकल्याणकारिता को वरीयता दी है। उदाहरण के रूप में जहां पेयजल योजनाओं पर 8687 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ 15.68 प्रतिशत व्यय की वृद्धि की गयी है वहीं एचडीएफसी जैसे नवाचार और ग्रामीण जल प्रबंधन की सामाजिक सहभागिता को निवेशित किया गया है। यानी स्ट्रेटेजिक पूरकता और सस्टेनेबल डवलपमेंट दोनों लक्ष्य पूरे हो सकेंगे, इस दृष्टि से कई जगह यह बजट विजनरी नेतृत्व को दर्शाता है। हमारी आदरणीय मुख्यमंत्रीजी का जो विजन है, उस विजनरी का यह आपके सामने डाकूमेंट है। प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार, सुधार और व्यय वृद्धि को अत्यन्त बुद्धिमतापूर्णता से इसमें जोड़ा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह भी निवेदन करूंगा कि बजट आज दिन तक पेश होते आये हैं, लेकिन यह विजन 2020 को ध्यान में रखकर, जैसा मैंने अभी आपके सामने निवेदन किया, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका साथ-सबका विकास, इसी को आधार रखकर विकास की परिकल्पना के तीन मुख्य आधार दिये गये हैं, तीन स्तम्भ दिये गये हैं। पहला स्तम्भ है निवेश को बढ़ावा देने के साथ ही साथ आर्थिक विकास में तेजी लाना। दूसरा विजन है रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना, सुशासन कायम करना, जिसके अंतर्गत न केवल जन-अभाव अभियोग का

(श्री जोगाराम पटेल)

निराकरण करना ही था बल्कि इसके अंतर्गत ease of doing business, governance service delivery को सुगमता तथा साथ ही बदलते समय के अनुसार नीतिगत सुधार के साथ-साथ आधुनिक एवं प्रशासनिक नीति निर्धारण भी शामिल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय व अधिकारिता के अंतर्गत सामाजिक समरसता कायम करने के साथ ही साथ बेहतर चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करना, जेंडर इक्विटी को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तीकरण को बढ़ाना देना शामिल है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कल ही राजस्थान ने हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा नाम कमाया है और महामहिम राष्ट्रपति के हाथों इनाम भी प्राप्त किया है।

जहां एक ओर आर्थिक आधारभूत संरचना, जैसे बिजली, पानी, सड़क को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है वहीं सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास एवं रोजगार के नये अवसर सृजित करना, राजस्थान को आकर्षक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार, कृषि, पशुपालन को मजबूती करने के साथ ही आपदा प्रबंधन आवश्यक है। ये सभी विजन इस डाकूमेंट में है। पहली बार, शायद हिन्दुस्तान में पहला राज्य होगा, मेरी जहां तक जानकारी है, जिसमें दो नवाचार किये हैं। जैसा कल बजट भाषण के दौरान यशस्वी मुख्यमंत्रीजी ने बताया, प्लान ऑर नॉन प्लान का वर्गीकरण समाप्त हुआ है। अब प्लान और नॉन प्लान का वर्गीकरण नहीं रहा है। बजट में प्लान डवलपमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में माना जाता रहा है इसके कारण सम्पत्तियों के रख-रखाव हेतु प्राय: समुचित प्रावधान नहीं हो पाते थे तथा बजट प्लान में व्यय का अधिकतम प्रावधान रखने का प्रयास किया जाता था, जैसा केन्द्र सरकार ने अपने बजट में किया है वैसा ही राजस्थान सरकार ने भी प्लान व नॉन प्लान के वर्गीकरण को समाप्त किया है। इस बजट के नवीन सुधार व्यय की समग्र दृष्टि से प्रावधान तथा संसाधनों का श्रेष्ठ एवं यथोचित उपयोग किया जा सकेगा। यह एक विजन है।

दूसरा, लैस पेपर। आज से पहले जब हम बजट घर लेकर जाते थे तो अटेची में बहुत बड़ा भार होता था, अकेले से उठता ही नहीं था। पहली बार

(श्री जोगाराम पटेल)
लैस पेपर बजट प्रस्तुत करने की दिशा में अग्रसर होते हुए बजट मुद्रण को कम करने का प्रयास किया गया है और इससे न केवल राजकीय खर्चे की कमी होगी बल्कि इससे अनावश्यक पेपर का वेस्ट भी नहीं होगा।

साथ ही साथ आधुनिक टैक्निक के इस युग में सारा मैटेरियल हमें चाहे लैपटॉप में डालकर हो चाहे कैसेट के रूप में हो, उपलब्ध कराया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला निवेदन यह था कि यह एक विजन डाकूमेंट है, यह एक दूरदृष्टिता का डाकूमेंट है, समग्र विकास का डाकूमेंट है, सबको साथ रखने का बजट है, सबके विकास का बजट है। साथ ही साथ, इस बजट को अगर थोड़ा सा आंकड़ों के आधार पर देखें तो भी आप पायेंगे कि बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े आये हैं, सरकार का विजन सामने आया है। जहां 1 लाख 30 हजार 162 करोड़ 7 लाख की टोटल राजस्व प्राप्तियां हैं वहीं 1 लाख 43 हजार 690 करोड़ 10 लाख का राजस्व व्यय हे। इस तरह से 13 हजार 528.03 करोड़ का राजस्व घाटा है। अगर इसको राजकोषीय घाटे के रूप में देखें सभी प्राप्तियों के बाद में तो 24 हजार 753 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूंजीगत खाते में प्राप्ति 51 हजार 653 करोड़ 64 लाख की है और पूंजीगत व्यय है वो 38 हजार 63 करोड़ 80 लाख का है। इस तरह पूंजीगत आधिक्य, सरप्लस 13 हजार 589 करोड़ 84 लाख का है और यह पहली बार है कि इतने विपरीत सर्कमस्टांसेज के अन्दर भी, जिस तरह से विश्वव्यापी मंदी है, देश और प्रदेश में जिस तरह की मंदी है, जिस तरह का वातावरण बना हुआ है उस सबके बावजूद भी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने इस तरह का बजट हमको दिया है।

आप एक बार आंकड़े देखें तो जो भार दिनों-दिन राजस्थान सरकार पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस दौरान बढ़ा है, राजस्व व्यय 2015-16 में 1 लाख 12 हजार 202 था, पूंजीगत 2015-16 में 23 हजार 447 था, लोक ऋण 2015-16 में 8 हजार 831 था वो 2016-17 में बढ़कर 5 हजार 36 हो गया, पूंजीगत व्यय बढ़कर 18 हजार 517 हो गया और राजस्व व्यय 1 लाख 32 हजार 52 हो गया। अब इस वर्ष जब यह बजट पेश हुआ है तो राजस्व व्यय 1 लाख 43 हजार 690 करोड़ का हो गया है। पूंजीगत व्यय 25 हजार 603

(श्री जोगाराम पटेल)
करोड़ का हो गया है और लोक ऋण 11 हजार 680 करोड़ का हो गया है। इसके अगेंस्ट में जो हमारी रिसीट साइड है वो 53 हजार 300 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा, 31 हजार 477 केन्द्रीय करों से प्राप्त होंगे और 24 हजार 388 सहायतार्थ अनुदान वगैरह से हमें प्राप्त होंगे।

इस तरह की परिस्थितियों के बावजूद भी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने एक विजन डाकूमेंट के रूप में जनता के सर्वांगीण विकास के लिए, आम-अवाम के विकास के लिए, हर सैक्शन के विकास के लिए जो बजट दिया है वो अपने आपमें उल्लेखनीय है। यह बिना उदय के 1 हजार 528 का घाटा होगा, उदय प्रभाव लेंगे तो 13 हजार 528 का घाटा होगा, यह सदन के सामने अनेक बार आ चुका है। पर विशेष बात यह है कि वर्ष 2017-18 में राजकीय घाटा 24 हजार 753.53 करोड़ का मैंने आपको अभी बताया है जो GSDP का 2.99 प्रतिशत है और जो FRBM एक्ट है उसके अन्तर्गत है, उसकी लिमिट के अन्दर है। वर्ष 2017-18 के बजट में कुल राजस्व प्राप्तियां 1 लाख 30 हजार 162 करोड़ रहने की सम्भावना है और वर्ष 2016-17 के संशोधित बजट अनुमानों से स्वयं का 39 हजार 853 करोड़ रुपये से अधिक है जो करीब 16.16 प्रतिशत अधिक है। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 1 लाख 19 हजार 626.91 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 15.80 प्रतिशत है।

इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने पूरी कोशिश की है कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो, हर सैक्टर में विकास हो और इसी को एक नजर से देखें तो आप पायेंगे कि ये जो 2016-17 के संशोधित अनुमान थे उससे इस बजट में क्या मिला, क्या कम मिला, क्या ज्यादा मिला जैसा मेरे साथी ने अभी कहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और जिस विभाग के आधार पर यह कहा जा रहा है कि रोड ही सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। John F. Kennedy ने एक कोटेशन में कहा भी है कि "America doesn't have a great roads because it is a great country. It is

(श्री जोगाराम पटेल)

a great country because it has a great roads." तो मेरा सब्मिशन है कि जिस प्रदेश और देश की रोड कनेक्टिविटी बढ़िया होगी, क्वालिटी की होगी, अधिक होगी वो ही देश और प्रदेश अधिक विकास करेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस साल का बजट 6 हजार 657 करोड़ 32 लाख रुपये है और जो पिछला बजट था उससे 58.47 प्रतिशत अधिक है। आप अनुमान लगायें कि इस बजट में कितना अधिक खर्च किया जा रहा है और वो खर्च इसीलिए किया जा रहा है कि हमारी रोड कनेक्टिविटी बढ़े, रोड सुदृढ हों, रोड बढ़ें। इसमें 3 हजार 465 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का रख-रखाव होगा, 1200 करोड़ से 1820 किलोमीटर की 808 मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण होगा, 16 करोड़ 54 लाख रुपये से हवाई पट्टियों का निर्माण होगा, 441 करोड़ रुपये की लागत से 402 किलोमीटर लम्बाई की 19 सड़कों को विकसित करने का कार्य होगा, राजमार्गों को विकसित करने के लिए एक हजार 580 करोड़ रुपये की लागत से 15 परियोजनाओं का कार्य शुरू होगा।

इतना ही नहीं, सड़क के मामले में और भी अधिक काम होंगे जिनमें 2 हजार ग्राम पंचायतों को 1200 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण गौरव पथ और मिसिंग लिंक से जोड़ा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर ठेठ ग्रामीण क्षेत्र में मेरे साथी गये हों या अपने-अपने क्षेत्र में रोज जाते ही होंगे तो जो ग्रामीण गौरव पथ बने हैं और साइड में हमने नरेगा के साथ डवटेल करके जो टाइल्स लगाई हैं वो रोड कोई देख ले तो वो शर्तिया कहे बगैर नहीं रह सकता है कि राजस्थान में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है रोड के मामले में, गांव के सुधार के मामले में। ऐसा किसी शहर में बढ़िया से बढ़िया जगह पर भी होगा और गांव में हम जाकर कहते हैं कि एक ही गली या मौहल्ला नहीं छूटना चाहिए जहां सी.सी. रोड या टाइल्स लगाकर रोड नहीं बन जाए। जो गौरव पथ हैं वो माननीय मुख्य मंत्रीजी की एक विशेष उपज है कि उन्होंने शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विकास में यह गौरव पथ का दिया। 800 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर अधिक लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी होगा। इसमें नवीनीकरण हेतु RIDP-23 के अन्तर्गत ये सारे प्रावधान किए जाएंगे। राज्य राजमार्गों को विकसित करने के लिए एक हजार 580

(श्री जोगाराम पटेल)

करोड़ रुपये की लागत से 796 किलोमीटर लम्बाई की 15 परियोजनाओं का कार्य भी प्रारम्भ होगा। 441 करोड़ रुपये की लागत से 402 किलोमीटर लम्बाई की 19 सड़कों को विकसित करने का भी प्रावधान है। इसमें लम्बा-चौड़ा प्रधान मंत्री सड़क योजना का भी है, उन्नयन का भी है, 17 किलोमीटर लम्बाई के केकड़ी बाइपास सड़क का भी है। यह सब अगर हम देखें तो आने वाले वर्ष में जो सड़कों का विकास होगा वो राजस्थान में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। पूर्व के समय में जब हम पिछली बार 2003 से 2008 में थे तो लोग कहते थे कि हां, अब राजस्थान आ गया और उधर निकलते थे तो कहते थे कि मध्य प्रदेश आ गया है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल के कार्यकाल के दौरान सड़कों की वो हालत हुई, वो दुर्दशा हुई कि वापस अब ज्यों ही मध्यप्रदेश पार करते हैं तो लोग कहते हैं राजस्थान आ गया है और सड़कों के मामले में गड़बड़ मामला है। इसके सुधार के लिए यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2017-18 में 6 हजार 667 करोड़ 32 लाख रुपये के व्यय का प्रावधान किया है जो 58.47 प्रतिशत अधिक है।

दूसरा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, यह विभाग भी अपने आपमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। 'जल है तो कल है और जल नहीं है तो कुछ भी नहीं है' जल के बिना रहना ही मुश्किल है। इसमें भी पूर्ववर्ती बजट 15.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और साथ ही इसमें भी अनेक तरह के नवाचार किये गये हैं। एक नवाचार मैं अभी थोड़ी देर बाद में आपसे निवेदन करूंगा जो मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन का कार्यक्रम है। फिर भी प्रदेश में 2039 गांवों में पेयजल की योजना है। इसके अलावा जयपुर और कोटा में 24 घंटे पेयजल देने की योजना इसमें बताई गयी है। ग्रामीण इलाकों में जहां शुद्ध पेयजल नहीं है वहां पर एक हजार 483 आर.ओ. प्लांट लगाये गये हैं। मेरे यहां पर 50 आर.ओ. प्लांट स्वीकृत हुए हैं और जो 50 स्वीकृत हुए हैं उनमें से 42 ने काम करना शुरू कर दिया है। जो बिसलरी की 15 रुपये की, 20 रुपये की बोतल लोग लेते थे वो सिर्फ 10 पैसे में एक लीटर पानी लेकर जा रहे हैं। जनता और विशेषकर वहां जो महिलाएं हैं वो वसुंधरा जी की वाह-वाही कर रही हैं कि 'वाह रे वसुंधरा वाह, घरै तो बिसलरी भेज दी म्हारै,

(श्री जोगाराम पटेल)
वाह रे वसुंधरा वाह' वे सब लोग ऐसे-ऐसे नारे लगा रहे हैं। टूटे जलाशय, बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए 32.54 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एनर्जी कन्जर्वेशन माडल की सफलता को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से अन्य जगह चालू किये गये हैं। जाखम बाँध से जलापूर्ति के बाद चार लाख आबादी को पेयजल मिलेगा। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की भी बात है। जनता जल योजना के सुदृढ़ीकरण के कार्य भी किये गये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पेयजल के मामले में ढाणियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। न केवल गांवों का ध्यान रखा गया है, बल्कि ढाणियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। 2,500 गांव और ढाणियों को शुद्ध पेयजल से लाभान्वित किया जायेगा। लम्बित 5,292 करोड़ रुपये की लागत की नौ वृहत् परियोजनाओं को आगामी वर्ष में प्राथमिकता के साथ पूरा किया जायेगा।

नवीन पेयजल परियोजनाएं जो पंचायत समिति प्रतापगढ़ में है, पंचायत समिति कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ में है, बूंदी में है, चाकन बांध की है, डीडवाना शहर की है, बारां की है। इन सबको प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। में यह विषय आम जनता से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर, गांव और ढाणी को ध्यान में रखकर, शहर को ध्यान में रखते हुए पेयजल की व्यवस्था के संबंध में बजट दिया गया है और यह बजट भी करीब 15.68 प्रतिशत अधिक बढ़ाया गया है, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी का, माननीय मंत्रीजी का, कि उन्होंने इस तरह से इस बजट में विशेष रूप से चरणबद्ध रूप से शहरी पेयजल योजनाओं के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी पेयजल व्यवस्था, एनर्जी कन्जर्वेशन माडल के आधार पर विद्युत व्यय में बचत करने, आरओ प्लांट लगाने और जो पेयजल योजनाएं पूर्ववर्ती शासन के कार्यकाल के दौरान बजट उपलब्ध नहीं कराने की वजह से पड़ी हुई थीं, जुलाई, 2008 में दांतीवाड़ा मांखला पेयजल योजना थी, अब उसका यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने शिलान्यास किया था। पिछले पांच साल तक उसको ऐसे ही पड़े रखा। मौजूदा सरकार के आने के बाद बजट उपलब्ध कराकर उसको पूरा कराया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा।

(श्री जोगाराम पटेल)

पर्यटन का मामला है, उसमें भी वृद्धि की गयी है। पर्यटन विभाग भी राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राजस्थान को जो रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है, वह पर्यटन से भी बहुत अधिक प्राप्त होने वाला है और यहां बहुत बड़ी गुंजाइश भी है। देश और विदेश के पर्यटक अनेक रूप में आते हैं चाहे जोधपुर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे उदयपुर हो या चाहे और कोई जगह हो, बून्दी, कोटा, भीलवाड़ा जो उधर का हो, पर्यटक को एग्रेसिव मार्केटिंग कैम्पेन के तहत प्रमोट किया जाएगा और इसमें भी 17.31 परसेंट पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो एक ऐतिहासिक वृद्धि है। 36 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। राज्य में 17.31 प्रतिशत पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। 88 करोड़ रुपये खर्च होने से पर्यटकों को बढ़ावा देने और सौन्दर्यीकरण करने की जो योजना बनाई गई है, उससे राजस्थान में शर्तिया एक बहुत अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होगा। रेवेन्यू ही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि विभिन्न पर्यटन स्थलों को आधारभूत सुविधाएं, संरक्षण, सौन्दर्यीकरण, जीर्णोद्धार इत्यादि के काम भी कराये जाएंगे। साथ ही साथ किस तरह से पर्यटकों को कनेक्टिविटी उपलब्ध हो, एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध हो, इसलिए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने कल घोषणा की थी कि चाहे जयपुर से जैसलमेर डाइरेक्ट हो, चाहे कोटा से हो, अन्य स्थानो से हो, सवाई माधोपुर से हो, एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए घोषणा की गयी है और जब चाहे देशी हो चाहे विदेशी पर्यटक हों, अगर इनको एयर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी तो इनका रूझान और बढ़ेगा। उनके समय में भी बचत होगी और वह अधिक आकर्षित होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कला और संस्कृति में भी 156.83 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, यह बजट कला और संस्कृति में भी 49.42 प्रतिशत पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष में जो बजट अनुमान था, उसमें 49.42 प्रतिशत अधिक है।

पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी विकास में भी 822.37 करोड़ रुपये है। इसमें भी 17.47 प्रतिशत बजट अधिक है। पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी में विशेष स्थान दिया गया है और यह आधारभूत संरचना है राजस्थान के लिए

(श्री जोगाराम पटेल)
क्योंकि राजस्थान पशुपालक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। अधिकतम पशु यहां पर हैं। भेड़, बकरी यहां अधिकतम हैं। गायें भी काफी हैं। ऐसी स्थिति में पशुपालन, भेड़पालकों के लिए "अविका कवच योजना" पुन: प्रारम्भ की गयी है। आगामी वर्षों में 4,160 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाएंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय है। इससे पहले भी खोले हैं। मंत्रीजी, आपको बहुत धन्यवाद है कि टोटल जो पहले खोले हैं और भविष्य में आप 4,160 ग्राम पंचायतों में खोलेंगे तो मेरा निवेदन है कि सोंखा में आप कहकर आये हैं औषधालय को क्रमोन्नत करने का, कृपया वह भूलें नहीं।

आठ पंचायत समितियों में और दो तहसील मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा संस्थानों को प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की घोषणा हुई है, वह भी काबिले तारीफ है।

जयपुर, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर के बहूद्देशीय पशु चिकित्सालयों में कलर डोपलर मशीन एवं अन्य उपकरण जो आवश्यक हैं, ताकि पशुओं की सुरक्षा हो सके, सेवा हो सके, बीमारियों से बचाया जा सके।

संभागीय मुख्यालयों पर टेलीमेडिसिन के माध्यम से और बीकानेर विश्वविद्यालय से जोड़ा जाएगा, यह भी एक बहुत बड़ी घोषणा है। मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा मंत्रीजी, आपका कि यह आधुनिक टैक्नीक युग में आपने यह सब चीजें राजस्थान में लाई हैं, इससे राजस्थान के पशुपालन का विकास ही होगा।

पिछली बार राजस्थान दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर आया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी इस तरह से अगर होगा, दूध उत्पादन में प्रदेश का पहला स्थान रहेगा। हर साल दूध का उत्पादन बढ़ रहा है और आंकड़े मैं पेश करूंगा तो आपको लगेगा कि हर वर्ष दूध का उत्पादन बढ़ रहा है। गाय, भैंस, बकरी का दूध उत्पादन 11,377 से लगातार 2014-15 में 16,936 लीटर तक का बढ़ गया था और इसी का परिणाम है कि आपने पशुपालन की ओर भी विशेष ध्यान दिया है, जिसके लिए यह बजट प्रावधान है, यह ऐतिहासिक बजट है।

(श्री जोगाराम पटेल)

जल संसाधन और सिंचित क्षेत्र, यह विभाग भी अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इसका विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि राजस्थान एक सूखा प्रदेश है। इसका टोटल भौगौलिक क्षेत्र है, जो उपलब्ध पानी है, जो पीने का पानी है, वह 1.16 प्रतिशत ही है। ऐसी स्थिति में 3,313.80 लाख रुपयों का जो बजट प्रावधान किया गया है, इसमें भी पिछले वित्तीय वर्ष के बजट प्रावधानों से 11.14 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और इसमें 11 जिलों में 36 लघु सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार, चंबल नहर के वितरण प्रणाली के तहत 125 करोड़ रुपये की लागत से सुधार, परवन बहूद्देशीय परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इतना ही नहीं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगामी दो वर्षों में 36 लघु परियोजनाओं का जीर्णोद्धार कर 56.70 करोड़ रुपये की लागत से इनका विकास किया जाएगा। चम्बल नहर वितरण प्रणाली में 125 करोड़ रुपये की लागत से सुधार कार्य करवाये जाएंगे। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली, सिद्धमुख नहर प्रणाली तथा अमरसिंह नहर शाखा में 18 करोड़ रुपये की लागत से लाइनिंग का कार्य कराया जाएगा। माही, पांचना, चवली, छापी, गंभीरी, जवाई, भाखड़ा फेज-2 एवं गंग नहर के फेज-3 के नहर प्रणाली में पक्के खालों का निर्माण कराया जाएगा। बूंदी जिले के गरड़दा बांध का पुनर्निर्माण किया जाएगा। धौलपुर लिफ्ट परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इन सबको हम देखें और पूर्ववर्ती शासन के कार्यकाल के दौरान की अगर योजनाओं और उनके बजट को देखें तो लगेगा कि यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है, ऐतिहासिक कार्य होने वाला है और इस बजट में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।

मानव संसाधन एवं सामाजिक न्याय विभाग में 5,596.80 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास सामाजिक सरोकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। 1,904.51 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है और इसमें भी पिछले साल से इस बार 17.06 प्रतिशत की वृद्धि करने के साथ ही साथ हिन्दुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में राजस्थान पर यह कलंक था कि यहां जो लिंगानुपात है, वह बहुत कम है। लिंगानुपात का धब्बा था, वह खतम हुआ है और प्रत्येक 1,000 पर 933

(श्री जोगाराम पटेल)
या 947 बालिकाओं का लिंगानुपात हुआ है। स्त्री शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के मामले में नारी शक्ति का अवार्ड कल ही पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान को प्रथम स्थान आने के आधार पर मिला है, मैं मंत्रीजी को और माननीय मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद दूंगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 1,904.51 करोड़ रुपये के प्रावधान का वास्तविक व्यय भी बढ़ गया है। योग्य आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को, कल ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास फोन आये थे, जब भी गांव में जाते थे, वह महिला हमसे एक ही बात कहती थी, हम पूरे दिन काम करते हैं,...

एक हजार रुपये में काम करते हैं, कांग्रेस वालों ने कुछ भी नहीं किया आप कुछ न कुछ करो, हमारा कुछ मानदेय बढ़ाओ और कल यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने 2 सौ रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। उससे महिलाओं में जो आंगनबाड़ी केन्द्रों पर काम करती हैं, मिड-डे मील में जो महिलाएं काम करती हैं, वो बहुत खुश हैं और वो महिलाएं विशेष रूप से एक-दो दिन में जयपुर आकर के बड़ी संख्या में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करने वाली भी हैं। वो अब बहुत खुशी-खुशी काम करेगी। बाबूसिंह जी का सुझाव है कि इसको तीन सौ रुपये बढ़ाया जाए और पांच सौ रुपये किया जाए सभी माननीय सदस्यों की भावना है, सबकी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनका कुल पांच सौ रुपये मानदेय बढ़ाया जाए। लिंग आधारित हिंसा के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य के सात जिलों बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, जालौर, झालावाड़, नागौर, प्रतापगढ़, बूंदी में चिराली योजना प्रारंभ की गयी है उसके लिए भी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद है।

जनजाति विकास - आदरणीय मंत्रीजी, आपके विभाग का भी 5,996 करोड़ 82 लाख रुपये का प्रावधान बजट में रखा गया है। अल्पसंख्यक जिसका अभी सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, आप थोड़ा सा ध्यान रखें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अल्पसंख्यक विभाग में भी 106 करोड़ 8 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 24.30 प्रतिशत अधिक है। एकदम इस विभाग में 30 प्रतिशत बजट

(श्री जोगाराम पटेल)

अधिक बढ़ाया गया है। उच्च शिक्षा, दोनों ही शिक्षा के मामले में चाहे प्राथमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो इसमें बहुत ही आमूल-चूल परिवर्तन किया गया है। उच्च शिक्षा के मामले में भी 1,399 करोड़ 42 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 11.1 प्रतिशत अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है मैं अभी आपसे निवेदन करूंगा राजस्थान में हम पिछली बार आईआईटी एडमिशन में प्रथम आये थे। हमारे बच्चे हिन्दुस्तान में सबसे टॉप रहे थे और टॉप रहने में हमारा प्रतिशत बढ़ा। पिछली बार आपने पढ़ा होगा जो आईएएस के एग्जाम हुए उसमें भी राजस्थान का परसेंटेज और बढ़ा है। राजस्थान में पहले लोग आते ही नहीं थे, अब हमारा प्रतिशत भी बढ़ने लगा है और इन टैस्टों में गत वर्ष के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 1,965 बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। उत्तर प्रदेश से 1249 हैं, बाकी में महाराष्ट्र में 800, आन्ध्रप्रदेश में 700, तेलंगाना में 700, मध्य प्रदेश में 700, बिहार में 600, दिल्ली एनसीआर में 500, झारखंड में 400, हरियाणा में 300 हुए, इस तरह से हमारे विद्यार्थियों ने जो परचम फहराया है। उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इसमें भी 11.1 प्रतिशत बजट में बढ़ोतरी की है, यह वाकई काबिलेतारीफ है और आईएएस परीक्षा में वरीयता के हिसाब से प्रदेश में पचास छात्रों को पांच हजार की सहायता दी जाएगी उसके लिए भी हम आभारी हैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के।

एससी/एसटी वर्ग के मेघावी बच्चों के लिए अलग से योजना लायी है सरकार और कल घोषणा की गयी है। आईआईटी, एम्स जैसे संस्थानों में प्रवेश पाने वाले प्रथम सौ को पच्चीस हजार रुपये की सहायता देने का भी प्रावधान किया है। राज्य के आठ इंजीनियरिंग कालेजों में ढांचागत सुविधाओं के लिए पिछले साल दी गयी राशि की तुलना में दुगुनी बढ़ोतरी की गयी है, इस बार यह राशि 7.10 करोड़ रुपये होगी। राज्य के नयी पॉलिटैक्निक कालेजों में पूर्व कालेजों की तरह इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट इंटरएक्शन सैल का गठन किया गया है, स्किल यूनिवर्सिटी जिसका कि हमने दो दिन पहले एक्ट पारित किया है, स्किल यूनिवर्सिटी को प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही प्रस्तावित निजी क्षेत्र की स्किल यूनिवर्सिटी भी इस साल खुलेगी। ये सब

(श्री जोगाराम पटेल)

कार्य बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय मंत्रीजी और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में भी आमूल-चूल परिवर्तन होने की संभावना है। इसका 6,315 करोड़ 38 लाख का बजट प्रावधान किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 8.21 प्रतिशत अधिक है। सात जिलों में स्थापित ब्लड बैंक को विकसित किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र के जिलों के लिए ट्रोमा अस्पताल, जोधपुर में आईसीयू कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी का कल उन्होंने बिलाड़ा में ट्रोमा सेन्टर और ये मथुरादास माथुर अस्पताल में लंबे समय से कैथ मशीन ऐसे ही पड़ी थी उसका टाइम एक्सपायर हो गया था उसके लिए दस करोड़ रुपये देकर नयी मशीन लाने की, आईसीयू कैथ लैब की जोधपुर में घोषणा की उसके लिए हम जोधपुर वाले बहुत आभारी हैं। बिलाड़ा वाले विधायक तो बहुत ही खुश हैं कि उनके क्षेत्र में ट्रोमा सेन्टर खुल गया है। अनेक हास्पिटलों का, पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत करने की जो लंबी लिस्ट है वो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा।

मैं निवेदन करूंगा कि चिकित्सा शिक्षा में भी बजट में बहुत अधिक बढ़ोतरी की गयी है। 2,574 करोड़ 86 लाख रुपये के बजट प्रावधान किये गये हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 33.40 प्रतिशत अधिक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-चार विभाग हैं जिनके खाली परसेंटेज आपके सामने निवेदन करूंगा। कौशल राजस्थान व रोजगार में 1,700.44 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है जो 21.32 परसेंट अधिक है। राजस्व एवं श्रमिक कल्याण में 5,653 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जो 11.83 प्रतिशत है। श्रम विभाग में 1,700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले बजट से 21.32 प्रतिशत अलग है। उद्योग विभाग में 3,056 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 17.10 प्रतिशत अधिक है। गृह विभाग में 5,653 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है। सामाजिक न्याय विभाग में 5,596 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो

(श्री जोगाराम पटेल)
पिछले वित्तीय वर्ष से दो प्रतिशत अधिक है। जनजाति विकास में 5,096 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 6 प्रतिशत अधिक है। कृषि विभाग में 3,156 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से 3 प्रतिशत अधिक है। यूडीएच विभाग में 6,337 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष से चार प्रतिशत अधिक है। पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास में भी 14,689 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से पांच प्रतिशत अधिक है और शिक्षा विभाग में 25,215 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से सात प्रतिशत अधिक है। देवस्थान विभाग में 55 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से पांच प्रतिशत अधिक है और राजस्व विभाग में 1,407 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से आठ प्रतिशत अधिक है।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूं कि राजस्व विभाग में 'न्याय आपके द्वार' जो कार्यक्रम चला था वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आंकड़े आपके सामने है कि कितने प्रकरणों का निपटारा हुआ। कई वर्ष लग जाते हैं भाई-भाई हो, बहन-भाई हो, पड़ौसी हो, वो मुक़दमे कोर्टों में लड़ते रहते हैं, किसी का निर्णय नहीं हो पाता है। लेकिन राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सूझबूझ से वर्तमान युग में जो लोक अदालत का कंसेप्ट चला चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई भी हाई कोर्ट हो, चाहे अन्य न्यायालय हों, चाहे मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय हो, उस कंसेप्ट को एडोप्ट कर 'न्याय आपके द्वार' कार्यक्रम के द्वारा बहुत अधिक प्रकरणों का निपटारा किया गया है। इसमें न केवल राशि की बचत हुई है, न केवल आपस में प्रेम भाव बढ़े हैं, लेकिन अनेक पंचायतें पूर्ण रूप से झगड़े विहीन हो गयी हैं। ऐसी स्थिति में जो ग्राम पंचायतें पूर्ण रूप से विवाद विहीन हो गयी हैं वो भी धन्यवाद की पात्र हैं और अभी एक विभाग के बारे में सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कहा और बिजली विभाग के बारे में समय-समय पर आपके सामने बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं। मैं इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि बिजली विभाग के मामले में राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जितना ध्यान दिया है बिजली में जितना सुधार करने का प्रयास किया है, बिजली में

(श्री जोगाराम पटेल)

उदय योजना हो या एमनेस्टी योजना हो या अभी जो काश्तकारों को रियायत दी वो मामले हो, अगर ये सब नहीं होता तो बिजली विभाग बंद होने के कगार पर था, शायद बंद हो जाता। लेकिन हर व्यक्ति को लाभ हो, हर इंडस्ट्री को लाभ हो, हर कृषि वाले को लाभ हो, इन सबको ध्यान में रख कर आने वर्ष में 33 केवी के 200 नये सब स्टेशन स्थापित किये जाएंगे। हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान जो स्थापित हुए उनको और इनको देखा जाए तो कांग्रेस के कार्यकाल में दस परसेंट भी ऐसे 33 केवी के सब स्टेशन कायम नहीं हुए।

बूंद-बूंद फव्वारा एवं डिग्गी सिंचाई आधारित योजना को प्रोत्साहित किया गया है। कृषि कनेक्शन तीन वर्ष बाद होंगे...

(15.00 बजे)

और जैसे कल घोषणा हुई एक लाख कृषि कनेक्शन, मैं मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों से पूछना चाहता हूं कृपया आप आंकडे देकर बताएं कि आपके पांच साल के कार्यकाल के दौरान कितने कृषि कनेक्शन दिये गये। अगले दो वर्ष में जो एक लाख कृषि कनेक्शन दिये हैं, काश्तकार उसका इंतजार कर रहे थे और इस मामले में भी सरकार धन्यवाद की पात्र है। 132 केवी क्षमता के 15 नये स्टेशनों का निर्माण किया गया है और यह सब इस बजट की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं जो मैंने आपको आंकडों के साथ आपको निवेदन की।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मात्र आंकड़े नहीं है, अगर आपने इसको वास्तविकता में देखा है और एक साथ अगर आप इसका अनुमान करें, जिस तरह से सरकार ने इस बजट को प्रस्तुत किया है उस समय की आर्थिक समीक्षा को देखें तो श्रीमान इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राज्य की अर्थव्यवस्था मूलत: कृषि एवं ग्रामीण पर है जैसा इन विभागों में बजट बढ़ाया गया है। सकल घरेलू उत्पादन राज्य के विकास एवं आर्थिक उत्पाद को मानने के महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। इससे राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत निर्धारित समयावधि सामान्यत: एक वर्ष में बिना दोहरी गणना किये हुए अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के लिए प्रदान की गयी सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। आर्थिक

(श्री जोगाराम पटेल)

एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पादन के अनुमान प्रचलित एवं स्थिर कीमतों पर तैयार किये जाते हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करुंगा कि 2016-17 के जो बजट अनुमान थे, सकल राज्य घरेलू उत्पादन, उसमें 749692 करोड़ अनुमानित किये गये थे जो गत वर्ष 2015-16 के रुपये 672700 के 11.25 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाते हैं। इसी तरह अन्य आंकड़ों में भी वृद्धि दर्शाते हैं। अगर हम 2010-11 से लेवें, सकल राज्य घरेलू उत्पादन और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन को हम देखें तो राजस्थान के इस मौजूदा बजट में यशस्वी मुख्य मंत्री जी बहुत अधिक सुधार इन विपरीत परिस्थितियों में भी लायी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन मिनट और लेते हुए निवेदन करूंगा, आप कैसे तोलेंगे कि यह बजट कैसा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासनकाल में वर्ष 1999-2000 में 4282 करोड़ खर्च कर 1517 करोड़ की परिसम्पत्तियां यानी 35 प्रतिशत की परिसम्पत्तियां बनाईं। अभी सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने तो लोन लिया, पर हमने कम लिया है। लोन लेना बुरा नहीं हैं, लोन लेकर उपयोग क्या करते हैं, वह देखने योग्य बात है। इन्होंने जो टोटल लोन लिया था उसका 35 प्रतिशत ही परिसम्पत्तियां बनाने में उपयोग किया। 2000-01 में 46 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनाईं और 2001-02 में सिर्फ 36 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनाईं। 2002-03 में 43 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनाईं। उसके अगेंस्ट में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में 2004-05 में 51 प्रतिशत की परिसम्पत्तियां बनाईं। 6770 का कर्ज लिया गया, 3488 करोड़ की परिसम्पत्तियां बनाई गयी जो 51 प्रतिशत के बराबर बनती है। 2005-06 में 68 प्रतिशत परिसम्पत्तियां बनाई गयी। वर्ष 2006-07 में भी 101 प्रतिशत की परिसम्पत्तियां बनाई गयी। 2007-08 में भी 109 परसेंट की परिसम्पत्तियां बनाई गयी। अब आप इसको तोलें, यह लोन लेकर परिसम्पत्तियां बनाने के उपयोग में नहीं कर रहे थें और हमारे यहां लोन लेकर परिसम्पत्तियां बनाने के उपयोग में ली गयी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 7100 करोड़ का कर्ज लिया गया और 8896 करोड़ रुपये की परिसम्पत्तियां बनाई गयी, जो 82 प्रतिशत के आस पास ही नहीं थी। वर्ष 2009-10 में 7553

(श्री जोगाराम पटेल)

करोड़ का कर्ज लिया गया और 5100 करोड़ की परिसम्पत्तियां बनाई गयी। इनके कार्यकाल और हमारे कार्यकाल का राजस्व घाटा, पूंजीगत व्यय, बिजली कंपनियों का घाटा, इसके आंकड़े पेश करूं तो आप जानेंगे कि वास्तव में यह सिर्फ बताने के लिये कर रहे हैं।

लास्ट में आपसे प्लान साइज का निवेदन करूंगा, प्लान साइज बनाना और वास्तविक व्यय करने में फर्क है। इनके समय 2009-10 में 18653 करोड़ का प्लान साइज बनाया और 18022 का खर्च हुआ, माइनस 600 करोड़ का हुआ। 2010-11 में 23562 करोड़ का प्लान बजट बनाया, 20829 करोड़ रुपये कम हुआ, करीब 3-4 हजार करोड़ कम खर्च हुआ। 2010-12 में 29261 करोड़ का प्लान बनाया और 25039 करोड़ खर्च हुआ, माइनस 4222 करोड़ कम खर्च हुए। 2012-13 में 36365 का रिवाइज प्लान बनाया और 19920 करोड़ ही खर्च हुए। इससे स्पष्ट है कि यह प्लान बनाकर खर्च भी नहीं कर रहे हैं।

समय समय पर सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश की सिर्फ वह आपके सामने निवेदन करुंगा। इनके वित्तीय प्रबंधन के संबंध में कटाक्ष किया है। वित्तीय प्रबंधन और बजटीय नियंत्रण, वर्ष 2012-13 के दौरान कुल अनुमानों एवं विनियोगों के समक्ष 6836.94 करोड़ की समग्र बचत हुई जो दोषपूर्ण बजट को दर्शाती है, यह इनके कार्यकाल के दौरान का है और सीएजी की यह रिपोर्ट है। अनुदान संख्या 11 एवं 20 में हुए आधिक्य व्यय पर 0.79 लाख का भारत के संविधान की धारा 205 के अधीन नियमितीकरण अपेक्षित है और इन्होंने संविधान के प्रावधानों के विपरीत खर्चा कर दिया। सभी 55 अनुदानों, विनियोगों में रुपये 6717.45 करोड़, कुल बचतों का 6830.9 करोड़ रुपये का 98 परसेंट वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में किया गया। 98 परसेंट खर्चा लास्ट महीने में किया गया। पूरे साल 2 परसेंट और लास्ट में 98 परसेंट किया गया, जिससे निधियों का उपयोग किसी अन्य विकास संबंधी कार्यक्रम में करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। 179 मामलों में रुपये 1539.34 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान करते हुए संशोधित राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। रुपये 1539.34 करोड़ में से 1275.9 करोड़ रुपये, 83 प्रतिशत अनुपयोगी रहे, उपयोग ही नहीं कर सके

(श्री जोगाराम पटेल)

इनके कार्यकाल के दौरान। वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता एवं अन्य चिरकालिक प्रवृत्ति कमजोर बजटीय नियंत्रण का सूचक है। राज्य सरकार द्वारा मार्च 2013 के दौरान आहरित की गयी रुपये 2198.60 करोड़ की राशि बजट अनुमान को व्ययगत होने से बचाने के लिये शेष में जमा कराई गयी और इस तरह से संविधान के विपरीत, बजटीय प्रणाली के विरुद्ध और नियमों के विपरीत इन्होंने इस तरह से बजट पालना की जिसका सीधा उल्लेख इसमें किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत तीन परियोजनाओं में 22.39 करोड़ का संपूर्ण बजट आबंटन बिना कोई व्यय किये ही समर्पित कर दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा बजट कोई खर्च ही नहीं किया और वापस जमा करा दिया, समर्पित कर दिया। गृह विभाग में 2010-11 एवं 2011-12 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमश: 61.9 एवं 97.25 की कमी हुई, जबकि राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के लिये किया गया 0.50 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान बिना व्यय किये 31 मार्च, 2013 को समर्पित किया गया।

शिक्षा, कला, संस्कृति विभाग के अनुमानित प्राप्तियों का उचित रूप से आकलन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप वर्ष 2010-2013 के दौरान प्राप्तियों में माइनस 2.71 से 575 प्रतिशत का अंतर रहा। यह इनकी बजटीय व्यवस्था है, इनका वित्तीय प्रबंधन है। मैं और भी आंकडे देकर आपके सामने निवेदन कर सकता हूं। लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। मैं सिर्फ एक मिनट में निवेदन करना चाहूंगा कि कल हमारे बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि इतने विभागों में हमने इनाम प्राप्त किया। उनके अलावा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, पोस से राशन, अन्नपूर्णा भंडार, भामाशाह योजना, आदर्श विद्यालय, राजस्थान संपूर्ण कौशल व प्रशिक्षण, ई मित्र, इसमें राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में लीड लिये हुए है, प्रथम स्थान पर है।

इतना ही नहीं, पांच-सात ऐसे भी विषय हैं। ऐसे भी हैं। यह आपके लिये है:-

'बिजली जब चमकती है, आकाश बदल देती है,

आंधियां जब चलती हैं, दिन-रात बदल देती हैं,

धरती जब दरकती है, सीमाएं बदल देती है, और

वसुंधरा समान नारी मां जब गरजती है, तो इतिहास बदल देती है'

इतिहास बदलकर राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री ने आपको बता दिया। मैं आखिर में इतना ही निवेदन करूंगा कि ऐसे अनेक सैक्टर हैं, जिसमें हम हिन्दुस्तान में प्रथम स्थान पर आये हैं। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहला अवसर है कि ऐसे टोटल पन्द्रह महकमे हैं, जिनमें राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है और इस सबका कारण यह है। अगर एक काम आप कर सकें तो करें। एक काम आप करें तो करें और नहीं करे तो कोई बात नहीं, हम करेंगे और आपका जो काम है....

'जरा-सा भी साथ दे तो क्या बात है,

सारा जहां भी साथ दे तो क्या बात है,

तू जरा भी साथ दे तो क्या बात है,

चलने को तो कोई एक पांव से भी चल सकता है,

पर दूसरा भी साथ दे तो क्या बात है'

आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आपने यह किसके लिए पढ़ा है? जरा, यह और बताओ आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह प्रतिपक्ष के लिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): अच्छा, सबके लिए है क्या?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): बाकी आगे खोदो मत।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैंने सोचा आप केवल डूडी साहब के लिए पढ़ रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लाल जी गुप्ता।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): मैं साथ मांगा है, उसके लिए कह रहा था। इन सबको साथ रखते हुए कि:-

(श्री पूरणमल सैनी)

'हम लड़ेंगे यह लड़ाई, हमारी पीर देखना,

और बहुजनों की बदलेंगे तकदीर देखना'

अगर साथ हो तो साथ हैं हम।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसका यह है। सुनो आपके लिए भी। अब आपका इधर आने का मौका हो गया।

'अब धीरे-धीरे मौसम बदलने लगा है,

वातावरण सो रहा था, अब जगने लगा है,

पिछला सफर तो ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ था,

जो रुक गया था कहीं पर,

फिर साथ चलने लगा है,

आ जाओ आप भी फिर साथ चलने लगा है'

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सर,

'हम लहू से भरेंगे रंग, इस आकार में देखना,

और सदियों पुरानी बदलेगी तस्वीर देखना'

श्री जोगाराम पटेल (लूणी):

'आपकी निगाहें मंज़िले थीं, गिरे और गिरकर सँभलते रहे,

हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग जलते रहे'

उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकने का प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष: देखिए, यह आपको एक संदेश था कि जो इधर-उधर बात कर रहे थे और कुछ निद्रा अवस्था थे, वे वापस जाग्रत अवस्था में आ गये। श्री मोहन लाल जी गुप्ता। अब एकाग्रचित्त होकर आपको सुनना है। कोई भी बीच में टोका-टोकी नहीं होगी और इधर-उधर वार्तालाप नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): उपाध्यक्ष महोदय, अब एक भी माननीय सदस्य नहीं सोयेगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, वह अपने आपमें अनूठा,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

राजस्थान के विकास को नया आयाम देने वाला और 2020 के विजन को प्रस्तुत करने वाला है। मैं समझता हूं सभी वर्गों के लिए उन्होंने बजट दिया था। आज मैंने जब अखबारों में प्रतिक्रियाएं देखीं तो सोचा था कि शायद प्रतिपक्ष के नेता इस बजट का कुछ तो स्वागत करेंगे, लेकिन इनकी प्रतिक्रिया क्या आई? आप नेता प्रतिपक्ष की प्रतिक्रिया सुनिए। इन्होंने कहा, झुनझुना पकड़ाया, बजट से किसान निराश, बेरोजगार युवा सब निराश, महिला दिवस पर महिलाओं को भी निराश किया, सिंचाई परियोजनाओं की अनदेखी कर दी, किसान मुद्दों की उपेक्षा कर दी। यानी बजट पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, शायद देखा ही नहीं। पेयजल योजना, शिक्षा, अल्पसंख्यक, एस.टी. वर्ग को कोई राहत नहीं और लोगों को झुनझुना पकड़ा दिया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रतिक्रिया कोई अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं दे सकता। कुछ तो सोचो, कुछ तो तोलो। अपने पी.ए. से ही लिखवाकर अख़बार में भेज दिया, यह तो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है।

अब पायलट साहब की प्रतिक्रिया सुनो। हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पायलट साहब अपने ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप नाम न लें किसी का, पद नाम लें लें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यस सर। भाजपा सरकार के तीन वर्षों से कुशासन के लिए किया गया असफल व दिशाहीन प्रयास। दिशाहीन, कोई दिशा ही नहीं है। असफल है। पायलट ने कहा, 'राजकोषीय घाटा बढ़ा है, जिससे उबरने के लिए सरकार ने कोई नीति स्पष्ट नहीं की। बजट में मंहगाई को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, सरकार को बजट में गैस व चीनी पर सब्सिडी की घोषणा करनी चाहिए'। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह स्टेट का बजट है या सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, जो गैस और चीनी पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। यह ज्ञान हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी का है, जो स्टेट गवर्नमेंट पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, 'गैस और चीनी पर सब्सिडी करो। इनको किसने लिखकर दिया, यह मुझे पता नहीं है। लेकिन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से अपनी प्रतिक्रिया भेजी, जहां से वे हार कर आ रहे हैं और दस-पांच सीटों पर लौट जाएंगे। उन्होंने प्रतिक्रिया भेजी है कि मैट्रो का क्या हुआ ? अब उनको पता नहीं है कि

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मैट्रो वन फेज भी पूरा हो रहा है। क्या प्रतिक्रिया भेज रहे हैं वे? मैट्रो चल रही है। फेज वन चालू है। रिफाइनरी का क्या हुआ? अभी आपके खुद के नेता सपोटरा वाले ही बोल गये कि एक हजार करोड़ का प्रावधान रखा है। घाटे की सरकार तो हम चला नहीं सकते। तो जो लोग अपने पी.ए. के माध्यम से प्रतिक्रिया भिजवा रहे हैं, अनपढ़ लोगों के माध्यम से प्रतिक्रिया भिजवा रहे हैं। उनके ज्ञान और बुद्धि का स्तर क्या होगा? यह मेरी समझ से परे है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): आपने जो प्रतिक्रिया भेजी है वह हूबहू पढ़ दो भी अभी, अभी पता चल जाएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): भेजी है। कांग्रेस के लोगों को किसान नहीं दिख रहे, किसानों के लिए क्या किया? पेयजल के लिए क्या किया, दिख नहीं रहा है। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया, यह दिख नहीं रखा है। किसानों को राहत दी, वह नहीं दिख रहा है। ये सब चीजें उनको दिख नहीं रही है। किसानों के लिए क्या किया? आप बैठे हैं ना इसलिए मैं कह रहा हूं। बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया, वह नहीं दिख रहा है। किसान तो ढोल बजाकर स्वागत कर रहा है। वसुंधरा जी के यहां आकर कह रहा है, वसुंधरा जी की जय जयकार। आपने बिजली की दर बढ़ाने का कान्ट्रेक्ट किया था। वसुंधरा जी ने तो बिजली की दरें कम की हैं। आपने नियामक आयोग में कहा है। यह आपको दिखता ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, यह इनकी प्रतिक्रिया है और दूसरी तरफ प्रतिक्रिया है एक अर्थशास्त्री नेशार अहमद साहब की। उन्होंने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है- 'मुख्यमंत्री ने 2017-18 का बजट पेश करते हुए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया, पर्यटन, संस्कृति, धरोहरों, पुस्तकालयों, मज़ारों'। संसदीय कार्य मंत्री नहीं हैं, जरा वे सुन ले तो ठीक रहता। नेशार अहमद साहब जो अर्थशास्त्री है, उनकी प्रतिक्रिया है। दुबारा कह रहा हूं - माननीय मुख्यमंत्री ने 2017-18 के लिए बजट पेश करते हुए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया, पर्यटन, संस्कृति, धरोहरों, पुस्तकालयों, मज़ारों, मदरसों, गुरुद्वारों, मन्दिरों सहित तमाम घोषणाएँ करते हुए मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों को राहत प्रदान की है।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(15.19 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

यह अर्थशास्त्री कह रहे हैं। एक दूसरे अर्थशास्त्री हैं, राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा। उन्होंने भी एक प्रतिक्रिया अख़बारों में दी है। इनकी प्रतिक्रिया मैंने अखबारों से ली है। इस साल के बजट की खास बात यह है कि यह बजट धरातलीय आवश्यकताओं को लेकर बनाया गया है। आसमान से नहीं बनाया है। धरातलीय आवश्यकताओं को लेकर बनाया है। इसका बड़ा कारण क्या है? मुख्यमंत्री ने संभागवार 'आपके द्वार' माध्यम से फीड बैक लिया। मुख्यमंत्री महोदय ने फीडबैक लिया। जन-सुनवाई की।

विधायकों व अधिकारियों से फीडबैक लिया और राजस्थान के समग्र विकास का सपना इस बजट में देखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में आय की संभावनाएं कम हैं। यह रेगिस्तान है, यहां पर कोई समुद्र नहीं है। दुबई में समुद्र को पाटकर आप डवलपमेंट कर सकते हो लेकिन रेगिस्तान में संभावनाएं बहुत कम है। पानी नहीं है, बिजली महंगी है उसके बावजूद भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बोर्ड को इस वर्ष के बजट में 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान दिया है। 60 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया है ताकि वह अपने ऊपर भार ले सके। आपके कर्मों को उन्होंने ढका है। उन्होंने यह कहा है कि 60 हजार करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। आपके पाप किए हुए हैं, राजस्थान की जनता पर भार डालने का प्रयास किया है लेकिन अब क्या करें।

सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि पांच हजार करोड़ रुपया लगेगा। 60 हजार करोड़ रुपया आप छोड़कर गये हो, क्या करेंगे उसका? 80 हजार करोड़ छोड़कर गये हो, उसमें से 60 हजार का लोन लिया है।

उदय योजना के तहत बिजली कम्पनियों के घाटे को पूरा करने का प्रयास किया है। सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं आपने बिजली कम्पनियों को घाटा दिया, आप छीजत को कम नहीं कर रहे हो, तो उनको दिखता नहीं है क्या? माननीय सभापति महोदय, उनको दिखता है कि

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे ऊर्जा मंत्री जी, हमारी सरकार इस बात में लगी हुई है कि छीजत को कम किया जाए, उसके प्रयास भी सामने आ रहे हैं।

मैं एक बात पूछना चाहूंगा, हमारा यह तीन साल का बजट है, आपके तीन साल के बजट से उसकी तुलना कर लेते हैं। आपने क्या किया, हमने क्या किया, कर लें क्या? कर लेते हैं आपने नाड़ हिलाई है तो। सड़क पर कांग्रेस के तीन सालों में 9157 करोड़ रुपया व्यय हुआ और हमारे तीन सालों में 20822 करोड़ रुपया व्यय हुआ है, तीन गुणा। तोलो तो सही। कहां 20 हजार और कहां 9 हजार?

कांग्रेस ने अपने तीन सालों में 661 गांव और ढ़ाणियों को सड़क प्रदान की और हमने कितनी की, कल्पना करो, सोचो, 4281 गांव और ढांणियों में हमने सड़क की व्यवस्था की। कांग्रेस ने अपने पांच साल में 12554 किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई थी। सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि बीजेपी के तीन साल के शासन में उनके पांच साल के 12554 के अगेन्स्ट 15278 किलोमीटर की सड़कें बना दी। यह एफिशियंसी है, विजन है, डिसीजन मेकिंग क्षमता है, यह हमारी अपनी कार्यप्रणाली है जो आपकी कार्य प्रणाली को बताती है कि आप किस प्रकार से काम करते हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मोहन लाल जी भाईसाहब एक मिनट, एक मिनट बोल दूं क्या आप कहो तो, नहीं तो बैठ जाऊं। मैं यह कह रहा हूं जो पोर्च में बात कह रहे थें वह तो बताओ आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप पेयजल की बात ले लो। कांग्रेस के तीन साल में पेयजल पर 6097 करोड़ रुपया खर्च हुआ और बीजेपी के राज में 13473 करोड़ रुपया खर्च हुआ, यानी दुगने से भी ज्यादा। यह केवल दो ही आंकड़े हैं, और भी आंकड़े दूंगा तो आप कहोंगे कि क्या बोलते हो आप।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्य में आय का जो स्रोत है वह सभी सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि 5 परसेंट स्टेट एक्साइज ड्यूटी से आता है, 2 परसेंट टैक्सेज ऑन व्हीकल से आता है, 4 परसेंट अदर टैक्सेज

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

से आता है केवल मात्र 19 परसेंट ही वैट से आता है, 8 परसेंट नोन टैक्स रेवेन्यू से आता है, 13 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस से आए, 21 परसेंट शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेज है, 28 परसेंट बोरोइंग है, यह हमारा टोटल रेवेन्यू का परसेंटेज है।

हमारा एक्सपेंडीचर Six percent repayment of interest and debt, One percent loans and advances देते हैं, 68 परसेंट रेवेन्यू एक्सपेंडीचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडीचर, 11 परसेंट इन्टरेस्ट और 14 परसेंट कैपिटल एक्सपेंडीचर।

सभापति महोदय, हम जो खर्च कर रहे हैं उसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा। फसल बीमा कृषि एवं सामान्य सेवाओं के लिए 5 परसेंट, ग्रामीण विकास आवास नरेगा, स्वच्छ भारत के लिए 13 परसेंट, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के लिए 0.32 परसेंट, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 3.24 परसेंट, विद्युत पर 20 परसेंट, यह हमारी अपनी इकोनोमिक्स है, जनता के सामने जानी चाहिए।

उद्योग एवं खनिज 1.77 परसेंट, यातायात 7.86 परसेंट, वैज्ञानिक सेवाओं में 0.8 परसेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बजट का 43 परसेंट से ज्यादा हिस्सा शिक्षा, चिकित्सा, पेंशन, पिछड़ी जाति, महिलाओं, किसानों इन लोगों को जा रहा है। यह ऑफिशियल आंकड़े हैं, 43 परसेंट। अब आप कह रहे हो कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पेयजल के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आर्थिक सेवाओं के 2.28 परसेंट, सामान्य सेवाओं के लिए 1.60 परसेंट।

माननीय सभापति महोदय, समय की सीमा है, आपने फर्स्ट स्पीकर के नाते सारी बातें बोल दीं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त। हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ट्रासपरेंट राजस्थान की स्थापना के लिए काम किया है। हम नम्बर वन पर शिष्टाचार में आए हैं, आप लोग भ्रष्टाचार में आए हो। सारे देश से कांग्रेस खतम हो रही है। आज राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार नजर आता है क्या आपको? पहले दलाल छोड़ रखे थे। पोस मशीनों के माध्यम से लोगों को ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे प्लीज नहीं बोले।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पोस मशीनों के माध्यम से राशन की दुकानों पर भ्रष्टाचार खतम नहीं हुआ क्या? आज सारी सामाजिक योजनाएं, पहले विधवा आती थी, महाराज हमारा डाकिया ही नहीं आया, पैसे ही नहीं लाया, पैसे लाता है तो पैसे और मांगता है। हमारी सरकार ने कह दिया।

स्कॉलरशिप हो, विधवा पेंशन हो, सामाजिक सहायता हो, कोई भी बात हो, सबके लिये आपके पास में बैंक में पैसा पहुंच जाएगा और आपके मोबाइल पर एस.एम.एस. आ जाएगा कि आपका पैसा आ गया है। यह भ्रष्टाचार खतम नहीं किया तो क्या किया हमने। हमारे किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं। जिस भी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसी अधिकारी को सस्पेंड करके जेल की सींखचों में हमने ठूंस दिया। भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार का समझौता नहीं है। माननीय सभापति महोदय, अब इनको यह दिखता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

टाइम हो गया, इसलिये मैं कुछ ही बातें कहूंगा कि ऑनलाइन फिल्म टिकट सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, आंखें खोलकर देखो। विमान सेवाएं सस्ती होंगी ईंधन की दरों में कमी करने पर। स्टाम्प ड्यूटी के तहत राहत से मुख्य मंत्री आवास योजना के मकान भी सस्ते होंगे, आज ही अखबारों में आया है। स्टार्ट अप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उनको लोन की सुविधा मिल रही है। गांवों में उद्योग लगाना सस्ता हो रहा है। इंटरेस्ट की रेट कम हो रही है। किसानों को ऋण के ब्याज पर अनुदान मिल रहा है, सहकारी बैंकों के माध्यम से। अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कम से कम आप अपने भाषण में बोल तो देना कि हां, यह मिल रहा है। आपने सही काम किया है, मैडम, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं, यह तो कह देना कम से कम, माननीय विपक्ष के नेता।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): शुरू किसने किया था, मोहनलालजी, बिना ब्याज ऋण शुरू किसने किया था, यह तो बता दो, डेढ़ लाख तक।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): व्यापारियों को भी रिलीफ दी है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आपने बढ़ाया क्या, उसको डेढ़ लाख से आगे लेकर गये क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): भंवरसिंहजी, आपका नम्बर आने वाला है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी हमारे सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कर रहे थे, कंसल्टेंसी की बातें कर रहे थे, आपके हर डिपार्टमेंट में एक कंसल्टेंट लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका कंसल्टेंट कौनसा अच्छा था, जिसने मैट्रो में कंसल्टेंसी दी थी। करोड़ों रुपये ले गया और कहा था कि मैट्रो में 25 हजार सवारियां बैठेंगी, बैठ रही हैं दो हजार, करोड़ों रुपये ले गया आपके कांग्रेस के राज में। यह आपकी कंसल्टेंसी है। भट्टा बैठा दिया। आपकी कंसल्टेंसी है, रिफाइनरी लगाने में फायदा होगा, लॉस ही लॉस हो रहा है। यह किस प्रकार की बातें करते हैं। किसी ने लिख कर दे दिया, बोल दिया। मैं चैलेंज करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं, वह सही बोल रहा हूं और उसके लिये सदन के बाहर भी जिम्मेदार हूं।

कहते हैं रिंग रोड का क्या हुआ। अब आपको पता नहीं है कि रिंग रोड बन रही है कि नहीं बन रही है। बहुत सारी जगहों पर तो काम चालू हो गया। कुछ दिक्कतें आयीं तो नितिन गडकरीजी से मिलकर ठीक कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री तक इंटरेस्ट ले रहे हैं। वहां मीटिंग्स हो रही हैं। आपको पता ही नहीं है। आप जनता में भ्रम क्यों फैलाना चाहते हो। जयपुर में द्रव्यवती नदी बन रही है। क्या यह आपको पता नहीं है क्या, और द्रव्यवती नदी का काम चालू है, यह आपको पता नहीं है क्या। रिंग रोड बन रही है, पता नहीं है क्या। आप केवल सस्ती वाहवाही लूटने के लिये इस प्रकार से प्रचार कर रहे हो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शहरों में रोजगार करने के लिये और नगर पालिका के तहत सारे शहरों में सफाई के प्रति जागरूकता का एक अभियान, चार शहर स्मार्ट सिटी, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खिलाते थे घूघरी, आप खिलाते थे कोई पूरी-सब्जी, आप खिलाते थे कोई कलेवा, और हम खिला रहे हैं अन्नपूर्णा रसोई।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)
माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय नेता जाकर देखें, चखें और खायें, कितना बढ़िया स्वादिष्ट भोजन गरीबों के लिये आठ रुपये में, नाश्ता पांच रुपये में।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य चार्टेड अकाउंटेंट हैं। इनसे ज्यादा बजट का मैथेमैटिकल विश्लेषण कोई नहीं कर सकता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अब मैं कहना चाहता हूं कि इतना बढ़िया नाश्ता आपने कभी किया नहीं। शहरों में जो लोग रोजगार की तलाश में आते हैं, रोजगार की तलाश में आने वाले उन व्यक्तियों को सस्ता नाश्ता, अच्छा नाश्ता, फाइव स्टार कल्चर का नाश्ता, रेस्टोरेंट की कीमत में मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या काम होगा। माननीय वसुन्धराजी, इससे बढ़िया क्या कर सकती हैं। जो गांव में आपके यहां से आते हैं ना, कुली, मजदूर। ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके यहां से नहीं आते?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यहां से भी आते हैं, मैं शहर का हूं, इसलिये, मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि आपको यह दिखना चाहिये। कम से कम यह तो कहना चाहिये, हां, आपने यह काम अच्छा किया है। 51 करोड़ की लागत से जयपुर में प्लास्टिक इंजीनियरिंग का कालेज स्थापित होगा, 51 करोड़ रुपये की लागत से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगा मैं। ये तो कह रहे हैं, आप बोले जाओ।

श्री सभापति: आसन की तरफ थोड़ा ध्यान दें। आसन अपनी व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैटेरियल बहुत है। लेकिन आपने बोल दिया, बहुत सारी बातें हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ...(व्यवधान)... वाई-फाई, सब जगह वाई-फाई हो रहा है, स्कूलों में, कालेजों में, अस्पतालों

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

में। बच्चे वाई-फाई देखेंगे। यह रोजगार का आंकड़ा दिखता नहीं है क्या। अंतिम बात कह रहा हूं मैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम 15 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में भी यह है कि हम रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। थोड़ा सा पढ़ कर आओ, ग्रामर, कोमा, फुल स्टॉप देखो। हमने रोजगार के अवसर दिये हैं, इसीलिये कौशल विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। हमारे रोजगार केन्द्रों को जाकर देख आओ। रेमण्ड वाले को देख आओ जो रोजगार दिखा रहा है। कोई हास्पिटल में जाकर देख आओ। किसी ज्वैलरी सेण्टर में जाकर देख आओ। किसी गांव में जाकर देख आओ। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर देख आओ कि किस प्रकार के रोजगार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रांसपरेंट ढंग से। कोई भ्रष्टाचार नहीं है उसमें। बाकायदा पोस मशीन से एण्ट्री होती है। ट्रेनिंग दी जाती है। सर्टिफिकेट दिया जाता है। उनको नौकरी भी दी जाती है। और आप सुन लो, ऐसे 09 लाख लोगों को रोजगार के अवसर हमने प्रदान कर दिये, ...(व्यवधान)... 11 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर दिये। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो विधान सभा में घोषणा हुई थी कि पांच हजार कांस्टेबल्स की हम भर्ती करेंगे, यह इनको नहीं दिख रही है। सैंतीस हजार नये शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, वह नहीं दिख रही है। नीमराणा में जापान के सहयोग से इंस्टीट्यूट की स्थापना कही है, यह नहीं दिख रहा है। गौरव पथ इन्हें नहीं दिख रहा है, न्याय आपके द्वार नहीं दिख रहा है। केवल आंखों पर पट्टी बांध करके सरकार की आलोचना करना, यह विपक्ष का धर्म नहीं है। कृपया धर्म निभाएं। प्रजातंत्र का धर्म निभाएं और जो गलत काम हैं उनको उजागर करें। सही कामों में हमारा सहयोग करते हुए वसुन्धराजी का साथ दें। धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री रामलालजी शर्मा। (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री जयरामजी जाटव।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापतिजी, राजस्थान की विधान सभा में वर्ष 2017-2018 का 109 पेज का बजट दस्तावेज हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धराजी ने, लगभग तीन घण्टे में बिना पानी पिये पढ़ करके प्रस्तुत किया।

(श्री जयराम जाटव)

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा-लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा लेकिन जब यह देश आजाद हुआ 15 अगस्त, 1947 को तो हिंदुस्तान के लोगों ने समझा कि अब सब कुछ इस देश में सारी व्यवस्थाएं देश के जो चुनाव में जीत कर लोक सभा और विधान सभा में व्यक्ति होंगे, वह ऐसी नीति बनाएंगे और हमारे देश का कल्याण होगा।

26 जनवरी, 1950 को जब भारत के संविधान को लागू किया गया, जिसमें मानव के मौलिक अधिकार दिये गये ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: कृपया सुनें, व्यवधान नहीं करें।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): जब यह तय हो गया, गांव, शहर, किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी के लिए सारी सुख-सुविधाएं होंगी। हिंदुस्तान का कानून होगा। लोक सभा में हमारी चुनी हुई सरकार होगी, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस देश का भला होगा। देश को आजाद हुए 70 वर्ष हो गये, किसका दोष है?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की विधान सभा में 34 विधायक अनुसूचित जाति के हैं और लगभग 27 विधायक अनुसूचित जनजाति के हैं। 34 में से 31 विधायक भाजपा के हैं, केवल एक विधायक कांग्रेस का है। एक राजपा का है। एक जमींदारा पार्टी का है। 27 विधायक जो अनुसूचित जनजाति के हैं, उनमें से भाजपा के लगभग 25 विधायक हैं। क्या हुआ यह? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के नाम से इन लोगों ने वोट लिया। आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, वह किया है माननीय नरेन्द्रजी मोदी ने जीरो बैलेंस पर खाता खोलकर। भामाशाह कार्ड के माध्यम से श्रीमती वसुन्धराजी ने योजना बनाई, गांव के गरीब का किसी भी तरह की योजना का लाभ सीधा बैंक के खाते में जाए।

इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को। साथियों, मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह कांग्रेस के लोग घबरा गये हैं। इनका दोष नहीं है। इनकी मजबूरी है कि कुछ न कुछ बोलना जरूरी है क्योंकि नहीं बोलेंगे तो बाहर जनता पूछेगी कि आप क्यों गये थे? संख्या

(श्री जयराम जाटव)

बहुत कम है और कम में भी दो ही है, तीन होंगे मेरे ख्याल से बैठे हुए। सुनने को तैयार नहीं, बोलने के लिए कुछ है नहीं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को कि राजस्थान की ऐसी ग्राम पंचायत कोई नहीं बचेगी जहां पर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, राजकीय माध्यमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर रहे हैं। लगभग आधी ग्राम पंचायतों से ज्यादा, 5200 राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया पिछले वर्ष, क्यों नहीं धन्यवाद देना चाहते हम?

जिस गांव में गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर, अन्य पिछड़ा वर्ग, वह गांव में लोग बचे हैं। जो सम्पन्न हो जाता है, शहर की तरफ पलायन कर जाता है। आज गांव में उस घर में भी वह बच्चा पढ़ रहा है, जो 10वीं पास, 8वीं पास करके गांव से नहीं निकलता था, आज वह 12वीं पास कर रहे हैं। बेटियां 12वीं पढ़ रही हैं इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि गांव की अगर सुध ली है, शिक्षा का अगर स्तर बढ़ाया है तो उनका नाम है श्रीमती वसुन्धराजी।

आज ग्रामीण गौरव पथ की बात करते हैं। यह रोड्स की बात करते हैं। मैं एक गांव में चला गया, वहां दिल्ली से कोई आदमी आया, हमारे पड़ौस का कोई रिश्तेदार था, उसने यह कहा कि एम.एल.ए. साहब, हमारे दिल्ली में ऐसा रोड नहीं है, जो आपका ग्रामीण गौरव पथ कालोनी में बना है। दिल्ली में ऐसा रोड नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में राजस्थान प्रदेश का गौरव अगर बढ़ाया है तो श्रीमती वसुन्धराजी ने बढ़ाया है। आज क्यों नहीं कहेंगे इस बात को?

आज शिक्षा की बात को हम क्यों नहीं कहेंगे? निश्चित रूप से मैं कई उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे पड़ौस के एक गांव में एक बेटी थी पड़ौसी की, 8वीं पास करके वह घर बैठ गयी और जब माननीय वसुन्धराजी पिछली बार 2003 से 2008 तक यहां प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने एकमुश्त राजस्थान के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया था। उस लड़की ने जब क्रमोन्नत हुआ विद्यालय तो नाइंथ में एडमिशन लिया और अबकी बार जब 12वीं बनी तो

(श्री जयराम जाटव)

उसने पुन: फिर 11वीं में एडमिशन लिया और वह लड़की बी.एड. कर रही है। यह कितना बड़ा है?

मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में विकास हुआ है, यह बिजली की बहुत बात करते हैं। अभी हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य, जब मैं खाना खा रहा था तो वह कह रहे थे कि कम्पनियों से बहुत सस्ती बिजली लेते हैं और महंगी देते हैं, पता नहीं क्या-क्या बात कह रहे थे? वह बहुत बचाव की बात कर रहे थे। शिक्षा दे रहे थे राजस्थान की सरकार को। अब मैं उस भाषा में तो नहीं कहना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि जब आपके लोगों के हाथ में बागडोर थी, तब कहां थे? किसको कहते हैं 80 हजार करोड़? अगर गिनने बैठ जाएं तो सारी विधान सभा के 200 विधायक, सारे मंत्री बैठें तो कई दिनों तक तो 80 हजार करोड़ गिना नहीं जा सकता। गिनती भूल जाएं। 80 हजार करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ गये। पांच साल तक सच के अलावा झूठ नहीं बोली। एम.ओ.यू. भर कर देते रहे और जब हमारी राजस्थान की गवर्नमेंट आई तो किसान के साथ भला किया है। इस किसान के साथ भला इसलिए किया कि 80 हजार करोड़ में उदय योजना के माध्यम से 60 हजार करोड़ तो दिया, वहां उसमें लिया और बाकी हम उसको पूरा करेंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके मुंह से सच निकला कि पांच साल तक सच के अलावा झूठ नहीं बोली।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): हमारे अलवर जिले की बानसूर से आने वाली विधायक माननीय शकुन्तलाजी, यह जरूर सच में विश्वास करती हैं। मैं वह बातें नहीं कहूंगा जो पिछले बता गये कांग्रेस, बी.जे.पी. की। निश्चित इनका दिल भी देखता है। 21 फरवरी को जब हमारे विधायक दल की मीटिंग थी तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबको बुलाकर कहा और सारे विधायकों ने कहा, राजस्थान के जितने भी विधायक हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, किसानों के साथ गलत होगा, इस बिजली की बढ़ी हुई दर को वापस लिया जाएं।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने हमारे कहने से, संगठन के कहने से किसानों की

(श्री जयराम जाटव)

बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लिया।

आज बिजली की बात करते हैं, मैं जब 2003 से 2008 तक यहां राजस्थान विधान सभा में विधायक था, पर्याप्त बिजली किसान को मिलती थी। घर में बिजली मिलती थी, जिसको घरेलू बिजली कहा जाता है। मैं 2008 और 2013 के बीच में गांव में रहा, माननीय सभापति महोदय, एक मिनट बिजली घर की नहीं आती थी। पावर की बिजली चार घंटे से ज्यादा नहीं आती थी। बिजली का ट्रांसफार्मर किसान का फुकता था तो तीन महीने, ढाई महीने में मिलता था। अब 72 घंटे में भी ट्रांसफार्मर दिया जा रहा है। एक टेलीफोन कर दें, यह भी नहीं है। फुकने के बाद में जे.ईएन. बनाता था रिपोर्ट कि किसान का ट्रांसफार्मर, एप्लीकेशन देकर आए, जे.ईएन. उसकी पहले रिपोर्ट बनाए, तब देंगे, ऐसा अब नहीं है। अब तो सूचना मिलने के पश्चात सहायक अभियंता, बिजली बोर्ड का 24 घंटे में किसान को ट्रांसफार्मर देगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है यह? कितना बड़ा फायदा हुआ किसान को?

आज यह लोग कहते हैं रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, आप तुलना कर लीजिए। इस बजट की किताब को उठाकर देखिए और दिल में मनन करिए कि 109 पेज में ऐसा कोई पेज खाली नहीं है, जिसमें कुछ पैसा नहीं दिया हो। बजट खाली बजट की घोषणा नहीं है। मैं अख़बार पढ़ रहा था सुबह राजस्थान पत्रिका, मैंने उसमें देखा कि कांग्रेस का क्या उलटा, इस तरह का इन लोगों का कुछ नहीं लिखा। उसमें यहां के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह जनता को लुभावना बजट है। जनता तो लुभावनी है? उत्तर-प्रदेश में पता चल जाएगा 11 तारीख के बाद में, साइकिल के पीछे धक्का लगाओगे, बैठकर जाओगे, गिरोगे नीचे। निश्चित रूप से आज जनता देख रही है। राजस्थान विधान सभा में हम आते हैं। डिबेट करते हैं किसान के लिए, ओलावृष्टि के लिए तो यह वॉक-आउट करते हैं। बाहर जाते हैं। मीडिया के सामने 6 नम्बर गेट के बाहर जाकर सारे जितने चैनल्स हैं, उनके सामने खड़े होकर, हमने यह कह दिया, हमने वह कह दिया, हम इधर से लाए थे। कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं?

मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना, उसमें मैं अलवर जिले का रिकार्ड बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, नटनी के बारां से जयसमंद एक

(श्री जयराम जाटव)

हमारा बांध है, अलवर जिले में दो बांध है, एक जयसमंद और एक सिलीसेढ़। जयसमंद बांध में लगभग 12 साल से एक घूंट पानी नहीं था, एक बूंद पानी नहीं था बरसात का। माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

नटनी का बारा से जयसमन्द बांध के लिये हमको साढ़े तीन करोड़ रुपये दिये और उसके परिणाम यह हुए कि उसमें 17 फीट पानी आया। आज लगभग 50 गांवों की जमीन का जलस्तर ऊंचा हो गया है। आज बोरिंगों में पानी है। यह सब मुख्य मंत्रीजी की देन है। हमारे जिले के लिये 2003 में हम जब सत्ता में थे, हमारे प्रदेश की मुख्य मंत्री थीं तो अलवर जिले के लिये राजऋषि भर्तृहरि महाराज के नाम से मत्स्य यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई। पांच साल तक कांग्रेस के राज में रहे, यह लोग जमीन की व्यवस्था तक नहीं कर पाये। हमारे आने के बाद वर्ष 2015-16 में जमीन की व्यवस्था हुई और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वहां के लिये साढ़े तीन करोड़ रुपया दिया जिससे उस जमीन की चारदीवारी का निर्माण हुआ है। मैं प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने 50 करोड़ रुपये चार जिलों की यूनिवर्सिटी के भवन निर्माण के लिये दिये हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

आज गांव-गांव में पानी का जलस्तर बढ़ाने में किसानों ने मदद की। किसानों ने अपने ट्रैक्टर लगाये, जे.सी.बी. लगायी, कर्मचारी-अधिकारियों ने सहयोग किया, सारी फैक्ट्री वालों ने सहयोग किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन साथियों को भी, हम जैसे विधायकों के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के जितने कर्मचारी थे, उन्होंने अपना एक दिन का वेतन देकर मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन में सहयोग किया। आज जलस्तर बढ़ा है। पानी का लाभ हुआ है। बाकी बचे हुए जितने गांव हैं, शहर हैं, ढाणियां हैं, या उनकी जो बावड़ियां हैं, उनमें पानी किस तरह आये, पानी का जल स्तर कैसे बढ़े, इसके लिये निश्चित रूप से बाकी बचे हुए गांव इस बजट सत्र में जोड़े हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने। इसलिये मैं कहना चाहता हूं अगर राजस्थान के भले के लिये सोचा है, किसी ने किसान की और गांव के मजदूर की चिन्ता की है, तो वह श्रीमती वसुन्धराजी हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज गांव का व्यक्ति यह चिन्ता करता है कि हमको कैसे रोजगार मिले।

(श्री जयराम जाटव)

आज बजट पर जो मैं बातें यहां पर कह रहा हूं, यह बातें बाहर जा रही हैं। माननीय सभापतिजी, राजस्थान में एक लाख दस हजार के लगभग सरकारी नौकरियों के माध्यम से स्थायी रोजगार दिया गया, स्थायी नौकरी दी गयी। स्किल इंडिया के नाम से रोजगार कार्यालय के माध्यम से मेला लगाकर अलवर जिले में नीमराणा, भिवाड़ी, खुशखेड़ा, टपूकड़ा क्षेत्र में लगभग पांच लाख लोगों को तो रोजगार राजस्थान सरकार ने दिया है। अभी यहां पर परसों बिल आ रहा था, जो स्किल यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी, उसमें लोग कह रहे थे, कहां से खोलोगे, कैसे खोलोगे, किस तरह का रोजगार दोगे? शिक्षा में हमारे यहां इस तरह की व्यवस्था की जा रही है उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हमारा बच्चा पढ़कर ट्रेंड होकर, इस तरह की कला सीखकर आएगा, उन्हीं को रोजगार मिलेगा।

पिछली सरकार हमें कुछ नहीं दे पायी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट के माध्यम से निश्चित रूप से किसान, मजदूर, गरीब का भला होगा। गांवों में पहले सड़कें नहीं होती थीं। मैं अपने क्षेत्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक अलवर ग्रामीण से बना। मुझे एक भी सड़क साबुत नहीं मिली। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 20 किलोमीटर सड़कें, जिसको मिसिंग लिंक कहा जाता है, बहुत दूर-दूर गांव होते थे, लोग चक्कर लगाकर आते थे, उनको सीधा 20 किलोमीटर सड़कें दीं, जिनकी लागत पूरे राजस्थान में अगर हम आंकते हैं तो पांच साल इन लोगों ने जो राज किया, उस संख्या से, उस करोड़ों के बजट से हमारा चार गुना बजट ज्यादा है। यह मिसिंग लिंक की बात करते हैं, नोन पेचेबल की बात करते हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं आज सड़कों की बात करें, पानी की बात करें तो आज जहां फ्लोराइड पानी है, मेरे क्षेत्र में बहुत आर.ओ. प्लांट लगे, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद मैं ही नहीं दे रहा हूं, बल्कि वहां गांव का व्यक्ति दे रहा है, जो कुबड़े हो गये थे, जिनके दांत पीले पड़ गये थे, जिनको बीमारियां हो गयी थीं। वह लोग आज धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसी भली मुख्य मंत्री, जिन्होंने हमारे गांव की सुध ली। चाहे सड़कों का मामला हो, ग्रामीण गौरव पथ का हो, रोजगार का हो, मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री जयराम जाटव)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

साथियों, राजस्थान की तीन साल की कल्याणकारी सरकार इसे इसलिये कहा जाता है, मैं पांच-छह उदाहरण देना चाहता हूं। तीन वर्षों में सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता, जो गोल्ड ट्रॉफी प्राप्त हुई, सर्वश्रेष्ठ इनाम, राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स कांफ्रेंस में ई-गवर्नेंस स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, भामाशाह परियोजना को मैरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ, राजधारा जी.आई.एस., अभी हाल में उत्कृष्ट राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ, अनुसूचित जाति, जनजाति विकास सहकारी निगम को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, कृषि कर्मठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, छठा 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह छह पुरस्कार राजस्थान की सरकार को भारत सरकार ने उत्कृष्ट होने पर दिया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी कोई ज्यादा तैयारी नहीं थी, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के, कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी। जो साथी रह गये, उसके लिये मैं सहयोग करूंगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री भंवर सिंह।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा 08 मार्च, 2017 को रखे गये बजट के वाद-विवाद के अवसर पर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा बजट के बारे में काफी सराहना की गयी। सभापति महोदय, 2013 में राजस्थान की एक लाइफ-लाइन कहे जाने वाले प्रोजैक्ट रिफाइनरी का मैं जिक्र करना चाहूंगा। कांग्रेस सरकार के प्रयासों से, हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से केन्द्र सरकार के द्वारा बाड़मेर में रिफाइनरी प्रोजैक्ट मंजूर किया गया और उसका शिलान्यास भी हुआ। परन्तु काम जब शुरू होने की स्थिति में आया तो उस समय आपकी सरकार बनी और उसके बाद पिछले तीन-साढ़े तीन सालों से रिफाइनरी का जो प्रोजैक्ट था, वह राजस्थान का एक ड्रीम प्रोजैक्ट था और यदि वह चालू होता तो मैं समझता हूं कि राजस्थान को रॉयल्टी के रूप में सरकार का जितना बजट अभी वर्तमान में है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उस रिफाइनरी के माध्यम से मिलता।

(श्री भंवरसिंह)

लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद में उस रिफाइनरी के बजट को जान-बूझकर एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसका खामियाजा आज पूरे राजस्थान के आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है।

सुराज संकल्प पत्र की यदि हम बात करें तो आपने राजस्थान के जो नौजवान थे, युवा थे, उनसे 15 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पिछले तीन सालों में मैं समझता हूं कि बहुत ही कम नाम मात्र की नौकरियां दी गयी हैं। इस बजट में भी 5500 कांस्टेबलों की भर्ती करने की घोषणा की गयी है, 900 पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद भरने का कहा गया है और 4 हजार पशुधन सहायक भर्ती करने का इस बजट में कहा गया है। पिछले तीन सालों में मैं समझता हूं कि लगभग एक लाख के करीब नौकरियां निकाली गयीं, लेकिन बहुत ही कम उसमें नियुक्तियां हो पायी हैं। एस.बी.सी. के आरक्षण का जो निर्णय या सरकार की जो इच्छा शक्ति थी, वह नहीं होने की वजह से 68 हजार के करीब नौकरियां आज भी कोर्टों में अटकी हुई हैं।

(16.00 बजे)

कृषि उपज मंडियों में चतुर्थ श्रेणी के पद भरने का एक लम्बा अभियान चला और लोगों को मशक्कत करने के बाद हमारे बेरोजगार लम्बे समय तक इन्टरव्यू देते रहे लेकिन उस भर्ती में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ, उसमें बहुत सारी कमियां रखी गयीं जिसकी वजह से वो भर्ती भी आज अटकी हुई पड़ी हैं।

वर्ष 2013 में पंचायती राज के करीब 25 हजार पदों पर भर्तियां निकाली गयी थीं और उसमें से 7600 पदों पर एल.डी.सी. की भर्ती कर दी गयी थी और उसके बाद हाई कोर्ट का यह निर्णय हो गया था कि उन पदों को बोनस अंकों का सही निर्णय नहीं हुआ था और भर्ती का स्टे आ गया था। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी और सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले दिनों निर्णय हो गया और जिस प्रकार से भर्ती शुरू में निकाली गयी थी उसके अनुसार भर्ती करने का आदेश भी दे दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की इन बेरोजगारों को, जो पिछले तीन-चार सालों से लगातार पंचायती राज विभाग में जो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी हैं उनको एडजस्ट करने की,

(श्री भंवरसिंह)

उनको नौकरी देने की मंशा नहीं लगती है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद वो नौकरियां आज तक सरकार ने लटका रखी है।

चाहे 25 हजार विद्यार्थी मित्रों को आपकी सरकार बनने के बाद नौकरी से निकालने की बात हो, इन विद्यार्थी मित्रों को सात साल पहले लगाया गया और बहुत ही कम मानदेय पर इन लोगों ने काम किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहले इन 24 हजार विद्यार्थी मित्रों को घर का रास्ता दिखाने का काम किया। जब पूरे प्रदेश में इन विद्यार्थी मित्रों का मुद्दा उठा और पूरे सदन में यह आवाज आयी कि नहीं, इन विद्यार्थी मित्रों के साथ अन्याय हुआ है तो फिर एक विद्यालय सहायक के नाम का शगूफा छोड़ा गया और वो विद्यालय सहायक के पदों की भर्ती भी कोर्ट में अटक गयी।

उसके बाद अभी हाल ही में ग्राम पंचायत सहायक के नाम पर भर्ती निकाली गयी। लेकिन सभापति महोदय, इस प्रकार बिना नियमों के, ना जिसमें कोई दिशा-निर्देश हैं, न कोई गाइड लाइन है, इस तरह की भर्ती निकाली गयी, उसका जिम्मा पूरा का पूरा एस.डी.एम.सी. कमेटी को दिया गया और मैं कह सकता हूं एक दिशाहीन भर्ती थी। उसमें न तो विद्यार्थी मित्रों का कोई समायोजन करने का निर्देश था, न ही जो हर पंचायत में दो या तीन कर्मचारी लिये जाने हैं उनको भर्ती करने के लिए कोई गाइड लाइन तय की गयी। मैं समझता हूं कि इन विद्यार्थी मित्रों के साथ साढ़े तीन सालों में अभी तक सरकार एक छलावा कर रही है, एक मजाक के अलावा इनके साथ कुछ नहीं किया गया है।

स्कूल व्याख्याता जो 2013 में चयनित हुए थे, वो भी आज बीकानेर डाइरेक्ट्रेट में धरने पर बैठे हुए हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी उनको अभी तक पोस्टिंग देने की सरकार की मंशा मुझे नहीं लगती है।

सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग में हमारी सरकार ने एएनएम के, जीएनएम के जो पद खाली थे उन पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली थी। उसमें सारी प्रक्रिया होने के बावजूद जितने पद उस समय स्वीकृत थे उनमें से आधे से भी कम पदों को भरा गया और अधिकांश जो योग्यता रखने वाले एएनएम, जीएनएम या नर्सिंग पैरा-मैडिकल स्टॉफ के लोग हैं, या जो

(श्री भंवरसिंह)

संविदा पर लगे हुए हमारे कर्मचारी हैं, उस भर्ती को भी आज तक लटका कर के रखा गया है।

सभापति महोदय, सरकार के घोषणा पत्र में सुराज संकल्प पत्र में यह साफ-साफ लिखा गया था कि हम पांच सालों में 15 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। आपका चौथा साल शुरू हो गया है लेकिन सभापति महोदय, राजस्थान के बेरोजगार आज अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अच्छे दिन आने की बात पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर, उनके विश्वास पर, राजस्थान की जनता ने एक प्रचण्ड बहुमत से आपकी सरकार बनायी थी लेकिन सबसे बड़ा यदि विश्वासघात इस सरकार ने किया है तो वो राजस्थान के बेरोजगारों के साथ किया है।

चाहे आपके घोषणा पत्र में राजस्थान के हर उपखण्ड मुख्यालय पर सरकारी महाविद्यालय खोलने की घोषणा हो, चाहे हर उपखण्ड पर आई.टी.आई. खोलने का मुद्दा हो, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार के जो वायदे थे उन वायदों पर सरकार आज भी अमल नहीं कर पा रही है। उलटा जो 43 राजकीय महाविद्यालय हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा खोल गये थे, उनमें प्रिंसिपल लगा दिये गये, सिर्फ कालेज चालू होना बाकी थे, लेकिन राजनीतिक द्वेषता की वजह से उनमें से अधिकांश कॉलेजों को बंद कर दिया गया। उसमें हमारे बीकानेर जिले के और मेरे विधान सभा क्षेत्र कोलायत और डूंगरगढ़ का महाविद्यालय भी शामिल है।

सभापति महोदय, हमारे बारबार निवेदन करने के बावजूद प्रतिपक्ष के जो विधायक हैं, हालांकि सरकार बनने के बाद सरकार का यह कर्तव्य होता है कि पूरे सदन की नेता, पूरे सदन की सरकार होती है लेकिन चाहे हमारे महाविद्यालयों की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, उसमें पूरी तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है।

सड़कों की स्थिति, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो सड़कें हैं उनमें आज से तीन साल पहले जिस प्रकार की सड़कों की स्थिति थी, जो बजट पेचवर्क के लिए दिया जाता था, सभापति महोदय, आज राजस्थान की सड़कों में पेचवर्क के लिए भी बजट नहीं दिया जा रहा है।

(श्री भंवरसिंह)

नोन-पेचेबल सड़कें, जो राजस्थान में 20 हजार किलोमीटर से भी ज्यादा है उनका बजट मात्र हर साल दो हजार किलोमीटर, प्रति विधान सभा क्षेत्र दस किलोमीटर सड़क दिया जा रहा है। सभापति महोदय, मेरे अकेले विधान सभा क्षेत्र में 500 किलोमीटर की नोन-पेचेबल सड़कें हैं और उसमें एक साल में यदि दस किलोमीटर नोन-पेचेबल सड़क का बजट दिया जाता है तो मैं समझता हूं राजस्थान की सड़कों की स्थिति आने वाले पांच सालों में क्या हो जाएगी?

बजट घोषणा की यदि हम बात करें तो आपकी सरकार के पहले बजट में यह घोषणा की गयी थी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की जो टूटी हुई 476 किलोमीटर की करीब 98 सड़कें हैं, उन सड़कों का हम आने वाले सालों में, पहले बजट में यह घोषणा की गयी थी कि हम इनका नवीनीकरण करेंगे, हम इनका सुदृढ़ीकरण करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि बजट की घोषणाएं भी सिर्फ और सिर्फ कागजी घोषणाएं रह गयी हैं। सभापति महोदय, इन तीन सालों में आई.जी.एन.पी. क्षेत्र की 98 सड़कों की मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गयी थी, एक भी सड़क के ऊपर एक भी पैसा आज तक नहीं लगाया गया है।

एम.डी.आर. और स्टेट हाइवेज की स्थिति भी इतनी ही खराब हैं। जो सड़कें हैं, मैं बताना चाहूंगा कि अभी बजट में मात्र 15 सड़कों की घोषणा की गयी है स्टेट हाइवेज की। आपके द्वारा यह कहा गया था कि हम राजस्थान स्टेट हाइवे ऑथोरिटी का गठन करेंगे और उसके बाद राजस्थान के जितने भी स्टेट हाइवे हैं उन तमाम स्टेट हाइवेज का रिनुअल करेंगे, उन सबको ठीक करेंगे। राजस्थान में स्टेट हाइवेज की संख्या बहुत ज्यादा है और सिर्फ 15 स्टेट हाइवेज की सड़कों को ठीक करने की घोषणा वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गयी है। मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि बीकानेर जिले में जितने भी स्टेट हाइवेज हैं, आपके इस बजट में बीकानेर जिले के एक भी स्टेट हाइवे का रिन्युवल करने नवीनीकरण करने की कोई घोषणा नहीं की गयी है।

इसके साथ-साथ खनिज क्षेत्रों में डेढ़ सौ करोड़ रुपये का पिछले साल प्रावधान किया गया, पांच सौ करोड़ रुपये का इस साल प्रावधान किया गया

(श्री भंवरसिंह)

है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा खनिज से रॉयल्टी प्राप्त होती है उसमें बीकानेर जिले का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन बीकानेर जिले में डेढ़ सौ करोड़ में से एक रुपया भी खनिज क्षेत्र की सड़कों को ठीक करने के लिए नहीं दिया गया है।

यदि हम बजट घोषणाओं की बात करें तो 2015-16 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तीन सड़कें बीकानेर जिले में नई सड़कें बनाने की घोषणा की गयी थी उसमें डूंगरगढ़-सरदारशहर-राजगढ़-159 किलोमीटर, श्रीगंगानगर-रायसिंहनगर-बीकानेर-227 किलोमीटर, सीकर-लाड़नू-नौखा-200 किलोमीटर, लेकिन इन सड़कों पर अभी तक एक रुपया खर्च नहीं किया गया है और न ही वहां कोई काम शुरू किया गया है।

सभापति महोदय, परिवहन के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो लोक परिवहन की बसों को शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन यह कहा गया था कि हम लोक परिवहन में नए रूट खोलेंगे और जो बस अड्डे हैं उनमें बस टर्मिनल बनाएंगे। उन बसों का संचालन भी बस टर्मिनलों, जो रोडवेज के बस अड्डे हैं, वहां से करेंगे। आज स्थिति यह है कि लोगों ने परमिट ले लिये और वह लोक परिहवन की बसें चल जरूर रही हैं लेकिन वह अपना टैक्स भी नहीं निकाल पा रही हैं। सरकार ने पूरी तरह से अपना हाथ लोक परिवहन की बसों से खींच लिया है। आज लोक परिवहन की कई बसों के परमिट सरेंडर कर दिए गये हैं। मैं समझता हूं कि यह सेवा जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं हरी झंडी दिखाकर किया था, आने वाले समय में बंद होने के कगार पर है।

सभापति महोदय, अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी मुख्यमंत्री जी ने बिजली की दरें घटाईं। मैं कहना चाहूंगा कि बिजली की दरें सितम्बर, 2016 में बढ़ाई गई। बिना सोचे-समझे एक कदम राजस्थान के आम जन और किसानों के खिलाफ उठाया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं पांच मिनट का समय और लेना चाहूंगा।

श्री सभापति: समय की भी मर्यादा है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: आपका समय हो गया। दो-तीन मिनट ऊपर हो गए। प्लीज, विराजें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, कुछ विशेष बाते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): देवीसिंह जी को हराकर आए हैं, दो-तीन मिनट तो एक्सट्रा चाहिए।

श्री सभापति: कोई यहां पर विशिष्ट नहीं होता।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सभापति महोदय, सामने जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, वह वाहवाही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि जरूरत क्या थी बिजली की दरें बढ़ाने की? राजस्थान में घरेलू बिजली की दरें बढ़ा दी गयी। राजस्थान में किसानों की बिजली की दरें बढ़ा दी गयी? जब 10 फरवरी को बीकानेर में महापड़ाव हुआ और उसमें सरकार के प्रभारी मंत्री, सरकार के सीएमडी, सरकार के चेयरमैन, सरकार के एमडी जाते हैं .....

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सरकार को बीकानेर में आना पडा और किसानों के आगे झुककर के घोषणा करनी पड़ी कि हमने जो कहा था, जो योजना हम 5 साल में पूरी करने वाले थे, किसानों के दबाव में सरकार झुकी और निर्णय वहां लिया।

उसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि चाहे लोड कम करने की बात हो, चाहे सिंगल फेस की घरेलू बिजली बढ़ाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर सहमति वहां बनी। हमारे माननीय विधायक कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को हमने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। जनता के दबाव में किया। गलत लिया हुआ निर्णय था।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। कृपया समाप्त करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय सभापति महोदय, सरकार की झूठी वाहवाही करने वाले जो लोग हैं, उनको आप इतना समय दे रहे हैं। सरकार की जो कमियां रही, जो राजस्थान का आम आदमी सोचता है कि बजट में क्या मिलना चाहिए था, वह तमाम मुद्दे हम आपके सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन आपने समय सीमा लगा दी है।

सभापति महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यह बजट सिर्फ और सिर्फ असत्य का पुलिंदा है। इस बजट में राजस्थान के आम आदमी को कुछ नहीं मिला है। चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के हर वर्ग को ठगने का काम इस बजट में किया गया है। मैं इस बजट की पूरी निंदा करना चाहूंगा।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आज सदन के सभी माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने 2017-18 का जो बजट पेश किया है, उसके वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया का इस बात के लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त करुंगा कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में यह बजट पेश किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने कुप्रबंधन के आधार पर प्रदेश को ऐसी परिस्थितियों में छोड़ा था, जिनसे निकालना भी मुश्किल था। सभापति महोदय, ऐसी परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने प्रदेश का कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, जिसका ध्यान नहीं रखा हो।

सभापति महोदय, मैं शुरूआत कृषि क्षेत्र से करुंगा। कृषि क्षेत्र के लिए जिस तरह से इस बजट में घोषणाएं की गयी हैं, वह गरीब आदमी को केन्द्र बिन्दु में रखकर की गयी हैं। पिछले 3 सालों में कृषि के क्षेत्र में जो विकास हुए, जो काम हुए, वह भी प्रदेश की जनता के सामने हैं।

सभापति महोदय, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का परीक्षण तो कराता है, लेकिन वर्षों से हम परंपरागत खेती पर चले आ रहे थे। उस परंपरागत खेती को तकनीकी रूप से बदलने के लिए राजस्थान की धरा पर पहली बार यह लगने लगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, आप देखो, मंत्रीजी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

को यह एहसास नहीं है कि माननीय सदस्य रामलाल जी बोल रहे हैं, आप विराजमान हैं और आपके बीच में से निकलकर, आकर के बैठे हैं।

श्री सभापति: सही बात है। मंत्री जी, कृपया ध्यान रखें। नियमों की पालना करें। सख्त चेतावनी दी जाती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दो घंटे जाकर सो जाते हैं, फिर नींद में आते हैं और यहां आकर के बैठ जाते हैं। अपनी जगह पर आओ।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई नहीं सोता। गलत बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप सोते हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, कतई नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अभी उठकर आए हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं। अभी डाक्टर्स की हड़ताल चल रही है। उनसे वार्ता करके आया हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपनी जगह पर आइए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गलत बात मत करिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपने स्थान से बोलिए, मंत्री जी।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, अपने स्थान पर जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अपने स्थान से बोलिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। मंत्री जी, कृपया अपने स्थान पर विराजें और वहां से बोलें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं बता रहा था कि सबसे पहले राजस्थान में एक ग्लोबल एग्रो मीट का आयोजन हुआ। इस मीट का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि राजस्थान के किसानों के हितों को हम आधुनिक तकनीक के आधार पर किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। राजस्थान का जल स्तर दिन प्रति दिन गिरता जा रहा है, कम पानी से हम अधिक पैदावार कैसे कर सकते हैं? परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक

(श्री रामलाल शर्मा)

तकनीकी पर हम कैसे आ सकते हैं?

सभापति महोदय, राजस्थान में सबसे पहला जो परिवर्तन का दौर शुरू हुआ, वह 19 फरवरी, 2015 को शुरू हुआ। जब राजस्थान की धरती से, राजस्थान में सोइल हैल्थ कार्ड योजना शुरू की गयी। इस योजना में अब तक लगभग 29 लाख कार्ड किसानों को वितरित किए गये। किसानों की जो जमीन है, उसकी उर्वरक क्षमता को देखते हुए उसके अंदर कौनसी पैदावार हो सकती है और कौनसे तत्व की कमी है, उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं?

सभापति महोदय, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगभग 53 लाख कृषकों का बीमा किया गया है। यह खरीफ में किया गया। रबी की फसल में लगभग 30 लाख किसानों का बीमा किया गया।

सभापति महोदय, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुन्धरा जी ने 1 लाख कृषि कनेक्शन देने की घोषणा भी की। यह कृषि कनेक्शन आने वाले समय में किसानों के भविष्य को संवारने वाले साबित होंगे।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आपने भी देखा होगा, आपके जिले के अंदर भी और कई बार आपके पड़ौसी जिले बाड़मेर से भी खबरें आती थी कि जब किसान खाद लेने के लिए जाता था तो लंबी-लंबी लाइनें लगती थी। वहां 2-4 घंटे लगने के बाद भी उसको खाद नहीं मिलता था। कई बार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अपना काम भी करती थी। इस सरकार ने पहली बार किसानों के हितों को संरक्षित करते हुए डीएपी और यूरिया का भंडारण करने की व्यवस्था की। इतना ही नहीं किया, इस भंडारण के लिए 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की गयी।

सभापति महोदय, आपने इस बजट में देखा होगा कि यह मात्र घोषणा ही नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार जिस तरह से घोषणाएं करके चली जाती थी, इस बजट में घोषणाओं के साथ-साथ बजट का प्रावधान भी किया गया।

सभापति महोदय, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ड्रिप इर्रिगेशन में भी 5 प्रतिशत अनुदान बढ़ाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री

(श्री रामलाल शर्मा)
महोदय ने की है। 2003-08 में जब विधान सभा का मैं सदस्य था, सीकर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि किसानों को नकली बीज मिलने की वजह से उनकी फसल चौपट हो चुकी है। उस समय उन्होंने मुआवजे की मांग की थी। वास्तविकता भी यही है कि होता भी यही था। कई बाहर की कंपनियां आतीं, बीज तैयार करतीं, बीज किसानों को देतीं और उस बीज को खेतों में डालने के बाद जब वह विकसित नहीं होता, अंकुरित नहीं होता

तो किसान को निराशा हाथ लगती थी। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू करने की घोषणा की, यह किसानों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। जिसके अंदर गेहूं, ग्वार, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, और उड़द की फसलों के बीज उत्पादन करने का काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 1180 किसान सेवा केन्द्र ऐसे हैं जिनमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पहली बार पांच करोड़ चालीस लाख रुपये, जिसमें बिजली है, पानी है, फर्नीचर है, इन सबकी व्यवस्था करने की घोषणा भी की है। कृषि विभाग के लिए तीन हजार एक सौ पचास करोड़ इकसठ लाख रुपये के बजट का प्रावधान भी रखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि विगत सरकार ने किसानों के हित में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से किसान इनके प्रति सहानुभूति रखे। बिजली के मामले में सभापति महोदय, आप सबको पता है कि किस तरीके से वर्ष 2000 में अलग-अलग कम्पनियों के अंदर, बिजली कम्पनी को बांटा गया और उस समय तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा था कि तीन हजार करोड़ का घाटा हम विभाग के ऊपर नहीं छोड़ सकते, वहन नहीं कर सकते इसलिए कम्पनियां बनाना जरूरी है। आज उस घाटे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के अवाम के ऊपर उसे डाला गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पशु पालन के क्षेत्र में भी इस बजट के अंदर एक घोषणा की गयी

(श्री रामलाल शर्मा)

और अविका कवच योजना प्रारम्भ दुबारा से की गयी। अस्सी परसेंट जो प्रीमियम की राशि है वह सरकार वहन करेगी। एससी, एसटी, बीपीएल के लिए और जनरल के लिए 70 परसेंट की जो सहायता राशि है जो बीमा की किश्त की राशि है वह भी सरकार द्वारा वहन करने की बात कही गयी है। निश्चित रूप से से यह किसानों का कायाकल्प करने की बात है।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन के क्षेत्र में जिस तरीके से विगत वर्ष के अंदर भी लगभग एक हजार छह सौ सब सेंटर खोले गये और पहली बार मुख्य मंत्री महोदया ने यह घोषणा की कि आने वाले वर्षों के अंदर एक भी ग्राम पंचायत ऐसी नहीं रहेगी जहां पर कोई सब सेंटर नहीं हो। योजना बनाकर बिना किसी भेदभाव के, चाहे किसी भी विधान सभा क्षेत्र से कोई भी विचारधारा का माननीय सदस्य हो लेकिन उसके साथ भी कोई अहित नहीं हो और राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन सबके अंदर पशु केन्द्र खोलने की बात कही गयी है। जो पंचायत समिति वंचित हैं उनमें और जो तहसील मुख्यालय वंचित हैं, वहां पर भी पशु चिकित्सालय खोलने की बात की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व में भी कहा है, मात्र बजट के अंदर ही घोषणाएं नहीं की गयी है, उनके बजट का प्रावधान भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इसी तरीके से आने वाले समय में दो सौ पशु चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण के लिए 49 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी हुई। रोजगार जनरेट करने के लिए 900 चिकित्सा अधिकारी और 4000 पशु धन सहायकों की भर्ती की घोषणा भी इस बजट में की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, बात इतनी ही नहीं है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महिला दिवस के दिन बजट रखा और दिन को विशेष करने के लिए जैसा कि 2017-18 के अंदर नवीन महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खोलने की बात भी कही गयी है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारिता के क्षेत्र में भी किसानों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए 370 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। साथ में सहकारी बैंकों को अनुदान की राशि देने के लिए 150 करोड़

(श्री रामलाल शर्मा)

रुपये दिए गये और 2 प्रतिशत ब्याज के अंदर अनुदान था उसको भी निरंतर जारी रखने का काम हुआ। आज यदि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मजबूत नहीं करेंगे, कांग्रेस कहती थी कि 'एक सबके लिए, सब एक के लिए' लेकिन इन्होंने उस नारे को कभी चरितार्थ करने का काम नहीं किया। वर्तमान सरकार ने सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए दस करोड़ रुपये और क्रय विक्रय सहकारी समितियों के गोदाम बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के किसान जब इन जीएसएस और क्रय विक्रय सहकारी समितियों के भवन बनेंगे तो उसका लाभ भी वे निश्चित रूप से उठाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विवेक के आधार पर, अपनी-अपनी समझ के आधार पर कई बातें कहीं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि 13 हजार विद्यालयों को बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पदोन्नति करके आपने पदों को समायोजित करने का काम कर दिया। लेकिन माननीय सभापति महोदय, वास्तविकता से यह बहुत दूर है। माननीय सभापति महोदय, यह कहां का न्याय है कि एक विद्यालय जिसमें छात्र संख्या है लेकिन पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है और एक विद्यालय ऐसा है जहां पर पढ़ने के लिए कोई छात्र नहीं है लेकिन पढ़ाने के लिए वहां टीचर पांच-पांच, सात-सात लगे हुए हैं। सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया कि जिन विद्यालयों के अंदर छात्र संख्या है वहां शिक्षक पहुंचे। इनके राज में राजनीतिक आधार के ऊपर डेपुटेशन इन्होंने असंख्य रूप से कर रखे थे अपने चहेतों को लाभ देने के लिए, अपने कार्यकर्ता इन लोगों ने बना रखे थे, वास्तविकता यह है माननीय सभापति महोदय, विद्यालयों का एकीकरण और समानीकरण की वजह से, इस स्टाफिंग पैटर्न की वजह से आज पूरे प्रदेश के विद्यालयों के अंदर शिक्षक पहुंचने लगे हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र की जनता का विश्वास भी इसके अंदर बना है। आए दिन जिस प्रकार की शिक्षकों के अभाव में जो हड़ताल हुआ करती थी, ताले बंदी हुआ करती थी और लोग सड़कों पर आ जाते थे, माननीय सभापति महोदय, यह होने के बाद में आज प्रदेश के अंदर ऐसी

(श्री रामलाल शर्मा)

कोई घटना या कोई भी अख़बार के अंदर पढ़ने को नहीं मिलता कि किसी जिले में या किसी तहसील के अंदर शिक्षकों के अभाव के अंदर लोग सड़कों पर आए हों। इनकी सरकार की यदि मैं बात करूं तो 54 प्रतिशत पद रिक्त थे, आज वह परसेंट घटकर 24 परसेंट पर आ गये और माननीय सभापति महोदय, जब यह भर्तियां पूरी हो जाएंगी, आज न्यायालय के अंदर मामले विचारार्थ रहने के कारण भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। जिस दिन यह भर्तियां कम्पलीट होगी तो मेरा यह मानना है कि यह संख्या घटकर 11 परसेंट तक आ जाएगी। इनके कार्यकाल के अंदर 54 परसेंट पद रिक्त थे, आज वह घटकर 11 परसेंट पर आ जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा। विद्‌यालयों के एकीकरण, समानीकरण और स्टाफिंग पैटर्न की वजह से आज विद्‌यालयों के नामांकन के अंदर 32 परसेंट वृद्‌धि हुई है। माननीय सभापति महोदय, लोगों का विश्वास बना है तो ही यह वृद्‌धि हो रही है, अगर लोगों को विश्वास नहीं होता तो यह वृद्‌धि कैसे होती? आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक जो घोषणा की है उसकी सभी माननीय सदस्य तारीफ कर रहे हैं कि जिन विद्‌यालयों के अंदर नियमानुसार छात्र संख्या है, उस छात्र संख्या के आधार पर विद्‌यालयों का क्रमोन्नयन और उस क्रमोन्नयन के बाद में वहां की जो छात्र संख्या है उसके आधार पर सब्जैक्ट खोलना। इस बात के ऊपर अगर पूर्ववर्ती सरकार को देखें तो राजनीतिक द्‌वेषता के आधार पर चलते, विद्‌यालयों को संचालित करने का काम करते थे।

माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश के अंदर 772 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर 40 से अधिक विद्‌यार्थी हैं और उन विद्‌यालयों को भी क्रमोन्नत करने की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है। मैं यह मानता हूं कि आने वाले समय में इस बजट का प्रभाव धरातल पर देखने को मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने भी अपने विधान सभा क्षेत्र में देखा होगा, विद्‌यालय में जो पोषाहार बनाने का काम करती थी मिड डे मील के अंदर, वास्तविकता है कि उस महिला के दर्द की कहानी आप भी यदि सुनते थे तो आपके मन में भी आता था कि इनका मानदेय

(श्री रामलाल शर्मा)

बढ़ाना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा इस अवसर पर माननीय सभापति महोदय, 200 रुपये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मानदेय वृद्धि की बात कही है लेकिन जैसा माननीय सदस्य भी कह रहे हैं कि 200 रुपये बहुत कम है तो आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इसको बढ़ाकर कम से कम 1500 रुपये किया जाएं ताकि यदि 500 रुपये की मानदेय में वृद्धि होती है तो सम्मानजनक उस महिला के पालन पोषण के लिए ठीक रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से थोड़ा सा तुलनात्मक आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन में माध्यमिक विद्यालय थे, इन्होंने आजादी से लेकर अब तक 70 साल के इतिहास में सिर्फ 4435 विद्यालय क्रमोन्नत करने का काम किया जिनको हम सीनियर कहते हैं। गत तीन वर्षों में अपनी सरकार आने के बाद में 9435 विद्यालय जिसमें एक साथ 5 हजार विद्यालयों को क्रमोन्नत किया। आज यह संख्या 9000 के आसपास है। माननीय सभापति महोदय, बालिका छात्रावास गत तीन सालों में 153 खोलने का काम हुआ। अनुकंपा नियुक्ति, जहां ये कहते हैं कि हम आम आदमी की भावनाओं के आधार पर काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि इनके पांच साल के कार्यकाल में सिर्फ 962 को अनुकंपा नियुक्ति दी गयी जबकि हमारी सरकार ने 2821 को अनुकंपा नियुक्ति दी। महिला कार्मिक नियुक्ति इनके शासन में सिर्फ 338 हुईं, 3 सालों में वर्तमान सरकार ने 4750 को दी।

माननीय सभापति महोदय, प्रधानाचार्यों की पदोन्नति, इनके शासन काल में मात्र 2148 और गत 3 सालों के अंदर 10978 प्रधानाचार्यों को पदोन्नति दी गयी। इसी तरह माननीय सभापति महोदय, लिस्ट लंबी है, चाहे व्याख्याताओं की पदोन्नति हो, चाहे शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे प्रधानाचार्यों के रिक्त पद की बात हो,

मैं यह मानता हूं जहां बालिका शिक्षा की बात करते थे, आज बालिका शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गार्गी पुरस्कार, इनके 5 साल के शासन में सिर्फ 68530 गार्गी पुरस्कार दिये गये और आज तीन सालों के अंदर एक लाख से अधिक बच्चियों को गार्गी पुरस्कार दिये गये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, थोड़ा सा समय और लूंगा। सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन

(श्री रामलाल शर्मा)

है, काफी समय से यह मांग चली आ रही थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने इसके अंदर जस्ट दुगुनी विधवा पेंशन की है 500 से बढ़ाकर 1000 तथा 750 से बढ़ाकर 1500 रुपये की है निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है।

सभापति महोदय, हमेशा कांग्रेस ने वर्ग संघर्ष कराने का काम किया है, लोगों को उकसाने का काम किया है, समस्या का समाधान करने का काम नहीं किया। हमेशा मुद्दा जीवित रहे यह काम कांग्रेस करती आयी है। लोगों को बांटकर, अशिक्षित रखकर उनका वोट बैंक बना रहे इसी मानसिकता और विचार के साथ काम करते थे। मैं धन्यवाद दूंगा, कई माननीय सदस्य भी आर्थिक आधार पर लोगों के हित को संरक्षित करने की बात कहते थे। इस बजट के अंदर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया ने भी आर्थिक आधार पर जो पिछड़े हुए लोग थे, जो पढ़ना चाहते थे, जिनमें बुद्धि और विवेक की कोई कमी नहीं थी, आर्थिक रूप से जिनको संबल प्रदान करने की बात कही गयी है निश्चित रूप से इससे आने वाले समय के अंदर उस गरीब आदमी को मदद मिलेगी। मैं उन चीजों को कोट नहीं करना चाहता जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने की हैं कि 90 परसेंट से अधिक अंक दसवीं में लाने पर छात्राओं को 100 स्कूटी, बारहवीं में कला, विज्ञान, वाणिज्य में 100-100 कुल 300 स्कूटी दी है। मैं यह कह सकता हूं कि इस बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने जो राजस्थान की 36 कौम है उन 36 कौमों को साथ लेकर चलने का संकल्प दोहराया है।

सभापति महोदय, अंत में आपके माध्यम से मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज प्रदेश के अंदर यशोदाएं हैं, इन यशादाओं के लिए उदार मन रखकर इनके मानदेय में थोड़ी वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी का जो नारा है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: बंद करो माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): दो मिनट। सभापति महोदय, आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इनके मानदेय में थोड़ी वृद्धि हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र की दो मांग आपके सामने रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। 6 हजार विद्यार्थी मेरे यहां कालाडेरा कालेज के अंदर अध्ययनरत हैं। ये पूरे के

(श्री रामलाल शर्मा)

पूरे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। कालाडेरा कालेज के अंदर अगर रसायनशास्त्र में पीजी होती है तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा।

एक अंतिम मांग और रखना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर चार ग्राम पंचायतें हैं हस्तेड़ा, आस्टी, किशनमानपुरा और नांगल गोविन्द। पड़ौस के अंदर फुलेरा विधान सभा क्षेत्र है, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतें बीसलपुर से जुड़ चुकी हैं। इन चारों ग्राम पंचायतों के अंदर भी फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो चुकी है। मैं चाहता हूं आने वाले समय में ये चारों ग्राम पंचायतें बीसलपुर योजना से जुड़ें ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य सूर्यकान्ता जी व्यास।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतना जबर्दस्त बजट दिया है सबका विकास, सबका काम। मैं उनके समर्थन में कहना चाहती हूं राजस्थान के विकास के लिए एक विजनरी योजना लेकर लगातार चलने का संकल्प लेकर राजस्थान में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार लगातार ठोस कार्य कर रही है। लगातार तीसरे बजट में राजस्थान के विकास की ठोस योजना का यह विजन आकार लेता दिखने लगा है। इस बजट में हमारे प्रदेश की हवाई सेवाओं को सुधारने के प्रावधान हैं तो दूसरी ओर स्मार्ट गांव विकास का इरादा है। डिजिटल क्रान्ति को प्रदेश के हर कोने में पहुंचाने की आधुनिक सोच है तो सनातन श्रद्धा केन्द्र बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी, काशी, वृन्दावन धाम दर्शन को जाने वाले राजस्थानियों की सुगम तीर्थयात्रा की व्यवस्था भी है।

माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के स्किल डवलपमेंट के स्वप्न को साकार करने में राजस्थान की प्रदेश सरकार सबसे आगे है। इस वर्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर में उद्यमिता शिक्षण केन्द्र की घोषणा इसी प्रयास को और गति देगी।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

राजस्थान की वीर प्रसूता धरा महाराणा कुम्भा, महाराणा प्रताप, मीराबाई, पन्नाधाय, सागरमल गोपा की भूमि है। इस भूमि की स्वास्थ्य जांच कर किसान इससे अधिकतम पैदावार कम से कम खाद में कैसे ले सके इसके लिए एक लाख किसानों को मिनीकिट के वितरण की घोषणा किसान हितैषी विजन प्रकट करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूं कि उन्होंने खेलों का महत्व व्यक्तित्व विकास से लेकर देश के गौरव से जोड़ा है। हमारी सरकार खेल सुविधाओं के विकास के लिए तत्पर है। जोधपुर में इंडोर गेम्स के लिए विशेष प्रावधानों के लिए मैं जोधपुर के खेल प्रेमियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्रीजी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मुझे टोकना नहीं, मैं अपने आप ही जितना बोलना है उतना बोलकर बंद हो जाऊंगी। आप कह दो, फिर मैं भूल जाऊंगी।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा क्षेत्र में इस बजट की बात करूं तो जोधपुर को नया ट्रोमा अस्पताल की मेरी वर्षों से लंबित मांग को मानकर सिलिकोसिस की नई विंग, नई कैथ लेब की घोषणा ने पश्चिमी राजस्थान के संभागीय मुख्यालय पर सरकारी चिकित्सा सुविधाओं को आमजन के लिए वरदान बनाया है।

माननीय सभापति महोदय, जोधपुर के अंदर एक गांधी होस्पिटल है जो राजा-महाराजाओं के समय महाराजा उम्मेदसिंह जी ने क्या मालूम किस सोच से वह हास्पिटल बनाया था। आज की तारीख में मैं चाहती हूं मथुरादास माथुर और आगे बढ़े, मगर गांधी होस्पिटल की महत्ता खत्म हो रही है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्रीजी से आग्रह करूंगी कि इसके लिए कुछ विचार किया जाए। वहां की यूनिट वहां नहीं ले जाएं, यहां की यूनिट यहां ही रहने दें। क्योंकि गांधी हास्पिटल ऐसा हास्पिटल ऐसा है कि महाराजा साहब ने सोचकर बनाया। उस समय की बात है कि महारानी भटियाणी बड़ी नाराज हुई कि औरतों ने क्या गुनाह किया। फिर उम्मेद हास्पिटल बनाया। पहले के जमाने में इसका नाम था मिनम हास्पिटल। फिर कांग्रेस का राज आया तो इन्होंने इसका नाम गांधी हास्पिटल कर दिया। आज यह गांधी हास्पिटल

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, स्टेशन से 10 मिनट की दूरी नहीं है। इस हास्पिटल की महत्ता कम नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में इस हास्पिटल की स्थिति अच्छी नहीं है। यहां माननीय मंत्रीजी विराजमान है, इसको थोड़ा पाइंट आउट करें, इसको देखें कि किस तरीके से इसका किया जाए।

जल स्वावलंबन अभियान की ग्रामीण क्षेत्र की सफलता से प्रेरित होकर अब इसे शहरों तक बढ़ाया गया है जिससे अब हमारी प्राचीन जल संरक्षण परम्परा पुनर्जीवित हो रही है। जोधपुर में आपने शहर के महत्वपूर्ण जलाशयों को इस योजना से जोड़ा है, इस हेतु मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय जी, जीजी के लिए मंत्रीजी को बुलाओ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की मुख्यमंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करती हूं केवल 21 रुपये में दो समय भोजन और एक समय नाश्ते की व्यवस्था अन्नपूर्णा रसोई योजना का विस्तार प्रदेश के सभी नगरीय निकायों तक कर दरिद्रनारायण की सेवा का यथार्थ प्रयास किया गया है।

स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधार जीएसटी व्यवस्था के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के संकल्प के अनुरूप व्यवस्थाओं के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधानों से प्रदेश की सरकार की व्यापारियों और आम नागरिकों के नई व्यवस्था में ले जाने की चाक-चौबंद व्यवस्था का प्रयास दिखता है।

एक समय था जब कांग्रेस सरकार के राज में स्थानीय निकाय से प्रदेश और केन्द्र सरकार तक केवल और केवल भ्रष्टाचार के मामले ही सुनाई दे रहे थे। जब राजस्थान की मुख्यमंत्री ने यह राज संभाला है तो अब समय है जब स्थानीय निकाय से लेकर प्रदेश की वसुन्धरा राजे सरकार से लेकर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार तक केवल विकास के नये कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं।

केवल मेरे जोधपुर की बात की जाए तो कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे जयनारायण व्यास शिक्षक भर्ती घोटाले, जोधपुर विकास प्राधिकरण के हजारों करोड़ के घोटाले और अब तो नगर निगम, जोधपुर में भी कांग्रेस कार्यकाल के घोटाले सामने आ रहे हैं त्यों-त्यों कांग्रेसी इधर-उधर फिर रहे हैं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

अभी सामने विराजने वाले महानुभाव बहुत ऊंची आवाज में बोल रहे थे मगर सबसे ज्यादा राज आपने किया है और सबसे ज्यादा राज करने के बाद भी आपने कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जो बी.जे.पी. सरकार दे रही है।

हमारी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार के खड्डों से उबारा है। शिक्षा के मामले में एक समय था तब केवल कागजों में ही स्कूलें चलती थीं, पद रिक्त ही रहते थे, नकलों और पेपर आउट के समाचार से प्रदेश शर्मसार होता था।

माननीय सभापति महोदय, अभी सामने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, कालेजों की बात कर रहे थे और मैं दो-तीन दिन से भी यह सुन रही हूं मगर इनको पता हो जाना चाहिए कि जोधपुर में पहले आपकी सरकार थी तो जोधपुर में कालेज तो कर दी मगर कालेज पेड़ के नीचे चल रही थी। वसुन्धरा जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इन्होंने सोचा कि कहां-कहां कालेज चल रही है तब पता लगा कि पेड़ के नीचे कालेज चल रही है तो उस कालेज को सूरसागर के अन्दर स्थापित किया। उसके लिए जमीन भी दी, बनवाना भी शुरू किया और आज करीब-करीब ढाई-तीन हजार स्टूडेंट उसमें मौजूद हैं। यह एक बहुत ही खुशी की बात है और मैं वसुन्धरा जी का, राजस्थान की मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं।

आज हमारी सरकार द्वारा बजट में की जानी वाली घोषणा के लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करती हूं कि जोधपुर में माचिया सफारी पार्क से संलग्न कायलाना, अखेराजजी का तालाब, सिद्धनाथ चौपासनी मंदिर, सुंदर बालाजी सनसेट पाइंट, मसूरिया पहाड़ी ब्रहमपुरी, मेहररानगढ़ दुर्ग तलहटी भीतरी शहर और प्राचीन जलाशयों को पनघट स्वरूप का पर्यटन गलियारा बनाया जाए। विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर उत्खनन व्यवसाय को उद्योग का दर्जा दिया जाए। सोजती गेट, पावटा, जालोरी गेट पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। राजकीय महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाए। राजुवास बीकानेर का एक अनुसंधान केन्द्र जोधपुर में खोला जाए।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इसके अलावा प्रदेश स्तर के लिए मेरी मांग है कि प्रदेश में नगरीय परिवहन सेवा के व्यस्त रूटों पर विशेष महिला बसें चलाई जाएं। इस हेतु बजट प्रावधान नहीं केवल दृढ़तापूर्वक आपके संकल्प व्यक्त करने की आवश्यकता है। चल रही बसों में से ही कुछ प्रतिशत महिला बसों के रूप में बदल जाएंगी।

जल स्वावलम्बन अभियान की तर्ज पर गोचर और देशी गौ संरक्षण संवर्द्धन अभियान चलाया जाए और इसके अन्तर्गत प्रदेश की समस्त गोचर भूमि को संरक्षित कर इसे ग्राम पंचायतों के माध्यम से डिजिटलाइज्ड मैपिंग के बाद यहां देशी उन्नत किस्म की घास के नि:शुल्क चारागाह विकसित किए जाएं।

प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में वर्षा जल संरक्षण संरचना, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के ऑन ग्रिड सिस्टम, हरित कार्यालय, सी.सी.टी.वी. की मॉनीटरिंग की केन्द्रीयकृत व्यवस्था अनिवार्यता से लागू की जाए। इसके लिए 30 प्रतिशत राशि जन सहयोग से, 20 प्रतिशत राशि निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के कोष से और 50 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जाए।

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में प्रवेश द्वार, आउटडोर और वार्ड में सी.सी.टी.वी. तंत्र स्थापित किए जाएं और इसे अस्पताल अधीक्षक के कमरे में मास्टर सर्वर से जोड़ा जाए और प्रत्येक अधीक्षक के कमरे के सर्वर को जयपुर स्थित निदेशालय के मास्टर सर्वर से जोड़ा जाए ताकि केन्द्रीयकृत लाइन मॉनीटरिंग होने से जमीनी स्थिति की योजना क्रियान्वयन से उच्च पदस्थ मंत्री और अफसर परिचित रह सके। ऐसा ही प्रयोग पुलिस विभाग में भी किया जा सकता है।

जोधपुर को जो बजट मिला उसमें जोधपुर को आगरा से जोड़ा जाएगा, जोधपुर में नई आईटीआई खुलेगी, जोधपुर के राजमार्ग के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ मंजूर किए गये हैं। बाप से सोलर पार्क तक पहुंचने के लिए कानासर तक अच्छी सड़क बनाई जाएगी। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में दस लाख रुपये की लागत से कैथ लैब मशीन लगाई जाएगी, सर्वपल्ली डा. राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय छह विषयों में चिकित्सा

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

इकाई शुरू की जाएगी। जोधपुर की कायलाना नहर का चरणबद्ध रूप से एनर्जी मॉडल के रूप में विकास होगा। जोधपुर से रामदेवरा तक पैदल पथ थोड़े परिवर्तन के साथ सुगम बनाया जाएगा। जोधपुर के जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में उद्यमिता प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाएगा। इसके अलावा जोधपुर में इन्डोर स्टेडियम के लिए सौगातें मिलेंगी, आयुर्वेद जोधपुर में चिकित्सा इकाई शुरू की जाएगी। जोधपुर के उम्मेद स्टेडियम में बास्केटबॉल सिंथेटिक ट्रैक बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जोधपुर के राजकीय मंडोर संग्रहालय का पुनरोद्धार होगा, जोधपुर के 5 स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू किए जाएंगे। जोधपुर के पॉलिटेक्निक कालेज को आइसर की सौगात मिलेगी। जोधपुर में राजकीय महाविद्यालय औसियां में समाज शास्त्र संकाय प्रारम्भ होगा, जोधपुर के उपखण्ड मुख्यालय, बाप में कन्या महाविद्यालय खुलेगा। माननीय सभापति महोदय, जोधपुर सहित कई स्कूलों में विज्ञान संकाय शुरू होंगे और आगामी वर्ष में जोधपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के लिए मेरी मांग है। आपने मुझे समय दिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। विशेष तौर से मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री जी की बहुत-बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इतना जोरदार बजट दिया, मैं इसका समर्थन करती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री मानवेन्द्र सिंह जी। एक मिनट माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मानवेन्द्र सिंह (शिव): सभापति महोदय, बजट 2017-18 पर बोलने की आपने मुझे अनुमति दी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं आपका आभारी हूं।

वैसे पहले तो मैं बजट पर बोलने वाला था परन्तु मेरे साथी कोलायत के विधायक ने अपने उद्‌बोधन में रिफाइनरी की बात की, रिफाइनरी का विषय बाड़मेर जिले से जुड़ा हुआ है और उनके आंकड़ों में कुछ बात सही नहीं थी इसलिए मैं रिफाइनरी के बारे में कुछ बोलना चाह रहा था। माननीय विधायक महोदय ने कहा कि यदि रिफाइनरी बनती तो राजस्थान में रॉयल्टी और अधिक आती। वो बात सत्य नहीं है क्योंकि रॉयल्टी वैसे भी तेल से आ रही है। राजस्थान की रॉयल्टी रिफाइनरी को बनाने में जाती जैसे कि कांग्रेस की सरकार ने जो एम.ओ.यू किया था रिफाइनरी बनाने का, उसमें रिफाइनरी का जो खर्चा था वो रॉयल्टी जितना खर्चा बनता इसलिए माननीय विधायक ने जो कहा उसके लिए मैं उनको थोड़ा ज्ञान देना चाह रहा था।

आपने अपने उद्‌बोधन से ओपनिंग बैटिंग की सत्ता पक्ष की तरफ से और सब आंकड़े दिए, सब विषय पर विस्तार से आपने अपनी बात रखी तो आंकड़े दुबारा दोहराने के आवश्यकता नहीं है। मैं केवल कुछ बिन्दुओं पर मेरे सुझाव रखना चाह रहा था, कुछ मुख्य बातें जो मुझे इस बजट उद्‌बोधन से ध्यान में आई वो सराहनीय है। आंकड़े तो सभी पढ़ते हैं, सभी ने आंकड़ों के बारे में चर्चा भी की परन्तु जिन बिन्दुओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ उनमें एक पहला विषय है विधवा पेंशन। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उद्‌बोधन में इस बात को छेड़ा है और विधवा पेंशन बढ़ाई है इसका हम सब स्वागत करते हैं,

सराहनीय कदम है और इस दिशा में सरकार करे या समाज करे, जितना भी हम करें, वह कम पड़ेगा क्योंकि विधवा का जीवन, मैं समझता हूं, इससे कठिन कोई जीवन हो नहीं सकता। इनके जीवन के सुधार के लिए जिम्मेदारी हम सबकी है, विशेषकर समाज की है और जिस प्रकार सरकार की घोषणा हुई है, उसका मार्गदर्शन लेकर समाज भी अपना योगदान दे। मैं यही प्रार्थना करता हूं।

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

दूसरी बात जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, सहायता और नगरीय सुरक्षा पर चर्चा हो रही थी, जब मुख्य मंत्रीजी ने अपने उद्बोधन में बोला कि इसमें सभी नागरिकों को सहायता के लिए आगे आना चाहिए। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को स्वयंसेवक के रूप में सहायता देनी चाहिए आपदा में, ऐसी कठिनाइयों में। मैं समझता हूं कि यह भी एक बहुत सराहनीय बिन्दु है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि भारत और अन्य देशों में अंतर क्या है? विकसित देशों में अंतर क्या है? आम नागरिक विकसित देश में अपनी जिम्मेदारी समझता है, निभाता है और हम यहां सरकार पर निर्भर रहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ सरकार करेगी। मुख्य मंत्रीजी के वक्तव्य में जो यह वाक्य बोला है, सबको स्वयंसेवक के रूप में कार्य करना है, जिम्मेदारी लेनी है। यह भी एक बहुत सराहनीय बिन्दु है। मैं इसकी भी प्रशंसा करता हूं, इसका स्वागत करता हूं। यह भी समाज की जिम्मेदारी है और मैं समझता हूं, इससे भी हम सभी मार्गदर्शन लें तो सबकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। मेरा सुझाव है नगरीय सुरक्षा में और सहायता में कि प्रत्येक महाविद्यालय में, कई-कई विद्यालयों में एनसीसी के छात्र और छात्राएं सक्रिय हैं और एनसीसी के जो भी छात्र और छात्राएं हैं, उनको हम इस अभियान से जोड़ें तो मैं समझता हूं कि समाज की जिम्मेदारी, एक नागरिक की जिम्मेदारी वह पूरी करेंगे। उनका भविष्य भी सुधरेगा, सेना की भर्ती में इनको और अंक मिलेंगे, क्योंकि जैसा मेरा अनुभव है।

बजट के मुख्य बिन्दु हैं, आपने और अन्य वक्ताओं ने, मेरे से पूर्व बोलने वाले सभी वक्ताओं ने सभी बिन्दुओं को टच किया है। दुबारा दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं।

सड़क के मामलों में बजट में बढ़ोतरी हुई है, वह लगभग 58 प्रतिशत से ऊपर हुई है और इसका असर दिख रहा है। राजस्थान में राज्य की तरफ से और केन्द्र सरकार की तरफ से जो राष्ट्रीय हाइ वेज बन रहे हैं, जगह-जगह सिक्स लेनिंग हो रही है, यह कार्य दिख रहे हैं, विकास दिख रहा है इस दिशा में। हमारे बाड़मेर जिले और मेरे गृह जिले बाड़मेर में बड़ी सड़क परियोजना की घोषणा हुई है बाड़मेर-सिणधरी-जालौर को जोड़ने की, यह कई वर्षों से पैंडिंग थी। दोनों जिला मुख्यालय इतने वर्षों से सिंगल लेन से जुड़े

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

हुए थे, अब डबल लेन से जुड़ेंगे और इसके लिए बजट की भी घोषणा हुई है। मैं स्वागत करता हूं।

मेरा एक सुझाव इस दिशा में है कि सड़क के हिसाब से थोड़ा और बजट रखा जाए धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए। धार्मिक स्थान को हम जनसंख्या के हिसाब से ले नहीं सकते क्योंकि वहां कोई परमानेंट जनसंख्या लगभग होती नहीं है, परन्तु धार्मिक स्थान पर यात्री दर्शन करने जाते हैं। वह प्रतिदिन कोई न कोई जाते रहते हैं। बड़ी कठिनाइयों से जाना पड़ता है। बाड़मेर और जैसलमेर के बीच में जैसे स्वामियों के गांव से लेकर जोगीदास के गांव वाली सड़क बने, जो माइनिंग के कारण टूटती रहती है। यदि वह सड़क बने तो रानी भटियाणी के जन्मस्थान पर जो दर्शन करने जाते हैं। वहां मेला लगता है। उससे लोगों को लाभ मिलेगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव में शैली माता का मंदिर है झणकली के पास, वहां भी हमेशा मेला लगता है। बड़ा मेला लगता है। वहां दोनों जिलों, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के रहने वाले लोग आते हैं। उनको भी लाभ मिलेगा।

गागरिया के पास एक मजार पहाड़ी के ऊपर है, उसको बीबी की मजार बोलते हैं। वहां यदि सड़क बने तो वहां हिन्दू-मुसलमान सभी दर्शन करने जाते हैं और उनको भी इससे लाभ प्राप्त होगा।

पेयजल के विषय में जो आंकड़े मिले हैं, वह बहुत गम्भीर हैं क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है। हम सब जानते हैं और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान जहां का मैं निवासी हूं। धोरों की धरती है, वहां हमेशा पेयजल की समस्या रहती है। मुख्य मंत्रीजी ने अपने उद्‌बोधन में कहा है कि राजस्थान में कुल 1,21,648 गांव ढाणी हैं, अभी तक लगभग 55,650 गांव ढाणियों को पेयजल व्यवस्था से जोड़ा गया है तो आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना गम्भीर है। अन्य योजनाओं से सरकार सक्रिय रहकर इन सबको जोड़ रही है। कई जगह पाइप लाइन संभव नहीं है क्योंकि धोरे ऐसे होते हैं और कई जगह वैसे भी पानी उपलब्ध नहीं है। पानी बाहर से आ नहीं सकता क्योंकि पावर नहीं मिलती है। हमारे यहां बिजली की कटौती कभी भी हो जाती है। लाइन फेल हो जाती है।

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

मुख्य मंत्रीजी ने अपने उद्बोधन में सोलर डी-फ्लोरीडेशन प्लांट, आरओ प्लांट ऐसी योजना जिनकी घोषणा हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों कार्यों से हम और लाभान्वित हों। इस दिशा में कुछ और एडिशनल बजट मिले तो मैं समझता हूं हमारी जो ढाणियां वंचित हैं, वे भविष्य के लिए भी अन्य योजनाओं से वंचित रहेंगी, इनको भी जोड़ सकते हैं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक चार मुख्य पेयजल योजनाएं नहर संबंधित कार्यरत हैं। तीन विधान सभा क्षेत्र नर्मदा से जुड़े हुए हैं गुढामालानी, चौहटन और शिव। बाड़मेर लिफ्ट कैनाल से बाड़मेर और शिव, पोकरण-फलसूण्ड से बायतू, कुछ पचपदरा और धवा, फिर उम्मेदसागर से पचपदरा और सिवाना, इन चारों योजनाओं से पूरा जिला कवर हो जाता है और कार्य चल रहे हैं, विशेषकर धवा, उम्मेदसागर पर तो कार्य अधिक प्रगति पर है। हमारे यहां नर्मदा योजना में कुछ तकनीकी कारणों से मामला गम्भीर है क्योंकि अभी तक लगभग 24.6 प्रतिशत कार्य हुआ है जबकि 2017 में उसको पूर्ण करना था। कई जगह डेजर्ट नेशनल पार्क से परमिशन नहीं मिली है, कोई रेलवे की परमिशन नहीं मिली है और कई नेशनल हाइवेज अथोरिटी से परमिशन नहीं मिली है तो मेरी यह प्रार्थना है जलदाय विभाग से कि ये परमिशन की शीघ्रता हो जाए। बजट है और कम्पनी भी सक्रिय है। यह कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाए क्योंकि पेयजल सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमारे प्रभारी मंत्रीजी भी इसी से जुड़े हुए हैं, वे हमारे डिवीजन के ही हैं, वह हमारी कठिनाई को समझते हैं।

कला और संस्कृति के हैड में टोंक में संस्था है अरबी फारसी की, जहां डिजिटाइजेशन के लिए कुछ बजट दिया गया है। मेरी प्रार्थना है कि पूरे राजस्थान की आर्काइव्ज बीकानेर में है। इतिहास, राजनीति विज्ञान के, सोशियोलोजी के, अन्य सब्जैक्ट के मेरे रिसर्चर्स मित्र हैं, वह कभी बीकानेर जाते हैं आर्काइव्ज में और आकर बड़ी उसकी निंदा करते हैं कि आर्काइव्ज की हालत बहुत खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। कुछ रेती से, कुछ पंछियों से, कुछ पशुओं से वह आर्काइव्ज डेमेज हो रही हैं। यदि टोंक में हम डिजिटाइजेशन कर सकते हैं अरबी फारसी डाक्यूमेंट्स की तो, मेरी यह प्रार्थना है कि राजस्थान की आर्काइव्ज बीकानेर में है। बीकानेर की आर्काइव्ज पूरी

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

डिजिटाइजेशन हो जाये तो हमारा जो रिकार्ड है, वर्षों का रिकार्ड है, वर्षों के जो ग्रंथ हैं, जो वहां बहियां पड़ी हुई हैं हर स्टेट की, हर तहसील की, कई गांवों के रिकार्ड पड़े हैं पुराने रेवेन्यू रिकार्ड्स,..

(17.00 बजे)

वो बच जाएंगे क्योंकि अगर हम उसको अभी नहीं बचाएंगे और डिजीटलाइजेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है बचाने का। मेरी यही प्रार्थना है कि बीकानेर की आर्काइव्ज को डिजीटलाइजेशन से जोड़ा जाए।

वन संबंधित हमारे आकल वुड फोसिल पार्क के लिए घोषणा की है। जैसलमेर के पास वुड फोसिल पार्क है। हमारे अन्य सदस्य जो यहां विराजमान हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, मैं आप सबको वहां निमंत्रण देता हूं। जैसलमेर से निकलते ही बाड़मेर की दिशा में है और देखने लायक है उसके लिए घोषणा की है, उसका मैं स्वागत करता हूं। डेजर्ट नेशनल पार्क जिससे बाड़मेर और जैसलमेर जिला दोनों प्रभावित होते हैं, शिव विधान सभा क्षेत्र और जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र दोनों प्रभावित होते हैं उसके लिए भी बजट घोषणा की है ग्रास लैंडं बनाने की। समस्या ग्रास लैंडं की नहीं है। समस्या गोडावण जो अपना राजकीय पक्षी है...।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, 14वीं विधान सभा में आज मेरा पहला भाषण है और संसदीय परम्परा और नियमों की जहां तक मेरी जानकारी है पहले भाषण में घंटी नहीं बजती और न कोई टोकाटाकी होती है।

श्री हीरालाल (निवाई): इसलिए थोड़ा लिबरल हो जाइये, सभापति महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, पहला भाषण अगर लेट होता है तो यह नियम लागू नहीं होता है। यह आपका भाषण बहुत लेट हो रहा है।

श्री सभापति: धन्यवाद। संसदीय कार्य मंत्री समय नहीं बढ़ा रहे हैं न।

श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): डीएनपी के लिए कुछ बजट की घोषणा हुई है उसका मैं स्वागत करता हूं। समस्या ग्रास लैंडं की नहीं है, डीएनपी में समस्या यह है कि गोडावण जो अपना राजकीय पक्षी है उसकी संख्या जितनी

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

क्लेम की है उतनी है नहीं और उसका जो क्षेत्र रिजर्व कर रखा है वो पूरे डीएनपी का लगभग पांच परसेंट से भी कम है और 95 परसेंट डीएनपी में आबादी है। यदि कोई पशु पक्षी वन्य जीव को सुरक्षित रखना है तो आम जनता जो वहां की रहने वाली है उनके लिए भी सुविधा हो तो वो उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे। आम जनता जो वहां की रहने वाली है उसको अगर आप दूर रखेंगे इस अभियान से तो उनका लगाव नहीं होगा उस पक्षी या पशु में। उसका लोकल संरक्षक उचित होता है, तो मैं यह चाहता हूं कि ग्रास लैंडं के लिए जो बजट दिया गया है उसके साथ-साथ जो डीएनपी के रहने वाले हैं उनको सड़क की अनुमति दी जाए क्योंकि अभी सड़क रोकी गयी है। कई जगह गांवों में सड़क बनाने में प्रतिबंध है। कई विद्यालयों पर प्रतिबंध है और बिजली के कनेक्शन पहले थे, अब दुबारा दे नहीं रहे हैं। घरेलू कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये रोक हटे तब जाकर इस पक्षी का सही संरक्षण होगा।

इसमें मेरा एक सुझाव है गोडावण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, गोडावण को लेकर जब राजस्थान फुटबाल संघ के चुनाव हुए, आपके आशीर्वाद से मुझे अध्यक्ष बनाया तो हमने राजस्थान फुटबाल संघ का नया चिन्ह बनाया है जिसमें फुटबाल के साथ गोडावण का चित्र हमने रखा है और गोडावण हमारा सबका पक्षी है। अमेरिका का जो राष्ट्रीय पक्षी जिसका हम चित्र देखते हैं जिसको अमेरिकन बोल्ड ईगल बोलते हैं, लगभग खतम हो गया था उनके देश में और उन्होंने कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम से उसको दुबारा जीवित किया है, लगभग पूरे जंगलों में वापस वो उड़ रहा है। तो मेरा यही सुझाव है सरकार से कि ग्रास लैंडं का जो बजट आबंटन हुआ है, यह बजट कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम में अगर हम डालें तो गोडावण को बचाने में ज्यादा लाभदायक होगा और हमारे वहां डीएनपी में रहने वाले जो बंधु हैं, गांव वाले हैं, उनके लिए भी ज्यादा लाभदायक होगा।

पर्यावरण, एक बिन्दु आया है। बिठुजा सीपीडी प्लांट बने वो कास्टिक प्लांट, मेरा गांव लगता है, उसके बगल में अमराराम जी का एरिया है हमारे राजस्व मंत्री जी का। उसका भी मैं स्वागत करता हूं कि जिस प्रदूषण से कई वर्षों से वहां के कृषक प्रभावित हैं। हमारे गांव में निजी ट्यूबवैल 32 सालों

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

से चले नहीं हैं, चल सकते हैं बिजली के कनेक्शन हैं लेकिन हम जब उसको चलाते हैं तो कास्टिक का पानी आता है। कभी लाल रंग का आता है, कभी नीले रंग का आता है, कभी हरे रंग का आता है। खेती के लायक नहीं है इसलिए हमारा ट्यूबवैल बंद पड़ा है। हमारे जैसे सैकड़ों किसान हैं जो लाभान्वित होंगे इस घोषणा से।

कृषि क्षेत्र में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का मैं स्वागत करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि बीज स्वावलंबन योजना में बाजरा भी जोड़ा जाए क्योंकि बाजरा पश्चिमी राजस्थान का मुख्य धान है और सैकड़ों जिलों में मुख्यत: हम बाजरा ही काम में लेते हैं हर प्रकार से चाहे रोटी हो, चाहे राब हो, खींच हो जैसे भी हो अन्य प्रकार से भी लेते हैं तो मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इसमें आप बाजरा भी जोड़ें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): दो बिन्दु और हैं। पशुपालन में पशुपालन संबंधी जो घोषणा हुई है उच्चतर चिकित्सालय की उसकी भी मैं बहुत सराहना और स्वागत करता हूं। पशुपालन से हमारे राजस्थान का एक सांस्कृतिक जुड़ाव है और हमारी परम्परा रही है। हम सब पशुपालक किसी न किसी दृष्टि से हम पशुपालक रहे हैं और हैं। अभी भी हमारे परिवार में हम लगभग 90 से ऊपर गायें रखते हैं और ऊँट हैं। पुरानी राजस्थानी भाषा में हम तो धन इसी को बोलते थे। बाकी चांदी सोना में तो धन बाद में शब्द आया, पहले धन हम पशुधन ही बोलते थे। पशु के हिसाब से ही धन की गिनती होती थी। मैं इसका बहुत स्वागत करता हूं। मेरी एक ही प्रार्थना है कि ये जो उच्चस्तरीय चिकित्सालय बनें पशु गणना के आधार पर बनें। हमारी गड़रा, रामसा तहसील जो खेती से वंचित है, अभी भी पशुधन पर निर्भर है, वहां भी एक उच्चस्तर का चिकित्सालय हो जाए। विशेषकर गड़रा तहसील पूरा रेगिस्तानी एरिया है और लगभग 90 प्रतिशत वहां के रहने वाले पशुधन पर ही निर्भर हैं। तो मेरी एक प्रार्थना है कि वहां भी एक पशु चिकित्सालय हो जाए।

जो पॉलिक्लिनिक्स को टेलीमेडिसिन से जोड़ने की योजना, है यह बहुत ही सराहनीय बात है। इसका हम जितना स्वागत करें, कम है। आज जो टैक्निक अवेलेवल है सबके पास और गांव में विशेषकर छोटे कस्बों में जो

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

पॉलिक्लिनिक बने हैं, बनेंगे वहां डेटा बैंड विथ है और मैं समझता हूं कि इससे पशुपालक अति लाभान्वित होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

परम्परा आप चेंज कर रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: आसन अपनी व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है क्या करें।

श्री मानवेन्द्रसिंह (शिव): शिक्षा की दृष्टि से जैसे लगभग एक वर्ष से अधिक समय से पीडीएस की योजना पोस मशीन से चल रही है और हण्ड्रेड परसेंट अब पोस मशीन पर कार्यरत है। अगर गांव में पीडीएस का काम पोस मशीन से हो रहा है तो इसका मतलब बायोमेट्रिक डेटा और ये सब बायोमेट्रिक टैक्निक है वहां गांवों में।

शिक्षा से संबंधित मेरा एक सुझाव है कि अध्यापक जहां कार्यरत हो उनकी वहां बायोमेट्रिक मीटर से डेटा से उपस्थिति गिनी जाए। सरकारी विद्‌यालयों में अनेक ऐसे अध्यापक हैं, मैं अधिकतम नहीं बोलूंगा, अनेक ऐसे अध्यापक हैं जिनकी उपस्थिति कागज पर है लेकिन बायोलोजिकल उपस्थिति नहीं है। अगर वहां बायोमेट्रिक कार्ड हो, चैक करने का तरीका हो तो मैं समझता हूं कि वह पकड़े जाएंगे और अपनी शिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा।

आपने बार बार घंटी बजाई इसलिए मुझे थोडा जल्दी खतम करना पड़ेगा।

अंत में मेरी प्रार्थना है मेरा जन्म सेना में हुआ था। मैं एक सैनिक परिवार का सदस्य हूं, अभी भी मैं सेना से जुडा हुआ हूं। पूर्व सैनिक एवं सैनिकों के लिये जो घोषणा हुई है उसका मैं स्वागत करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण विषय मेरे लिये यही है और हमेशा यही रहेगा। मेरा पहला परिवार सेना ही है इसलिए मेरा ज्यादा जुडाव इस विषय से है।

पूर्व सैनिकों के लिये सरकार सुविधा देती है, अन्य विभागों में भर्ती की, जैसे पुलिस में, रेवेन्यू में, शिक्षा में भर्ती होती है, पर आज का जो युग है उसमें सबसे बड़ा संकट है जो सैनिक अभी सर्विस में है उनका जीवन सबसे कठिन जीवन है और हकीकत यह है कि 90-95 प्रतिशत से ऊपर आर्मी, एयरफोर्स या नौसेना वालों की जो आत्महत्या होती है वह केवल घर में

(श्री मानवेन्द्रसिंह)

तनाव के कारण होती है। घर में तनाव, गांव में व्यवस्था बदल गयी है, छोटे कस्बों में व्यवस्था बदल गयी हैं, उनकी पत्नियां अब ज्यादा शिक्षित हैं, उनके ससुराल वाले उनको परेशान करते हैं, पतियों को परेशान करते हैं। पत्नियों के पास और कोई चारा नहीं वह सैनिक के ऊपर अपना गुस्सा निकालती है, आर्मी में ऑन ड्यूटी मैंने जो भी डैथ देखी हैं, सुसाइड देखी है, वह 90 प्रतिशत से ऊपर डैथ केवल घर के तनाव के कारण हुई है, सर्विस के कारण बहुत कम होती है।

वर्तमान में जो सर्विस में हैं उनकी सुविधा के लिये मेरा सरकार को एक सुझाव है कि हर जिला मुख्यालय पर विश्राम गृह बनाते हैं, हर जिला मुख्यालय पर सैनिक विश्राम गृह है, परंतु एक सैल चाहे मुख्य मंत्री कार्यालय में हो, चाहे अन्य मंत्रालय में हो, उस सैल में सैनिक डाइरेक्ट जो सर्विस में है, कश्मीर में, सियाचीन में, आसाम या नागालैण्ड में पोस्टेड हैं, उनकी जो समस्या हो, घर की समस्या जैस भूमि नपाई की होती है, पशुओं को लेकर होती है, वह विषय वहां पहुंचे और उनका समाधान वह सैल करे। एक समय ऐसा होता था कि कंपनी कमांडर लैटर लिखता था कलेक्टर को और कलेक्टर सावधान होकर वह कार्य करते थे। आज की स्थिति में चाहे जरनल साहब कलेक्टर को पत्र लिखें वह जवाब नहीं भेजता जरनल साहब को। यदि जयपुर में यह सैल बनाया जाए तो जो सर्विस में सैनिक हैं जिनके लिये कोई प्रशासनिक व्यवस्था होती नहीं है, उनके परिवार में शांति के लिये और जो घर में विवाद होते हैं, गांव में जो विवाद होते हैं उनको सुलटाने के लिये यह सैल कार्यरत हो, इसकी मैं मांग करता हूं।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्य सुखराम जी विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद।

कल 8 तारीख को सदन की मुखिया ने बजट पेश किया, बजट पेश करने से पहले पूरे प्रदेश के सभी लोगों को आशा थी कि बजट में बहुत कुछ

(श्री सुखराम विश्नोई)

आएगा, परंतु बजट में स्पष्ट रूप से नोटबंदी का असर दिखा। स्वाभाविक है जो टैक्स, वेट की राशि, सैस आना चाहिये था, नहीं आया। उनके हाथ भी बंधे हुए थे किस तरह से स्कीमें लागू करे।

सभापति महोदय, बेरोजगारों के लिये जो विद्यार्थी मित्र हडताल कर रहे थे, लैब टैक्निशियन हड़ताल कर रहे थे, कम्प्यूटर टीचर हड़ताल कर रहे थे, पिछले चार साल से हडताल चल रही थी, उनके लिये एक भी शब्द नहीं कहा गया। जो पहला बजट पेश किया था वह बड़ा जोश में था, बडी उम्मीदें थीं, 15 लाख को नौकरी देंगे। स्वाभाविक है जब वह चीज नहीं बनती है तो साइलेंट रहना ठीक है।

कुल मिलाकर जब बजट पढ़ा जा रहा था, कई मंत्री साथी, विशेषकर हमारे सत्ता पक्ष के जो व्हिप हैं वह बडे आराम से नींद ले रहे थे। उससे यह महसूस हो रहा था कि बजट उबाऊ ज्यादा है, उम्मीदें कम हैं।

किसानों के बारे में, बीमा पालिसी के बारे में बार बार सत्ता पक्ष के मेरे साथी विधायक, लाइट की रेटें वापस ले लीं, रेटें बढ़ाई किसने ? आप ही बढ़ाने वाले, आप ही लेने वाले। चार दिन पहले बढ़ा दी फिर वापस ले ली। किसी दूसरे ने बढ़ाई हो और आपने वापस ले ली हो, तब तो हम आपको धन्यवाद दें। रेटें बढ़ाई आपने, आपने वापस ली, अपने आप ही वाहवाही लें। हमारी पिछली सरकार ने सत्ता में आते ही ऐलान किया कि हम किसानों की रेट नहीं बढ़ाएंगे, वाकई में पांच साल नहीं बढ़ाईं। बढ़ी रेट कृषि के क्षेत्र में वापस ली, परंतु घरेलू बिजली की वापस नहीं ली। तीन गुणा लाइट की रेट बढ़ी, 44 पैसे पर-यूनिट के पैसे थे, अब डेढ़ रुपया हो गया है।

रिफाइनरी की बात बार बार चलती है। पहले बजट में रिफाइनरी के लिये चार दीवारी की घोषणा की थी कि चारदीवारी बनाएंगे, इतनी राशि सैंक्शन की थी और फिर बिल्कुल ही बात शांत कर ली। रिफाइनरी की कोई बात हो ही नहीं रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप भी उस संभाग से है, तेल के 33 कुएं वर्तमान में बाडमेर-सांचौर बेसिन पर चल रहे हैं और जैसलमेर से बाडमेर सांचौर बेसिन गैस के कुएं भी चल रहे हैं। कुल मिलाकर 61.77 लाख टन खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है। 480.87 एमएमएचसीएम, यह इनका टैक्निकल नाम है, गैस का

(श्री सुखराम विश्नोई)

उत्पादन हो रहा है जो फोकस एनर्जी आयल इंडिया से मिलकर तैयार कर रही है। कुल मिलाकर 2015-16 में 234143 करोड़ रुपये राजस्व वसूल हो रहा है। इस वित्त वर्ष के 2-3 महीने पहले 1657 करोड़ रुपये वसूल हुए। माननीय सभापति महोदय, हम उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, किस कारण से रिफाइनरी नहीं बन रही, कारण क्या है, क्यों बात दब गयी। पाइप के जरिये जो तेल जा रहा है, जामनगर में अंबानी बंधुओं की रिफाइनरी है, पूरा का पूरा तेल पाइप के जरिये वहां जा रहा है और उस तेल में एक समस्या है ...(व्यवधान)... तेल गाढ़ा है। पाइप लाइन से न जाने की वजह से गैस की जो वहां पाइप लाइन है बाकायदा उस पाइप में दोनों तरफ गैस की पाइप लाइन डाली हुई है, गर्म लाइन चल रही है ताकि तेल गर्म रहे और जामनगर पहुंचे। केवल केवल एक मात्र कारण है उसके अलावा कोई कारण नहीं है, क्योंकि अंबानी बंधुओं को बाकायदा रिफाइनरी का टैक्स मिलता है, चार्ज मिलता है, इस कारण से ही रिफाइनरी को ठंडे बस्ते में डाला गया है। पिछले सत्र में बात की थी, दूसरी कंपनी से बात चल रही है, उस कंपनी से बात चल रही है, कुल मिलाकर पश्चिमी राजस्थान में अगर रिफाइनरी लगती उस रिफाइनरी में प्रोडक्शन से कम-से-कम पन्द्रह-बीस तरह के उद्योग लगते और पूरा पश्चिमी राजस्थान सरसब्ज होता, उसमें कई लोगों को फायदा मिलता। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन की नेता से पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी 163 की मैजोरिटी दी है। बहुत सारी उम्मीदें थीं। बहुत सारी आशाएं थीं। उन आशाओं को आप पुन: जीवित करें और रिफाइनरी की पुन: घोषणा करें। समय बीत जाएगा, क्या पता दो साल के बाद में क्या स्थिति आएगी? पहले वाली स्थिति नहीं रही है। फटाफट परिवर्तन होते हैं। आज इसकी व्यवस्था है, कल दूसरे की व्यवस्था आएगी। मेरा निवेदन है कि रिफानरी पर पुनर्विचार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी समस्या वैस्टर्न राजस्थान में पानी की आती है। पूर्वी राजस्थान में नहरें चलती हैं। परन्तु पीने के पानी की बहुत समस्या है। पीने के पानी की समस्या को लेकर..। माननीय सभापति महोदय, बजट में जलदाय विभाग के बारे में देखेंगे। उसमें लिखा है कि इतने-गांव और इतनी ढाणियां इससे जोड़ दी गयी। जबकि 1 लाख 21 हजार 648 गांव-

(श्री सुखराम विश्नोई)

ढाणियां हैं, उसमें से 55 हजार 25 गांव व ढाणियों को मार्च, 2016 तक जोड़ दी। 2016 में कम-से-कम 625 गांव और लाभान्वित हो जाएंगे और इस वर्ष, इस वर्ष से मतलब जो मार्च में बीत रहा है, में 2 हजार 39 गांव-ढाणियों को और जोड़ेंगे। अगले में 2 हजार गांव-ढाणियों को और जोड़ेंगे। यह कुल-मिलाकर 60 हजार गांव-ढाणी होते हैं। 1 लाख 21 हजार 648 गांव में से निकालने पर 59 हजार गांव-ढाणियां बचती हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा क्या यह सही बात है कि तीन साल के अन्दर इतने गांव-ढाणियां जुड़ गयी और पिछले 67 साल से 60 हजार गांव जुड़े। तो यह जो आंकड़ा पेश किया गया है, यह पेयजल के संबंध में बढ़ा-चढ़ाकर बात की गयी है। इस बात को पुन: दुरुस्त किया जाए।

साथ ही, माननीय सभापति महोदय, जो आर्थिक समीक्षा पेश की गयी है। आर्थिक समीक्षा के अंदर स्पष्ट कहा हुआ है कि 114 दीर्घकालिक परियोजनाएं पैंडिंग थीं, उसमें से 53 हमने पूरी कर दीं 54 पुन: पैंडिंग रही हैं। माननीय सभापति महोदय, यह जो आर्थिक समीक्षा है, आर्थिक समीक्षा के अंदर बाकायदा 114 परियोजनाओं का हवाला दिया गया है और जो बजट पेश किया गया है, बजट में केवल मात्र 9 परियोजनाओं का ही हवाला दिया गया है। उसके आगे कुछ भी बात नहीं की गयी है। पुरानी जो 67 परियोजनाएं थीं, 37 पूरी कर दीं। 37 को पूरी करते-करते 9 पीछे बची है। यह जो विरोधाभासी बातें इसमें कही गयी हैं, इनको पुन: दुरुस्त किया जाए, ताकि अपने सामने सही स्थिति सामने आए। पानी के बारे में हालात क्या हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जालौर जिले के तीन-चार माननीय विधायक साथी यहां बैठे हैं और अब तो ड़ेढ़ साल बचा है। साल ही समझो, साल ही बचा है। मेरे सांचौर में नर्मदा के तीन महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट लगे हुए हैं। पूरे जालौर जिले को उन तीनों प्रोजैक्ट से पानी सप्लाई होने वाला है। एक FR प्रोजेक्ट है, एक DR प्रोजैक्ट है और एक ER प्रोजैक्ट है। माननीय सभापति महोदय, आप कल्पना करोगे कि FR प्रोजैक्ट को बीजेपी की पिछली सरकार आई थी, उस सरकार ने मंजूर किया था। उसका काम धीमी गति से चला और काम न चलने से आज दिन तक..। अब 2017 चल रहा है, दस साल हो गये हैं। शंकर जी मैं आपकी

(श्री सुखराम विश्नोई)

बात कर रहा हूं। मैं आपकी पैरोकारी कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, आज दस साल हो गये। जालौर शहर को कच्चा पानी जा रहा है। ये हालात बने हुए हैं। अब नहीं बोलोगे तो पछताओगे। इसलिए अपनी बात को रखो।

माननीय सभापति महोदय, बजट पेश किया गया। तीन महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट थे। इसके साथ में दो प्रोजैक्ट और हैं। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे हमारे चौहटन का है। मेरे गांव के पास बना हुआ है। जमीन एक्वायर की है। कोई काम नहीं चल रहा है। संसदीय सचिव लादूराम जी ने भी सिणधरी के अंदर पानी जाने के लिए.. इन चारों-पांचों प्रोजैक्टों को इस बजट में एक भी पैसा आवंटन नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इतने महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट हैं। जब दो जिले जुड़े हुए हैं। दोनों जिलों के लोगों को पानी पीने के लिए.. पश्चिमी राजस्थान में कहावत है, राजस्थान के जैसलमेर-बाड़मेर में कि 'खून सस्ता पानी महंगा'। ऐसे हालात बने हुए हैं। ऐसे हालात के अंदर इस बजट में घोषणा नहीं की है। मैं जालौर जिले के मेरे साथी विधायकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी बात रखें। हमारे सदन की नेता से मिलें, ताकि जवाब आए और जवाब में तीनों प्रोजैक्ट की अगर राशि होगी, तभी तो काम चलेगा। क्लस्टर के लिए तीनों में एक पैसा नहीं दिया। जब क्लस्टर का पैसा नहीं दिया, किस तरह टंकियां बनेंगी? किस तरह से पाइप लगेंगे? माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे साथी विधायक यह बात रखें। मैं तो जालौर जिले में एक ही जगह से जीता हूं। जालौर हमारा संसदीय क्षेत्र हैं, उसमें आठ हैं। आठों में से मैं एक ही जीता हूं। इनकी ड्यूटी बनती है कि अपनी बात रखें। वर्ना बात नहीं रखेंगे और फील्ड में जाएंगे तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछला सत्र चला और नया सत्र आया है, इसमें काफी घटनाक्रम चेंज हुए। हमारी जो पूर्व जलदाय मंत्री थीं, उनका महकमा छीन लिया। दूसरा दे दिया गया। क्या कारण रहे? क्यों छीना गया? इसलिए छीना गया, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं ......

श्री सभापति: बजट में आए, बजट में। महकमा किसके पास है और किस के पास नहीं, यह नहीं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कोई बात नहीं शार्ट में कर देता हूं।

एस.पी.एम.एल. कम्पनी है। मेरे जो तीनों प्रोजैक्ट हैं, तीनों प्रोजैक्टों में से दो प्रोजैक्ट उसके पास है। सांचौर, जालौर के, नर्मदा के और एक जो क्लस्टर का काम चालू किया है, वह उसके पास में है। माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो कम्पनी के लोग हैं, इन लोगों की सत्ता तक पहुंच है और जलदाय विभाग में जो घूसकाण्ड हुआ है, इसमें इस एस.पी.एम.एल. कम्पनी का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस रोल का यह कारण है कि भरतपुर के अंदर ऑलरेडी 192 करोड़ का टैंडर चल रहा था, उसको निरस्त कर 262 करोड़ का उस दूसरी कम्पनी को दे दिया। मंत्री जी से जवाब पूछा। जवाब दिया नहीं।

माननीय सभापति, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पहले लोग प्याऊ लगाते थे। आजादी से पहले गांव में जो सम्पन्न लोग होते थे, वे प्याऊ लगाते थे। पानी पीने के लिए प्याऊ लगाते थे और पानी के लिए इस तरह का भ्रष्टाचार हो, माननीय सभापति महोदय, यह अशोभनीय बात है। इसमें पम्प लगे हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने एम.एल.एल. फंड के पैसे दिए और क्या पी.एच.डी. की पॉलिसी है कि जो स्टैण्डर्ड पम्प हैं, जैसे टैक्समो कम्पनी का है, वह नहीं लगाकर एक घटिया कम्पनी का पम्प लगाया और चार दिन में जल गया। माननीय सभापति महोदय, एम.एल.ए. फंड से पैसे दिए और मैंने निवेदन किया कि आप स्टैण्डर्ड कम्पनी का पम्प लगाओ। उत्तर यू.पी. की कम्पनी का घटिया पम्प लगाया। चार दिन में जल गया। मतलब इस तरह की खरीददारी करते हैं। जो केबल की खरीददारी करते हैं, इसमें कई तरह के घोटाले हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम-से-कम एम.एल.ए. फंड को ये नहीं छोड़ते हैं। इस तरह से जो बजट आता है, इस तरह से जो पैसे आते हैं, उनमें जो ऊपरी लोग मिल जाते हैं। मौके पर क्या स्थिति होती है? मौके पर क्या हालात होते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक शिक्षा का मामला है। शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर माननीय सभापति महोदय, विद्या

(श्री सुखराम विश्नोई)

ददाति विनयं... बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा जालौर जिला है, सिरोही है, जैसलमेर है, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है और ब्लैकलिस्टेड जिले घोषित किये हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, आप कल्पना करो कि जो ब्लैकलिस्टेड जिले हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वहां पर जो टीचर लगे हैं, उनको हटा देते हैं। हम कहते हैं हमारे वहां पर टीचर लाओ। ये वहां पर लगाते नहीं है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि विद्या का बड़ा महत्व है।

विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्।

पात्रत्वात्धनमाप्नोति धनात्र्मं ततः सुखम्

विद्या ग्रहण करोगे, तब ही पात्र आदमी बनोगे, और पात्र आदमी यहां आएंगे तब ही कामयाब होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहूंगा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक तो सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, जो 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चल रहा है। एक सतत् शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक साक्षर भारत मिशन, 1988 चल रहा है और आप इसके आंकड़ें देखेंगे कि एक लाख अनपढ़ लोगों को उन्होंने पढ़ा दिया। पन्द्रह साल से ऊपर के लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, अपन गांव में रहते हैं। एक भी साक्षरता का कार्यक्रम गांव में नहीं चलता है। क्या पता किस हिसाब से, इतने लोगों को उनमें पढ़ा दिया ऐसे जो कार्यक्रम चलते हैं इनको बंद किया जाना चाहिए ताकि लोगों को महसूस हो, शिक्षा के प्रति भावना बने। वर्ना लोग क्या कहते है कि साक्षरता, यह तो पैसे खाने की स्कीम है। सरल शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा कार्यक्रम हैं, इनकी पूरी रकम छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, उन पर खर्च की जाए तो वह आगे बढ़ेगे।

माननीय सभापति, बजट पेश किया गया है, हमारे शिक्षा मंत्री है बढ-चढ़कर अपना बखान करते हैं, मैंने सैटअप चेंज के नाम से लोगों को निहाल कर दिया। प्राइमरी स्कूल के जो टीचर थे, आप सब यदि कल्पना करोंगे, एक 55 साल का टीचर है, 55 साल के टीचर को सैटअप चेंज के नाम से

(श्री सुखराम विश्नोई)

ट्रान्सफर कर बड़ी स्कूल भेज दिया। ना तो वह स्कूल का सैट होता है, दूर का आदमी है, ना ही कोई आने जाने का रास्ता है। जो आदमी 30 साल अपने गांव के पास रहा, रिटायरमेंट में 5 साल बचे हैं और सैटअप चेंज के नाम पर चेंज कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, यह आंकड़े स्पष्ट बोल रहे है कि प्राइमरी लेवल की शिक्षा, स्टूडेंट का नामांकन घटा है। प्राइमरी लेवल पर नामांकन घटा है। 2012-13 में 48.68 लाख विद्यार्थी थे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

2016-17 में 40.92 लाख, 48.67 लाख विद्यार्थी प्राइमरी शिक्षा में पढ़ रहे थे। देवनानी जी की नीति लागू होने से, सैटअप चेंज करने के बाद, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 10-12 स्कूलों में तालाबंदी हुई, लोग ताला देखकर बाहर बैठ गयें कि हम ताला नहीं खोलने देंगे, पहले टीचर लगाओ। टीचर कहां से लगाएं। थर्ड ग्रेड टीचर तो लिए नहीं। यह बढ़ चढ़कर बात कर रहे हैं कि नामांकन बढ़ा है। प्राइमरी स्तर पर 4 लाख नामांकन कम हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि निजी विद्यालय के अंदर गरीब बच्चों, बीपीएल परिवार के लड़कों को पढ़ने के लिए व्यवस्था की गयी है, बाकायदा सरकार की तरफ से जो निजी विद्यालय है उनको पुनर्भरण करने की व्यवस्था है। इतने लड़के पढ़े, उनके पैसे सरकार देती है। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनकी ना तो कोई जांच होती है, ना कोई सर्वे होता है। केवल उन्होंने आंकड़ा पेश कर दिया कि इतने लड़के मेरे यहां पढ़े और पुनर्भरण कर देते हैं। इस तरह का जो फर्जी वाड़ा होता है उस पर रोक लगनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच मिनट, पांच मिनट।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं। आपके तो ऊपर हो गये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरे दस मिनट ही नहीं हुए, दस मिनट तो बोलने दो।

श्री सभापति: ऐसा थोड़े ही है, दस मिनट ही हुए है आपको।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): दस मिनट तो हुए नहीं।

श्री सभापति: बीस मिनट हो गये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं हुए साहब।

श्री सभापति: नोट होता है, ऐसे थोड़े होता है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): दस मिनट हुए हैं साहब।

श्री मदन राठौड़, (उप मुख्य सचेतक): 19 मिनट हुए.....

श्री सभापति: ऐसा नहीं होता। प्लीज खतम करें आप।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): ध्यान रखते हो, 19 मिनट का ध्यान रखते हो।

श्री सभापति: खतम करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पहले खल चलाते थे, हम जाते थे, छोटे थे तो बाकायदा...(व्यवधान)... घड़ी चल गयी।

श्री सभापति: एक मिनट में समअप करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): राठौड़ साहब, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने पूरे 19 मिनट का ध्यान रखा।

माननीय सभापति महोदय, विद्युत के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना निकाली है, 2013 में बिजली की फाइलें जमा हुई ग्रुप-5 की और 2013 के बाद एक भी कनैक्शन उनको नहीं दिया गया। कनैक्शन नहीं दिया गया, उलटे नई योजना लाकर दे दी मुख्य मंत्री उजाला योजना। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उजाला योजना के अंदर 100 रुपये की रसीद कटाओ उन्हीं फाइलों की जो पहले योजना के अंदर 2013 में जमा कर दी उन्हीं की 100 रुपये की रसीद कटाओ और मिनिमम दस हजार का डिमाण्ड आएगा। उसमें फिर एक मीटर पर 100 रुपये अतिरिक्त लगेगे। कम से कम 15 हजार में एक कनैक्शन होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पांच आदमी अगर कनैक्शन लेना चाहेंगे, गांव में गरीब आदमी किस तरह से कनेक्शन ले पाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराज जाएं। समाप्त करें।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): एक मिनट, बस पूरा करता हूं। बिजली बोर्ड ने ना तो बूंद-बूंद सिंचाई स्कीम की घोषणा की, केवल कहा इतने कनैक्शन देंगे। बूंद-बूंद सिंचाई में पूरे कनैक्शन का सैल्फ चार्ज, किसान खुद चार्ज वहन करता है, उसमें सरकार को कहां तकलीफ है, जब किसान खुद वहन करता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बूंद-बूंद सिंचाई व्यवस्था है, यह व्यवस्था चालू की जाए ताकि किसान पानी बचत करके व्यवस्थित खेती करे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे साथी बहुत बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे, बूंद-बूंद सिंचाई में ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हीरालाल जी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): धन्यवाद साहब।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री महोदया ने राजस्थान का बजट पेश किया। हमारी सरकार द्वारा यह बजट ना केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि प्रदेश में तीन वर्षों में किए गये विकास कार्यों का दर्पण है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, युवा, महिला, सबको नई दिशा और दशा देने वाला बजट है। पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण जो चरमराई व्यवस्था मिली, उस सरकार का वित्तीय प्रबंध अकुशल था, उस कारण यह सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है। परन्तु हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया है।

पिछले तीन वर्षों में अनेक पुरस्कार, सम्मान प्रदेश को मिले हैं। लगातार दो वर्षों से सर्वश्रेष्ठ कौशल प्रदाता राज्य के रूप में काफी राष्ट्रीय, ई-गवर्नेंस, कांफ्रेंस व स्वर्ण पदक, भामाशाह योजना पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, दिव्यांगों को सर्वाधिक ऋण, एससी निगम को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। कृषि कर्मण पुरस्कार, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं, योजनाओं में भी राष्ट्रीय पुरस्कार राजस्थान सरकार को मिले हैं जो बहुत महतवूर्ण बात है। सरकार के लिए गौरव की बात है, पूरे प्रदेश की जनता के लिए गौरव की बात है। रोजगार के अवसरों का सृजन करना, विकास में तेजी लाना, सुशासन कायम करना, जन अभाव अभियोग

(श्री हीरालाल)

निराकरण करना, वास्तविक आकलन के बाद सड़क, पेयजल, शिक्षा, कृषि, जल सरंक्षण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, सामाजिक उत्थान, खाद्य सुरक्षा एवं निवेशकों के क्षेत्र में तीन वर्षों में समग्र विकास, यही प्रयास अपनाकर प्रत्येक सैक्टर में अलग-अलग नवाचार प्रारम्भ किए हैं। हमारी सरकार का यही महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

सरकार ने तीन वर्षों में सड़कों के क्षेत्र में 20 हजार 822 करोड़ रुपये का व्यय करके 4 हजार 281 गांव, ढ़ाणियों और मजरों को जोड़ा है, जबकि गत सरकार ने 9 हजार 157 करोड़ व्यय करके केवल 661 गांव, ढ़ाणियों, मजरों को जोड़ा था। 15 हजार 278 किलोमीटर नवीन सड़क का निर्माण कर 4 हजार 637 करोड़ रुपये का व्यय किया, जबकि गत सरकार ने 5 वर्षों में 12 हजार 554 किलोमीटर लंबाई पर 2 हजार 993 करोड़ रुपये ही खर्च किए थे।

मिसिंग लिंक के प्रथम चरण में 2 हजार 246 किलोमीटर लंबी सड़कें और दूसरे चरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एक हजार 820 किलोमीटर लंबाई की 808 मिसिंग लिंक का कार्य आगामी वर्षों में पूर्ण किया जाएगा।

गौरव पथ, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी, उन्होंने सोचा जब शहरों में अच्छी सड़कें है तो मेरे गांवों में भी, दूर गांव में बैठा आदमी है उसको भी अच्छी सुविधा मिले, तो 9 हजार 894 ग्राम पंचायतों में 5 हजार 907 ग्रामीण गौरव पथ अथवा मिसिंग लिंक के कार्य से जोड़ा गया।

प्रदेश की एक लाख 21 हजार 648 ग्राम ढ़ाणियों में से अब तक 55 हजार 25 गांव ढ़ाणियों को मार्च 2016 तक पेयजल से लाभान्वित किया गया। शेष समस्याग्रस्त गांव एवं ढ़ाणियों में से 625 गांव ढाणियों को नवम्बर, 2016 तक लाभान्वित किया जा चुका है। गत सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षों में 6 हजार 97 करोड़ रुपये व्यय किए गये जबकि हमारी सरकार ने तीन वर्षों में 13 हजार 473 करोड़ रुपये व्यय किए हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में, जो पिछली सरकार थी, उसने कम्पनियों में इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बांटा, और वह विरासत में मिला हमारी भारतीय जनता

(श्री हीरालाल)

पार्टी की सरकार को 2003 में, विद्युत वितरण निगम पर 31 मार्च, 2014 तक ऋण भार 72724 करोड़ रुपये हो चुका था। उदय योजनान्तर्गत विद्युत निगम को 62421 करोड़ 96 लाख रुपये का ऋण सरकार द्वारा दिया गया ताकि विद्युत वितरण निगम की व्यवस्थाएं सुधर सकें। यह एक उदाहरण है।

(17.39 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राज्य में उद्योग की स्थापना एवं संचालन को आसान बनाने हेतु सिंगल विण्डो प्रणाली को वर्ष 2016 में ऑनलाइन प्रणाली में बदला गया। राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमिता को प्रोत्साहन योजनाओं के तहत परियोजना स्थापित करने हेतु पांच करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान की गयी, जिसमें 90 लाख तक के ऋण पर छह प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस योजना को वायबल बनाने के लिये लागत कम करने के उद्देश्य से ब्याज अनुदान की सीमा को एक करोड़ 50 लाख तक बढ़ाया जाएगा।

कृषि एवं पशुपालन, 'स्वस्थ धरा एवं खेत हरा', यह विजन रखते हुए हमारी सरकार ने सोइल कार्ड योजना का शुभारम्भ माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के द्वारा 19 फरवरी, 2015 को गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में करवाया। इस योजना के तहत जनवरी, 2017 तक 29 लाख सोइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करवाये गये। आगामी वर्ष में एक लाख किसानों को मिनिकिट वितरित कराये जाएंगे।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष खरीफ में 53 लाख कृषकों तथा रबी में 30 लाख कृषकों के 29 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल का बीमा किया जाएगा।

कृषि विभाग के लिये आगामी वर्ष में 3156 करोड़ 61 लाख रुपये का प्रावधान है। एक हजार 180 किसान सेवा केन्द्र-कम-विलेज नॉलेज सेण्टर्स की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पानी, बिजली, फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जाएगी।

जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र में गत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं

(श्री हीरालाल)

के क्रियान्वयन में 44 हजार 782 हैक्टेयर नवीन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार द्वारा 32 लघु परियोजनाओं के जीर्णोद्धार पर 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

माननीय जल संसाधन मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार हमारे टोंक जिले में बीसलपुर बांध है, जिसके 16 गेट हैं, तीन बार उन गेटों को खोला गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरी मांग है, मेरा निवेदन है कि कच्चे धोरे बना कर जो ओवर-फ्लो का पानी है, उसको टोरड़ी में, टोरड़ी से मांसी डैम में डाल कर पीपलू और मालपुरा टोडा, जो कि ऊंचाई पर है, उसको अगर लिफ्ट करके डाल दिया जाए तो इन तीनों उप खण्डों में भी किसानों को लाभ मिलेगा।

सामाजिक विकास एवं मानव संसाधन, छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुप्रति पालनहार सहयोग एवं उपहार योजनाओं को ऑनलाइन किया गया है। विधवा पेंशन के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को एक जुलाई, 2017 से पेंशन बढ़ा कर एक हजार रुपये, 75 वर्ष से अधिक की महिलाओं के लिये 1500 रुपये करने की सरकार की योजना है। मुख्य मंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, 18 वर्ष से कम आयु वालों को भारत सरकार पेंशन नहीं देती है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने, माननीय वसुन्धराजी ने यह तय किया कि एक जुलाई, 2017 से आयु को आधार नहीं मान कर विशेष योग्यजन को समान रूप से साढे सात सौ रुपये की पेंशन स्वीकृत करने की योजना है।

जनजाति विकास, हमारी सरकार सबजन विकास-सबजन उत्थान के मूल मंत्र पर कार्य कर रही है और जनजाति वर्ग के सम्पूर्ण विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी माननीय जनजाति मंत्री महोदय ने हमारे आवासीय महिला विद्यालय, एकलव्य छात्रावास में कुछ सीटें बढ़ायी हैं, उसके लिये धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय जनजाति विकास मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का उप खण्ड पीपलू बहुत पिछड़ा हुआ है। उसमें भी एक एकलव्य आवासीय विद्यालय खोल दिया जाए तो उस पिछड़े उप खण्ड का विकास होगा।

शिक्षा, दूर दराज के जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों में शिक्षक उपलब्ध

(श्री हीरालाल)

कराने हेतु प्रदेश के सभी 13527 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक तथा 50983 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पदों को समानीकरण करके भरा गया। प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु 5000 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में छह पंचायतें उच्च माध्यमिक विद्यालयों से वंचित रह गयी हैं, ढाणी जुगलपुरा माध्यमिक विद्यालय, सुनारा माध्यमिक विद्यालय, बिडोली माध्यमिक विद्यालय, नटवाड़ा माध्यमिक विद्यालय, सैदरिया माध्यमिक विद्यालय और शहीद जयनारायण जाट लुहारा माध्यमिक विद्यालय इसीलिये क्रमोन्नत नहीं हो पाये कि वहां पर निजी क्षेत्र में सीनियर हायर सैकण्डरी चल रही है। इन क्षेत्रों में जो सीनियर हायर सैकण्डरी चल रही हैं, वह नाम मात्र की हैं। उनमें लड़के भी नहीं हैं। लेकिन मेरे क्षेत्र के बच्चे उससे वंचित हो रहे हैं। इसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस नियम में शिथिलता देते हुए, और राजस्थान में ऐसी कई जगह हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही ऐसी जगह नहीं हैं, जहां-जहां निजी क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं, वहां पर वह पंचायतें वंचित रह गयी हैं। वहां भी ये स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किये जाएं।

इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में आदर्श विद्यालय भी शिक्षा विभाग द्वारा किये गये हैं। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे यहां एक राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किया। उस भवन के लिये तीन करोड़ रुपये दिये, जो प्रारम्भ हो गया। लेकिन उस भवन में बाउण्ड्री नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजकीय महाविद्यालय में बाउण्ड्री हो। वह भवन बहुत ही अच्छे स्थान पर है, बाई-पास पर है, जहां लड़के और लड़कियां एक साथ, सह-शिक्षा है, अगर उसकी बाउण्ड्री बन जाती है तो बच्चों के हित में अच्छा रहेगा।

मेरा एक और निवेदन है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, मेरे पीपलू उपखण्ड में, जो काफी पिछड़ा हुआ है, वहां पर बच्चों के लिये राजकीय

(श्री हीरालाल)

महाविद्यालय नहीं है। उनको टोंक जाना पड़ता है या जयपुर आना पड़ता है। बरसात के दिनों में उस उपखण्ड की ऐसी स्थिति हो जाती है कि बनास नदी आती है, गहलोत पुलिया टूटने के बाद, गहलोत टोंक से दस किलोमीटर होते हुए भी वह कट जाता है, वंचित हो जाता है, शिक्षा, चिकित्सा सब सुविधाओं से, तो मेरा अनुरोध है कि पीपलू में एक महाविद्यालय खोला जाए।

साथ ही चिकित्सा मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरे यहां झिलाय में 1970 की एक पी.एच.सी. है। उसके बाद मेरे ख्याल से काफी पी.एच.सीज. हैं जो सी.एच.सीज. में कन्वर्ट हो गयीं, क्रमोन्नत हो गयीं। लेकिन मेरा झिलाय कस्बा निवाई विधान सभा क्षेत्र का दूसरे नम्बर का कस्बा है, वहां आज तक भी पी.एच.सी. है। झिलाय में पी.एच.सी. को सी.एच.सी., और राहोली निवाई से 30 किलोमीटर दूर है, वहां से मरीजों को आने में असुविधा होती है तो वहां पी.एच.सी. से सी.एच.सी. और नटवाड़ा ऐसा क्षेत्र है, जो माधोपुर जिले से सटा हुआ है, वहां नटवाड़ा में भी पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

अब मैं निवेदन करूंगा कि पांच माननीय सदस्य हैं, एक माननीय सदस्य यहां से बोलेंगे निर्दलीय उसमें से और तीन आपके हैं तो समय हमारे पास में 60 मिनट है। मेरे ख्याल से 15 मिनट से कम तो किसी माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्य को क्या दिया जाए? कम से कम 15 मिनट तो वह बोलें लेकिन उसके हिसाब से।

मैं आदरणीय गृह मंत्रीजी भी विराजे हुए हैं, आपके नियम यह कहते हैं कि आप कागज से नहीं पढ़ सकते। आप रैफरेंस के लिए कागज जरूर रखें पर मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि बिलकुल वस्तुत: जो लिखा हुआ है, उसका यूं का यूं पढ़ा जा रहा है और रिपीटेशन है। कुछ सदस्यों ने पहले पढ़ लिया और कुछ सदस्य बाद में पढ़ रहे हैं तो अगर आपके पास में, मैं आप पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, सम्माननीय सदस्य, आप इसको अन्यथा मत लेना, मैंने तो सिर्फ, क्योंकि यह इसमें है।

अगर आपके पास में जो चीज पहले कही जा चुकी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है तो अनिवार्य भी नहीं है कि अपन बोलें। जो कुछ आपको अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में अगर निवेदन करना है तो आप वह करें और आपके अगर पास में और कोई ऐसी बात है तो वह करें, क्योंकि कुछ बातें तो ऐसी हैं जो पिछले तीन घंटे में कई बार आ चुकी हैं।

माननीय सदस्य।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जल स्वावलंबन योजना गांवों के साथ-साथ शहर में भी इस बार दूसरे चरण में लागू की है। इस जल स्वावलंबन योजना से राजस्थान को पानी के क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ है और जैसा कि मैंने अभी बीसलपुर बांध का हवाला दिया कि कुएं, बावड़ी, पोखर, तालाब सब भर गये हैं तो शहरों में भी इस योजना को लिया है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के क्षेत्र हमारी यशस्वी शिक्षा मंत्रीजी ने, पंचायती राज मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जन कल्याण शिविर और जन कल्याण शिविर हमारे आदर्श पुरुष महामानव पंडित

(श्री हीरालाल)

दीनदयाल उपाध्यायजी के नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर चलाए गये, जो चल रहे हैं। उसमें सभी पंचायत समितियों में 9593 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किये जा चुके हैं। शिविरों में 7169 पट्टों का आवंटन किया गया, 20291 व्यक्तियों को पुराने भवनों का कब्जा दिलवाकर नियमन किया गया। इस तरह की एक योजना गुरु गोलवलकर योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें अधिक से अधिक राशि सरकार द्वारा व्यय की जा रही है। गत तीन वर्षों में अब तक 2393 कार्य पूर्ण किये गये हैं। इस योजना के माध्यम से 125 करोड़ रुपये का प्रावधान आगामी वर्षों के लिए किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राजस्व शिविरों का भी आयोजन किया गया है। राजस्व शिविरों में 69 लाख 89 हजार प्रकरणों का निस्तारण किया गया और 523 ग्राम पंचायतों को वाद-मुक्त किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो 2014-15 में राजस्व शिविर लगे, मेरा विधान सभा क्षेत्र पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा और मेरे विधान सभा क्षेत्र का उपखंड पीपलू दूसरे नम्बर पर रहा। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को और माननीय राजस्व मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पंचायती राज के जो जन कल्याण शिविर चलाए, उसमें हमें बहुत फख्र होना चाहिए। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य आलोचना, समालोचना की बात करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने, और माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, कल इन्होंने एक महिला थाने का गांधीनगर में शुभारंभ किया, जिसमें सारा स्टॉफ महिला होगी और यह निश्चित है कि जब इस तरह की योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है तो उससे जनता को और महिला को एक विशेष फायदा मिलेगा।

मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हर बजट में मैंने निवेदन किया है और मांग की है और सिद्धांत: माननीय गृह मंत्रीजी भी

(श्री हीरालाल)

इस बात से सहमत होंगे कि मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र में दुर्घटनाएं, अपराध काफी होते हैं और उसको कंट्रोल पुलिस तो कर ही रही है लेकिन निवाई का पुलिस स्टेशन, उस पर काफी भार पड़ता है। माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरे निवाई विधान सभा क्षेत्र में एक सदर थाना भी खोलने की कृपा करें।

साथ ही, अभी प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य, एक मिनट, बोलने दो न, दो मिनट और लूंगा साहब, आपकी। प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्य सरकार की आलोचना कर रहे थे। आलोचना, समालोचना होनी चाहिए लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि अच्छे काम के लिए आप प्रशंसा भी करें और माननीय मुख्य मंत्री महोदया तो इस तरह की मुख्य मंत्री हैं कि-

'फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे,
वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।'

हमारी सरकार के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया की शान में और सम्मान में और माननीय मोदीजी के लिए भी मैं उनकी शान में यह दो लाइन कहना चाहूंगा कि -

'खुदी को कर बुलंद इतना
कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे
बता तेरी रजा क्या है?'

माननीय वसुन्धराजी की सरकार और माननीय मोदीजी की सरकार कोई इस तरह की सरकार नहीं, यह जनता के हित के लिए है, जनता का न्याय करने के लिए माननीय मोदीजी कहते हैं कि हम राज करने के लिए नहीं आए हैं। वह प्रधान सेवक हैं और वह यह कहते हैं कि मैं देश को चलाना चाहता हूं। आपको विदित है कि अब देश चला रहे हैं। विदेशों में, पूरा संसार आज मोदीजी को एकटक देख रहा है और कल आप भी देखना कि क्या-क्या रिजल्ट होंगे?

मैं फिर भी एक निवेदन आपकी शान में करना चाहूंगा, प्रतिपक्ष के भाइयों की शान में कि- तुझे उस पार जाना है तो तूफान भी मिलेंगे, माननीय बेनीवालजी -

(श्री हीरालाल)

तुझे उस पार जाना है

तो तूफान भी मिलेंगे,

डर लगता है

तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते?

जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती अनीता।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हमारी माननीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट रखा है, वह उनका जो विजनरी सोच है, उसमें 2020 को आधार मानकर उन्होंने बजट रखा और इसी में आप समझिये कि 2020 को उन्होंने अभी से सोचना शुरू किया है तो यह उनकी दूरगामी सोच है और यह विकासोन्मुख बजट है। यह सच है कि विरासत में मिली चरमराई अर्थव्यवस्था, अकुशल वित्तीय प्रबंधन की वजह से उनके लिए यह बजट रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। इसीलिए जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य हीरालालजी कह रहे थे, दो लाइनें तो मैं भी दो लाइनें कहना चाहती हूं कि-

जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते,

जो पा लिया उसके खोया नहीं करते।

उनके ही सितारे चमकते हैं,

जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट रखा, इसमें 395 बिंदु रखे हैं हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने और तीन घंटे का लंबा भाषण दिया। इसके अंदर हर वर्ग को, हर संभाग को, हर सैक्टर को, हर विधान सभा क्षेत्र को कुछ न कुछ मिला है।

(18.00 बजे)

इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कृषि, धार्मिक, पर्यटन और व्यक्तिगत लाभ की पेंशन योजनाओं की भी बहुत सारी सौगातें हमारे प्रदेश को मिली हैं और

(श्रीमती अनीता)

ओवर ऑल मैं इस बात को कह सकती हूं कि सबको थोड़ा-थोड़ा मिला है, लेकिन मिला सबको है। इस सदन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि इस बजट में उसको कुछ नहीं मिला। हरेक को थोड़ा-थोड़ा देने की कोशिश की गयी है।

जो सबसे अच्छी बात मुझे इस बजट में लगती है, वह यह लगी कि यू.डी. टैक्स के अंदर ब्याज और पैनल्टी की राशि में 100 प्रतिशत छूट दी गयी है। यह एक अप्रैल से 30 सितम्बर तक यह छूट रहेगी। इसमें शहर में रहने वाले जो हमारे नागरिक बंधु हैं, उनको बहुत दिनों से यह उम्मीद थी कि यह सरकार आएगी तो उनके लिये कुछ न कुछ करेगी और उन सबके लिये यह बहुत बड़ी सौगात है।

एक सौगात कर्मचारियों के लिये भी है। कर्मचारियों को बहुत दिनों से आशा थी कि कब सातवां वेतनमान लागू होगा। मैं हमारी मुख्य मंत्री की बहुत प्रशंसा करना चाहती हूं कि उन्होंने अपने इसी बजट के अंदर सातवें वेतनमान के बारे में लिखा कि उन्होंने कमेटी बना दी है, काम शुरू भी हो गया और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान जल्द मिलेगा जो कर्मचारियों के लिये बहुत बड़ी खुशखबरी है।

इस बजट के अंदर युवाओं को भी सौगात मिली है। कांस्टेबलों की भर्ती, जिसके लिये मैं तो स्पेशली हमारे क्षेत्र भरतपुर के लिये कहना चाहती हूं कि हमारे यहां के बच्चे जब दसवीं और बारहवीं में पढ़ते हैं तभी से, हम रात को या सुबह अगर गाड़ियों से निकलते हैं, तो वहां पर उनकी दौड़ देखते हैं और बीस-बीस, पचास-पचास बच्चे दौड़ लगाते रहते हैं। उनके मन में भावना रहती है कि कब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी और कब वह उसमें भर्ती होंगे। यह बहुत अच्छी सौगात हमारे युवाओं को मिली है।

एक अच्छी सौगात युवाओं को यह भी है कि आर.एस.एल.डी.सी. के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, आई.टी.आई. में काम चल रहा है। पालीटैक्निक रोजगार मेला, स्वरोजगार योजना और उद्यमिता विकास कार्यक्रम के जरिये सरकार ने रोजगार को आगे बढ़ाने का और हमारे बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ स्किल करने की जो योजना बनाई है, वह अपने आप में बहुत परिपूर्ण है। जब अंग्रेजों का राज आया तो उस समय में पढ़ाई के

(श्रीमती अनीता)

ऊपर सिर्फ इतना ही ध्यान दिया जाता था कि शिक्षा केवल ज्ञान के लिये थी। बाद में हमने बी.ए., एम.ए. बहुत सारे ऐसे डिग्री कोर्सेज बना दिये, उस डिग्री कोर्सेज को जब किसान का बेटा कर लेता है तो वह घर के या खेती के कामों को नहीं करता। उसको आगे जाकर नौकरी नहीं मिलती तो वह इतना परेशान हो जाता है, उसके मां-बाप भी परेशान हो जाते हैं कि वह किसानी के काम से भी गया और आगे जाकर उसको नौकरी नहीं मिली तो उसके परिवार को सब कुछ भुगतना पड़ता है। सरकार की जो यह सोच है, वह बहुत सराहनीय सोच है और इसी सोच से हम सब लोगों को वह साथ लेकर चल रहे हैं और मैं समझती हूं कि राजस्थान के अंदर अगर यह सबसे अच्छा चल रहा है तो उसका कारण हमारे मुख्य मंत्री की सोच हैं, उनका विजन है और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, उनकी कार्यविधि है जिसकी वजह से यह बहुत अच्छा चल रहा है।

राजस्थान प्रदेश के अंदर रियल एस्टेट का भी बहुत अच्छा बिजनस होता था और जब मंदी चल रही थी उस दौर के अंदर जहां भी बात करो, हर जगह सबको यही लगता था कि रियल एस्टेट का काम नहीं हो पा रहा है। कोई किसान जमीन बेचना भी चाहता था तो उसको लगता था कि उसकी जमीन के दाम वह नहीं मिलेंगे, जो दाम उसको चाहिये थे। कारोबारी जो मंदी की मार झेल रहे थे, उनको राहत देने के लिये सरकार ने इस बजट के अंदर कई श्रेणियों में स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की फीस में भारी छूट दी है। मैं समझती हूं कि इस छूट से बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा होगा, कारोबार में भी कुछ जान आएगी और इसमें बहुत सारा काम होना शुरू हो जाएगा।

सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग ज्यादातर यह समझते थे कि बच्चों को हम पढ़ा देंगे तो पढ़ाने के बाद जो बच्चे नौकरी लग जाते थे या जितनी आर्थिक स्थिति सही हो जाती थी, वह गांव से निकलकर शहरों की भागा करते थे। उनको लगता था कि हम शहरों में रहेंगे तो हमारे बच्चों को और अच्छी शिक्षा देंगे, शहरों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है और गांवों को स्मार्ट बनाने का जो उन्होंने तय किया है, मैं समझती हूं कि इससे शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा और

(श्रीमती अनीता)
गांवों के अंदर वह सारी सुविधाएं, जिन सुविधाओं की कल्पना हम करते थे कि शहर में हमको मिलेगी, वह गांवों में ही हमको मिलने लग जाएंगी तो यह बहुत बड़ी योजना रहेगी। मैं यह समझती हूं कि किसानों के जो बच्चे हैं, उनको बहुत सारी योजनाएं मिलेंगी।

इन्होंने बजट में कहा है कि गांवों में ई-पुस्तकालय होगा, नॉलेज सेंटर होगा, वाई-फाई का नैटवर्क होगा तो मैं समझती हूं कि आज के युवा को अपनी पढ़ाई और अपने और भी जो काम हैं उनके लिये इन सब चीजों की सख्त आवश्यकता रहती है। आजकल पढ़ाई भी सब कुछ ऑनलाइन होने लग गयी है, नैटवर्क पर हो गयी। वाई-फाई तो वह अपने कम्प्यूटर्स पर उस पढ़ाई को कर सकते हैं। चाहे अमरीका की हो, या मुम्बई की हो या जयपुर की हो, उस पढ़ाई को बैठा-बैठा आज अपने गांव में सीख सकता है, वहां भी पढ़ सकता है। यह बहुत अच्छा काम किया है।

एक सबसे अच्छी बात किसानों के लिये यह भी है जो अभी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने कुछ दिन पहले ही किसानों के जो बढ़े हुए बिल थे, उनको वापस लिया। उसमें बहुत सारी घोषणाएं कीं और उन घोषणाओं के साथ-साथ बजट के अंदर जो एक लाख नये कृषि कनेक्शन की घोषणा की है, मैं यह समझती हूं कि इस वर्ष में अगर सबसे बड़ी चीज और जो कोई सौगात किसानों को अगर मिली है तो वह कृषि कनेक्शन के लिये मिली है। आजकल जमीन के अंदर पानी बहुत नीचे चला गया है कि उस पानी को बिना बिजली से वह खींच नहीं सकता और किसान अपनी सिंचाई की व्यवस्था नहीं कर सकता। अगर हर किसान को बिजली की व्यवस्था मिल जाए तो अपने खेतों को अच्छी तरह से सिंचित करेंगे, जब अच्छे से सिंचित करेगा तो निश्चित रूप से अच्छी फसल लेगा। अच्छी फसल लेगा तो उसका भविष्य अच्छा होगा और उसके साथ-साथ प्रदेश का भी बहुत अच्छा भविष्य होगा।

हमारे यहां प्रदेश में बहुत दिनों से यह बात चली आ रही थी कि हम लोगों ने एस.सी. के, एस.टी. के, ओबीसी के और अब एस.बी.सी. का भी था, लेकिन आज की तारीख में नहीं है, इन सब लोगों के लिये, उनके बच्चों के पढ़ने के लिये बहुत सारी व्यवस्थाएं कीं। जैसे एस.बी.सी. के लिये देवनारायण

(श्रीमती अनीता)

योजना बनाई, एस.सी., एस.टी. के लिये भी बहुत सारी योजनाएं बनाईं, लेकिन सवर्णों के लिये भी आयोग का गठन करके उनके बच्चों की, जिनकी ढाई लाख से कम सालाना आय है, मैं समझती हूं जो गरीब बच्चे हैं, लेकिन गरीब के होने के साथ-साथ वह मेधावी बच्चे हैं, उन छात्राओं के लिये स्कूटी, उन छात्रों के लिये स्कॉलरशिप की जो योजना बनाई है, वह सबसे अद्‌वितीय योजना इस बजट के अंदर है। जो नारा हमारी भारतीय जनता पार्टी का है कि 'सबका साथ, सबका विकास' उसको साकार रूप देने का यह बहुत अच्छा काम इसमें हो जाएगा, मैं यह समझती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन वर्षों के अंदर मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरकार की ओर से बहुत सारे काम किये गये। हमारी जो महिला मंत्री हैं, मैं उनका भी आज इस भाषण के जरिये धन्यवाद करना चाहती हूं। हमारी किरण माहेश्वरी जी हैं, जब उनके पास पी.एच.ई.डी. विभाग था तो बहुत सारे काम किये। अभी उच्च शिक्षा में भी यह बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगी। मेरे क्षेत्र में काफी सारे काम हुए हैं। हमारी जो वीमन एण्ड चाइल्ड वैलफेयर मिनिस्टर हैं अनिता भदेल जी, मुझे आज इस बात की बहुत खुशी भी है कि कल उनको पूरे देश में प्रथम पुरस्कार मिला और आज उनका लंच हमारे प्रधान मंत्रीजी नरेन्द्र मोदी के साथ हैं। मैं उनके लिये बहुत गर्व अनुभव करती हूं कि इन दोनों महिलाओं ने और हमारी दीपा जी, कृष्णेन्द्र कौर जो हमारी पर्यटन मंत्री हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन बिलकुल जीरो पड़ा था कांग्रेस के शासन में, लेकिन जब से आपके पास यह विभाग आया, आपने हमारे भरतपुर क्षेत्र में बहुत से आर्कोलॉजी की सब चीजों को धीरे-धीरे लेकर आज इस बजट में काफी घोषणाएं करायी हैं तो आप तीनों का बहुत अच्छा काम है। कमसा मेघवाल जी का भी बहुत अच्छा काम अब सामने आएगा, उनको अभी एक महीना ही हुआ है मंत्री बने, लेकिन अगले बजट में निश्चित रूप से उनके काम की प्रशंसा मैं इस मंच से अवश्य रूप से करूंगी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहती हूं, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, वह ग्रामीण एरिया है और वहां के लोग ज्यादातर कृषि पर ही डिपेंड रहते हैं। हमारे लोगों की मांग थी, मैं यह समझती हूं कि जब से विधान सभा चलने लगी है तब से उनकी डिमांड थी कि हमारे खेतों को पानी मिले।

(श्रीमती अनीता)

गुड़गांवा मेन कैनाल का वहां पानी आता था लेकिन वो कामां में ही रह जाता था और पहाड़ी तक आता था, हमारे क्षेत्र में नहीं आता था। हमारे मंत्री रामप्रताप जी अगर यहां होते तो उनको भी मेरी ओर से बधाई कि उन्होंने मेरे क्षेत्र के लिए 71 करोड़ रुपये सैंक्शन किये। मुख्यमंत्री 5 जनवरी को जब हमारे यहां आयी थीं तब उन्होंने घोषणा की, अब यहां बजट के अन्दर भी इसकी घोषणा है, जो हमारे पूरे क्षेत्र, मैं समझती हूं कि डीग, जो मेरी विधान सभा का क्षेत्र है उसमें एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर नहर का पानी हमको नहीं मिलेगा। यह बात अलग है कि हम हरियाणा से कितने पानी को खींच लाते हैं। अब हमारी सबसे बड़ी बात यह रह जाएगी कि हम हरियाणा से ज्यादा से ज्यादा पानी, जो हमारा हिस्सा है 1271 का वो हिस्सा पूरा हम उनसे लें तो हमारे क्षेत्र में किसान बहुत खुशी मना रहे हैं। अभी मंत्री जी गये थे, उन्होंने उनका भी स्वागत किया था, मेरा भी स्वागत किया और वहा के लोगों को यह लग रहा है कि इतने वर्ष हम लगातार कहते रहे, किसी ने हमारी नहीं सुनी, यही एक ऐसी सरकार है जिसने हमारी सुनी भी, हमारे लिए पानी भी आया और अब इतना बड़ा बजट। जो सिल्ट है, उसको हटा रहे हैं। जहां पर पानी उसमें निकल जाता है, उसके लिए भी दोबारा पक्की नहरें बनाने का जो काम किया है वो एक बहुत बड़ा काम है।

अलवर से भी रूपारेल नदी के द्वारा हमारे क्षेत्र में पानी आता है। हमारे हेमसिंह भड़ाना जी मंत्री महोदय बैठे हैं, उनके क्षेत्र में बरसात का पानी इकट्ठा होता है और वो पूरा घूम कर आता है। यह रूपारेल नदी हमारे यहां शुरू से आती थी, हजारों साल से चली आ रही है लेकिन 20 वर्षों से पानी हमारे क्षेत्र में नहीं आया था, मैं धन्यवाद करना चाहती हूं इस सरकार का कि इस बार जब बरसात हुई तो तीन बार मेरे क्षेत्र में पानी आया और पानी के आने की वजह से मेरे किसानों के, मेरे क्षेत्र के लोगों के चेहरों पर जो खुशी है, जो हंसी है वो इस सरकार की देन है और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ...(व्यवधान)...

हां, हमारे जयराम जी भी हमारे साथ रहे, इन्होंने भी हमारी उसमें बहुत मदद की, इनके क्षेत्र में भी पानी आया, हमारे क्षेत्र में भी पानी आया। बनवारी जी चले गये, उनके क्षेत्र को भी पानी मिला। हम तीनों की, विधान

(श्रीमती अनीता)

सभा की कमेटी बनायी थी और उस कमेटी का असर पड़ा कि हमको पानी मिला, अगर विधान सभा से यह कमेटी नहीं बनती तो पता नहीं पानी आता कि नहीं आता। लेकिन सरकार ने इसमें बहुत बड़ा काम किया है।

मैं हमारे मंत्री महोदय रामप्रताप जी का ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहती हूं कि यह जो रूपारेल नदी आती है वहां से यहां तक, यहां पर बहुत सारी बजरी को खींच लाती है और बजरी क्योंकि वो खान विभाग में आती नहीं तो लोग उसको वैसे ही ट्रैक्टर्स लगा-लगा कर खींच लेते हैं। उसमें बीस-बीस फुट गड्ढ़े उन्होंने बना दिये हैं, तो उनको सही करना बहुत जरूरी है जिससे पुल, जो हमने बनाये हैं, वो पुल नहीं टूटें और जो हमने व्यवस्थाएं की हैं उन नहरों को ठीक करने की वो खराब नहीं हो।

मैं यह समझती हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. की अगर हम बात नहीं करें तो ऐसी बात हो जाएगी कि सबसे मजबूत जो विकास का काम करने की स्थिति में है वो हमारा पी.डब्ल्यू.डी. है। मेरी 59 पंचायत हैं, 59 पंचायत में से 14 पिछली बार बन गयी, 14 अब बन रही हैं और अब आगे भी 14 उसमें बन जाएगी तो मैं समझती हूं कि आधे से भी ज्यादा हमारे जो पंचायत हैडक्वार्टर्स हैं उनमें एक ऐसी सड़क बन गयी है। लोग इस बात को कहने लग गये हैं कि बहुत अच्छा काम है, मैं समझती हूं कि दस, पन्द्रह साल, बीस साल सड़कें नहीं टूटेंगी क्योंकि नाली का इतना बड़ा प्रावधान उसमें है।

आज सरकार की जो बैक बोन है और जो डवलपमेंट दिखा रहा है, जो काम दिखा रहा है वो हमारा ग्रामीण पथ है। अब शहर में भी उसको मन्जूर किया है तो एक अलग काम शुरू हो जाएगा होली के बाद। बहुत अच्छा उसमें हो जाएगा और बहुत अच्छी देखने-दिखाने लायक वो सड़क बनेगी। नगर से गोवर्धन जाएंगे तो पता लगेगा कि कितना अच्छा डवलपमेंट हमारी मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा किया गया है।

मैं हमारी केन्द्र सरकार को भी बहुत बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में नोन एक्सीडेंटल जोन तय किया, जो नगर से लेकर बहरोड़ तक सौ किलोमीटर का है। इसमें दो ट्रोमा सेण्टर भी दिये हैं, जिसमें एक ट्रोमा सेण्टर मेरे यहां भी बनेगा। तो यह भी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना मेरे क्षेत्र में हुई है, उसके लिए मैं केन्द्र सरकार में हमारे नितिन गडकरी जी,

(श्रीमती अनीता)

हमारी मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रीजी, तीनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि इन्होंने इतने अच्छे काम किये हैं।

हमारी बहुत बड़ी समस्या थी हमारा जो एक रोड़ था, खेड़ली तक तो वो बन गया था, जयपुर से अपन खेड़ली तक जाते हैं, खेड़ली से नगर और नगर से पहाड़ी, यानी कि 61 किलोमीटर जो अब सैंक्शन किया है उसमें 35 और 40 किलोमीटर मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। हमारी मुख्य मंत्रीजी का मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि इसके लिए उन्होंने 117 करोड़ रुपये सैंक्शन किये, उसका वर्क ऑर्डर किया और बहुत जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा जिससे मैं समझती हूं कि मेरे क्षेत्र की जो मेन समस्या थी, जो रीढ़ की हड्डी हमारे क्षेत्र में से निकलती थी उसकी सैंक्शन कर के हमारे क्षेत्र पर और हमारे लोगों पर उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है।

स्कूल्स के बारे में भी मैं कहना चाहती हूं कि एक बार हमने पंचायत हैडक्वार्टर्स पर सारे सीनियर सैकण्डरी स्कूल कर दिये और सीनियर सैकण्डरी स्कूल में फिर रख दिया थोड़ा सा कि जहां पर प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां नहीं किये। लेकिन कई मेरे पंचायत हैडक्वार्टर्स थे, सरकारी स्कूलों में अच्छी स्थिति थी और उन लोगों की हमेशा डिमांड रहती थी कि हमारा नहीं हुआ। क्योंकि और तो सारे हो गये, वो दो-तीन बच गये तो उन्होंने अपना ध्यान कन्सन्ट्रेट कर लिया लेकिन इस बार मुख्य मंत्रीजी से हम मिले और उन्होंने हमारे जो दो स्कूल बच रहे थे बेरू और जालूकी, अब बजट के अन्दर वो दोनों सीनियर सेकण्डरी स्कूल आपने मन्जूर कर दिये। उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं।

एक हमारी महत्वाकांक्षी योजना जल स्वावलंबन की भी है। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में पीने के लिए पानी ही नहीं है। हमारा डिपेन्डेन्ट्स अलवर से या गुड़गांव कैनाल से हरियाणा से है या हमारे गम्भीरी नदी से पाचना से कोई पानी भरतपुर में आ जाए, तो वो ही हमारा ग्राउण्ड लेवल वाटर होता है, उसी से पीने के पानी की व्यवस्थाओं से हम रहते हैं। यह जल स्वावलंबन योजना जो की है कि उस पानी को हम रोकेंगे, तो हमारे यहां पर पिछले साल जो काम हुआ, हमारे गोयल साहब जब पंचायती राज मंत्री थे मैंने इनको भी बताया था, हमारे यहां डेढ़-डेढ़, दो-दो फुट पानी ऊपर

(श्रीमती अनीता)

आ गया जिससे लोगों ने खुशी जाहिर की कि यह काम भविष्य के लिए, कहते हैं न अगला, तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तो उस पानी का संरक्षण, उसको बचाना, हमारी इस सरकार की और हमारी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। उस योजना के रूप में प्रदेश को एक ऐसी सौगात मिलने वाली है आगे समय में कि हम इस बात को कह सकेंगे कि यह बहुत अच्छा काम हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के बारे में मैं कह सकती हूं कि मैं आज इस बात से बहुत खुश हूं कि मेरे क्षेत्र में पहले तो सरकार ने आते ही चम्बल परियोजना शुरू की लेकिन वो किन्हीं कारणों से, ठेकेदारों की वजह से, उनके भाग जाने की वजह से, उनके काम नहीं करने की वजह से वो योजनाएं जो अटकी पड़ी हैं, उसको तो मंत्री जी मेरी बात को सुन रहे हैं, उसमें से भी खींच-खांच कर जरूर करेंगे कि बहुत जल्दी वो भी चले। लेकिन उसके एवज में, क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि हमारे पीने के पानी की समस्या है और यह चम्बल वाली परियोजना में काम नहीं हो रहा है तो हमारे लोग कैसे पानी पीयेंगे? मैं कहना चाहती हूं कि मेरे यहां पर 118 आर.ओ. सैंक्शन किये जिससे आज मैं कहीं भी गांव में जाती हूं तो मैं उनसे इस बात को कह सकती हूं कि आपके लिए शुद्ध पेयजल है। जब तक यह पानी है आप पीजिये और समय रहते कोई न कोई व्यवस्था निकाल कर चम्बल की परियोजना का काम भी हम शुरू कराएंगे।

मैं धन्यवाद देना चाहती हूं हमारे गृह मंत्री महोदय को भी कि इन्होंने जो हमारी सबसे बड़ी मांग थी गो रक्षा चौकी की, वो मेरे क्षेत्र में पूरी की और आज उन चौकियों की बिल्डिंग्स, भी बन गयी और एक फायरिंग रेंज भी इन्होंने मेरी सैंक्शन की, जिसका काम अब चल रहा है। तो मैं हृदय से आपका भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि हमारे यहां पर बहुत समय से, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) पिछला कांग्रेस का राज था तो आप भी जानते हैं कि बहुत सारे झगड़े गांव वालों के गौ-कशी के ऊपर हुआ करते थे, आज वो सारे झगड़े बंद हो गये।

हमारी पुलिसिंग बहुत अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी, गृह मंत्री महोदय, हमारे यहां पर आपकी जो परमेश चन्द्र कमेटी है उस कमेटी ने

(श्रीमती अनीता)

हमारा सी.ओ. सर्कल नगर का बनना रखा है, तो आप उसका ध्यान दें, आपकी डिमांड आये जब उसकी घोषणा अवश्य रूप से करें। ऐसी मैं आपसे आशा करती हूं। क्योंकि जब आपने इतने सारे काम दे दिये हैं तो छोटा-मोटा भी मत रखो, कम से कम जनता यूं तो कहे कि जो काम दिये वो सारे के सारे हंड्रेड परसेंट हो गये।

हमारी बहुत सारी बातें अभी और कहनी है, क्योंकि मुझे तो खूब सारा मिला है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय की बारबार घंटी बज रही है। मैं आपका आदर करते हुए दो लाइनों में अपनी बात खतम करना चाहती हूं।

मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारी सरकार के लिए कहना चाहती हूं, 'परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं।' धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आपको मुझे इस बजट भाषण पर बोलने की अनुमति दी।

उपाध्यक्ष महोदय, 109 पृष्ठ और 395 बिन्दु इस बजट के अंदर हैं। इस बजट से राजस्थान की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद थी। अगला जो 2018 का बजट आएगा, वह तो चुनावी वर्ष है। पूरे राजस्थान का जवान और किसान इस बजट की ओर देख रहा था। बहुत बड़ी उम्मीद जवानों के अंदर थी। हमारे संविदाकर्मियों के अंदर थी। किसान उम्मीद के साथ राजस्थान की विधान सभा की तरफ देख रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और दिल्ली में भी जो बहुमत मिला है, उससे लोगों को, किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हमें इस बजट से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जब ढाई घंटे का बजट सुना और आज का अख़बार जिसने भी पढ़ा, निश्चित रूप से आपका 80 परसेंट काम तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन अखबारों से ही हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जवान को आपने 15 लाख रोजगार की बात कही थी। किसान के लिए, सुराज आएगा और हम यह करेंगे, वह करेंगे।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लेकिन साढ़े 3 साल में आप जिन योजनाओं का गुणगान कर रहे हो, उन योजनाओं से आपको बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा।

आप भामाशाह योजना लेकर आए। आपने गांव के सभी लोगों का ध्यान उस ओर बंटा दिया कि भामाशाह कैम्प लग रहे हैं। दूसरी आप जल स्वावलंबन योजना लेकर आए। लोग इतने डरने लग गए कि जहां भी जल स्वावलंबन का कैम्प होता है, आपके मंत्री जाते हैं, वहां लोगों ने जाना छोड़ दिया कि पता नहीं कितने की रसीद कटानी पड़ेगी। आपने चंदा इकट्ठा करने का काम कर दिया राजस्थान में। क्या अपने पास इतनी कमी पड़ गयी कि आप जल स्वावलंबन योजना के तहत सरकारी कार्यक्रम करो और वहां इस अधिकारी की इतने की रसीद काट दो, यह भामाशाह का है, इसकी इतने की काट दो।

उपाध्यक्ष महोदय, साढ़े 3 साल के अंदर आपका ज्यादातर टाइम वी.सी. के अंदर ही बीता। हर जगह देख लो, एसडीएम को टेलीफोन करते हैं तो एसडीएम साहब वी.सी. में, कलेक्टर वी.सी. में है। पूरे साढ़े 3 साल में जनता का कोई काम नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सबसे ज्यादा आंदोलन हुए। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2003-08 के अंदर भी सबसे ज्यादा आंदोलन का अगर दंश किसी राज्य ने झेला तो राजस्थान राज्य के अंदर सबसे बड़े आंदोलन हुए। सबसे ज्यादा गोलीकांड भी राजस्थान में आपकी पूर्ववर्ती सरकार के समय 2003-08 में हुए। आज भी राजस्थान का किसान कर्जे से तंग आकर के आत्महत्या कर रहा है। राजस्थान के अंदर 43 किसानों ने आत्महत्या कर ली।

उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी से तंग आकर के सबसे ज्यादा जवान अगर सड़क पर दम तोड़ रहा है तो राजस्थान का जवान है। वह सरकार को कोस रहा है। सुराज संकल्प यात्रा के अंदर आपने वादा किया था कि राजस्थान के जितने भी संविदाकर्मी हैं, उनको हम नियमित करेंगे। राजस्थान का जवान आपके बहकावे में आ गया। कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, 50 साल का

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राज था, उन्होंने भी जवानों का कोई विशेष भला नहीं किया। जवानों ने सोचा कि इस बार मोदी के नारे के साथ चलेंगें तो हमारा भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित है।

लेकिन 15 लाख रोजगार देने वाली जो बात है, आज तो आपने उस बात को ही नकार दिया। आपके कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने तो 15 लाख रोजगार की बात ही नहीं की। हमने तो कहा कि रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आप कहां करोगे, यह तो बताओ ? व्यवस्था किस जगह करोगे? आपने तो 15 लाख नौकरियां देने की बात की थी कि अगर हम सत्ता में आए तो 15 लाख जवानों को नौकरियां देंगे। सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आपने रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से, 6 महीने आपको जनता देखती रही कि रिसर्जेंट राजस्थान कर रहे हैं जयपुर के अंदर, बहुत बड़ा कार्यक्रम है।

आपको तो टाइम पास करना था कि 5 साल कैसे निकालें। पौने 200 की संख्या आ गयी। विधायकों को भी राज़ी रखना, क्योंकि सबको हम लाल बत्ती भी नहीं दे सकते। सारे मंत्री भी नहीं बन सकते। इसलिए आप नई बात हर बार लेकर के आए। रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से आपने करोड़ों रुपये जयपुर में खर्च किए। कई विदेश में रहने वाले लोग भी आए। आपके सी.एम. साहब ने बाहर रोड शो भी किए। देश में भी किए, विदेश में भी किए। लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी, 40 से ज्यादा एमओयू दम तोड़ते नजर आए। उस रिसर्जेंट राजस्थान का कोई फायदा अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। 2019-20 में आएगा, उसमें आपका कुछ भी नहीं होगा, वह तो 2018 के बाद आएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक आप स्किल डवलपमेंट की बात हमेशा करते हो। अजी, स्किल डवलपमेंट कहां करोगे? आपने अपने-अपने जो लोग थे उनको सब जगह दिला दिए स्किल डवलपमेंट के, कि आपको यह दिला दिया यूनिवर्सिटी, कालेज, स्किल डवलपमेंट सेंटर खुला दिया। जब सेंटर की कहीं जांच करने गये तो कहीं तो गौशाला नजर आई, कहीं दूसरा कुछ आया। कहां से स्किल डवलपमेंट हो रहा है?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी विड़म्बना है कि आजादी के 70 साल बाद जब हम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं, बजट पर चर्चा करते हैं तो एक पक्ष सिर्फ उसके पक्ष में ही बोलता है और दूसरा पक्ष उस बजट के खिलाफ, राज्यपाल के अभिभाषण के खिलाफ भाषण देता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान के जवान, राजस्थान के किसान को बचाना है तो आज आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ गयी। पिछली बार कांग्रेस की भी सरकार राजस्थान में थी, दिल्ली में थी। अब की बार आपकी राजस्थान में सरकार है। आपने कहा कि हमारे एम.पी. बनाओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। हम राजस्थान को विकसित राज्य बना देंगे। हम राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन राजस्थान को 3 साल में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। आज राजस्थान जो शर्तें होती हैं, वह सारी पूरी करता है। हमारा सीमावर्ती इलाका है। राजस्थान के पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। आदिवासी इलाका और जो यहां की संस्कृति है, वह सारे के सारे मापदंड पूरे करने के बाद भी राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन की नेता ने 3 विशेष बातें यहां पर कही थी कि एक तो आर्थिक विकास में तेजी, रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना और सुशासन कायम रखना है। मगर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि रिसर्जेंट राजस्थान में जो आपका जुमला था, वह फेल हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा बिन्दु, रोजगार के अवसर देने का था। चौथे साल के अंदर भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया कि नौकरियां आप एक साल के अंदर लगाएंगे। क्या आप करने जा रहे हो, क्या नहीं करने जा रहे हो? आपने तो एक काम किया कि बजट बहुत अच्छा आपने दिया और इस बार सी.डी. भी बनाकर दी और पैन ड्राइव दिया। इसके साथ-साथ कुछ टैबलेट और दे देते ना, तो पढ़ने के बाद उसको लेकर के सो जाते। वह एक थोड़ी सी चूक हो गयी।

उपाध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या 9 में आपने कहा कि 'नवीन सुधार से व्यय का समग्र दृष्टि से प्रावधान तथा संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग किया जा सकेगा'। मगर सरकार यह बताए कि व्यय करेगी कहां पर? बजट तो आपके लैप्स होते जा रहे हैं। आप जो बजट है उसको पूरा नहीं कर रहे हो। इसकी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

वजह से केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले फंड पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या 12 से लेकर के 28 तक सड़कों की बात कही है कि हजारों किलोमीटर हमने सड़क बना दी। गौरव पथ बना दिए। उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे और मैं भी था। जब राजस्थान के अंदर सड़कें बनी, चाहे मिसिंग लिंक बनी, गौरव पथ तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन धार्मिक महत्व की जो सड़कें बनी थी तो उसमें राजस्थान के सारे विधायकों की अभिशंसा पर सड़कें बनी थीं। आपने तो जो छोटा सा विपक्ष है, 23-24 तो इस साइड के अंदर हैं, 5-7 हम लोग हैं, आपको तो हम इतने भी नहीं सुहाते हैं। आपने तो हमारी अभिशंसाओं को दरकिनार करके फेंक दिया। विधायकों से अभिशंसा तक नहीं कराई। जो आपके हारे हुए प्रत्याशी थे, कोई तो अपनी ढाणी के अंदर सड़क बना रहा है, कोई अपने खसरे के अंदर बना रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, खींवसर के अंदर तो हमारे मंत्री जी वहां से आते हैं। अब मैं उन पर आरोप नहीं लगाना चाहता। लेकिन उन्होंने अपने गांव के चारो तरफ रिंग रोड बना दी कि हनुमान बेनीवाल की अभिशंसा पर सड़क नहीं बननी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सरकार जितनी बदले की भावना से काम करेगी, उतने ही हम और आगे बढ़ेंगे। यह सड़कें, बिजली, इनसे आप हमारा हौसला कम नहीं कर पाओगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिए था कि प्रत्येक विधायक की अभिशंसा को आगे रखती। गौरव पथ बनाने थे, 2 डामर सड़कें जो गांव के बीच से निकलती हैं, उस भाग के अंदर जहां ज्यादा खराबी होती है, उसको गौरव पथ के माध्यम से सी.सी. रोड बनाकर के ठीक करने की बात की। आपने तो सारे नियमों, कायदों की धज्जियां उड़ा दी। मेरे वहां से लोग हाई कोर्ट गये। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि खींवसर में आपने सड़कें गलत बना दी। आपने एफिडेविट दिया कि जैसा विधायक जी चाहते हैं या जैसी इनकी अभिशंसा थी, वह हम बना देंगे। इससे आपको हाई कोर्ट की फटकार के बाद दुगुना बजट खर्च करना पड़ा। खींवसर विधान सभा क्षेत्र में सड़कें बनी। अब फिर लोग हाई कोर्ट गये हैं, पीआईएल लगाई है। जनता का पैसा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आप दूसरे लोगों को जो कि नजदीक का विधायक ही नहीं है, उनकी अभिशंसाओं पर आप काम करोगे तो कौनसा लोकतंत्र रह जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जब चुनी हुई सरकार इस तरह से भेदभाव करेगी तो हम कैसे विश्व के सबसे बेहतरीन लोकतंत्र होने का दावा करेंगे। अब आपको हम सुहाते ही नहीं हैं। पहले भी परंपराएं थी। आप भी भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग, ज्यादातर विधायक इस बार चुनकर आए हैं, हम भी थे, पानी का काम होता था या दूसरा काम होता था तो हम लैटर लिखते थे और सरकार हमारा काम करती थी। लेकिन इस बार तो आपने सारी हदें पार कर दीं।

उपाध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या 32 के अंदर सिंधी कैंप बस स्टैंड के विकास की बात कही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पर भी सिंधी कैम्प बस स्टैंड की बात हो गयी थी। काम चालू हो गया था लेकिन तीन साल तक तो आपने सिंधी कैम्प बस स्टैंड का विकास नहीं किया। जब करोड़ों रुपये का रेवेन्यू लोस हो गया तो आपने तीन वर्ष तक बदले की भावना से कार्य को रोकना और अब वापस शुरू करके सुराज की भावना से कोसों दूर आपने कहा कि हम सिंधी कैम्प का काम करेंगे।

बिन्दु संख्या 33 में प्रदेश के गांव ढाणियों को पेयजल से लाभांवित करने की बात कही मगर आज मैं मेरे जिले की बात करूं तो मेरी परियोजनाओं में भयंकर देरी और लापरवाही हो रही है और सरकार इस बात पर समय पर ध्यान देती तो अब तक घर-घर तक पानी पहुंच जाता। जब तक यह पूरी नहीं हो तब तक प्रत्येक गांव के अंदर दो-दो हैंडपम्प लगाएं ताकि लोग मटके से जो पानी लेकर जाते हैं, दूर दराज जिनकी ढाणियां हैं, गांव के अंदर तो आपने पाइंट लगा दिए लेकिन ढाणियों तक वह पानी नहीं जा रहा है, दो-दो हैंडपम्प की मैं इसलिए मांग करूंगा।

बिन्दु संख्या 33 में पेयजल योजना की बात सरकार कर रही है जिसमें मैं सदन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि केवल पुरानी सरकार की योजनाओं को लंबित बताकर टाइम पास किया और यह जो एसपीएमएल, मैं कोई

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आरोप नहीं लगाना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एसपीएमएल घोटाले की बहुत बड़ी आंच सरकार पर आई। मंत्री पर आरोप लगे और आपके जो वर्तमान मंत्री हैं वह बाहर मीडिया से कह रहे थे कि पूर्व मंत्री के घोटाले की जांच करा दो। हमें तो आवश्यकता नहीं पड़ी, आप तो खुद ही आपस में कर रहे हो सब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक उस कम्पनी के प्रमोटर्स को सरकार पकड़ नहीं पाई, पिछले सरकार के सी एम के नजदीक थे ओम मैटल्स कम्पनी को आपकी भाजपा सरकार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बताया। एसपीएमएल कम्पनी के मालिक और ओम मैटल्स के मालिक दोनों सम्बन्धी हैं, इस प्रकार जब आपकी सरकार हो तो एसपीएमएल और कांग्रेस की सरकार हो तो ओम मैटल्स। अब आप बताओ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय ?

बिन्दु संख्या 43 के अंदर शहरी जलप्रदाय योजना की बात की मगर आज भी राजस्थान के शहरों में अधिकतर कॉलोनियों में फ्लोराइडयुक्त गंदा पानी जनता पीने को मजबूर है और जयपुर के अंदर भी पीने के पानी से मौतें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में गूंजती है। बिन्दु संख्या 49 से लेकर 56 तक ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं पर आपने बात की। 1 लाख कृषि कनेक्शन देने की बात की माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आपकी तो, फरवरी, 2010 की जो फाइल किसान ने भरी है अभी तो वही पेडेंसी चल रही है, सात साल पीछे चल रहे हैं आप, कनेक्शन किसको दोगे आप यह तो बताओ। ज्यादातर इलाकों को तो आपने डार्क जोन घोषित कर दिया। हमने इस बात को कहा कि आप किसान का भला करना चाहते हैं तो एफेडेविट पर इस राजस्थान के किसान को जिसका कोई दोष नहीं है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इन इलाकों में डार्क जोन हो गया और डार्क जोन के बाद जब वह अपना कागज लेकर एईएन ऑफिस में फाइल लेकर पहुंचता है तो कहा कि आप तो आरआई और पटवारी से लिखवा कर लाओ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब वह आरआई और पटवारी से लिखवाने गया तो आरआई पटवारी ने कहा कि दो लाख रुपए दे दो तो मैं लिख दूंगा कि आपका कुआ डार्क जोन का आदेश जो हाई कोर्ट का आया था उससे पहले खुदा हुआ है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसके

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अंदर हुआ और हमने इसकी बार-बार मांग की, हमने बहुत बड़ा महापड़ाव भी डाला था तब सरकार ने हमारी बात पर कमेटियां बनाई और इस मुद्दे को मैंने पहले भी राजस्थान की विधान सभा में उठाया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे राजस्थान की सरकार को दस हजार करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति होगी और आठ सौ करोड़ रुपये अतिरिक्त आपको मिलेंगे, अगर डार्क जोन से पुराने जितने भी कृषि कनेक्शन हैं उनको किसान के एफेडेविट पर आप नियमित करो और नए कनेक्शन दो तो निश्चित रूप से जो राजस्व घाटे के अंदर जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 के आंकड़े को 70 हजार भी माने तो बिजली कम्पनियों का घाटा एक लाख ग्यारह हजार सात सौ करोड़ रुपये हो गया। जो बिजली देश भर में सर्वोच्च स्तर पर है उसकी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी द्वारा जांच होने की आवश्यकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान की सारी बिजली फ्री कर देते हैं 15 साल के अंदर 2002 के अंदर 2002 में आए 2002 में कम्पनियां बनाईं और उसके बाद हर साल घाटा बढ़ता गया, घाटा बढ़ता गया, अगर पूरे किसान की बिजली माफ होती तो 1 लाख 11 हजार करोड़ नहीं जाती, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं बिजली कम्पनियां, मंत्रियों तक, बिजली की खरीद में घोटाले हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी ऑडिट 2000 से लेकर 2015 तक की होती, 2017 तक निश्चित रूप से बिजली के मामले में बहुत बड़ा किसान का भला होता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इसको लेकर हम बहुत बड़ा आंदोलन भी राजस्थान में कर रहे हैं, बिजली की दरें पहले बढाकर फिर आनन-फानन में दरें कम कर दीं, मैं कह रहा हूं दर कम करने के बजाय अगर आप राजस्थान के किसान की बिजली माफ करते तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान आपको दुआ देता मन से क्योंकि आप जो बिजली साढ़े चार, पांच रुपये, साढ़े पांच रुपये पर यूनिट में खरीदते हैं और किसान को नब्बे पैसे के अंदर दे रहे हो तो किसान को साढ़े तीन रुपये, पौने चार रुपये, चार रुपये की सब्सिडी दे रहे हो तो आपको तो नब्बे पैसे और सब्सिडी देनी थी, आप नब्बे पैसे की और सब्सिडी किसान को दे देते किसान का भला हो जाता, किसान वाहवाही करता, दुआ देता और 2018

(श्री हनुमान बेनीवाल)

के अंदर आप भी आराम से वापस जाते वोट मांगने। तो यह माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को करना चाहिए था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या 54 में आगामी दो वर्षों में जो कनेक्शन देने की आपने बातकी है, अभी तक तो 2010 वाली पैंडिंग है और 2003-04 तक तत्कालीन सरकार द्वारा फीडर रिनोवेशन का कार्यक्रम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाथ में लिया था। उस समय आर.जी. गुप्ता हुआ करते थे और दस हजार करोड़ रुपये उसके अंदर खर्च होना बता दिया लेकिन फीडर सुधार के नाम पर राजस्थान में न तो कोई नई लाइन आई, न कोई नए पोल, न कोई तार, और जो निकाल लिए तार, पोल, लाइनें उनका भी कोई पता नहीं, नया भेज दिया और पुराना कहां गया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा घोटाला इस फीडर सुधार कार्यक्रम के नाम पर हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट के बिन्दु संख्या 57 से 59 तक पर्यटन की बात सरकार ने की लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केवल अपने पसंदीदा लोगों को पर्यटन बढ़ाने के नाम पर, मार्केटिंग के नाम पर बजट में लाभांवित किया जा रहा है जिसकी कोई एकाउंटेबिलिटी नहीं है। कभी पर्यटन के नक्शे पर 'पधारो म्हारे देश' छाया हुआ इसको बदल कर आपने अब न जाने क्या दिख जाए हो गया, जिसका विपरीत प्रभाव पड़ा है।

बिन्दु संख्या 75 से लेकर 81 तक वन क्षेत्र, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की मूल नीति है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने आजीवन निजीकरण का विरोध किया कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा आंदोलन किया, अपने प्राण त्याग दिए और आप तो सब बातों में निजीकरण कर रहे हो, उनके विचारों के खिलाफ जाकर जंगलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, निजी कम्पनियों की दखलंदाजी से वन क्षेत्र के जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइगर भी खतरे के अंदर है। माननीय मंत्रीजी, टीटी साहब, जंगलों में टाइगर भी खतरे के अंदर है और सरकार ने

(श्री हनुमान बेनीवाल)

राजनीतिक हित की आड़ में अपने चहेतों को जंगलों में जिनकी बाहर होटलें हो गयीं उनको लगा कि अपने तो सब जगह होटलें हो गयीं, अब जंगल, सवाईमाधोपुर में हमारी होटल नहीं है रणथम्भौर में तो वहां मेरी होटल कैसे हो, तो पता नहीं क्या दिमाग में आया होगा, लोगों ने बताया होगा कि साहब यह करो तो आपकी होटल वहां हो जाएगी अगर निजी हाथों में दे दो तो हमारी भी वहां होटल का जो काम कर रहे हैं उनकी होटल सवाई माधोपुर में भी हो जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के महत्वपूर्ण नेशनल पार्कों को निजी हाथों में सौंप रही है सरकार तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या 82 और 83 में पर्यावरण की बात कही गयी है। मगर आज फैक्ट्रियों से निकला हुआ दूषित पानी व धुआं, नावां के नमक प्लांट की बात कहना चाहता हूं वहां सबसे बड़ा नमक प्लांट है, वहां बहुत बड़ा आंदोलन भी हम लोगों ने किया था और सरकार ने आश्वासन दिया कि जितनी भी फैक्ट्रियां इस हाई वे पर नावां क्षेत्र में बनी हुई है। वहां वह प्रदूषण रहित जो नमक को साफ करते हैं तो वह जो धुआं और डस्ट निकलती है उनकी चिमनी लगती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो करोड़ों रुपये फैक्ट्री के अंदर खर्च करता है तो पन्द्रह से लेकर अठारह, बीस लाख रुपये की उसकी कीमत होती है, वह लगाए तो निश्चित रूप से जो रोग फैल रहे हैं लोगों के अंदर उससे मुक्ति मिल सकती है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर बार यह बात करने के बावजूद भी आज भी नमक प्लांटों के अंदर प्रदूषण से सैंकड़ों लोग बीमार पड़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या 84 से 92 तक निवेश व आर्थिक वृद्धि की बात कही गयी है। प्रदेश की तकदीर बदलने वाले बाड़मेर के रिफाइनरी प्रोजैक्ट का कोई जिक्र नहीं किया। यह तो राजनीति की भेंट चढ़ गयी रिफाइनरी। परसों तो हम सोच रहे थे, कोई कह रहे थे कि रिफाइनरी का प्लांट छोटा आएगा, मैंने कहा कि जैसा भी आएगा आ तो जाएगा। पहले तो आपने कहा दिया कि बाड़मेर के अंदर बने, बालोतरा में बने, नए-नए शिगूफे आपने छोड़ दिए, फिर कहा कि यह तो कांग्रेस के टाइम का है, तो हम बनाएं कि नहीं बनाएं, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अब आपने कहा कि छोटा प्लांट लाएंगे, अब तो रिफाइनरी का कोई जिक्र ही नहीं किया। पूरा प्रदेश और बाड़मेर जिला जहां तेल निकलता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन रिफाइन होने के लिए वह गुजरात जाता है। आज वहां रिफाइनरी लग जाती तो हजारों लोगों को रोजगार मिलता, विकास के मामले में जिस तरह की घुट्टी बाड़मेर को मिलनी चाहिए थी, निश्चित रूप से रिफाइनरी से बाड़मेर को दिशा मिलती, बाड़मेर के विकास को गति मिलती, हमारा सीमावर्ती इलाका है और बाड़मेर, जैसलमेर के लोग किन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने संघर्ष किया, हमसे ज्यादा संघर्ष उन्होंने किया और आज बाड़मेर का जवान निश्चित रूप से शिक्षा के अंदर आगे आ रहा है।

तो रिफाइनरी की जो मांग है वह वाजिब है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि मुख्यमंत्रीजी जब बजट पर रिप्लाई दें या वित्त विधेयक पर चर्चा हो तो इस रिफाइनरी के मामले में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलेगा, राजस्थान के जवान को बाड़मेर के अंदर रोजगार मिलेगा और बाड़मेर का विकास होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर पहली बार चिकित्सा शिक्षा में दिनांक 7.3.2017 को एक आदेश निकाला कि राज्य के सभी मेडिकल कालेज के एमओ, जेएस, एसएस को एक गैर संवैधानिक आदेश द्वारा आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य बना दिया गया। इस गैर संवैधानिक आदेश के विरोध में राज्य के सभी मेडिकल टीचर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया जिसके कारण राज्य की चिकित्सा सेवाएं एकदम से ठप्प हो गयी। सरकार ने अपने चहेतों को फायदा देने के लिए राज्य का कोई खयाल नहीं रखा। राज्य में पिछले 24 घंटे में त्राहि-त्राहि मच रही है। ऐसा राज्य के पिछले 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि सारे प्रोफेसर, सारे लैक्चरर और सारे डाक्टर एक साथ हड़ताल के अंदर आये। मंत्रीजी यहां बैठे नहीं, मंत्रीजी मुझे गैलेरी के अंदर मिले, मैं कह रहा था कि आप ने दो-तीन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा हिटलरशाही आदेश कैसे जारी कर दिया। कह रहे थे कि मैं वापस ले लूंगा। फिर आदेश क्यों जारी किया? जब वापस लेंगे, अख़बार में छपेगी, पांच-दस लोग डाक्टरों की हड़ताल की वजह से मर जाएंगे तब जाकर आदेश लोगे। आपको थूककर चाटने की आदत कहां से पड़ गयी?

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हर कोई काम करते हो, फिर बैक हो जाते हो, काम करते हो, फिर बैक हो जाते हो

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कहते हो यह कर देंगे, फिर बैक हो जाते हो। उपाध्यक्ष महोदय, वही काम करना चाहिए जिससे राजस्थान के अंदर जनमानस का नुकसान नहीं हो, जन-धन की हानि नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को एक ही बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान को बचाने के लिए सबको मिलकर एक नये राजस्थान के निर्माण के लिए प्रयास करना चाहिए। राजस्थान आगे बढ़े, राजस्थान का जवान आगे बढ़े, राजस्थान का किसान आगे बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़े घोटालों की गूंज इस राज्य के अंदर हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खान घोटाला। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। प्रिंसिपल सैक्रेट्री को आपने जेल के अंदर डाल दिया। लेकिन इसकी आंच ऊपर तक थी, पूरी जांच नहीं हुई। एसपीएमएल कंपनी का घोटाला। अधिकारियों को जेल के अंदर डाला। गर्मी से मौते हुईं, स्वाइन फ्लू से मौते हुईं। बजरी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन बजरी घोटाले के अंदर वह इतना बड़ा आदमी हो गया, उसने नदी-नालों का स्वरूप बिगाड़ दिया और चाहे जैसी गुण्डागर्दी करता है। एक-एक ट्रैक्टर की दो तरह रसीद रखता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार के टोल नाके पर 152 रुपये और 800 की रसीद काट रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से एक ही आग्रह है कि राजस्थान के अंदर जितने भी घोटाले पिछले साढ़े तीन साल के अंदर या उससे पहले हुए, उनकी सही जांच होनी चाहिए। आपने जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो एसीबी की कार्यवाही करवाई उसका मैं स्वागत करता हूं कि आपने बहुत बड़ा गिरोह वहां पकड़ा जिन्होंने सिफारिश के आधार पर नौकरी ली है। मैं इसमें किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करता। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं। अच्छा

(श्री हनुमान बेनीवाल)

तो यह होता कि आप उत्तराखण्ड की तर्ज पर यहां भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए मजबूत लोकायुक्त लेकर आते तो राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देती।

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट आंकड़ों का मायाजाल है, इस बजट से राजस्थान का भला नहीं होने वाला है। इसलिए मैं इस बजट के खिलाफ अपनी बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती राजकुमारी।

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सुबह से ही बजट पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। माननीय वसुन्धरा जी ने जो बजट पेश किया वाकई में वह बजट राजस्थान की आम जनता के लिए समर्पित बजट है। यह राजस्थान सरकार का चौथा बजट है। बजट के आंकड़े देखें और पिछली सरकार का जो कार्यकाल हम सब लोगों ने, कुछ विधायक थे, कुछ बाहर थे, राजस्थान में हमने देखे। राजस्थान में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान में निकलीं और हर विधान सभा क्षेत्र में गयी। हमारे करौली जिले के हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र में गयीं तो हम उनके साथ थे। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में माननीय वसुन्धरा जी की सभा थी। जब कांग्रेस का राज था और कांग्रेस के शासन में जनसभाओं में माननीय वसुन्धरा जी ने आम जनता से पूछा कि लाइट मिल रही है तो जनता एक ही आवाज में कहती कि नहीं। लेकिन आज राजस्थान के तीन साल के कार्यकाल में जनता को बिजली भी 24 घंटे मिल रही है। सुराज संकल्प में जो माननीय वसुन्धरा जी ने वादा किया वह किसानों के लिए पूरा किया है।

अभी इस फसल के टाइम पर भी, जब हम विधायक बने तो हर जगह गांवों से फोन आते थे कि लाइट नहीं मिल रही है। लेकिन इस बार कहीं से भी किसानों की ऐसी समस्या नहीं आयी। सुचारू रूप से बिजली मिल रही है और बिजली घाटे को जिस कदर राजस्थान की पिछली सरकार छोड़कर गयी

(श्रीमती राजकुमारी)

थी, विपक्ष के सदस्यों ने, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी-अपनी बात को रखा, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सरकार अच्छा काम करती है तो जनता उसका जवाब देती है। जब हमारी पिछली सरकार ने 5 साल तक कुछ नहीं किया और जाते-जाते स्वाभिमानी जनता को साड़ियों का वितरण किया, हमारी महिलाओं को साड़ी बांटी गयी तो उसका स्वाभिमानी जनता ने जवाब दिया। जनता को विकास चाहिए और जनता की भावनाओं के अनुरूप जनता की समस्याओं को देखते हुए आम जनता के हर वर्ग का ध्यान रखा है। एससी, एसटी, राजस्थान के अन्य वर्ग, समाज, महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियां सबका ध्यान रखा गया है। बच्चियों की शादी के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उसको मुख्यमंत्रीजी ने दुगुना किया है। कृषि कनेक्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्रीजी ने एक लाख कृषि कनेक्शनों की घोषणा की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि मेरे क्षेत्र में भी बहुत सारी घोषणाएं पिछले बजट में कीं। अभी कुछ सदस्य कह रहे थे कि सरकार ने क्या किया है? सरकार ने वो काम किये हैं जिनकी आम जनता को जरूरत थी। जैसे रोड की जरूरत थी, शिक्षा की जरूरत थी, पिछली सरकार द्वारा राजस्थान का ढांचा चरमराया हुआ मिला। स्कूलों में बच्चे नहीं थे, कहीं शिक्षक थे तो बच्चे नहीं थे। हास्पिटल हैं तो डाक्टर नहीं थे। हमारी सरकार ने उस पर पूरे तरीके से अध्ययन किया और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 19 विद्यालय क्रमोन्नत किये और हर पंचायत मुख्यालय पर बारहवीं तक के स्कूल खोले।

इसी तरीके से पिछली बार मुझे सीएचसी मिली। काफी लम्बे समय से हमारे विधान सभा क्षेत्र के महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोलने की मांग चली आ रही थी। माननीय वसुन्धरा जी ने उस मांग को इस बजट में घोषित किया है, पूरा किया है, इसके लिए हजारों लोगों ने माननीय वसुन्धरा जी को धन्यवाद दिया है। इस सदन के माध्यम से मैं उनकी बात पहुंचाना चाहता हूं।

इसी तरीके से 5 हजार वृद्धों के लिए इस बजट में वर्णन किया है कि 5 हजार वृद्धों को हवाई यात्रा करायी जाएगी। पानी के लिए हमारे जिले की

(श्रीमती राजकुमारी)

बहुत महत्वपूर्ण मांग चली आ रही थी। पिछली सरकार में एक महीने तक लगातार किसानों ने धरना दिया था और कभी भी सरकार का प्रतिनिधि उनसे बात करने तक नहीं पहुंचा। हमने माननीय मुख्यमंत्री के सामने हमारे करौली जिले की पानी की समस्या के बारे में बताया।

आते ही सरकार ने मेरे विधान सभा क्षेत्र शहर के लिए 55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए और 55 करोड़ रुपये से मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 13 टंकियों का निर्माण हो रहा है।

इसी तरीके से जो यह बजट भाषण की किताब है इसके अन्दर 134 नम्बर पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 13 जिलों के लिए पानी की योजना बनाने की बात की है उसमें करौली जिले को भी शामिल किया गया है इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इस तरीके की जो योजना हाथ में ली है, जल स्वावलम्बन योजना, इसके बारे में कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। ये इनको छोटे-छोटे काम लगते हैं लेकिन जनता की जरूरत के हिसाब से सरकार काम कर रही है। जनता को चाहिए पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और कमजोर वर्ग के लिए जैसा कि खाद्य विभाग के जो अनाज वितरण होता है उसमें पिछली सरकार के द्वारा पूरा का पूरा गेहूं, पूरा का पूरा तेल ब्लैक किया जाता था लेकिन हमारी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए पोस मशीनों के....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती राजकुमारी (हिण्डौन): पोस मशीनों के द्वारा गेहूं का वितरण होने लगा है। इससे हमारे गांवों के गरीब परिवारों को गेहूं मिलने लगा है, तेल मिलने लगा है, चीनी मिलने लगी है। यह विपक्षी लोगों को दिखाई नहीं देता। ये तो यह सपने देख रहे हैं कि इस सरकार का डेढ़ साल का, पौने दो साल का कार्यकाल रहा है, कब चुनाव आएं और हम कब सत्ता में आएं। ऐसा प्रचार जनता में करते हैं। अभी अखबारों में पढ़ने को मिला माननीय गहलोत साहब ने अधिकारियों को धमकाया और कहा हमारी सरकार आने वाली है, मैं लिस्ट बना रहा हूं कि आप लोग, जो-जो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके की जो सोच विपक्ष लेकर चल रहा है तो निश्चित रूप से सरकार की तारीफ कर ही नहीं सकता, सरकार की योजनाओं के बारे में बता ही नहीं सकता। आज मैं कह सकती हूं कि जिले के अन्दर जो बजट पेश हुआ है, जिले से मैं बी.जे.पी. की एकमात्र विधायक हूं, चार सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन हमारे जिले के अन्दर जितने गौरव पथ मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनाए गये हैं इतने ही गौरव पथ हर विधान सभा क्षेत्र में बनाए गये हैं, इतने ही मिसिंग लिंक और विधान सभा क्षेत्र में बनाए गये हैं। लेकिन ये चीजें किसी भी विपक्ष के लोगों के मुंह से मैंने नहीं सुनी, कभी बाहर भी नहीं सुना। वो तो यह सोचते हैं कि सरकार का टाइम किस तरीके से बर्बाद किया जाए और अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं करें। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हैं, आध्यात्मिक हैं, इस कारण से वो मानव सेवा के लिए आई हैं। जनता को हमेशा कहती हैं कि मैं सेवा के लिए आई हूं और मुझे मौका मिला है। कल उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैंने हर वर्ग को मरहम लगाने का काम किया है।

जो आर्थिक स्थिति पिछली सरकार राजस्थान की छोड़कर गयी थी, किस कदर उसको समझा है और हर विभाग में, हर गांव में, हर जगह काम हुए हैं। किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, हर क्षेत्र में हमें मिला है। पशु औषधालय होने चाहिए तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल अपने बजट

(श्रीमती राजकुमारी)

भाषण में कहा था कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। पिछली सरकार ने कुछ पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले भी थे तो आज कहीं उनके भवन नहीं हैं, कहीं इधर-उधर उनके कम्पाउण्डर बैठते हैं। हमारी मुख्य मंत्री जी ने जो भी घोषणा की है उसके लिए बजट का भी प्रावधान किया है। तो यह थोथी घोषणा नहीं है और सरकार धरातल पर काम कर रही है। सरकार तो आती जाती रहती है, 5 साल में सरकार जाती है, कांग्रेस कहती है, और भी कांग्रेस के विधायक और मेरे क्षेत्र में जो पूर्व विधायक हैं वो भी यही बात कहते हैं यह तो राजस्थान का सिस्टम है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। इस तरीके के सपने जो देख रहे हैं वो कभी अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर सकते। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार जो काम कर रही है इसकी प्रशंसा करती हूं और यह तीन साल के कार्यकाल के आंकड़े बताते हैं कि ये कोई असत्य नहीं हैं। कांग्रेस के पिछले बजट हैं उनको उठाकर देख लीजिये, हमारी सरकार ने तीन साल के कार्यकाल में पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से 20822 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और कांग्रेस की जो पिछली सरकार थी उसके तीन साल के कार्यकाल में मात्र 3157 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसी तरीके से अभी बजट का प्रावधान हमारी सरकार ने रखा है। गांव-गांव के अन्दर हम जब जाते थे तो इतना कीचड़ भरा रहता था कि उसमें से निकलना भी दुश्वार था। इसी कारण से इनकी यह दशा हुई कि शायद कांग्रेस सदन में इससे कम संख्या में कभी नहीं आई। यही कारण था कि सरकार का जो बजट था वो बेवजह खर्च किया गया जिसका जनता में कोई उपयोग नहीं हुआ।

इन्हीं शब्दों के साथ काफी समय हो गया है, उपाध्यक्ष जी का भी आदेश हो चुका है इसलिए मैं सदन की नेता माननीय मुख्य मंत्री जी को, सरकार को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

चिकित्सा मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं, मेरे हिण्डौन शहर के अन्दर, हिण्डौन शहर करौली जिले से भी बड़ा शहर है, अमृत योजना में भी हिण्डौन शहर है, करौली जिला हैडक्वार्टर नहीं है और वहां की जनसंख्या को देखते हुए, वहां पर एक ब्लड बैंक की स्थापना के लिए आपसे निवेदन करती हूं कि वह जरूर कराएं। मांग तो हमने 200 बैड की की थी लेकिन आप ब्लड बैंक

(श्रीमती राजकुमारी)

का जरूर इसी बजट में प्रावधान करें, यह मेरा आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शकुंतला रावत। आपके बाद में एक और सदस्य हैं। 7 बजकर 15 मिनट तक आपका और 7 बजकर 15 मिनट के बाद में फूलसिंह जी मीणा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय में बांध दिया, फिर भी बजट पर वाद-विवाद में विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अभी जितनी भी बजट की बड़ाई की गयी, उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो बहुत बड़ाई की और फिर एक भी विधायक ने लास्ट में अपनी कोई कमी नहीं रखी हो, अपनी मांग नहीं रखी हो। ऐसा नहीं किया। इसका मतलब बजट में एक-एक कमी तो रह ही गयी और आपकी तरफ से भी दर्ज हो गयी। मैं तारीफ ही करने जा रही हूं, चिंता मत करो।

जो वादे किए गये थे और पिछले बजट में कुछ चीजों की घोषणा की गयी थी तो यह घोषणाओं का बजट, आंकड़ों का बजट प्रस्तुत किया गया है। 190 शहरों को वाई-फाई से जोड़ने की बात की गयी थी। बहुत बड़ी बात की गयी थी कि मजदूर की दिहाड़ी में जो विसंगति है उसको दूर किया जाएगा। डैजर्ट नेशनल पार्क में गोडावण संरक्षण हेतु 55 लाख की घोषणा की गई थी और पिछली बार सरकार ने ऊंट विकास योजना के नाम की एक बात कही थी तो आज तक किसी एक भी ऊंटपालक को अगर कोई एक रुपया मिला हो तो हमें बताएं, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ घोषणा थी। एक लाख को रोजगार देने की बात कही थी, टोटल 15 लाख की बात की थी तो क्या 14 लाख को तो दे चुके हैं? आपको इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए था लेकिन किसी माननीय सदस्य ने दिया नहीं। मंदिरों के विकास के लिए बीसियों करोड़ की बात की, शिक्षकों के खाली पदों को भरने की बात की, रमसा की बात की, पेयजल की हजारों करोड़ों की योजनाओं की बात की और जब भी हम कोई प्रश्न करते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर दिया जाता है पिछली सरकार द्वारा ये-ये काम किए गए थे, अभी हम आगे करेंगे।

(19.00 बजे)

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

एक-एक चीज को लें। अलवर जिले में नई चीज तो करने की बात ही छोड़ो, करने का कोई मतलब ही नहीं है, ईएसआई हास्पिटल 700-800 करोड़ रुपये का बनकर तैयार खड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं, सरकार को क्या दिक्कत आ रही है, उसको चालू ही नहीं कर रहे हैं। नया खोलने की बात तो दूर है, बनाने की भी बात दूर है, लेकिन इतना पैसा उसमें लग गया जो वेस्ट हो रहा है और वह तैयार है, उसको चालू ही कर दें तो भी हम धन्यवाद दें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ईएसआई अस्पताल में ही मेडिकल कालेज खुलेगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हां, खुलेगा तो कब खोलेंगे? तीन साल हो गये, हमको इंतजार है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसी सत्र से। जुलाई, 2017 से।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बजट के अंदर उसकी कोई घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए मैं इस चीज को आपकी नजर में ला रही हूं। ऊंट के बारे में भी अगर कोई मंत्रीजी जवाब दें कि हमने दिया है, तो कहां पर पैसा दिया है? किसको दिया है? कौनसी योजना में डाल दिया उसको? ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गयी कि ऊंट को ही निगला दिया। इसका कोई भरोसा नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऊंट के बारे में ही बता दो। इनको यह बता दो कि ऊंट कितनी बार बैठता है? ऊंट कितनी बार बैठता है, यह बता दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो गांव से आते हो। मैं शहर से आता हूं, इसलिए मुझे पता नहीं है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): रिफाइनरी का हो। टैक्स में कुछ नहीं घटाया। बच्चियों की सुरक्षा को लेकर हो। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय जा रहा है। रिसर्जेन्ट राजस्थान की बात हो। गैस सिलेण्डर की बात हो जिसको महंगा कर दिया। एकदम से इतना। एक गरीब, झोंपड़ी में बैठी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
महिला भी प्रभावित हो रही है और एक वर्किंग महिला भी प्रभावित हो रही है। रसोई तक का इतना महंगा, आंकड़े और जुमले का बजट है, महिला मुख्य मंत्री हैं।

महिलाएं उम्मीद लगा रही थीं शराबबंदी को लेकर, पूरे राजस्थान में धरने-प्रदर्शन चल रहे थे कि शायद शराबबंदी को कहीं किसी स्टेट से प्रेरणा लेकर करेंगी तो महिलाओं को राहत मिलेगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ।

महिलाएं जो सरकारी कर्मचारी हैं, वह आस और उम्मीद लगाकर बैठी थीं। मुख्य मंत्री महोदया ने कहा था, चाइल्ड केयर लीव महिलाओं को दी जाएगी, लेकिन न ही उसे बढ़ाया जाए या दी जाए, उसके बारे में बजट के अंदर कोई चर्चा नहीं की गयी। आप सब सुन रहे हैं, कोई चर्चा की हो तो आप बता सकते हैं कि यह चर्चा कर दी गयी है।

पिछले वर्षों में पुरस्कार प्राप्त किये गये हैं सर्वश्रेष्ठ कौशल विकास, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस में स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसके लिए सम्मान, अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदया इस नारे को सफल करना चाहती हैं तो जितने भी कर्मचारी हैं, उनके चाहे कितनी भी बेटियां हों, उनको एक ही यूनिट माना जाना चाहिए। इससे बेटियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद रहेगी क्योंकि कोई भी कर्मचारी, उसके अगर दो बेटी हो जाएंगी, उसका प्रमोशन नहीं होगा तो यह एक बड़ी विडम्बना है। इन चीजों का भी अगर जिक्र करतीं तो यह नारा आपका सफल हो जाता लेकिन नहीं किया गया।

गौ-माता की सिर्फ चुनावों में चर्चा होती है। बड़े जोर-शोर से भाषण दिये जाते हैं। आज की गौ-माता आप सबकी आंखों के सामने पालीथिन खा रही है क्योंकि सरकार का पैसा, फंड पता नहीं कौनसी गौशालाओं में जा रहा है। इतनी जटिल प्रक्रिया है। कम से कम जो गौशाला जन सहयोग से गांव वालों ने खोल ली, वह चला रहे हैं। उनका रजिस्ट्रीकरण होना है, उसको तहसील हैडक्वार्टर पर कर दें तो यह एक समस्या का समाधान हो सकता है। हिंगोनिया गौशाला का उदाहरण कोई दूर नहीं है। सैकड़ों गायें उसमें मर गयीं,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लेकिन नहीं, सरकार के जूं तक नहीं रेंगी।

पुलिस, गृह विभाग पर चर्चा में भी अगर कोई इस तरीके का जिक्र किया होता कि हर थाने पर नफरी बढ़ाई जाएगी। प्रमोशन होंगे। नये हथियार दिये जाएंगे, नई गाड़ियां दी जाएंगी या आपको कोई भत्ता मिलता है क्या? आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं? जिससे वह टैंशन मुक्त होकर काम करते, लेकिन कोई किसी तरीके का बजट के अंदर प्रावधान ऐसा नहीं किया गया। जो महिला कर्मचारी हैं, उनको आवास देने का कोई इसके अंदर जिक्र किया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

नाम तो बहुत किया गया है 2020 लेकिन हमें पता नहीं है, यह कौनसा 20-20 का मैच हो रहा है सरकार का?

सड़क की बहुत सारी बड़ाइयां की गयीं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि जयपुर से जब आप दिल्ली जाते हैं तो जरा एक नजर नीचे उतर कर कोटपूतली की पुलिया के पास भी देख लें, बहरोड़ की पुलिया के पास भी देख लें। जिसका सेंट्रल मिनिस्टर कई-कई बार उद्घाटन कर गये कि अब के दो महीने में बन जाएगा, छह महीने में बन जाएगा, लेकिन आज तीन वर्ष हो गये। उसमें एक पत्थर नहीं लगा। उसमें डेढ़-डेढ़ फीट के गहरे गड्ढे हो रहे हैं। उनको भी देख लेना।

सड़क की इतनी देर से उपलब्धियां गिना रहे थे लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं पर सड़कें बनी होंगी। हां, एक जरूर बजट के अंदर लिखा हुआ है कि आगामी वर्षों में, अभी हम करेंगे आगामी वर्षों में, तो हमें भी उस आगामी वर्ष का इंतजार करते-करते तीन वर्ष हो गये।

गौरव पथ, कई जगह बनी हुई सड़कों पर बन गये। मिसिंग लिंक का जैसे एक तहसील से दूसरी तहसील का हो या रेवेन्यू विलेज का, पीएमजीएसवाई में एक भी सड़क मेरे यहां उपाध्यक्ष महोदय, नहीं बनाई गयी। यह क्या दोहरी नीति है आपकी या दूसरी पार्टी वालों को नहीं देते हैं? सरकार तो एक ही होती है पूरे राजस्थान की, लेकिन नहीं दिया गया। यह कैसा बजट है और कुछ रोड्स तो ऐसे हैं जिनका बजट उठा लिया गया, बुचियावास रोड जो बानसूर से फतेहपुर तक जाता है, एक ज्ञानपुरा से ज्ञानसिंह की स्कूल की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ढाणी तक जाता है, जिसको आता है, रोलर खड़ा हो जाता है। हम फोन करते हैं, काम शुरू कर रहे हैं और फिर उस पर आज तक डामर नहीं डला है तो यह कैसी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। हमें उस पर डामरीकरण आप करके दिखा दें। क्या व्यवस्था है यह? क्या कर रहा है सार्वजनिक निर्माण विभाग? रिपोर्ट मंगवा लें इसकी भी। इस तरीके से नाबार्ड का, सभी चीजों का इसके अंदर जिक्र किया गया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह शायद हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कहीं बीजेपी वालों को मिली हो तो मुझे ध्यान नहीं है। नवीनीकरण के नाम पर सड़क के अंदर दो-दो फीट के गहरे गडढ़े हो रहे हैं।

परिवहन विभाग की सरकारी योजनाएं इतनी बता दी जाती हैं। जो मुख्य सड़क है, जिसके लिए बार-बार नोट करवाया जाता है, लिखकर भी दे दिया जाता है लेकिन एक भी बस कहीं पर हमें चलती हुई नजर नहीं आती है कि इस रोड पर बसें चल रही हैं। पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बसें चलाने के लिए हमसे लैटर तो लिया गया था कि आप जहां चलवाना चाहते हो, बता दें। हमारे पास चिट्ठी गयी थी, हमने लिखकर भी दे दी, बाई हैण्ड भी मैंने दे दी। मेन सड़क बानसूर, बहरोड़ रोड से बानसूर तक, आलनपुर से नारायणपुर, निमुचाणा और लोकल कौन-कौनसी जगह बस चलाना चाहते हैं। हमने ग्राम पंचायतों समेत लिस्ट दे दी, लेकिन आज तक इंतजार है जनता को कि वह बसें चलेंगी या यहीं पर आंकड़ों में रह जाएंगी। पेयजल के लिए लाखों ढाणियों-गांवों को पेयजल के लिए लाभान्वित किया जा चुकने के लिए इसमें जिक्र किया गया है, लेकिन एक भी गांव को अगर तीन वर्ष के अंदर कोई पेयजल की योजना दी हो तो वह नाम हमें बताएं कि चार हजार की जनसंख्या वाला हमने फलां गांव पेयजल की योजना से जोड़ दिया है। नहीं, बल्कि जो थ्री फेस बोरिंग है, सिंगल फेस बोरिंग है, उसकी हम मांग देते हैं तो भी उसमें भू-जल विभाग में फाइल जाएगी, फिर वहां से वापस आएगी, फिर पता नहीं, क्या-क्या नोर्म्स लगा दिये, जिसमें छह महीने एक बोरिंग करवाने में लग जाता है।

ऊर्जा, बिजली का बहुत अधिक बखान किया गया था। "उदय" योजना, जिसका जिक्र किया गया है पेज नम्बर-18 पर, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ज्योति योजना, जिसमें डिमांड नोटिस जमा करा लिये गये। ग्राम पंचायतों में कैम्प लग गये लेकिन कनेक्शन एक भी नहीं दिया गया और जब बात आती है आंकड़ों में, हमने इतने कनेक्शन दे दिये, लेकिन कहीं मुझे बिजली का बल्ब जलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सारी कागजी कार्यवाही हो रही हैं। यह दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना कागजों में तो बहुत सारी लाइट रोशनी दे रही होगी, शायद यहां जयपुर में दे रही है या विधान सभा के अंदर दे रही है।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र में 45 से 50 हजार तक कंज़्यूमर हैं और वहां एक ही एईएन बैठता है जबकि सरकारी नोर्म्स के हिसाब से तीन एईएन बैठने चाहिए। लेकिन नहीं, सरकार ने किसी भी एक कर्मचारी के बैठने की कोई किसा तरीके का जिक्र नहीं किया कि हम इतने लगाएंगे या बढ़ाएंगे।

वीसीआर, कहते हैं कि बिजली की छीजत कम करने के लिए, चोरी पकड़ने के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति ने अगर एक बल्ब गर्मी में घर के बाहर लगा लिया तो उसकी भी मोटी सारी वीसीआर काट जाएंगे। उसको पता भी नहीं लगेगा, बिल भी नहीं आएगा, रीडिंग लेने भी नहीं आएंगे। गांव में एक दुकान पर डाल जाएंगे, तब उसको पता लगेगा, नोटिस आएगा तब पता लगेगा।

ये कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये एक गरीब आदमी को ठगने की व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको तब पता लगेगा जब उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। वो ऑफिस में चक्कर काटता रहेगा, अपनी सफाई पेश करता रहेगा। हमने इतने जीएसएस बना दिये। कई-कई बार वित्तीय घोषणा भी कर चुके हैं कि मोठूका, देवसन, गुवाड़ा, लकड़ी, वो आज तक नहीं बन पाया, जमीन भी दे दी सारी कार्यवाही पूरी हो गयी। अगले महीने, अगले महीने करते-करते तीन वर्ष तो बीत गये, अब पता नहीं अभी आगामी वर्ष जैसा इस बजट में जिक्र किया गया है हर चीज के लिए आगामी वर्ष तो पता नहीं कौनसा आगामी वर्ष आएगा। मैंने पिछली बार हमारे यहां मौतें हुई थी। करंट लग कर तालवास में एक ही लड़का था। रामपुर में और बेराहास में चार बंजारे मरे थे एक साथ। यहां से चीफ सैकैटरी महोदय गये थे उन चारों को ढाई-ढाई लाख रुपये का चैक दिया था।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मैंने कहा कि साहब, आधे कब दे दोगे तो बोले कि डेढ़ से दो महीने में दे देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक शेष राशि एक रुपये भी नहीं मिली। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं। खुद सरकार के बोलने के बाद भी नहीं मिला और तालवास, रामपुर इनको तो एक रुपया ही नहीं मिला पूरे गांव में करंट आ गया था, शुक्र है पूरा गांव बच गया। एक व्यक्ति के मरने के बाद सब सावधान हो गये। घर के अन्दर स्विच बंद करने पर करंट आया, डीपी फट गयी रामपुर में। लेकिन नहीं, एक रुपया तक मुआवजा नहीं मिला। तो इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं।

पर्यटन को लेकर आगे से आगे बढ़ कर 88 करोड़, पता नहीं कितने करोड़ का कर दिया। संग्रहालयों को रखेंगे, हस्तलिखित ग्रंथों की हम रक्षा करेंगे लेकिन इसमें एक भी चाहे मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ का जिक्र किया है, उस किले का जिक्र किया है लेकिन सड़कों पर लोग उतर रहे हैं। रानी पद्मिनी के जौहर के लिए संघर्ष किया है उन्होंने और एक राजस्थानी महिला और महारानी की आन-बान-शान को तार-तार किया जा रहा है। ये कैसी विडम्बना है। क्यों सरकार बात नहीं करती है चाहे दंगे हो जाए...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी तो तीन मिनट बाकी हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)... थोड़ा सा तो सुन लो आपकी कमियां। आप पुरातत्व के बचाव की बात करते हैं। आप खासाकोठी की बात करते हैं, विधायकपुरी की, राजाओं के महलों पर नजर रखते हैं, उन पर सील लगा देते हैं मन करे तब खोल देते हैं, सौदा करने की बात करते हैं। राजस्थान की धरोहर को आप गिरवी रखने की बात करते हैं। जो हमारा राजस्थानी नारा था और एक राजस्थानी भाषा में था 'पधारो म्हारे देश' जिसका कलेण्डर भी प्रसिद्ध था ढोलामारू लेकिन आपने कर दिया न जाने क्या दिखेगा क्या कोई जिन्न-भूत दिखेगा कि क्या दिखेगा यह समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से ये रंगीले राजस्थान को क्या मटमैला राजस्थान करने के ऊपर तुले हुए हैं आप लोग। देवस्थान के लिए मंदिरों की, शिलालेखों की हमने इतना खर्च कर दिया, हमें कहीं एक रुपया भी खर्च होता नहीं दिखाई दे रहा है।

वन क्षेत्र - वन क्षेत्र में कितने ही एपीओ कर दिये, कर्मचारी, पद खाली

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पड़े हैं। कोई योजना नहीं है। वन्य पशुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं वैसे तो लेकिन वन्य पशु के लिए जो जल स्वावलंबन का ढिंढोरा पीटते हो, वहां पानी की व्यवस्था कर देते तो शायद वे गांव तक नहीं आते। नरेगा में चारदीवारी करते, कोई तार खिंचवाते लेकिन नहीं, वन क्षेत्र का बहाना लगा करके जंगली जानवर वहां से आकर किसानों की फसल नष्ट कर देते हैं, उसमें मुआवजे का जिक्र कर देते बजट के अन्दर। नील गाय और सूअर आकर के सारी फसल को नष्ट कर जाते हैं लेकिन नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था बजट के अन्दर नहीं की गयी है सरकार की तरफ से। विस्थापितों को मुआवजा न के बराबर दिया जाता है। उनको किस आधार पर दिया जाएगा कोई जिक्र नहीं किया इसमें। सिर्फ दस लाख रुपये जो पहले था वो ही आज है, कम से कम उनको एक करोड़ रुपये और 15-15 बीघा जमीन तो देनी चाहिए। सरिस्का का सीमांकन होना चाहिए मन में आये वहां तक वन विभाग को बढ़ा लेते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा तो बोल लूं। पर्यावरण की बात की गयी है। जैनपुरवास में फैक्ट्री से इतना पर्यावरण खराब हो रहा है, वहां के सारे पेड़ सूख रहे हैं। कृषि कनैक्शंस के लिए जो बिजली दी जाती है वो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक से डेढ़ घंटे आ रही है वो भी ट्रिपिंग होकर के आ रही है, बड़े शर्म की बात है। आप बीस घंटे, आठ घंटे बिजली की घोषणा कर देते हैं। ...(व्यवधान)... भेड़पालकों के लिए बनाया है, लेकिन, कहां देंगे या नहीं देंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पाइपलाइन योजना की घोषणा कर दी है लेकिन कहीं पर नहीं की गयी है। न्याय और सामाजिक अधिकारिता, जो गांव में कैम्प लगाये गये थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनमें एक भी रास्ते का कहीं निवारण नहीं हुआ है। जिस पर विवाद ही नहीं है कभी दे दिया उसका हुआ है। अगर करने वाले ही हैं तो श्मशान तक का कर दें। आशा सहयोगिनी हो, विद्यार्थी मित्र हों, फार्मासिस्ट हों, कम्प्यूटर शिक्षक हों, इतने लोग ...

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
महोदय, इतना सा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिलकुल नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: 7.15, आप टोटल बीस मिनट बोल चुकी हो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 7.15 तक मेरा टाइम था।

श्री उपाध्यक्ष: आप 6 बज कर 55 मिनट पर चालू हुई थीं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दो मिनट तो और दे दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: चूंकि 7.30 बजे तक का टाइम है कम से कम 15 मिनट फूल सिंह जी को, या तो सचेतक महोदय फूल सिंह जी मीणा की अभिव्यक्ति तक आप इसको बढ़ाइये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बढ़ा देंगे इतने से में क्या है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकरी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने खुद ने व्यवस्था दी है कि इतना टाइम है आधा-आधा लेना है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सदन के अन्दर नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे। सचेतक महोदय, पांच मिनट क्या हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): उसके बाद अब आप तो 'पधारो म्हारे देश' जा रही हो। आप बजट पर बोल रही थी या 'पधारो म्हारे देश' पर बोल रही थी? आप तो कह रही हैं 'पधारो म्हारे देश' कभी कहती हैं कि बिजली नहीं आती है और करंट आ रहा है जब बिजली नहीं आती तो फिर करंट कहां से आया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पांच मिनट। ये असत्य थोड़े ही है। पांच मिनट तो रुकें आप। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मुझे तो यह समझ में नहीं आया माननीय सदस्या, आप कह रहे हैं कि पूरे गांव में करंट आ रहा है, बिजली नहीं आती है तो आपके पूरे गांव में करंट कैसे आया?

श्री उपाध्यक्ष: श्री फूल सिंह जी मीणा का ही अंकित होगा।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 000

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की पंक्ति को पेश करने के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदया को शुभकामना देते हुए मैं बताना चाहता हूं कि इस बजट में सभी वर्गों को छूने का प्रयास किया। मैं मेरी बात शुरू करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले वक्ताओं ने पूर्व सरकार की इतनी उपलब्धियां बताई हैं, उनका खाका मैं आपके सामने सिर्फ मेरे विधान सभा क्षेत्र और उदयपुर के बीच में ही सीमित करता हूं कि पूर्व सरकार ने क्या किया और हमने क्या किया। आंकड़ों के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने हमारे जनजाति एरिया के लिए वोट तो ले लिया मगर विकास का कोई काम करने का नाम नहीं लिया। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत बताना चाहता हूं मेरे भाइयों को पहले 1957 में वन विभाग ने एक टीपी कानून लागू किया था जिस पर पूर्व सरकार ने जनजाति के साथ कुठाराघात किया। हमारे जनजाति परिवार कुहाड़, मुआ आदि वन उपज को दूसरे प्रदेश में जाकर बेचने को मजबूर कर दिया क्योंकि टीपी कानून होने की वजह से हमारे राजस्थान में पांच रुपये किलो कुहाड़ की रेट मिलती थी और गुजरात में ले जाकर वो दस-बारह रुपये में बेचते थे। हमारे जनजाति परिवार के साथ में इन्होंने धोखा किया और वर्तमान सरकार की मैं प्रशंसा करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, यहां बैठे हैं। हमारी मुख्यमंत्री जी के पास में हमारे वन्य जाति परिवार के सभी सदस्यों ने आकर आग्रह किया कि यह टीपी कानून को जब तक खतम नहीं करोगे तब तक जनजाति का भला नहीं होगा।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत बताना चाहता हूं कि 2015, सितम्बर माह में माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने इस टीपी कानून को हटा कर जनजाति एरिया के लिए बहुत बड़ा काम किया। जिससे दो वर्ष पहले, वन उपज में छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि कुहाड़ वन विभाग की खेती पांच रुपये किलो बिकने वाली साठ रुपये किलो बेच कर हमारे वन्य

(श्री फूलसिंह मीणा)

जनजाति परिवार लाभ ही नहीं मिला बल्कि सरकार को भी कम से कम एक-डेढ़ करोड़ रुपये का इससे फायदा मिला और सरकार को भी इसमें बहुत अच्छा रहा। पूर्ववर्ती सरकार को टीपी कानून को खतम करने से पहले मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि 2012 और 2013 से पहले 13 लाख रुपये की इन्कम होती थी और 2015 के बाद में एक करोड़ से ज्यादा इन्कम हमारी सरकार की हुई। यह कोई सोच नहीं सकता था। हमारी सरकार ने यह बहुत बड़ा काम किया। यही नहीं, हमारी फल वन उपज मण्डी जो गोगुंदा में मंडी का भूमि पूजन पूर्व सरकार ने 1989 में किया था, मगर 1989 से लेकर 2013 तक इनकी सरकारें आईं और गयीं लेकिन एक पैसे का काम इन्होंने नहीं किया क्योंकि इनकी सोच जनजाति एरिया को विकास की ओर ले जाने की नहीं थी।

साथ ही गौण मण्डी सलूम्बर में वर्ष 1982 में जमीन क्रय की गयी लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इतने वर्षों तक आदिवासियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने 16 मई, 2015 को निर्माण कार्य करवाकर लोकार्पण भी करवा दिया। यह वजह है कि 177 भूखण्डों के आबंटन की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी। गौण मण्डी झाड़ोल, जिसकी भूमि पूर्ववर्ती सरकार के समय 1996 में क्रय की गयी थी, उसके बाद में कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2013-15 में निर्माण करा दिया गया और 24 अक्टूबर, 2015 को लोकार्पण भी करवा दिया। हमारे जनजाति परिवारों को अगर बढावा दिया तो पूर्व सरकार ने नहीं दिया, हमारी सरकार ने दिया। मैं यशस्वी मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत सुध ली। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वन उपज को मण्डी एक्ट में शामिल किया जिसके कारण यह मण्डी राजस्थान की पहली लघु वन उपज विशिष्ट मण्डी बनी। इसके अतिरिक्त कृषक साथी योजना के अंतर्गत लघु उपज संग्रहण करते हुए मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 2 लाख रुपये तक की सहायता के साथ ही मण्डी यार्ड में भूखण्डों के आबंटन में महिला आदिवासी कृषक को 20 प्रतिशत हिस्सेदारी की ऐतिहासिक नीति बनाकर लाभ देने का काम किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारी सरकार ने किया। वन उपज मण्डी को आगे बढ़ावा दिया और आज हमारी जनजाति

(श्री फूलसिंह मीणा)
महिलाओं को दुकानों के मार्फत धंधा करने का मौका दिया तो वह हमारी सरकार ने दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा में दो जनजाति छात्रावास खोले गये। सरू और पाई में 70-80 किलोमीटर दूर हमारी बालिका पढ़ने के लिये नहीं आती थी, उनको आवासीय छात्रावास खोल कर हमारी सरकार ने सुध ली। पूरे प्रदेश में जनजाति छात्रावासों में खेल की तरफ बढ़ावा दिया और टूर्नामेंट करवा कर हमारे जनजाति बालकों को इसमें प्रतिभा को निखारने का मौका दिया, तो हमारी सरकार ने दिया। दो साल से खेल कूद प्रतियोगिता हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार और हमारी सरकार में क्या फर्क है। पूर्व सरकार में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ में मैं बताना चाहता हूं, 5054 आरआईडीएफ और 5054 धार्मिक पीएमजीएसवाई, गौरव पथ, मिसिंग लिंक, टीएडी यह सभी विभागों की ओर से केवल 39 कार्य पूर्ववर्ती सरकार ने 2008 से 2013 के बीच में करवाया, 3261 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च किया गया। उनके पांच साल के कार्यकाल में यह खर्च हुआ और हमारी मात्र तीन साल में सरकार ने जो काम किया, हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदिवासियों के प्रति विशाल हृदय को दर्शाते हुए इन्हीं कार्यों में वर्ष 2013 से 2017 में 11264 करोड़ राशि, जो लगभग चार गुणा ज्यादा है, यह मैं तीन साल का आंकड़ा बता रहा हूं। मेरे भाई कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने यह किया, मैं यह आंकड़ा लेकर आया हूं और आंकड़ों के माध्यम से ही बता रहा हूं, अगर इनको विश्वास नहीं तो आप चैक कर सकते हो।

यही नहीं उदयपुर में अभी इसी बजट में, सलूम्बर रोड की वर्षों से हमारी मांग आ रही थी, पूर्व सरकार भी आई थी, मगर हमारी मुख्य मंत्री जी ने 65 किलोमीटर का रोड देकर हमारे जनजाति एरिया को बढ़ावा दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति है गिर्वा, जिसमें पूर्व सरकार के पांच वर्ष में विकास के कार्यों में सभी मदों में 19,99,77,417 रुपये खर्च किये गये। हमारी सरकार ने आते ही मात्र गिर्वा पंचायत समिति में 2013 से 2017 तीन वर्ष में लागत राशि 46,98,21,304 रुपये खर्च करके विकास के

(श्री फूलसिंह मीणा)

कार्य करवाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आंकड़ों के माध्यम से दे रहा हूं। करीब ढाई गुणा ज्यादा खर्च इन तीन वर्ष में किया है। कहां उनके पांच वर्ष और हमारे तीन वर्ष। ढाई गुणा खर्च कर सकते हैं और यह कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जाकर यह आंकडे चैक कर सकते हैं।

पीएचईडी विभाग के अंतर्गत पूर्व सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में 9 करोड़ 95 लाख खर्च किये थे और हमारी सरकार ने मात्र तीन वर्ष में पीएचईडी में लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च करके 41 परसेंट ज्यादा काम करके बताया। हमारे तीन साल और इनके पांच साल से 41 प्रतिशत ज्यादा हमने विकास के काम किये, यह कहां इस सरकार का मुकाबला करेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने 144 कृषि कनेक्शन दिये, मैं बताना चाह रहा हूं अभी मेरी बहन कह रही हैं कि एक भी नजर नहीं आ रहा, बहन मैं आपको न्योता देता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आकर मैं बताऊंगा आपको और आप देखना ...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे भाई को न्यौता देती हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाकर चैक कर लें, एक भी हो तो जो वह कहे मैं कर लूं, मैं सदन में धन्यवाद दूं। ...(व्यवधान)...

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): उपाध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में नारायणपुर से लेकर हरसोला वाली सड़क, आपको जानकारी है कि एनसीआर में 60 करोड़ की बनने वाली है, उसको तो बोलते कम से कम आप।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बना दी क्या, आपकी तो बनवा लो, आप क्यों बोल रहे हो।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): बनेगी, बनेगी, हमारी भी बनेगी और आपकी भी बनेगी। ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, तीन वर्ष में तो नहीं हुआ ना ...(व्यवधान)...

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, उस समय मैं भी बोल सकता था, मगर आपके भाषण में

(श्री फूलसिंह मीणा)

मैं दखलंदाजी नहीं करना चाहता था, जैसे आपको हमने सुना, वैसे आप भी सुनो। जबकि वर्तमान सरकार ने मात्र तीन वर्ष के कार्यकाल में 5.82 करोड़ रुपये खर्च करके 291 कृषि कनेक्शन देकर, बहुत बड़ी उपलब्धि करके किसानों का ध्यान रखा। यही नहीं, दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिये हमारी सरकार ने जो कदम उठाया, उसमें 10 हजार हमारे वरिष्ठ नागरिकों को 13 धार्मिक स्थानों पर यात्रा करवाई और अबकी बार 20 हजार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ कराने का इन्होंने वादा किया। हमारे 5 हजार वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा कराने का ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बोलने तक का समय है।

श्री उपाध्यक्ष: आपके बोलने तक का समय नहीं है, साढ़े सात बजे तक का समय है।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट। मैं गृह मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। यूआईटी के माध्यम से पूर्व सरकार ने क्या किया, पूर्व सरकार के कार्यकाल में यूआईटी में 353 करोड़ 27 लाख रुपये खर्च किये और हमारी सरकार ने 371 करोड़ 83 लाख रुपये खर्च किये, उनके पांच साल और हमारे तीन साल में इतना काम करा कर इतिहास कायम किया।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक दिनांक शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2017 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.30 बजे शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2017 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

झुन्झुनूं में कुम्भाराम लिफ्ट योजना से पेयजल की आपूर्ति

194. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं के लिए स्वीकृत कुम्भाराम लिफ्ट योजना से पेयजल आपूर्ति का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था व इसके लिए कितने बजट की स्वीकृति कब-कब जारी की गयी?

(2) उक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) उक्त योजना से जनता को अब कब तक लाभान्वित कर दिया जाएंगा?

(4) क्या उक्त योजना के प्रारम्भ होने में कोई विलम्ब हुआ है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी कैनाल आधारित चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल के पानी को सतही स्रोत लेकर एकीकृत तारानगर-झुन्झुनूं-सीकर-खेतड़ी वृहत् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण में झुन्झुनूं जिले की तहसील झुन्झूनूं एवं खेतड़ी के कुल 5 शहर (झुन्झुनूं, बग्गड़, मण्डावा, खेतड़ी व गोठड़ा) तथा 258 ग्रामों (विधान सभा क्षेत्र, खेतड़ी के 85 ग्राम, झुन्झुनूं के 86 ग्राम एवं मण्डावा के 87 ग्राम) को लाभान्वित करने हेतु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 को राशि रुपये 954.74 करोड़ की जारी की गयी थी।

इस परियोजना के कार्यों को निष्पादन हेतु दो पैकेजों में कार्यादेश जारी किया गया तथा इन दोनों पैकेजों का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

पैकेजवार कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्यादेश अनुसार इन पैकेजों की पूर्ण होने की निर्धारित तिथि संबंधी वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

है। इन पैकेजों के कार्यों के निष्पादन हेतु वर्षवार बजट आवंटन एवं व्यय संबंधी विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त परियोजना के कार्यादेशित दोनों पैकेजों की माह फरवरी, 2017 तक की प्रगति संबंधी पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में निहित है।

(3) झुन्झुनूं जिले के उक्त 5 शहरों एवं 258 ग्रामों को उक्त परियोजना से मार्च, 2018 तक लाभान्वित करना अपेक्षित है।

(4) जी नहीं। उक्त परियोजना के कार्यादेशित दोनों पैकेजों का कार्य तय अवधि में ही प्रारम्भ किया गया है। अनुबंधक फर्मों द्वारा परियोजना अंतर्गत कार्यों की गति धीमी रखने एवं निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रथम पैकेज अंतर्गत रुपये 6.02 करोड़ तथा द्वितीय पैकेज अंतर्गत रुपये 5.07 करोड़ की राशि फर्मों से क्षतिपूर्ति के रूप में रोकी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटड़ा पंचायत समिति के कालीबोर बांध के पानी का उपयोग

195. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति कोटड़ा का कालीबोर बांध कब बनाया गया व उक्त बांध का पानी किस काम के लिये किस क्षेत्र को दिया जाता है?

(2) पंचायत समिति कोटड़ा को उक्त बांध से क्या-क्या लाभ है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त बांध के ओवरफ्लो होने पर पंचायत समिति कोटड़ा में फसलों व सड़कों आदि को नुकसान होता है? यदि हां, तो उक्त नुकसान के लिये किसका दायित्व निर्धारित किया गया है?

उत्तर

(1) कालीबोर बांध का निर्माण वर्ष 1997 में किया गया था तथा बांध से नहरों के माध्यम से ग्राम बेकरिया, तेजा का वास व लुहारचा में स्थित भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है एवं शेष पानी सेई बांध में अपवर्तित किया जाता है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) कालीबोर बांध जिला उदयपुर तहसील कोटड़ा में स्थित है जिससे इस क्षेत्र में स्थित ग्राम बेकरिया, तेजा का वास व लुहारचा में नहर के माध्यम से 536 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त बांध के पानी से इस क्षेत्र के कुओं आदि के भू-जल स्तर में वृद्धि होने से सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है।

(3) कालीबोर बांध के ओवरफ्लो से बाढ़ की स्थिति में फसलों एवं सड़कों आदि के नुकसान होने पर संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव जिला कलेक्टर (आपदा प्रबन्धन) उदयपुर के माध्यम से प्रस्तुत कर राज्य आपदा निधि कोष से भरपाई किये जाने का प्रावधान है।

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कार्मिकों की समस्या का समाधान

196. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुडे हुए कर्मियों की समस्याओं की समीक्षा की गयी है? यदि हां, तो क्या-क्या सकारात्मक समाधान निकाले गये व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारात्मक रूप से लागू करने के लिए सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में क्या प्रयास किए गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत स्थापित "उपभोक्ता विवाद निस्तारण मंच" को सुदृढ़ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में क्या-क्या कदम उठाएं गये व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त मंच के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए गत तीन वर्षों में कितना बजट किस-किस मद में व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(6) खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं मानदन्डों के संबंध में आम जन एवं छात्र-छात्राओं में जागृति लाने के संबंध में गत तीन वर्षों में क्या कार्यवाही की गयी व किस-किस मद में कितना बजट व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शत-प्रतिशत केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा प्रदेश को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर (ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम चयन सीमा 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में अधिकतम चयन सीमा 53 प्रतिशत) 4.46 करोड़ पात्र लाभार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 27.91 लाख मै.टन गेहूं प्राप्त होता है। उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थियों की दो श्रेणियां अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र परिवार हैं। अन्य पात्र परिवारों में बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अन्नपूर्णा लाभार्थियों के अतिरिक्त कुछ अन्य श्रेणियां भी सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत निर्धारित प्रावधानानुसार अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार व अन्य पात्र परिवारों को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट 2.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स गठित है, जिसकी समय-समय पर बैठकें आयोजित कर उक्त योजना की समीक्षा की जाती है।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कार्मिकों की समस्याओं की समीक्षा कर सकारात्मक समाधान निकालने के सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. राज्य की उचित मूल्य दुकानों को "अन्नपूर्णा भण्डारों" के रूप में विकसित कर उच्च गुणवत्ता युक्त मल्टीब्राण्ड उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत् लगभग 40-50 प्रकार की कैटेगिरी के 150 से अधिक प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में 5008 अन्नपूर्णा भण्डार प्रारम्भ किये जा चुके है। इससे न केवल

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तुऐं समुचित दर पर मिलेगीं अपितु उचित मूल्य दुकान डीलर के मुनाफे में भी वृद्धि होगी।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में उचित मूल्य दुकान पर पॉस मशीन स्थापित की गयी है।
3. पॉस मशीन संचालन में उचित मूल्य दुकान डीलर को कोई असुविधा न हो इस हेतु उन्हें समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
4. पॉस मशीन संबंधी समस्या तथा रिपेयर कार्य के लिए ब्लॉक व जिला स्तर पर वेण्डर के समन्वयक नियुक्त किये हुए है।
5. उचित मूल्य दुकानदार को खाद्यान्न वितरण कर दी जानेवाली मार्जिन मनी/कमीशन 30.00 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 70.00 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने एवं थोक विक्रेता का परिवहन एवं कमीशन 50.41 रुपये से बढाकर 60.00 किये जाने के आदेश दिनांक 03.09.2015 एवं 08.10.2015 को जारी किये गये।
6. जिन उचित मूल्य दुकानों पर पॉस मशीन के माध्यम से राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है, उन उचित मूल्य दुकानदारों को 17.00 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त कमीशन देय है।
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लाभकारी बनाने हेतु समुचित दर पर नॉन पीडीएस वस्तुएं उपलब्ध करायी जा रही है। नॉन पीडीएस वस्तुओं की संख्या में वृद्धि की गयी है, यथा चाय, नमक, साबुन, बिस्किट, मसालें, टूथपेस्ट, सीएफएल इत्यादि।
8. राज्य के उचित मूल्य दुकान डीलर को गेहूं व चीनी की एफ.ओ.आर. डिलीवरी के आदेश दिनांक 26.08.2016 को जारी किये गये है।
9. राज्य में उपभोक्ता पखवाड़ा प्रत्येक माह की दिनांक 10 से 24 तक निश्चित है। उपभोक्ता पखवाड़े की अवधि विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार बढ़ाये जाने हेतु जिला कलक्टर्स को दिनांक 23.06.2016 द्वारा अधिकृत किया जा चुका है।

आदेश दिनांक 03.09.2015, 08.10.2015, 26.08.2016 एवं 23.06.2016 की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारात्मक उपाय/सुझावों के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टॉस्क फोर्स गठित है। टॉस्क फोर्स की अनुशंसा के अनुसार ही खाद्य सुरक्षा योजना में समवेशन एवं निष्कासन की सूचियों को दो भागों में विभाजित कर कुछ श्रेणियों को जोडा तथा विलोपित किया गया है।

(4) जी हां। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों के सुदृढ़ीकरण के लिए 16.66 करोड़ रुपये के प्रस्ताव 12वें प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार को भेजे गये थे। केन्द्र सरकार द्वारा स्ट्रेन्थनिंग ऑफ कन्ज्यूमर फोरा स्कीम फेस-2 के अन्तर्गत राज्य में गठित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंचों के 10 भवनों के निर्माण हेतु रुपये 930.92 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है। भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में राशि रुपये 3,71,74,000/- राज्य को प्राप्त हो चुके है, जिसकी प्रशासनिक-वित्तीय स्वीकृति दिनांक 29.03.2016 एवं 04.08.2016 को जारी की जा चुकी है।

12 जिला मंचों के भवन निर्माण(विस्तार) हेतु भारत सरकार द्वारा 139.29 लाख की स्वीकृति जारी की गयी है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा रुपये 64.00 लाख की राशि आवंटित की जा चुकी है।

दिनांक 09.02.2017 को सक्षम समिति की आयोजित बैठक के निर्णयानुसार 64.00 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भवन(विस्तार) हेतु दिनांक 20.02.2017 को एवं गैर भवन मद में 304.30 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 23.02.2017 को जारी की जा चुकी है।

जारी स्वीक़ृति आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) गत तीन वर्षो में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित जिला मंचों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एवं 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर राज्य एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक, निबन्ध-चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी टी.वी.शो, संगोष्ठी, रैली आदि आयोजित की गई है, जिसके दौरान मुद्रित प्रचार सामग्री जनसाधारण को वितरित कराई गयी हैं। गत तीन वर्षो में आवंटित राशि का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि (रुपये)
1.	2014-15	2,96,000/-
2.	2015-16	10,00,000/- एवं 8,20,000/-
3.	2016-17	3,80,000/-, 5,00,000/- एवं 1,00,000/-

उक्त राशि आवंटित करने के संबंध में जारी स्वीकृति आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(6) खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता एवं मापदण्डों के संबंध में छात्र-छात्राओं में जागृति लाने के उद्धेश्य से राज्य सरकार द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित 1000 उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय किये जाने हेतु कार्य योजना दिनांक 12.03.2014 को जारी की गयी। इसी क्रम में उपभोक्ता विषयक गतिविधियों के संचालन हेतु 2000/-रुपये प्रति उपभोक्ता क्लब की वार्षिक वित्तीय सहायता स्वीकृत कर आदेश दिनांक 03.03.2015 द्वारा राशि रुपये 15.88 लाख का आवंटन किया गया। विभिन्न गुणवत्ता मानकों का प्रदर्शन विभागीय वैबसाइट पर किया जा रहा है।

कार्य योजना दिनांक 12.03.2014 एवं आदेश दिनांक 03.03.2015 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ के धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने की योजना

197. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्रसिद्ध धार्मिक मंदिरों से जनता का जुड़ाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तथा उक्त धार्मिक स्थानों तक आवागमन के रास्ते ठीक नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में प्रसिद्ध धार्मिक मंदिरों से जनता का जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सभी

(देवस्थान मंत्री)

धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कें सन्तोषजनक स्थिति में हैं। समय समय पर आवश्यकता अनुसार मरम्मत कार्य करवाया जाता है।

प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारियों के समकक्ष दर्जा

198. श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, साथिनों एवं सहायिका को कितना-कितना मानदेय दिया जा रहा है तथा उक्त से क्या-क्या सेवाएं ली जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, साथिनों एवं सहायिका द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालकों के समग्र एवं समुचित विकास के उद्देशित महत्वपूर्ण बेसिक सेवाओं की उपलब्धता के प्रति प्रतिबद्धता रखने के उपरान्त भी इन्हें राज्य कर्मचारियों के समकक्ष दर्जा नहीं दिया जा रहा है एवं इनके मानदेय में भी उपयुक्त एवं समुचित बढ़ोतरी नहीं की गयी है?

(3) क्या सरकार उक्त सभी का मानदेय बढ़ाने व राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगी, साथिन तथा सहायिका को दिये जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त मानदेयकर्मियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी को राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जा सकता क्योकिं यह मानदेय सेवा पर स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में सेवा करने वाली स्थानीय महिला होती है एवं इनका दैनिक कार्य 4 घंटे प्रति दिवस होता है। इस कार्य समय के उपरान्त ये किसी भी निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति नियम लागू नहीं है और ना ही श्रमिकों के बराबर कार्य के घंटे तय होते हैं।

(3) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही मानदेय में बढ़ोतरी की गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है। इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये पूर्णत: अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली मानदेयकर्मी हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण की घोषणा

199. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कुल कितनी राशि सड़क निर्माण पर व्यय की गयी? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2014-15, से 2016-17 तक किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में भारत सरकार द्वारा किन-किन सड़कों के निर्माण की घोषणा की है तथा उन पर कितनी धनराशि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाएगी? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कुल राशि रु. 11252 करोड़ तथा भारत सरकार द्वारा 9570.67 करोड़ रुपये कुल 20822.67 करोड़ रुपये राज्य में सड़क निर्माण हेतु व्यय किये गये, विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक सड़क निर्माण पर जिलेवार व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त अवधि में भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण के सम्बन्ध में की गई घोषणाओं तथा व्यय की जाने वाली राशि का विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण

200. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कोटपूतली व विराटनगर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रचुर मात्रा में खनन किया जाता है? यदि हां, तो उक्त तहसील क्षेत्रों में खनिजों के निर्गमन से सरकार को प्रतिवर्ष कितना राजस्व प्राप्त होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खनिज वाहनों के लगातार आवागमन से उक्त क्षेत्र की अधिकांश सड़कें अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खनन क्षेत्र के आस-पास के गांवों की सड़कों का पुनर्निमाण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2008 से 2016 तक सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी सड़कों का खनन विभाग के बजट से पुनर्निमाण व नवीनीकरण कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर जिले के कोटपूतली व विराटनगर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विभाग द्वारा स्वीकृत खनन पट्टों में विभिन्न खनिजों का खनन किया जा रहा है। दोनों तहसीलों में खनिजों से प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**तहसील**	**वर्ष (2015-16)**	**चालू वर्ष 2016-17 (जनवरी, 2017 तक)**
1.	कोटपुतली	53.25 करोड़	41.37 करोड़
2.	विराटनगर	2.14 करोड़	1.63 करोड़
	योग	55.39 करोड़	43.00 करोड़

(राज्य मंत्री, खान)

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र की अधिकांश सड़कें केवल मात्र खनिज वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त नहीं हुई हैं। खनन क्षेत्र के आस-पास की सड़कों का पुनर्निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(3) वर्ष 2008 से 2016 तक विधान सभा क्षेत्र 102 (विराटनगर, कोटपूतली) में खान विभाग द्वारा कोई खनिज उपागमन सड़क का पुनर्निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य नहीं कराया गया है।

प्रदेश में किसानों को लोहे की कोठी पर अनुदान

201. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार किसानों को अनुदानित दर पर लोहे की कोठी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या इस हेतु कितना अनुदान दिया जाएगा?

(2) क्या इस हेतु जिलों के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि हां, तो अलवर, नागौर व उदयपुर के लिये कितना लक्ष्य है?

(3) क्या सरकार उदयपुर जिले का लक्ष्य बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) योजना के लोकल इनिशिएटिव कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त जिलों को आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार किसानों को अनुदान पर सीड स्टोरेज बिन्स (लोहे की कोठियां) उपलब्ध कराई जा रही हैं। योजना के प्रावधान के अनुसार प्रति सीड स्टोरेज बिन लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1000 रुपये, जो भी कम हो, का अनुदान देय है।

(2) उक्त योजना सभी 33 जिलों में लागू है। योजनान्तर्गत अलवर जिले में 3852, नागौर में 3193 एवं उदयपुर में 3080 के लक्ष्य आवंटित किये गये हैं।

(3) उदयपुर जिले में सीड स्टोरेज बिन्स की अतिरिक्त मांग प्राप्त होने

(कृषि मंत्री)

पर योजनान्तर्गत बजट उपलब्धता की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लक्ष्य बढ़ाने के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जाएगा।

प्रश्न संख्या 202.

(स्थगित)

नवलगढ़ में पेयजल योजना के लम्बित कार्य

203. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में पेयजल की क्या-क्या व्यवस्था है? शहर एवं ग्रामवार मय जनसंख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति कितना पेयजल उपलब्ध कराये जाने के मानदण्ड निर्धारित हैं तथा क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के शहरों/गांवों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल की समस्या को देखते हुए नई पेयजल योजनाएं बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन शहरों/गांवों में नई पेयजल योजनाएं बनाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त क्षेत्र के पेयजल से संबंधित किस-किस कार्य के प्रस्ताव कहां-कहां और कितनी राशि के लंबित हैं? लंबित प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृतियां जारी कर दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के शहर नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ तथा समस्त 109 आबाद ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है। योजनावार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-क एवं ख पर संलग्न है।

(2) राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं/ परियोजनाओं के अभिकल्पन में पेयजल आपूर्ति हेतु लीटर प्रति व्यक्ति

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

प्रतिदिन के निर्धारित मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के शहर नवलगढ़ एवं मुकुन्दगढ़ तथा समस्त 109 आबाद ग्रामों में भू-जल उपलब्धता अनुरूप की जा रही पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है। योजनावार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-क एवं ख में निहित है।

उक्त क्षेत्र के शहर नवलगढ़ में जल सेवा स्तर में आवश्यक सुधार एवं पेयजल के समान वितरण हेतु राशि रुपये 2017.76 लाख की पुनर्गठित जल योजना की स्वीकृति जारी की जाकर उक्त योजना के चार पैकेजों का कार्यादेश दिया जा चुका है तथा योजना माह अप्रैल, 2017 तक पूर्ण करनी अपेक्षित है।

(3) उपरोक्तानुसार। विधान सभा क्षेत्र, नवलगढ़ के शहर नवलगढ़ में जल सेवा स्तर में आवश्यक सुधार एवं पेयजल के समान वितरण हेतु स्वीकृत पुनर्गठित जल योजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा यह योजना माह अप्रैल, 2017 तक पूर्ण करनी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के समस्त 109 आबाद ग्रामों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सुचारू एवं संतोषप्रद है।

क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान हेतु भू-जल की उपलब्धता, पेयजल की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जल योजनाओं का संवर्धन/पुनर्गठन का कार्य सतत प्रक्रिया के तहत कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र हेतु अन्य किसी जल योजनाओं के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) उपरोक्तानुसार। उक्त क्षेत्र हेतु अन्य किसी जल योजनाओं के प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बन्ध बारैठा से निकलने वाली नहरों को पक्का करने की योजना

204. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बन्ध बारैठा से निकलने वाली नहरें कच्ची

(श्री बच्चू सिंह)

होने के कारण खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी भरने से फसलें गल कर नष्ट हो जाती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार बन्ध बारैठा से निकलने वाली नहरों को पक्का करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा बन्ध बारैठा की नहरों हेतु कब-कब कितना-कितना बजट दिया गया है? क्या उक्त नहरों के किये गये कार्यों की भी जांच की गयी है? यदि हां, तो कब-कब व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कच्ची नहरों से होने वाले सीपेज से नहरों के पास के क्षेत्र में फसल के नुकसान की संभावना रहती है। बन्ध बारैठा से निकलने वाली कच्ची नहरों को पक्का करने एवं बांध मरम्मत के कार्यों हेतु प्रस्ताव राजस्थान जल क्षेत्र आजिविका सुधार परियोजना (RWSLIP) योजनान्तर्गत तैयार किये गये है। योजना के मापदण्डों के अनुरूप तकनीकी परीक्षण उपरान्त आवश्यक स्वीकृति एवं वित्तीय संसाधनो की उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) बन्ध बारैठा की नहरों की मरम्मत एवं सिल्ट सफाई हेतु आंवटित बजट के अन्तर्गत व्यय की गयी राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर तथा कराये गये कार्यो की समय-समय पर जांच हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के पैट्रोल पम्पों द्वारा की जा रही मिलावट की जांच

205. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के जिला रसद विभाग, बाट एवं माप विभाग व तेल कम्पनियों की मिलीभगत से पैट्रोल पम्पों पर मीटर में पूरी माप दर्शाने के उपरान्त भी डीजल पैट्रोल की कम मात्रा दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों? गत 5 वर्षों में सरकार को इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगसी राम)

(2) क्या यह भी सही है कि आम उपभोक्ता के वाहन में डीजल पैट्रोल डाल देने के बाद उसे बाहर निकाल कर संबंधित पैट्रोल पम्प इकाई पर ही मैन्युअली नाप तोल प्रक्रिया निर्धारित है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कम तेल देने की मंशा से नोजल से जुडे सॉफ्टवेयर में की गयी छेड़छाड़ को पकड़ना आम उपभोक्ता की पकड़ से बाहर है? यदि हां, तो पैट्रोल पम्प द्वारा इस प्रकार की चोरी को पकड़ने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या सरकार राज्य के प्रत्येक पैट्रोल पम्प की जांच एक माह में दो बार करवाने तथा उपभोक्ता वर्ग की शिकायत का निवारण ऑन दा स्पॉट कराने, सॉफ्टवेयर व बाट एवं माप विभाग की सील को विजिबल रखने व नोजल से जुड़े सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन कर आम तेल उपभोक्ता को राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि प्रदेश के जिला रसद विभाग, बाट एवं माप विभाग व तेल कम्पनियों की मिलीभगत से पैट्रोल पम्पों पर मीटर में पूरी नाप दर्शाने के उपरान्त भी डीजल पैट्रोल की कम मात्रा दी जा रही है। शिकायत निवारण की पूरी व्यवस्था है, जिसमें ग्राहक संबंधित कम्पनी के वेबपोर्टल अथवा टोल-फ्री नम्बर अथवा बिक्री अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। टोल-फ्री नम्बर तथा संबंधित बिक्री अधिकारी का मोबाइल नम्बर पैट्रोल पम्प पर प्रदर्शित किया जाता है। जब भी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है, तुरन्त उस एरिया के बिक्री अधिकारी को जांच के लिए भेजा जाता है और जांच के दौरान यदि कोई खामी पायी जाती है, तो मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के तहत तुरन्त कार्यवाही की जाती है। पिछले 05 वर्ष के दौरान इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि., भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. एवं हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि. द्वारा कम मात्रा प्राप्ति से संबंधित शिकायतें और उन पर की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) राज्य स्तरीय समन्वयक तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार यह सही नहीं है। जांच के लिए, बाट एवं माप विभाग द्वारा निर्धारित 5 लीटर माप सभी रिटेल आउटलेट (पैट्रोल पम्प) पर उपलब्ध है। कम वितरण की शिकायत या शक की स्थिति में ग्राहक 5 लीटर माप मांग कर सीधे वितरण पम्प से माप में 5 लीटर डीजल-पैट्रोल वितरित कर जांच कर सकते है।

(3) यह सही है कि सॉफ्टवेयर में की गई छेड़छाड़ को पकड़ना आम उपभोक्ता की पकड़ से बाहर है, किन्तु शक की स्थिति में, रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध 05 लीटर माप मांग कर जांच कर सकते है। रिटेल आउटलेटों (पैट्रोल पम्पों) पर नई पीढ़ी के वितरण पम्प उपलब्ध हैं, जिसमें बाट एवं माप विभाग द्वारा ई-अंशांकन (E-Calibration) की सुविधा और हेर-फेर नियंत्रण सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में की गयी छेड़छाड़ का स्वत: रिकार्ड बन जाता है, जो निरीक्षण के समय पकड़ा जा सकता है। बाट एवं माप विभाग द्वारा वार्षिक व तेल कम्पनियों द्वारा आटोमेटेड पम्प का वर्ष में 2 बार तथा बाकी पैट्रोल पम्पों का वर्ष में 4 बार निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त डिस्पेसिंग यूनिट के वेण्डर के द्वारा भी ए.एम.सी. में नियमित रख-रखाव के समय भी जांच की जाती है।

भारत सरकार द्वारा पैट्रोल पम्पों का मॉडल एप्रूवल किया जाता है। एप्रूव्ड मॉडल को कम्पनियों द्वारा क्रय कर पम्प लगाये जाते है। पम्प लगाने के पश्चात विधिक माप विज्ञान विभाग ऐसे लगाये गये पम्प की डिलीवरी की मात्रा की जांच कर सही होने पर भारत सरकार द्वारा निश्चित की गयी जगह यथा पलसर, टोटलाइजर, मीटर, असैम्बली, मदरबोर्ड एवं डिप स्वीच (ई-केलीब्रेशन डिवाइस) को सिल्ड किया जाता है।

(4) पैट्रोल पम्प की जांच माह में दो बार करवाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। शिकायत के निवारण की प्रक्रिया का विवरण प्रश्न के बिन्दु-1 के उत्तर में दिया गया है। सीलिडिंग अरेंजमेन्ट भारत सरकार के नाप-तोल विभाग द्वारा अनुमोदित सीलिडिंग अरेजमेन्ट के अनुसार ही किया जाता है। नोजल से जुडे सॉफ्टवेयर को उपभोक्ता के लिए ऑनलाइन अभी नहीं किया जा सका है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनी अपने पैट्रोल पम्प के संचालन प्रक्रिया को आटोमेट कर रही है, वर्तमान में लगभग 30 प्रतिशत नेटवर्क पर ऑटोमेशन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, और फैजेज में आने वाले समय में इसका विस्तार किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर भैंरू मन्दिर को सरकार के अधीन लेने की योजना

206. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में ऐसे कितने प्राचीन धार्मिक स्थल हैं, जो सरकार के अधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राचीन धार्मिक स्थलों को राजकीय बोर्ड/ट्रस्ट के अधीन लेने एवं विभिन्न सुविधा उपलब्ध कराने के क्या नियम एवं मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में पंचायत समिति भदेसर में प्राचीन धार्मिक स्थल "श्री भदेसर भैंरू" जी का मंदिर विद्यमान है? यदि हां, तो उक्त मंदिर का संचालन किस संस्था/ ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मंदिर सरकार की देखरेख में नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मन्दिर की देख-रेख एवं रख-रखाव के लिए श्री भदेसर भैंरू मन्दिर बोर्ड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में राजस्थान राजपत्र दिनांक 25 जून 1981 के अनुसार विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित निम्न मन्दिर है:-

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

क्र. सं.	श्रेणी	मन्दिरों की संख्या
1.	राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी	10
2.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	2

(2) सार्वजनिक धार्मिक स्थलों का पंजीयन राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत सार्वजनिक प्रन्यास के रूप में किया जाता है। किसी भी पंजीकृत लोक न्यास का प्रबंध राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत प्रबंध समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है।

(3) जी हां। यह सही है कि पंचायत समिति के ग्राम भदेसर में प्राचीन धार्मिक स्थल श्री भदेसर भैंरू जी का मंदिर विद्यमान है। वर्तमान में मंदिर का संचालन श्री भदेसरिया भैरवनाथ ट्रस्ट गांव भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (पंजीयन क्रमांक 7/चित्तौड़गढ़/86) द्वारा किया जा रहा है (पंजीयन प्रमाण पत्र परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)

(4) इस संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत भदेसर एवं ग्रामवासियों की ओर से मंदिर प्रबंधन और मंदिर से प्राप्त भेंट राशि को लेकर प्राप्त शिकायत के संबंध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 38 के अंतर्गत प्रकरण 14/2004 दर्ज किया गया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें बहस हेतु आगामी दिनांक 16.03.2017 नियत है। श्री भेदसर भैंरू मंदिर को उसके सम्पूर्ण विन्यास सहित देखरेख एवं रख रखाव के लिए श्री भदेसर भैंरू मंदिर को बोर्ड बनाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि प्रकरण धारा 38 के अंतर्गत विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

207. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कितनी सड़कें क्षतिग्रस्त (नॉन पैचेबल)

(श्री रामहेत सिंह यादव)

हैं एवं उनमें से कितनी लम्बाई की कौन-कौनसी सड़कों हेतु कितनी-कितनी राशि नवीनीकरण के लिये स्वीकृत की जा चुकी है? विधानसभावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में वर्ष 2016-2017 में नवीनीकरण हेतु कितनी लम्बाई की सड़कों हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में शेष रही क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अलवर जिले में कुल 718.92 किमी लम्बाई की क्षतिग्रस्त (नॉन पेचेबल) सड़कों में से 435.67 किमी. लम्बाई की सड़कें 8536.90 लाख रुपये की लागत से नवीनीकरण हेतु स्वीकृत की जा चुकी हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में वर्ष 2016-2017 में नवीनीकरण हेतु 23.00 किमी. लम्बाई की सड़कें स्वीकृत हैं। जिनकी कुल स्वीकृत राशि रु. 811.57 लाख है। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। उक्त क्षेत्र में शेष रही क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निजी खातेदारी में माइनिंग लीज जारी करने के नियम

208. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निजी खातेदारी में माइनिंग लीज जारी करने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त नियमों में संशोधन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खातेदारी भूमि में प्रधान खनिज के खनन पट्टे एमएमडीआर (संशोधन) एक्ट, 2015 की धारा 10ए(2)(बी) में संरक्षित प्रकरणों को छोड़ते हुए शेष प्रकरणों में खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 5 के अनुसार नीलामी से स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिज के खनन पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 4, 5 व 6 में संरक्षित प्रकरणों को छोड़ते हुए शेष प्रकरणों में नियम 14 के अनुसार संबंधित खातेदार को इन्कार का प्रथम अधिकार (right of first refusal) प्रदत्त करते हुए नीलामी से स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। संबंधित नियमों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत किसानों के क्षतिपूर्ति के लम्बित प्रकरण

209. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अन्तर्गत वर्ष 2013 से 2017 तक किसानों द्वारा कुल कितना प्रीमियम दिया गया तथा कितनी फसल नष्ट हुई, कुल कितने किसान प्रभावित हुए तथा अब तक कुल कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में वर्तमान में कितने किसानों के क्षतिपूर्ति के प्रकरण लम्बित हैं व उक्त प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की कितनी राशि देय है?

(3) उक्त बीमा योजना में बीमा प्रीमियम राशि व क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण का क्या आधार/ मानदण्ड निर्धारित है?

उत्तर

(1) वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू नहीं थी। राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के तहत राज्य में दो फसल बीमा योजनाएं क्रमश: मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं संशोधित

(कृषि मंत्री)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इन योजनान्तर्गत जिन कृषकों ने अधिसूचित फसल का बीमा करवाया है, उन्हीं कृषकों के बीमा क्लेम का निर्धारण किए जाने का प्रावधान है। खरीफ 2013 से रबी 2015-16 तक राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाएं चल रही थी। इसके बाद में खरीफ-2016 से सम्पूर्ण राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गयी।

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के तहत खरीफ 2013 से रबी 2015-16 तक कृषक प्रीमियम राशि रु. 1339.58 करोड़, राज्यांश व केन्द्रीयांश प्रीमियम राशि रु. 1832.59 करोड़, कुल प्रीमियम राशि रु. 3172.20 करोड़, दिया गया। वर्णित अवधि में 207 लाख कृषकों को क्षतिपूर्ति के रूप में 3707.05 करोड़ रुपये की राशि बीमा क्लेम के रूप में कृषकों को प्रदान की गयी।

खरीफ 2016 से सम्पूर्ण राज्य में नई कृषि बीमा योजना "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना एवं रबी 2016-17 में सम्पूर्ण जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया है। खरीफ 2016 की फसल बीमा क्लेम के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी 2015-16 तक के पात्र बीमित कृषकों को बीमा क्लेम दिए जा चुके हैं। वर्ष 2016 (खरीफ 2016) में बीमित कृषकों के बीमा क्लेम के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के अन्तर्गत कृषक प्रीमियम राशि बीमित राशि का 2 प्रतिशत एवं रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत कृषक द्वारा देय है। उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम दर 5 प्रतिशत निर्धारित है। शेष प्रीमियम राशि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में अनुदान के रूप में दी जाती है। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के परिणामों को गारण्टी उपज से तुलना कर बीमा क्लेम का निर्धारण किया जाता है।

मैसर्स जिंदल शॉ लिमिटेड के विरुद्ध पर्यावरण नियमों की पालना नहीं करने पर कार्यवाही

210. श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कार्यरत मै. जिंदल शॉ लिमिटेड द्वारा पर्यावरण नियमों की अवहेलना की जा रही है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त कम्पनी को नये नियमानुसार पर्यावरण व खनन एन.ओ.सी. लेने हेतु बाध्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। भीलवाड़ा स्थित मैसर्स जिंदल शॉ लिमिटेड के परिसर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 16.02.2017 को की गयी जांच के विश्लेषण परिणाम निर्धारित मानकों के अनुरूप है। पूर्व में दिनांक 30.11.2016 को की गयी जांच के विश्लेषण परिणामों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता तीन स्थानों पर मानकों के अनुरूप नहीं थी। उद्योग ने इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया था कि वायु मोनिटरिंग जांच के दौरान तेज हवाओं के कारण रेस्पैरेबल सस्पैंडेड पार्टिकुलेट मेटर (आर.एस.पी.एम.) की मात्रा ज्यादा पायी गयी, जो तर्कसंगत प्रतीत होने के कारण राज्य मण्डल द्वारा स्वीकार्य पाया गया था।

(2) जी नहीं। उपरोक्त उत्तर के अनुसार उक्त उद्योग द्वारा पर्यावरण नियमों की अवहेलना नहीं की जा रही है। अतः इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(3) जी नहीं। उक्त उद्योग द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जारी पर्यावरण समाघात अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति

(पर्यावरण मंत्री)

प्राप्त की हुई है अतः उद्योग को वर्तमान में पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हैं।

खनन कार्य करने हेतु भी अनापत्ति जारी की हुई हैं, पुनः खनन अनुमति लिये जाने का प्रावधान नहीं है।

खेतड़ी में पेयजल की समस्या हेतु विशेष कार्य योजना

211. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार ग्राम पंचायत गोठड़ा (खेतडी नगर) नानूवाली बावड़ी व नगरपालिका खेतड़ी की पेयजल समस्या हेतु विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान के अंतर्गत इंदिरा गांधी कैनाल आधारित चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल के पानी को सतही स्रोत लेकर एकीकृत तारानगर- झुन्झुनूं-सीकर-खेतड़ी वृहत् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण में विधान सभा क्षेत्र, खेतड़ी की नगरपालिका खेतड़ी व कस्बा गोठड़ा तथा वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 85 ग्रामों सहित जिला झुन्झुनूं की तहसील झुन्झुनूं एवं खेतड़ी के कुल 5 शहर (झुन्झुनूं, बगड़, मण्डावा, खेतड़ी व गोठड़ा) तथा 258 ग्रामों को लाभान्वित करने हेतु परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30.05.2013 को राशि रुपये 954.74 करोड़ की जारी की गयी थी।

इस परियोजना का कार्य दो पैकेजों में वर्तमान में प्रगति पर है जिसके अंतर्गत पैकेज प्रथम एवं द्वितीय का कार्य क्रमश: 85 एवं 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। विधान सभा क्षेत्र, खेतड़ी के कस्बा गोठड़ा, नगरपालिका खेतड़ी एवं ग्राम नानूवाली बावड़ी सहित झुन्झुनूं जिले के उक्त 5 शहर/कस्बों एवं 258 ग्रामों को उक्त परियोजना से मार्च, 2018 तक लाभान्वित करना अपेक्षित है।

मातृकुण्डिया बांध से बनास नदी को रिचार्ज करने की योजना

212. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बनास नदी पर मातृकुण्डिया बांध बनाया गया है? यदि हां, तो इसकी भराव क्षमता कितनी है व उक्त बांध के पानी का उपयोग कहां-कहां, कितनी-कितनी मात्रा में किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बांध के पानी को पुन: रिजर्व कर बनास नदी को रिचार्ज करने के लिए 200 एम.सी.एफ.टी. पानी रिजर्व करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मातृकुण्डिया बांध की मेजा फीडर की "O" चैन पर 70 मीटर छोटी नहर बना कर मातृकुण्डिया एनिकट व बनास नदी को रिचार्ज करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बनास नदी पर मातृकूण्डिया बांध जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया है एवं इसकी भराव क्षमता 1188 मिलियन घन फीट है। बांध के पानी के प्रस्तावित उपयोग व निर्धारण/आरक्षित किये गये पानी की मात्रा का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं, बांध में पानी की आवक के अनुसार बनास नदी को रिचार्ज करने हेतु 50 MCFT पानी आरक्षित किया हुआ है एवं बांध में पानी की आवक एवं इसके पूर्व निर्धारित उपयोग के मद्देनजर बनास नदी को रिचार्ज करने हेतु पानी को बढ़ाकर 200 MCFT किया जाना विचाराधीन नही है।

(3) जी नहीं। बनास नदी को रिचार्ज करने हेतु निर्धारित 50 MCFT पानी को बांध के ओवरफ्लो से छोड़े जाने का प्रावधान होने से '0' चैन पर 70 मीटर छोटी नहर बनाये जाना विचारधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छीपाबड़ौद व छबड़ा पंचायत समिति में एफ.पी.एस. डीलर बढ़ाने की योजना

213. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले की पंचायत समिति छबड़ा व छीपाबड़ौद में वर्ष 2016-17 में एफ.पी.एस. डीलर बढ़ाये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितने-कितने?

(2) क्या सरकार भविष्य में उक्त पंचायत समितियों में एफ.पी.एस. डीलर बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कितने-कितने? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बांरा जिले की पंचायत समिति छबड़ा में भूलोन, फलिया, जैपला, बारई(बाहरी), कडैयाबन एवं कड़ैयाहाट तथा पंचायत समिति छीपाबड़ौद में खेड़ला जागीर, बमोरी घाटा, मानपुरा, मौखमपुरा, हरनावदा शाहजी, बंजारी, पीथपुर, सहजनपुर, देवरी जोध, गोरधनपुरा, दीगोद खालसा में नये राशन डीलरों के प्राधिकार पत्र जारी किये गये है।

(2) राज्य सरकार द्वारा 500 राशनकार्ड अथवा 2000 यूनिट पर उचित मूल्य दुकान खोले जाने का प्रावधान है। उचित मूल्य की नवीन दुकानें खोलने हेतु यदि उक्त प्रावधानों के अनुरूप औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होते है, तो नवीन उचित मूल्य दुकान खोले जाने की कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है। इस संबंध में जारी आदेश दिनांक 11.07.2012 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले में मिशन पूर्ण शक्ति के प्रेरकों का बकाया मानदेय

214. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में वर्तमान में चलाएं जा रहे मिशन पूर्ण शक्ति में किन-किन गांवों में कौन-कौन प्रेरक कितने-कितने समय से कार्य कर रही हैं

(श्री ज्ञानचंद पारख)

एवं किस-किस गांव में कितने-कितने समय से पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रेरकों को कितने-कितने समय से किन-किन कारणों से मानदेय दिया जाना लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रेरकों को मानदेश राशि देने मे अत्यधिक विलम्ब होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इनका मानदेय समय पर देने के लिये कोई निर्देश जारी करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार प्रेरकों के रिक्त पद भरने एवं बकाया मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में पाली जिले में मिषन पूर्ण शक्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 217 ग्राम पंचायतों में 219 महिला ग्राम समन्वयक कार्य कर रही हैं। कार्यरत ग्राम समन्वयकों का ग्राम पंचायत वार अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं। मिषन पूर्ण शक्ति अन्तर्गत, पाली में 104 ग्राम पंचायतों में ग्राम समन्वयकों के 81 पद रिक्त हैं। ग्राम समन्वयकों के रिक्त पदों का विवरण ग्राम पंचायतवार अवधि सहित परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(2) कार्यरत रही ग्राम समन्वयकों का माह जून, 2016 से फरवरी, 2017 तक का मानेदय भुगतान किया जाना शेष है। भुगतान अवषेष रहने के कारणों का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न हैं।

(3) ग्राम समन्वयकों को मानदेय भुगतान जून, 2016 से फरवरी, 2017 में विलम्ब का कारण परिशिष्ट-स पर दिए गये विवरण के अनुसार हैं। मानदेय समय पर भुगतान हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देषित कर दिया गया है।

(4) जी हां। ग्राम समन्वयकों के रिक्त पदों को भरने का कार्य सतत् प्रक्रिया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा ग्राम समन्वयको के रिक्त पदों को भरा जाता है। बकाया मानदेय का भुगतान प्रक्रियाधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राष्ट्रीय योजनाओं से कृषि योजनाओं हेतु राज्य को प्राप्त राशि

204. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभाग के लिए कितना बजट स्वीकृत किया गया? उक्त स्वीकृत बजट में से किन-किन योजनाओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राष्ट्रीय योजना से भी वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कुल कितनी राशि व अब तक सरकार द्वारा राष्ट्रीय योजना में प्राप्त राशि का किन-किन योजनाओं में कितनी-कितनी राशि का उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2016-17 में कृषि विभाग के लिए कुल 309421.23 लाख रुपये के बजट प्रावधान मय पुनर्विनियोजन एवं अतिरिक्त प्रावधान के विरुद्ध फरवरी, 2017 तक 112035.39 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में उधानिकी विभाग के लिए कुल 44694.57 लाख रुपये के बजट प्रावधान मय पुनर्विनियोजन एवं अतिरिक्त प्रावधान के विरुद्ध फरवरी, 2017 तक 18604.02 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। योजनावार रखे गये प्रावधान एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कृषि विभाग के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/ मिशनों हेतु वर्ष 2016-17 में कुल 103092.37 लाख रुपये का बजट प्रावधान मय पुनर्विनियोजन एवं अतिरिक्त प्रावधान केन्द्रीय सहायता का रखा गया है। भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता के रूप में फरवरी, 2017 तक 49885.14 लाख रुपये प्राप्त हुए एवं वर्ष 2015-16 की अप्रयुक्त राशि 13449.76 लाख रुपये का पुनर्वैधीकरण प्राप्त हुआ, इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि 63334.90 लाख रुपये में से फरवरी, 2017 तक कुल 37726.84 लाख रुपये व्यय किये गये। उदयान विभाग के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/ मिशनों हेतु वर्ष 2016-17 में कुल 15584.77 लाख रुपये का

(कृषि मंत्री)

बजट प्रावधान मय पुनर्विनियोजन एवं अतिरिक्त प्रावधान केन्द्रिय सहायता का रखा गया है। भारत सरकार से केन्द्रिय सहायता के रूप में फरवरी, 2017 तक 11513.00 लाख रुपये प्राप्त हुए एवं वर्ष 2015-16 की अप्रयुक्त राशि 2683.61 लाख रुपये का पुनर्वेधीकरण प्राप्त हुआ, इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि 14196.61 लाख रुपये में से फरवरी, 2017 तक कुल 4910.38 लाख रुपये व्यय किये गये। केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं/मिशनों हेतु वर्ष 2016-17 अन्तर्गत रखे गये प्रावधान, भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं फरवरी, 2017 तक व्यय का विवरण परिशिष्ट-3 व 4 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मौसम आधारित फसल बीमा योजना का प्रीमियम

205. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंग:-

(1) मौसम आधारित फसल बीमा योजना का प्रीमियम गत पांच वर्ष पूर्व क्या था तथा गत तीन वर्षों में क्या संशोधन किया गया? संशोधन किए जाने के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में मौसम के लिए तापक्रम में भी कोई संशोधन किया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन बीमांकिक प्रीमियम दरों के आधार पर किया गया जिसमें खरीफ फसलों हेतु 10 प्रतिशत व रबी फसलों हेतु 8 प्रतिशत एवं उद्यानिकी/ वाणिज्यिक फसलों हेतु 12 प्रतिशत पर उपरी सीमा (कैप) निर्धारित थी जिसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है।

(2) मौसम आधारित फसल बीमा के तहत वर्ष 2014-15 में कृषक हित में मौसम के तापमान में किए गए संशोधन का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्ष 2015-16 में मौसम के तापमान में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुरवाटी के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

206. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधानसभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में पशु चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्रों में वर्तमान में किन-किन पदों के कितने-कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालय एवं पशु उप केन्द्रों में गत दो वर्षों में कितने रिक्त पदों को भरा गया? क्या सरकार शेष पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की पशु चिकित्सा संस्थाओं में स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की पशु चिकित्सा संस्थाओं में गत दो वर्षों में निम्नानुसार रिक्त पदों को भरा गया:-

क्र. सं.	पद का नाम	भरे गये पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	02
2.	पशु चिकित्सा अधिकारी	09
3.	पशु चिकित्सा सहायक	03
4.	पशुधन सहायक	10
5.	पशुधन परिचर	01
6.	जलधारी	01
	कुल	26

जी हां। पशु चिकित्सा अधिकारियों के 54 पदों को एवं पशुधन सहायकों के 1789 पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

रिक्त पदों को कर्मचारियों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से भरा जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

207. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले की मूंडवा, नागौर, खींवसर तथा मेड़ता तहसील के किसानों को एक जनवरी, 2012 से 31 जनवरी, 2017 तक प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की एवज में कितनी मुआवजा राशि का वितरण किया गया? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खसरे को इकाई मानकर किसानों को फसली नुकसान का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में चल रही फसली बीमा योजना के माध्यम से कृषकों से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितनी राशि का प्रीमियम लिया जा चुका है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 2012 से 2015 तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया है। योजनान्तर्गत कृषकों को दिए गये बीमा क्लेम एवं लाभान्वित कृषक संख्या का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ग्रामवार विवरण संधारित नहीं किया जाता है। खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है जिसका बीमा क्लेम भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। खरीफ 2016 से राज्य के 33 जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया गया है। इस योजना में फसल बीमा की इकाई पटवार व तहसील निर्धारित है। खसरे को इकाई मानकर योजना का क्रियान्वयन किए जाने का मार्ग-दर्शिका में प्रावधान निहित नहीं है।

(3) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित कृषकों से राशि रु. 225.19 करोड़ का प्रीमियम लिया जा चुका है। जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में खेल गांव बनाने की योजना

208. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जोधपुर में खेल गांव हेतु जमीन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उदयपुर के खेल गांव की तर्ज पर जोधपुर में भी खेल गांव बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार खेल गांव के साथ खेल शिक्षक-प्रशिक्षक कालोनी भी विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान में विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) वर्तमान में विभाग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अगावली ग्राम (बयाना) में प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर संचालित क्रेशर पर कार्यवाही

209. श्री बच्चू सिंह (बयाना): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर 200 टी.पी.एच. के स्टोन क्रेशर स्थापित किये जा सकते हैं? यदि नहीं, तो खनन पट्टा सं. 02/93 खनिज सिलिका सैण्ड शिवालिका सिलिका निकट ग्राम अगावली, तहसील बयाना में 200 टी.पी.एच. का प्रोसेसिंग यूनिट के नाम पर लगे स्टोन क्रेशर को अब तक बन्द नही कराये जाने के क्या कारण हैं? इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत स्थापना हेतु सम्मति प्राप्त कर 200 टी.पी.एच. का स्टोन क्रेशर स्थापित किया जा सकता है।

(पर्यावरण मंत्री)

खनन पट्टा संख्या 02/93 मैसर्स शिवालिका सिलिका सैण्ड स्टोन, निकट ग्राम अगावली, बयाना स्थित सिलिका सैण्ड क्रशिंग हेतु वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत संचालन सम्मति दिनांक 28/02/2019 तक वैध होने से प्रश्न में वर्णित स्टोन क्रेशर को बन्द नहीं किया गया है।

राज्य मण्डल द्वारा जारी मार्गदर्शिका दिनांक 15/10/2014 की प्रति परिशिष्ट-अ, स्थापना सम्मति दिनांक 20/02/2013 की प्रति परिशिष्ट-ब, तथा संचालन सम्मति दिनांक 17/05/2016 की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में खेल हेतु संचालित योजनाएं

210. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में वर्तमान में खेलू-कूद की कौन-कौनसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में खेल अधिकारी कार्यालय द्वारा वर्तमान में कितने खिलाड़ियों को विभिन्न योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले के स्टेडियम में वर्तमान में कौन-कौनसी खेल सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा कौन-कौनसी खेल सुविधाओं का अभाव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र, बाड़मेर पर क्रीडा परिषद द्वारा नियुक्त नियमित खेल प्रशिक्षकों तथा अनुबंध के आधार पर अल्पकालीन प्रशिक्षकों द्वारा नियमित रूप से प्रात: एवं सांय खिलाड़ियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें खेल मैदान, खेल सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध होती है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

मुख्यमंत्री खेल प्रतिभाखोज योजना के अन्तर्गत पांच खेलों (घुड़सवारी, तीरन्दाजी, निशानेबाजी, हॉकी एवं बास्केटबॉल) में संचालित की गई जिसमें पूर्ण राजस्थान से 145 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ियों को नियमानुसार रु. 1.00 लाख प्रति खिलाड़ी छात्रवृति प्रदान की जा रही है। ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर के तहत् बाड़मेर जिले में एथलेटिक्स, वालीबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबिल-टेनिस आदि खेलों में शिविर आयोजन कर 90 खिलाड़ियों को लाभान्वित किया गया। खेलों इंडिया योजनान्तर्गत पांच खेलों पर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कर राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खिलाडियों ने भाग लिया।

(2) निम्नांकित खिलाड़ियों को खेल अधिकारी कार्यालय से निम्न खेल में लाभान्वित किया गया है:-

क्र. सं.	खेल	श्रेणी	खिलाड़ियों की संख्या
1.	बास्केटबॉल	अन्तरराष्ट्रीय	1
2.	बास्केटबॉल	राष्ट्रीय	3
3.	वालीबॉल	राष्ट्रीय	8

इसके अतिरिक्त खेलों संघों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में बाड़मेर जिले से लगभग 300 खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वालीबॉल, हैण्डबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, जूडो, कुश्ती पॉवरलिफिटंग, बैडमिंटन आदि खेलों मे भाग लिया।

इसी प्रकार भारत सरकार की खेलो इंडिया योजनान्तर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता, बाड़मेर में लगभग 1500 खिलाड़ियों ने U-14 एवं U-17 वर्ग में भाग लिया तथा इनमें से चयनित 160 खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

इसी प्रकार लगभग 50 खिलाड़ी (बालक/बालिका) प्रतिदिन नियमित रूप से खेल अधिकारी कार्यालय के तहत विभिन्न खेलों में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(3) बाड़मेर जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद/युवा मामले एवं खेल विभाग का स्टैडियम नहीं है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

आदर्श स्टैडियम स्थित है, जिसका स्वामित्व नगरपालिका का है।

उक्त स्टैडियम पर एथलेटिक्स ट्रेक, वालीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इण्डोर हॉल (बैडमिंटन, टेबिल-टेनिस एवं जिम्नेजियम), क्रिकेट, खो-खो, कबड्डी आदि की सुविधा उपलब्ध है।

स्टेडियम विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत जिला मुख्यालयों पर 400 मीटर एथेलेटिक ट्रैक, फुटबॉल, हॉकी, हैण्डबॉल, बास्केटबॉल, वालीबॉल, टेनिस, खो-खो, कबड्डी मैदान, इण्डोर स्टेडियम, कार्यालय भवन, दर्शक दीर्घा, जिम्नेजियम का निर्माण करवाये जाने का प्रावधान है।

स्टेडियम पॉलिसी के अनुसार उक्त स्टेडियम में हॉकी, हैण्डबॉल एवं टेनिस खेल मैदान का अभाव है।

बस्सी के गांवों को रोडवेज बस सेवा से जोड़ने की योजना

211. श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कई ग्राम व पंचायत मुख्यालय रोडवेज बस सुविधा से जुड़े हुए नहीं हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों व पंचायत मुख्यालयों को रोडवेज बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के निगम/ग्रामीण परिवहन सेवा से जुडे/वंचित ग्राम पंचायत का विवरण निम्नानुसार है सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है:-

पंचायत समिति	कुल ग्राम पंचायत	निगम/ग्रामीण परिवहन सेवा से जुड़ी ग्राम पंचायत	निगम/ग्रामीण परिवहन सेवा से वंचित ग्राम पंचायत
बस्सी	41	25	16
चाकसू (आंशिक)	05	05	0

(परिवहन मंत्री)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के निगम/ग्रामीण परिवहन सेवा से जुडे/वंचित ग्रामों का विवरण निम्नानुसार है सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है:-

पंचायत समिति	कुल ग्राम पंचायत	निगम/ग्रामीण परिवहन सेवा से जुडे ग्राम	निगम/ग्रामीण परिवहन सेवा से वंचित ग्राम
बस्सी	217	70	147
चाकसू (आंशिक)	29	11	18

(2) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र बस्सी के निगम बस सेवा से वंचित पंचायत मुख्यालयों/ग्रामों को जोडने का फिलहाल कोई विचार नहीं है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनाई गयी सड़कों का रख-रखाव

212. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनाई गयी सड़कों के रख रखाव और पुनरूद्धार के लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों के रख रखाव का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रदेश में 250 से कम आबादी की ढाणियों /मजरों को डामर सड़कों से जोड़ने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि राज्य को केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण एवं सड़को की मरम्मत के लिये पर्याप्त राशि प्राप्त नही हो रही हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने के लिये योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी व नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश के धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिये कोई अलग से बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का रखरखाव 5 वर्ष तक सम्बन्धित संवेदक द्वारा किया जाता है एवं अनुबन्ध संवेदक द्वारा किया जाता है एवं अनुबन्ध के अनुसार संवेदक द्वारा मांगी गयी राशि का राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराकर संवेदक द्वारा मांगी गयी राशि का भुगतान किया जाता है। 5 वर्ष के पश्चात् प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़क के पुनरुद्धार हेतु आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, पारस्परिक प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की दिशा निर्देशानुसार 250 से कम आबादी की ढाणी/मंजरों को डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रावधान वर्तमान में नहीं है। इन ढाणियों/मंजरों को डामर सड़क से जोड़ा जाना राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय, पारस्परिक प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) जी नहीं। वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नवीन नीति अनुसार 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी जिसका प्रावधान दोनों स्तर पर उपलब्ध है, वर्तमान में 952 करोड़ रु. का प्रावधान है जो कि उपलब्ध है एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के 5 वर्ष तक रखरखाव हेतु अनुबन्ध के अनुसार राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है।

(4) धार्मिक स्थलों को जोड़ने हेतु मांग के आधार पर समय-समय पर स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

ससेड़ी ग्राम (करौली) में स्वीकृत स्थान के बजाय अन्य स्थान पर सड़क का निर्माण

213. श्री दर्शन सिंह (करौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम ससेड़ी में

(श्री दर्शन सिंह)

गौरव पथ योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण कार्य स्वीकृत स्थान के बजाय अन्य स्थान पर करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी व ठेकेदार के विरुद्ध जांच करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण कार्य माली बस्ती के नाम से स्वीकृत हुआ है, जिसका बोर्ड भी उक्त स्थान पर लगा हुआ होने के उपरान्त भी सड़क निर्माण कार्य ग्राम की टंकी के पास दूरस्त स्थान पर करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों व इसमें लिप्त दोषियों के विरुद्ध सरकार कब तक व क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र करौली में ग्रामीण गौरव पथ योजनान्तर्गत पंचायत मुख्यालय ससेड़ी में ही स्वीकृत है, कार्य के नाम में सहवन से सिर्फ माली बस्ती अंकित हो गया था। कार्य के स्वीकृत तकमीने में पंचायत मुख्यालय ससेड़ी का मुख्य मार्ग प्रजापत बस्ती से उप स्वास्थ्य केन्द्र वाया सीनियर सैकण्ड्री स्कूल लिया जाकर निविदा अनुमोदित की गयी एवं इसी अनुरूप कार्य के नाम में संशोधित स्वीकृति जारी की गयी है।

(2) जी नहीं। उक्त कार्य पंचायत मुख्यालय ससेड़ी में ही स्वीकृत हुआ। कार्य के नाम में सहवन से अंकित माली बस्ती को संशोधित कर दिया गया है।

सरदारशहर से रावतसर सड़क का नवीनीकरण

214. श्री भंवरलाल (सरदारशहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरदार शहर से रावतसर हनुमानगढ़ रोड (साड़ासर से बरजांगसर, जैतसीसर, रायपुरा, धाणसिया से नोहर तक) की मरम्मत करवाई गयी है? यदि हां, तो कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़क की मरम्मत पर 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर,

(श्री भंवरलाल)

2016 तक कितनी-कितनी राशि कब-कब व्यय की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क पर पंजाब-हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात प्रदेशों के वाहनों का आवागमन होने के कारण वर्तमान में उक्त सड़क की स्थिति वाहनों के आवागमन लायक नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत एवं नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। साड़ासर से बरजांगसर, जैतसीसर, रायपुरा, धाणसिया होते हुए नोहर तक सड़क की कुल लम्बाई 74 किमी. है, (25 किमी. जिला चूरू व 49 किमी. जिला हनुमानगढ़) समय-समय पर सड़क की मरम्मत करवाई गई है। मरम्मत कार्य का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सड़क की मरम्मत पर 1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2016 तक राशि रु. 7.36 लाख तथा सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण पर राशि रु. 693.00 लाख का व्यय किया गया। किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं। उक्त सड़क पर पंजाब-हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात प्रदेशों के वाहनों का आवागमन होता है एवं वर्तमान में इस सड़क की स्थिति आवागमन योग्य है।

(4) जिला हनुमानगढ़ के अधीन उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त किमी. 30/0 से 33/0 व 40/0 से 42/0 तक का नवीनीकरण का कार्य माह मई, 2017 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

शेष 8.50 किमी. लम्बाई की सड़क का नवीनीकरण करना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के प्रकरण

215. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)- क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 10 वर्षों में विभागीय अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/ अनियमितता के आरोप लगे हैं? यदि हां, तो किस प्रकार के आरोप एवं किस वर्ग के कितने कार्मिकों के विरुद्ध?

(2) उक्त आरोपों के कारण कितने कार्मिकों का कब-कब निलंबन किया गया तथा उनके विरुद्ध जारी आरोप पत्रों पर सुनवाई कर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत 10 वर्षों में विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध 18 प्रकरणों में भ्रष्टाचार एवं 137 प्रकरणों में अनियमितता तथा कर्मचारियों के विरुद्ध 26 प्रकरणों में भ्रष्टाचार एवं 48 प्रकरणों में अनियमितता के आरोप लगे हैं।

(2) भ्रष्टाचार के आरोप में 18 अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया। 16 प्रकरण माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में विचाराधीन हैं एवं 2 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

137 अधिकारियों पर लगे अनियमितता के आरोप अंतर्गत 10 अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया तथा 137 अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर 13 अधिकारियों को दण्डित किया गया। 73 अधिकारियों की जांच समाप्त की गई तथा 51 अधिकारियों की जांच कार्यवाई प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

भ्रष्टाचार के आरोप में 26 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। 23 प्रकरण माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में विचाराधीन हैं तथा 3 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

48 कर्मचारियों पर लगे अनियमितता के आरोप अंतर्गत 11 कर्मचारियों को निलम्बित किया गया तथा 48 कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर 11 कर्मचारियों को दण्डित किया गया। 14 कर्मचारियों की जांच समाप्त की गई तथा 23 कर्मचारियों की जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले की तहसीलों में चम्बल परियोजना से पेयजल की आपूर्ति

216. श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा जिले में चम्बल परियोजना से पेयजल की आपूर्ति हेतु कौन-कौन सी तहसीलों के लिये योजना बनाई गयी है?

(2) क्या उक्त योजना से तहसील सहाड़ा रायपुर व हमीरगढ़ में भी पेयजल की आपूर्ति की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले के 9 शहरों/कस्बों (क्रमश: भीलवाड़ा, गुलाबपुरा, गंगापुर, माण्डलगढ़, माण्डल, आसीन्द, जहाजपुर, शाहपुरा तथा बिजौलिया) एवं वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 12 तहसीलों (वर्तमान में बढ़कर 16 तहसील) के 1688 ग्रामों में सतही जल स्रोत चम्बल नदी से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चम्बल-भीलवाड़ा वृहत् पेयजल परियोजना की दो चरणों में स्वीकृति निम्नानुसार जारी की गयी है:-

(अ) प्रथम चरण में आधारभूत संरचनाओं के कार्य एवं भीलवाड़ा शहर की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय नीति निर्धारण समिति की 187वीं बैठक दिनांक 27.09.2011 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 727.99 करोड़ तथा

(ब) द्वितीय चरण मे भीलवाड़ा जिले के शेष 8 कस्बों एवं 1688 ग्रामों

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

को कलस्टर वितरण प्रणाली द्वारा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु विभागीय नीति निर्धारण समिति की 190वीं बैठक दिनांक 30.05.2013 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1495.68 करोड़ ।

द्वितीय चरण में सम्मिलित उक्त तहसीलों के 1688 ग्रामों को 8 पैकेजों में लाभान्वित करना प्रावधित है। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। चम्बल-भीलवाड़ा वृहत् पेयजल परियोजना की द्वितीय चरण की उक्त स्वीकृति के चतुर्थ पैकेज में तहसील सहाड़ा के 101 ग्राम, तहसील रायपुर के 89 ग्राम तहसील भीलवाड़ा के 136 ग्राम (तहसील हमीरगढ़ के सृजन उपरांत 41 ग्राम सहित), इस प्रकार कुल 326 ग्राम एवं गंगापुर कस्बे को उक्त परियोजना से लाभान्वित करने हेतु राशि रुपये 418.36 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 29.08.2013 को मैसर्स प्रतिभा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई को जारी किया गया। कार्यादेश अनुसार इस पैकेज का कार्य दिनांक 07.09.2016 तक पूर्ण करना निर्धारित था।

अनुबंधक फर्म द्वारा उक्त पैकेज के कार्यों की प्रगति अत्यन्त धीमी रखने एवं विभिन्न विवाद उत्पन्न करने के कारण परियोजना कार्यों में विलम्ब हुआ है। परियोजना के कार्यों की गति धीमी रखने एवं निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार विभाग द्वारा अनुबंधक फर्म से अधिकतम 10 प्रतिशत राशि रुपये 41.836 करोड़ शास्ति के रूप में आरोपित की जाकर रोकी गयी है।

अनुबंधक फर्म द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना के कार्यों की निर्धारित प्रगति नहीं देने के कारण विभागीय वित्त समिति की 709वीं बैठक दिनांक 19.09.2016 द्वारा निर्णय लिया जाकर अनुबंध के क्लॉज-2 एवं 3 के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.10.2016 को कार्य रिसाइण्ड किया जा चुका है।

उक्त पैकेज के शेष कार्यों को पूरा कराने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 14.02.2017 को निविदा आमंत्रित की गयी है जो दिनांक 16.03.2017 को प्राप्त की जानी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्यादेश उपरांत इस पैकेज

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

के कार्यों को आगामी 32 माह में पूर्ण करना अपेक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के फ्लोराइड क्षेत्र में आर.ओ. प्लांट लगाने की योजना

217. श्री रमेश (सपोटरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक कुल कितने आर.ओ. प्लांट कितनी राशि से लगाये गये? जिलेवार संख्या एवं कुल राशि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में आर.ओ. प्लांट लगाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं एवं इस हेतु स्थान का चयन किस आधार पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 तक किस-किस कंपनी के आर.ओ. प्लांट किस-किस दर से खरीदे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश के किस-किस फ्लोराईड प्रभावित क्षेत्र में कितने-कितने आर.ओ. प्लांट लगाये गये एवं कितने फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी आर.ओ. प्लांट कम संख्या में/नहीं लगे हैं व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के विभिन्न जिलों में माह जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 की अवधि में कुल 1004 आर.ओ.संयंत्रों के स्थापना कार्य पर रुपये 13009.47 लाख की राशि व्यय की गयी। जिलेवार संख्या एवं राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में आर.ओ. संयंत्र के स्थापन कार्य एवं स्थान चयन के आधार बाबत मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में आर.ओ. संयंत्र के स्थापन कार्य हेतु माह जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2016 की अवधि में विभाग द्वारा 9 निविदाएं आमंत्रित की जाकर इनके आदेश जारी किये गये। विभागीय वित्त समिति की दिनांक

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

29.01.2016 एवं 09.02.2016 को सम्पादित हुई 695वीं एवं 696वीं बैठकों के निर्णय में निविदा अंतर्गत स्वीकृत की गयी फर्म/कम्पनी एवं अनुमोदित दरों का विवरण परिशिष्ट-स में निहित है।

(4) प्रदेश में पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित गांवों की समस्या के अल्पकालिक समाधान हेतु जल में फ्लोराइड के आधिक्य से ग्रसित ग्राम/ढाणी में आर.ओ. संयंत्र स्थापना का कार्य नहीं किया जाता है अपितु वहां पर डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र का निर्माण किया जाता है। ऐसे गांव/ढाणी जो खारेपन एवं अन्य रसायनों के आधिक्य से ग्रसित हैं, वहां पर आर.ओ. संयंत्र स्थापना का कार्य किया जाता है। आर.ओ. संयंत्र पानी के खारेपन के साथ-साथ फ्लोराइड सहित अन्य घुलनशील रसायनों की मात्रा को कम करता है।

विभाग द्वारा स्थापित किये गये आर.ओ. प्लांट से 577 फ्लोराइड प्रभावित ग्राम/ढाणी लाभान्वित हुई हैं तथा शेष आर.ओ. संयंत्र की स्थापना से 1003 फ्लोराइड प्रभावित गांव/ढाणी लाभान्वित होंगे। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में ऊंची कीमत पर एल.ई.डी. लाइटें खरीदने पर कार्यवाही

218. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा बाजार दर से दस गुना उंची कीमत पर एल.ई.डी. लाइटें क्रय की हैं, यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रेट व क्वालिटी की जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलम्बित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में एल.ई.डी. लाइटें अधिक दरों पर क्रय किये जाने का

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में आने पर प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर की गयी जांच अंतर्गत प्राप्त अंतरिम रिपोर्ट में तत्कालीन वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), जयपुर को दोषपूर्ण एवं भ्रामक राय प्रदत्त करने का उल्लेख करते हुए विस्तृत जांच हेतु दिनांक 31.01.2017 को दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

समिति द्वारा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर तद्नुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

(2) उपरोक्तानुसार ।

सोजत नगरपालिका क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु कार्ययोजना

219. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सोजत नगरपालिका के कौन-कौनसे वार्डों में स्वच्छ पेयजल हेतु पाइप लाइन नहीं है? क्या सरकार पेयजल पाइप लाइनों से वंचित वार्डों में पाइप लाइन बिछाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त नगरपालिका क्षेत्र में हो रही अनियमित पेयजल आपूर्ति को सुचारु व व्यवस्थित करने के लिए नया उच्च जलाशय बनाने व पुरानी जर्जर लोहे की पाइप लाइनों की जगह नई पाइप लाईन बिछाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सोजत नगरपालिका के वार्ड संख्या 1, 3, 4, 6, 19, 21, 25 एवं 30 के विस्तारित क्षेत्रों (यथा नेहड़ा बेरा, मगरिया बेरा, पंचोल नाड़ी, निम्बली नाड़ी, नृसिंहपुरा कच्ची बस्ती, रेन्दड़ी रोड, घिनावास रोड इत्यादि) में पेयजल हेतु वितरण पाइप लाइनें वर्तमान में बिछी हुई नहीं हैं।

सोजत कस्बे के उक्त वार्डों के विस्तारित क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण कस्बे में नियमित पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु नवीन पम्पिंग मशीनरी, राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइनें, उच्च जलाशय इत्यादि कार्यों का प्रावधान लेते हुए

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पुनर्गठित जल योजना के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। सक्षम स्तर पर इन प्रस्तावों के प्राप्त होने एवं तकनीकी परीक्षण में इनके सही पाये जाने के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार इनकी स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

(2) जी हां। सोजत कस्बे में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि में पेयजल संबंधी विभिन्न कार्यों (जल भण्डारण क्षमता बढ़ाने हेतु नवीन जलाशयों का निर्माण, फिल्टर प्लांट के सुदृढ़ीकरण का कार्य, राइजिंग पाइप लाइन, नलकूप निर्माण इत्यादि) हेतु राशि रुपये 288.07 लाख की स्वीकृतियां जारी की जाकर समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सोजत कस्बे में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार हेतु उक्तानुसार पुनर्गठित जल योजना के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सिलीसेढ़ बांध (अलवर) की नहरों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

220. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिलीसेढ़ बांध अलवर से शहर के कम्पनी बाग एवं अन्य स्थानों पर सिंचाई आदि के लिये पूर्व में नहर बनी हुई थी? यदि हां, तो कहां से कहां तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नहरों पर काफी समय से अनेक लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर नहरों का स्वरूप समाप्त करने का कार्य किया गया है? यदि हां, तो किन-किन लोगों के द्वारा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त अतिक्रमियों से नहर के क्षेत्र को मुक्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सिलीसेढ़ बांध से अलवर शहर के कम्पनी बाग एवं अन्य स्थानों पर सिंचाई आदि के लिए दो नहरें क्रमश: अपर केनाल एवं लोअर कैनाल निर्मित थी। इनके निर्मित स्थलों सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। सिलीसेढ़ की अपर एवं लोअर कैनाल का अधिकतम कमाण्ड क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आने से नहरों के आसपास यू.आई.टी. एवं अन्य कालोनी के निर्माण हो जाने से नहरों पर अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण के अन्तर्गत चिन्हित व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। नहरों पर अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी किये जा चुके है। अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु जिला प्रशासन के सहयोग से कारवाई किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर के बांध एवं फीडरों के लिए स्वीकृत राशि

221. श्री शंकरसिंह (ब्यावर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कितने बांध एवं फीडर हैं तथा कितने बांध एवं फीडर पूर्ण व अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने तालाब ऐसे हैं, जो फीडर के अपूर्ण होने के कारण उनमें पानी नहीं भर रहा है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फीडरों के पूर्ण होने पर कई तालाब वर्षा के मौसम में पूर्ण रूप से भर सकते हैं?

(4) गत तीन वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने बांधों एवं फीडरों के लिए राशि स्वीकृत की गयी व कितनों के लिए राशि स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 9 तालाब एवं 5 फीडर है, इनमें से 3 फीडर पूर्ण एवं 2 फीडर अपूर्ण है विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(जल संसाधन मंत्री)

(2) विभाग के अन्तर्गत दो बांध क्रमश: काबरा तालाब एवं राजियावास तालाब ऐसे है जो फीडरों के अपूर्ण रहने के कारण नहीं भर पा रहे है।

(3) विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में दो अपूर्ण फीडरों में से एक देवाता फीडर का कार्य माह जुलाई, 2017 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है जिससे काबरा तालाब में 49.135 Mcft पानी की अतिरिक्त उपलब्धि होगी तथा सूराघाटा फीडर के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति की प्रक्रिया में प्रक्रियाधीन है। स्वीकृति उपरान्त अग्रिम कारवाई की जानी प्रस्तावित है। सूराघाटा फीडर से राजियावास तालाब में 11.11 Mcft अतिरिक्त जल की प्राप्ति होगी।

(4) गत तीन वर्षों में ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में स्थित बांधों एवं फीडरों पर स्वीकृत राशि एवं भविष्य में प्रस्तावित राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में नहरों को पक्का करने पर अधिशेष सिंचाई के पानी का उपयोग

222. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा श्रीगंगानगर जिले की सभी नहरों को पक्का किया जा चुका है? यदि हां, तो नहरों को पक्का करने के बाद अधिशेष सिंचाई के पानी का उपयोग कहां किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

श्रीगंगानगर जिले में स्थित गंगनहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत नहरों को पक्का करने का कार्य प्रगतिरत होने से अधिशेष जल का निर्धारण बकाया है, जिस क्षेत्र में नहरों को पक्का किया जा चुका है, उस क्षेत्र में अधिशेष जल का उपयोग उसी क्षेत्र में सिंचाई सघनता बढ़ाने में किया जा रहा है।

प्रदेश में सब्सिडीधारी व गैर सब्सिडीधारी

एल.पी.जी. उपभोक्ता

223. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कुल कितने एल.पी.जी. उपभोक्ता हैं तथा उनमें से कितने एल.पी.जी. उपभोक्ता रियायती श्रेणी के व कितने उपभोक्ता गैर रियायती श्रेणी के हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह सही है कि सभी तेल कम्पनियों ने प्रदेश में रियायती श्रेणी के एल.पी.जी. उपभोक्ताओं के लिए 30 नवम्बर, 2016 (पार्किग पीरियड) तक आधार कार्ड की अनिवार्यता लागू कर दी है? यदि हां, तो क्या पार्किग पीरियड के बाद आधार रजिस्ट्रेशन नम्बर नही देने पर, सब्सिडी प्राप्त कर रहे एल.पी.जी. उपभोक्ता सामान्य श्रेणी में हो गये हैं? यदि हां, तो अब कितने सब्सिडी धारी व गैर सब्सिडीधारी उपभोक्ता हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, राजस्थान से प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेश में कुल 1.08 करोड़ एल.पी.जी. सक्रिय उपभोक्ता हैं, जिनमें से 89.40 लाख एल.पी.जी.सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। (स्थिति दिनांक 01 फरवरी, 2017 के अनुसार)

(2) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के तहत प्रमाणित आधार नम्बर अथवा आधार के लिए नांमाकन भरने के सबूत एल.पी.जी. सब्सिडी लेने के लिए 30 नवम्बर, 2016 से अनिवार्य होगा। 30 नवम्बर, 2016 के बाद जो लोग उक्त सबूत देने में असमर्थ होंगे, उनकी सब्सिडी पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से रोक लगा दी जाएगी। अधिसूचना दिनांक 30 सिम्बर, 2016 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

दिनांक 01.02.2017 तक 1.08 करोड एल.पी.जी.ग्राहकों में से 89.40 लाख (82.71 प्रतिशत) एल.पी.जी.ग्राहकों को सब्सिडी उनके आधार लिंक बैंक खातों में स्थानान्तरित की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में नये राशन डीलर्स हेतु साक्षात्कार

224. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले में नये राशन डीलर्स बनाने हेतु साक्षात्कार लिये गये है? यदि हां, तो कौन-कौनसी तहसील में किस-किस दिनांक को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बारां जिले में नये राशन डीलर्स बनाने हेतु साक्षात्कार कमेटी द्वारा चयन किए गये अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है? यदि हां, तो कमेटी द्वारा किये गये चयनित अभ्यर्थियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में नये राशन डीलर की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार लिये गये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम क्षेत्र	साक्षात्कार दिनांक
1.	बारां शहर	08.06.2016
2.	बारां ग्रामीण	09.06.2016
3.	अन्ता शहर	10.06.2016
4.	अन्ता ग्रामीण	10.06.2016
5.	मांगरोल शहर	13.06.2016
6.	मांगरोल ग्रामीण	13.06.2016
7.	छबडा	14.06.2016
8.	अटरू	14.06.2016
9.	छीपाबड़ौद	15.06.2016

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार ही साक्षात्कार कमेटी द्वारा नियमानुसार चयनित अभ्यर्थियों का ही चयन किया गया है। चयनित अभ्यार्थियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के मानदण्ड

225. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुंनू): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जिन्सवार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) घोषित किए जाते हैं? यदि हां, तो इसके निर्धारण के क्या मानदण्ड है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की अभिशंसा/रिपोर्ट के आधार पर समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है?

(3) वर्ष 2014-15 में सरकार द्वारा भेजी गई सिफारिश एवं वर्ष 2014 से जनवरी 2017 तक जिन्सवार बढ़ाये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिन्सवार समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(2) समर्थन मूल्य निर्धारण हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को कोई अभिशंसा नहीं भिजवायी जाती है।

(3) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को वर्ष 2014-15 के तहत कोई सिफारिश नहीं भिजवायी गयी है। वर्ष 2014 से जनवरी, 2017 तक भारत सरकार द्वारा जिन्सवार घोषित समर्थन मूल्य का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा शहर के मन्दिरों में निर्माण कार्य करवाये जाने की योजना

226. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में गत पांच वर्षों में कितने मन्दिरों को नव निर्माण एवं मरम्मत हेतु कितनी-कितनी राशि आवंटित की गयी? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

(2) सरकार द्वारा कोटा नगरीय सीमा में उक्त अवधि में किन-किन मन्दिरों में कितनी-कितनी राशि का निर्माण कार्य करवाया जा चुका है तथा किन-किन मन्दिरों में निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु क्या-क्या योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में देवस्थान विभाग द्वारा नव निर्माण एवं मरम्मत हेतु आंवटित राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कोटा नगरीय सीमा में उक्त अवधि में मंदिरों में निर्माण हेतु व्यय की गयी राशि एवं भविष्य में प्रस्तावित योजना में निर्माण हेतु करवाये जाने वाले कार्य का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या 227

(स्थगित)

सिकराय में आंगनबाड़ी केन्द्रों से लाभान्वित बालक एवं महिलाएं

228. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय में आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां संचालित किए जा रहे हैं तथा उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने- कितने बालकों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त केन्द्र स्वयं के भवनों में संचालित हो रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार भवन विहिन केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी केन्द्रों पर पोषाहार समय पर उपलब्ध करवाया जाता हैं? यदि हां, तो खाद्य सामग्री किसके द्वारा व कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध करवाई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के अन्तर्गत 02 परियोजनाएं क्रमश: बाल विकास परियोजना सिकराय एवं दौसा ग्रामीण संचालित है, जिसमें परियोजना

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

सिकराय में 197 एवं दौसा ग्रामीण में 75 आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 272 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसमे 270 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाडी केन्द्रवार लाभान्वित बालकों एवं महिलाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र सिकराय में संचालित 270 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 69 केन्द्र विभागीय भवनों में, 143 केन्द्र राजकीय विद्यालयों में, 28 केन्द्र अन्य राजकीय भवनों में तथा 30 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य भूमि आवंटन व उपलब्धता के पश्चात् विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(3) जी हां। समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत समस्त इच्छुक पंजीकृत आयु वर्ग 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार वर्ष में 300 दिवस पूरक पोषाहार स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जमवारामगढ़ में राजश्री योजना से लाभान्वित बालिकाएं

229. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो उक्त योजना के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजश्री योजनान्तर्गत अब तक कुल कितनी बालिकाओं को लाभान्वित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए दिनांक 1 जून, 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना संचालित की जा रही है। योजना के दिषा-निर्देषों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में योजना के अन्तर्गत 1 जून, 2016 से 31 जनवरी, 2017 तक कुल 575 बालिकाओं को राजश्री योजनान्तर्गत प्रथम किष्त से लाभांवित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खरसाण (वल्लभनगर) में आंगनबाड़ी चयन में अनियमितता

230. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की खरसाण पंचायत में आंगनबाड़ी तृतीय के चयन में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की खरसाण पंचायत आंगनबाड़ी तृतीय पर प्रशासन गावं के संग अभियान के तहत दिनांक 28.12.2010 को आयोजित ग्राम सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनी का चयन के संबंध में जिला कलक्टर महोदय के यहां शिकायत प्राप्त हुई थी, प्राप्त शिकायत का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

इस संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय के पत्रांक 477 दिनांक 31.03.2011 द्वारा उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय को जांच हेतु प्राप्त हुई थी, जिस पर उप निदेशक द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी, भीण्डर को जांच कर, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था। बाल विकास परियोजना अधिकारी, भीण्डर द्वारा जांच करने पर उक्त चयन विभागीय नियमानुसार पाया गया जांच रिपोर्ट का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में खनन कार्य में हुए खड्डों को नहीं भरने पर कार्यवाही

231. श्री दलीचन्द डांगी (मावली): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में आवंटित खानों में कितने फीट गहराई तक खनन कार्य करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा आवंटित खानों में खनन कार्य के उपरान्त 100-100 फीट तक गहरे खड्डे हो जाते हैं एवं वर्षा काल में इनमें पानी भर जाने से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं? यदि हां, तो उक्त खानों की भराई के क्या नियम व प्रावधान हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आवंटित खानों के खड्ड़ों की भराई की जिम्मेदारी खान मालिक की है? यदि हां, तो उक्त खड्ड़े खान मालिकों से नहीं भराने की जिम्मेदारी किन-किन विभागीय अधिकारियों की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों व खान मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा आवंटित खानों में खनन कार्य की गहराई के संबंध में खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन्स उर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में कोई प्रावधान नहीं है। खान धारक अनुमोदित माइनिंग प्लान/माइनिंग स्कीम/सिम्पलीफाइड माइनिंग स्कीम में वर्णित अल्टीमेट पिट डैप्थ तक खनन कार्य कर सकता है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा आवंटित खानों में खान धारकों द्वारा खनन कार्य किये जाने से कई स्थानों पर काफी गहरे खनन पिट (गढ्ढ़े) हो गये हैं, जिनमें वर्षाकाल में पानी भर जाता है। खनन पिट में पानी भरने से दुर्घटना का कोई प्रकरण विभाग के ध्यान में नहीं आया है। प्रभावशील खनन पट्टों में खनन पिट की सुरक्षा हेतु सामान्यतया खानधारकों द्वारा खनन पिट के चारों ओर बाड्बंदी (फेन्सिंग) करवाई जाती है। खनन पिट के री-क्लेमेशन की कार्यवाही खानधारकों द्वारा अनुमोदित माइन क्लोजर प्लान के अनुसार की जाती है।

(राज्य मंत्री, खान)

(3) जी हां। आवंटित खानों में खनिज समाप्त हो जाने के पश्चात् अथवा खनिज आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होने पर से खनन के दौरान हुए खड्ड़ों के रि-क्लेमेशन की जिम्मेदारी खानधारक की होती है। इस हेतु खानधारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान प्राप्त किया जाता है जिसमें खनन के दौरान हुए खड्ड़ों के पुनर्भरण अथवा अन्य प्रकार से रि-क्लेमेशन किये जाने का विवरण होता है। यदि खानधारकों द्वारा माइन क्लोजर प्लान के अनुसार क्षेत्र का रि-क्लेमेशन नहीं किया जाता है तो उसके द्वारा जमा कराई गयी वित्तीय आश्वासन की राशि सम्बन्धित खनिज अभियन्ता/सहायक खनिज अभियन्ता द्वारा नियमानुसार जब्त की जाकर उस राशि से उस खान का रि-क्लेमेशन कराये जाने का प्रावधान है। विभाग के ध्यान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है जिसमें आवंटित खान में खनिज समाप्त हो गया हो व ऐसी खान के री-क्लेमेशन की कार्यवाही नहीं की गयी हो।

(4) जी नहीं। विभाग के ध्यान में ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया हैं। प्रकरण सामने आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

बारां-अटरू में खनन सामग्री की ओवरलोडिंग पर रोक

232. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार अटरू क्षेत्र में अवैध खनन व खनन सामग्री की ओवरलोंडिंग पर अंकुश लगाने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन व खनन सामग्री की ओवरलोडिंग के कितने प्रकरण सामने आये व उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खान विभाग द्वारा अवैध खनन/निर्गमन पर अपने स्तर पर अंकुश लगाने के साथ-साथ अन्य विभागों यथा राजस्व, पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ संयुक्त रूप से समय-समय पर चैकिंग की जाती है। चैकिंग के दौरान अवैध खनन/निर्गमन के प्रकरण पाये जाने पर पैनल्टी वसूली की

(राज्य मंत्री, खान)

कार्यवाही/एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही की जाती है। जहां तक वाहनों में खनन सामग्री की ऑवरलोडिंग पर अंकुश लगाने का प्रश्न है, इस पर आवश्यक कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाती है।

(2) गत 2 वर्षो में बारां-अटरू विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन के मामलों में खान विभाग द्वारा 96 प्रकरण बनाये जाकर 5 मामलों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी तथा शेष 91 मामलों में 33.84 लाख रुपये की शास्ति वसूल की गयी। परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कुल 14 चालान बनाए जाकर प्रशमन राशि 1.28 लाख रुपये वसूल किये गये। पुलिस विभाग द्वारा 20 प्रकरणों में सक्षम न्यायालयों के समक्ष चालान पेश किये गये।

प्रदेश में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम संख्या 37 एन की पालना

233. श्री हीरालाल (निवाई): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम संख्या 37 एन की पालना के लिये जारी नोटिसों की अवहेलना करने वाले लीज धारकों/क्वारी लाइसेंस धारकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला राजसमंद, वृत्त अजमेर, वृत्त बीकानेर और वृत्त जोधपुर में उपरोक्त नियम 37 एन की पालना संबंधी नोटिस नहीं जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्य में लापरवाही बरतने और अनियमितता करने पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त नियम 37 एन के तहत नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी व्यक्तियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(राज्य मंत्री, खान)

(4) क्या सरकार उपरोक्त नियम के तहत नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी व्यक्तियों को उचित वेतन देने हेतु मानिटरिंग की व्यवस्था करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेंज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 निरसित कर दिये गये है। जिन लीजधारकों/क्वारी लाइसेंसधारकों को तत्समय प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37एन की पालना नहीं करने पर नोटिस जारी किये गये हैं, नोटिस अवधि समाप्ति पश्चात् नियमानुसार शास्ति आरोपित करने, खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अन्तर्गत की जावेगी।

(2) जिला राजसमंद, वृत्त अजमेर, वृत्त बीकानेर एवं वृत्त जोधपुर के अधीन आने वाले खनन पट्टाधारकों/क्वारी लाइसेंसधारकों (सहायक खनि अभियंता, चुरू कार्यालय में 57 खनन पट्टें वन क्षेत्र में आने के कारण खनन गतिविधियां बंद है, उन्हें नोटिस जारी नहीं किये गये) को तत्समय प्रभावी राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 37एन के तहत नोटिस जारी किये गये। नोटिस अवधि समाप्ति पश्चात् नियमानुसार शास्ति आरोपित करने, खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अन्तर्गत की जावेगी। इन वृत्तों में किसी भी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने या अनियमितता करने का प्रकरण नहीं है।

(3) जी नहीं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 निरसित कर दिये गये है। इन निरसित नियमों/नये राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 30 के तहत नियुक्त किये जाने वाले तकनीकी व्यक्तियों का न्यूनतम वेतन निर्धारण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) नियमों में वेतन निर्धारण का प्रावधान नहीं है। अत: इस संबंध में मानिटरिंग की आवश्यकता नहीं है।